राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–1 दसवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का नवां दिवस संख्या–5

बुधवार,

5 जनवरी, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 40

श्री अध्यक्ष : डाक्टर हरिसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नेक्स्ट, श्री कुबेर सिंह।

जयपुर नगर निगम क्षेत्र के पार्कों की भूमि की नीलामी

41. **श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :** क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित जयपुर की आवासीय कालोनीज के पार्कों को आवासन मण्डल द्वारा जयपुर नगर निगम को स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस कालोनी के पार्कों को व क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर नगर निगम द्वारा मालवीय नगर कालोनी के सेक्टर 2, 3 व 4 के पार्कों की भूमि नीलामी द्वारा विक्रय की गई है। यदि हां, तो यह भूमि किस प्रयोजन से व किन नियमों के आधार पर विक्रय की गयी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर अनधिकृत निर्माण कार्य हो रहे हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि आवासन मण्डल द्वारा पार्कों की भूमि स्वच्छ पर्यावरण व सार्वजनिक कार्यों हेतु छोड़ी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार निगम द्वारा नीलाम की गयी भूमि की नीलामी निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 41 स्थगित किया गया। नेक्स्ट, श्री खेतसिंह।

शेरगढ़ (जोधपुर) में खाद्यान्न वितरण

42. **श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :** क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर में प्रति व्यक्ति कितना किलो अनाज दिया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में प्रति व्यक्ति ज्यादा अनाज दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या शेरगढ़ तहसील में भयंकर अकाल होने से गेहूं की बड़ी मांग है ? यदि

(श्री खेतसिंह राठौड़)

हां, तो क्या सरकार गेहूं का कोटा बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) जोधपुर जिले को पिछले 6 माह में किस हिसाब से कितना गेहूं व चावल आवंटित किया गया ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री रामप्रताप) : (1) तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर में माह अप्रेल, 93 से सितम्बर, 93 तक 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति दिया जा रहा था। लेकिन अक्टूबर, 93 से 7 किलो गेहूं का प्रति व्यक्ति आवटन किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा अनाज का आबंटन जिलेवार किया जाता है, जो जिलों की मांग, पूर्व माहों में उठाव और केन्द्र सरकार से प्राप्त आबटन आदि को ध्यान में रख कर किया जाता है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उप-आबंटन जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है।

(3) जी हां। जोधपुर जिले की सभी तहसीलों से गेहूं की बढ़ी हुई मांग के आधार पर जिला प्रशासन ने गेहूं का ग्राबंटन बढ़ाने का निवेदन किया है, जिस पर केन्द्र सरकार से राज्य को अधिक ग्राबंटन होने पर ही कार्यवाही सम्भव होगी।

(4) जोधपुर जिले को पिछले 6 माह में केन्द्र सरकार से प्राप्त आबंटन के आधार पर गेहूं एवं चावल का निम्न प्रकार आबंटन किया गया :—

माह	गेहूं	चावल
	(आबंटित मात्रा मी. टनों में)	
जुलाई, 93	11000	1000
अगस्त, 93	11000	1000
सितम्बर, 93	11000	1000
अक्टूबर, 93	9720	150
नवम्बर, 93	9000	150
दिसम्बर, 93	9000	150

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान पत्रिका में पढ़ा था कि एफ. सी. आई. के पास में गेहूं की कोई कमी नहीं है और गेहूं सड़ रहा है। हजारों टन गेहूं सड़ रहा है और यहां से आपकी मांग न जाने की वजह से गेहूं का ग्राबंटन कम हुआ और उसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह भी निवेदन करूंगा कि 4 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से आज शेरगढ़ तहसील के अन्दर गेहूं मिल रहा है। यह जो फिगर्स दिये हैं आपने 10 किलो और 7 किलो, बिलकुल गलत हैं। आप निश्चित तौर पर जांच करवा लीजिये, 4 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिल रहा है। बाजरी के भाव वहां पर 550 रुपये क्विंटल हैं और फेमिन में काम खुला नहीं है, लोग बेहद परेशानी में हैं। विरोध है तो आपका और मेरा है, जनता का तो विरोध नहीं है। जनता के साथ तो कम से कम आपको न्याय करना चाहिये। जनता ने क्या बिगाड़ा है आपका ? आपने जो इसमें लिखा है, यदि आप 7 किलो प्रति व्यक्ति दे देते हैं तो भी, मैं आपको

(श्री खेतसिंह राठौड़)

निवेदन करूंगा, काफी है। लेकिन हकीकत में 4 किलो से ज्यादा धान नहीं मिल रहा है। वहां फेमिन के वर्क्स नहीं, धान नहीं और यही हाल फलौदी का है। माननीय सदस्य, फलौदी वाले भी अभी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में आपके जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा आबटन किया जा रहा है। उसके बाद में दूसरा निवेदन आपसे यह है कि जोधपुर जिले में भी आपकी शेरगढ़ तहसील को सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। जहां तक एफ.सी.आई. में ज्यादा की बात है उसके बारे में जो हमारे यहां से मांग की गयी है उसका भी एक बड़ा अजीब-सा रेश्यो है। हमने मांग की उस वक्त तो एफ. सी. आई. से हमारी मांग कम थी और ज्यादा दिया जा रहा था। जुलाई, 93 से नवम्बर, 93 तक हमने मांग की थी 76,500 मीट्रिक टन की। जुलाई से लेकर सितम्बर तक सेण्टर 95,000 मीट्रिक टन देना चाहता था, आबंटन कर रहा था और उसके बाद में जब हमारी मांग दिसम्बर, 93 से बढ़ी तो यह वापस 76,500 पर आ गया। तो जितना आबंटन हमें भारत सरकार से मिलता है उसके बाद में जिलेवार जो हमारे पास मांग आती है उसके हिसाब से आबंटन किया जाता है। जहां तक सेण्टर से मांग की बात है उसके लिए हमने सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट को 3-4 पत्र भी लिखे हैं और एक फैक्स भी दिया है। आज सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट की आबंटन के बारे में मीटिंग हो रही है, जो कि हर महीने के पहले हफ्ते में होती है, मैं आपको विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे फूड सैक्रेटरी साहिबान विशेष तौर से इसी बात के लिये आज दिल्ली पधारे हैं और जितना भी आबंटन हमें मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको दिया जायेगा। ज्यादा से ज्यादा मिलते हुए भी अगर आप यह बात कहते हैं तो यह मेरी समझ में नहीं आ रहा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह समझ में तो आपको इसलिए नहीं आ रहा है कि आप गंगानगर जिले के हैं और वहां कमी है नहीं और दूसरे में आपने कहा कि साहिबान गये हुए हैं, साहिबान के जाने से कुछ नहीं होगा यह तो मुख्य मंत्रीजी स्वयं प्रयत्न करेंगे तभी जाकर के फूड मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया कोटा बढ़ायेगा। आपके कोई फूड सैक्रेटरी को भेजने से और मंत्रीजी ने कह दिया कि हमारे साहिबान वहां गये हुए हैं उन साहिबान के कहने से कोई असर होने वाला नहीं है। आप मेहरबानी करके प्रयत्न कीजिए और कोटा बढ़वाइये। हकीकत में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जोधपुर पूरा जिला फेमिन अफेक्टेड है। आप जानते हैं शहर के अन्दर भी कन्जम्पशन के लिए गेहूं चाहिए ही और 4 किलो से ज्यादा फलौदी और शेरगढ़ के किसी गांव में आज गेहूं नहीं मिल रहा है इसी की वजह से बाजरी के भाव साढ़े पांच सौ पहुंच गये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा था कि यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसके बारे में है, यह गैट का प्रस्ताव लागू हो जायेगा उसके बाद में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली खतम हो जायेगी उस समय फिर आप यह प्रश्न किससे पूछेंगे? नरसिम्हा रावजी से या इनसे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपसे, जो सरकार में बैठे हुए हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : यह माननीय सदस्य को भ्रम है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बिलकुल समाप्त हो जायेगी और आप सारे देश को भ्रम में डाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न से भिन्न है। गैट इस प्रश्न में नहीं आता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है जिस समय हमारी मांग गयी थी उस समय खाद्य निगम से या भारत सरकार से हमें आबंटन अधिक हुआ और अब जब मांग बढ़ी है तो आबंटन कम हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आपने जैसे कहा, अधिकारी यहां से गये हुए हैं और मैं भी बात करके प्रयत्न करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमें अनाज का आबंटन हो।

श्री अध्यक्ष : नैकस्ट, श्री रामपाल उपाध्याय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जहां तक जनता का विरोध होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, आप जहां से जीतकर आ गये अब विरोध कहां रहा? जनता ने भूल अपने आप ही बुला ली उसका मेरे पास इलाज कहां है?

श्री अध्यक्ष : श्री रामपाल उपाध्याय। हो गया आपका, माननीय मंत्रीजी, बिराजिये।

सहाड़ा–रायपुर क्षेत्र की प्रस्तावित सड़क योजनाएं

43. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहाड़ा–रायपुर तहसीलों में सड़क निर्माण की भावी योजना क्या है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अत्यधिक यातायात वाले गंगापुर-फतेहनगर, गंगापुर-राशमी, पोटलां-गिलुन्ड, रायपुर-कोट-ग्रामेट, रायपुर-जगदीश कोशीथल-आमली मार्गों को पक्का किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा अकाल राहत विभाग सहाड़ा-रायपुर क्षेत्र में सड़क निर्माण का कोई समन्वित कार्यक्रम बना रहा है? यदि हां, तो क्या? नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सहाड़ा क्षेत्र की नेगड़िया, खेड़ा-कुरज तथा रायपुर क्षेत्र की मोखुन्दा-जीलोला की शेष सड़क टुकड़ों को इसी वर्ष पूरा कराना प्रस्तावित है?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) भीलवाड़ा जिले की तहसील रायपुर-सहाड़ा क्षेत्र में आठवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु 7 सड़कों के प्रस्ताव 89.25 लाख रुपये की राशि के 7 गांव, जिनकी जनसंख्या वर्ष 1971 में 1000 से अधिक रही है, को

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

जोड़ने हेतु सम्मिलित किये गए जिनमें से 2 गांव जोड़ दिये गये हैं जिससे 1500 से अधिक आबादी के समस्त गांव सड़क से जुड़ गये हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं, केवल रायपुर-कोट (1129, आबादी) आमेट सड़क को कोटग्राम तक 33·55 लाख रुपये की राशि से पक्का करने का प्रस्ताव आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। परन्तु 93-94 की वार्षिक योजना में स्वीकृत नहीं है। शेष सड़कें निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत न आने के कारण वर्तमान में पक्का करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) जी हां, रायपुर-सहाड़ा अकालग्रस्त क्षेत्र में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कों में से जब अकाल राहत कार्यों को प्रारम्भ किया जायेगा तब इनको प्राथमिकता दी जायेगी।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 7 सड़कें हैं, जिनमें से केवल दो छोटी-छोटी सड़कें डामर से जुड़ी हुई हैं और 5 नहीं जुड़ी हुई हैं, जिनके आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्ताव रखे हैं, कब तक उनका डामरीकरण हो जायेगा? नम्बर एक।

नम्बर दो, रायपुर-कोट-आमेट सड़क को आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना में रखा है और उसके लिये आपने 33.55 लाख रुपये रखे हैं, तो क्या यह 1994-95 में स्वीकृत हो जायेगी?

नम्बर तीन, यह निवेदन है कि आपने फरमाया कि अभी सड़क निर्धारित मापदण्ड में नहीं आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन सड़कों के लिये मैंने निवेदन किया है उनमें एक-एक सड़क पर 18-18, 20-20 बसें रोज आती-जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण मण्डियों से जुड़ी हुई हैं जैसे गंगापुर-फतेहनगर रोड, गंगापुर-आमली रोड से आगे, तो ऐसी सड़कें निर्धारित मापदण्ड में क्यों नहीं आ रही हैं?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न में जिन 7 गांवों को जोड़ने की माननीय सदस्य ने बात कही है, मैंने कहा है कि 1992-97 तक की जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है तब तक डामरीकरण उनका निश्चित रूप से हो जायेगा। 33.55 लाख रुपये रायपुर-कोट सड़क के लिये स्वीकृत हैं, उसमें आपने कहा कि 1994-95 में हैं। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं कहा है। यह बात सच है, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है कि सारे प्रदेश भर के लिये योजना इस प्रकार की बनी है कि ऐसे समस्त गांव जिनकी आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार एक हजार से अधिक है उनको आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1992 से लेकर 1997 तक डामर से जोड़ दिया जायेगा। इस दृष्टि से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के 5,707 गांव

6

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

एक हजार से अधिक की आबादी के हैं। 752 गांव इसमें इस प्रकार के हैं जो किसी भी रोड से जुड़े हुए नहीं हैं, 787 गांव ऐसे हैं जो ग्रेवल सड़क से जुड़े हैं, पर 220 गांव ऐसे हैं जो मैटल सड़क से जुड़े हुए हैं। इस काम को करने के लिये, इनको डामर की सड़क में परिवर्तन करने के लिये 352.43 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। 1710 सड़कें बनेंगी जिनकी लम्बाई कुल 9442 किलोमीटर होगी। इस बात को ध्यान में रखकर यह जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है इसमें इन सारी सड़कों को 352 करोड़ रुपया खर्च करके बनायेंगे। इसके लिए पैसे की व्यवस्था भी हमने कर ली है। विश्व बैंक से जो हमको सहायता मिली है 93 80 करोड़ रुपये, कृषि उपज मण्डी को जो विश्व बैंक से सहायता मिली है, 58.63 करोड़ और सार्वजनिक निर्माण विभाग का मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है, उसमें से 200 करोड़ रुपये, इस प्रकार 352.43 करोड़ रुपये 1997 तक व्यय करके हम इनको सड़क से जोड़ने की योजना बना रहे हैं।

अब माननीय सदस्य ने यह कहा कि इन पर बसें चलती हैं। यह बात सच है किन्तु यह दोनों स्थान एक्स्ट्रीम दो जिलों में हैं. सड़कों से जुड़े हुए हैं। आज प्रदेश की आवश्यकता यह है कि अधिक से अधिक गांव किसी नाते जुड़ते चले जायें।

मैं माननीय सदस्य को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना के पश्चात् हमने इस प्रकार की योजना बनाने का तय किया है कि अब आगे जो 1971 की एक हजार की आबादी है उसके बाद 1981 की एक हजार की आबादी की योजना बनायें, उसके बाद 1991 के 1500 की आबादी की योजना बनायें और उनको इस नाते से जोड़ते चले जायें।

श्री अध्यक्ष : कितने साल लगेंगे और कितने साल पीछे रहेंगे ? 20 साल रहेंगे पीछे या इससे ज्यादा ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 2000 तक की आबादी का राजस्थान का प्रत्येक गांव हम जोड़ देंगे डामर की सड़क से।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपका राज ही साल तक रहेगा।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने जो लम्बी चौड़ी अपनी प्लानिंग बनायी है और हमको बताया है उसमें मेरा प्रश्न कहां खड़ा होता है ? मेरे प्रश्न का स्थान कहां पर है ? नम्बर एक।

नम्बर दो, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण सड़कें हैं गंगापुर-फतेहनगर गंगापुर-राशमी, पोटलां-गिलूण्ड, रायपुर-कोट-आमेर, रायपुर-जगदीश, कोशीथल-आमली आदि जितने मार्ग हैं, इनके लिए 1992 से 1997 के बीच में कोई फंडिंग करने की चेष्टा विभाग ने नहीं की है। मेरा आपसे निवेदन यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम में जैसा मैंने प्रश्न के तीसरे चरण में पूछा है कि इन सड़कों के लिये जो कि राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में हैं, भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा सहाड़ा-रायपुर में अभाव का समय है,

(श्री रामपाल उपाध्याय)

अकालग्रस्त क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग, अकाल सहायता विभाग और कृषि उपज मण्डी समितियों का कोई समन्वित प्रोग्राम बनाने का आपका प्रयास रहेगा या नहीं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समन्वित योजना अकाल राहत कार्य और प्लान की बनायी गयी है उसके अन्तर्गत जितने भी पंचायत केन्द्र हैं उन सबको जे. आर. वाई. और अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत मैटल मे जोड़ने की योजना है, जिनका डामरीकरण हम बाद में कराने वाले हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री रतनलाल ताम्बी ।

जयपुर शहर की नगरीय बस सेवा

44. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में सिटी बस सेवा के तहत कुल कितनी बसें चल रही हैं ? क्या राज्य सरकार इन बसों को जयपुर शहर की आवश्यकता हेतु पर्याप्त समझती है ? यदि नहीं, तो इस सुविधा को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी तक जो बस सेवा शुरु की गयी है उससे गांधीनगर, बजाज नगर आदि क्षेत्र जहां पर विधायकगण, कर्मचारी, अधिकारी व हजारों की तादाद में अन्य जनता भी रहती है, को वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी सुविधा हेतु अनिता कालोनी से वाया बढ़ी चौपड़-जोरावरसिंह गेट व अनित कॉलोनी से गांधीनगर गर्ल्स स्कूल होते हुए ब्रह्मपुरी तक बस सेवा तुरन्त शुरु करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व): (1) जयपुर शहर में सिटी बस सेवा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 189 बसें तथा 504 निजी बसें संचालित हैं । वर्तमान में संचालित मार्गों पर बसों की यह संख्या पर्याप्त है । उपलब्ध संसाधनों के आधार पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कुछ नये मार्गों पर बस सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा ।

(2) जी नहीं । यह सही नहीं है । गांधीनगर, बापूनगर व बजाजनगर क्षेत्र निजी मिनी बसों के विभिन्न मार्गों से जुड़े हुए हैं । बापूनगर क्षेत्र में निगम की सेवाए भी संचालित हैं । सांगानेरी गेट से सांगानेर वाया मुस्लिम मुसाफिरखाना, मोती डूंगरी सर्किल, पुलिस मेमोरियल, जे. डी. ए. सर्किल यूनिवर्सिटी, कानोड़िया कॉलेज, गांधीनगर क्लब, डिस्पेंसरी मोड़, टोंक फाटक, दुर्गापुरा मार्ग पर निकट भविष्य में निगम की नगरीय बस सेवा संचालित की जाने की योजना है, जिसका संचालन प्रारम्भ होने पर गांधीनगर क्षेत्र में परिवहन निगम की नगरीय बस सेवा का विस्तार हो जायेगा । अनिता कॉलोनी से बड़ी चौपड़-जोरावरसिंह गेट व अनिता कॉलोनी से गांधीनगर होते हुए ब्रह्मपुरी तक बस सेवाए

(श्री रोहिताश्व)

उपलब्ध कराने हेतु कुछ मार्गों के पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपने जो स्थान और मार्ग बताये हैं उन पर बस सेवाए कब तक उपलब्ध करवा देंगे ?

श्री रोहिताश्व : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो वर्तमान में वित्तीय संसाधन हैं उसमें वर्ष 1992-93 में राज्य सरकार ने हमको 2 करोड़ रुपया दिया, 1993-94 में हमको करीब 4 करोड़ रुपया मिला, जिससे हमने 100 बसें चलायी और अब 1994-95 में हमको राज्य सरकार 6 करोड़ रुपया और उपलब्ध करवा रही है जिससे हम 100 बसें और चलायेंगे। तो हम चाहते हैं कि चालू सत्र में इनको चलाने में सक्षम होंगे।

श्री अध्यक्ष : ताम्बी जी का काम हो गया।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह जो प्राव-धान बतलाया है राशि का, वह नगरीय सेवा के लिये है या सम्पूर्ण राजस्थान के लिये ?

श्री रोहिताश्व : यह नगरीय सेवा के लिये है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जोगेश्वर गर्ग।

जिला जालौर की खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाएं

45. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग सम्बन्धी कौन-कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं ?

(2) इन संस्थाओं द्वारा कुल कितना खादी का उत्पादन एवं विक्रय किया जाता है ? गत 5 वर्षों का संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जालौर जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के विस्तार एवं विकास की योजना विचाराधीन है ?

राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री श्रीकिशन सोनगरा) : (1) जालौर जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग सम्बन्धी एक संस्था 'वीरम खादी ग्रामोद्योग संघ, जालौर कार्यरत है।

(2) वीरम खादी ग्रामोद्योग संघ, जालौर द्वारा गत 5 वर्षों में किया गया खादी का उत्पादन एवं विक्रय का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	खादी उत्पादन (लाख रुपयों में)	कुल खादी बिक्री (लाख रु. में)
1988-89	6.72	24.19
1989-90	10.73	26.85
1990-91	9.18	24.00
1991-92	8.88	20.75
1992-93	5.88	13.75

(3) जी नहीं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

से मैं जानना चाहूंगा कि वीरम खादी ग्रामोद्योग संघ, जालौर के विक्रय और उत्पादन के आंकड़े दिये हैं, उससे लगता है कि वह संस्था निरन्तर प्रगति कर रही है। इस प्रगति के साथ में यह भी जानना चाहूंगा कि यह लाभ भी प्राप्त कर रही है?

श्री अध्यक्ष : प्रगति कर रही है कि उत्पादन कम हो रहा है?

श्री जोगेश्वर गर्ग : प्रगति कर रही है।

श्री अध्यक्ष : 9, 8, 5,....में उत्पादन को पूछ रहा हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह संस्था लाभ में है कि नहीं? और यदि लाभ में है, तो इस संस्था को और अधिक विस्तार दिया जाना चाहिये जबकि खण्ड तीन में सीधे-सीधे उत्तर दिया है, जी, नहीं। मन्त्री महोदय से मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस संस्था के अन्तर्गत कितने कताई और बुनाई के केन्द्र चल रहे हैं और विक्रय केन्द्र कितने चल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : संस्था का जहां तक लाभ का सवाल है, खादी संस्थाएं शुद्ध रूप से बिना लाभ-हानि के चलायी जाती हैं, खादी आयोग के द्वारा यह नियम है। फिर भी यह संस्था विक्रय के आंकड़ों को देखें तो कोई नुकसान में नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य ने कताई केन्द्र और विक्रय केन्द्र के बारे में पूछा है, कताई केन्द्र....

श्री अध्यक्ष : इसमें आपने लागत तो दी नहीं, पता नहीं चलता लाभ है या हानि है। यह तो उत्पादन दिया है। लागत तो है नहीं इसमें। बिक्री दी है।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : नहीं, ऐसा है, इसमें जो विक्रय होता है, जो उत्पादन होता है, वह तो एक संस्था को....

श्री अध्यक्ष : लागत कितनी है यह नहीं है।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : यह तो पूछा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप जवाब दे रहे हैं कि वह बराबर है. इसलिए कह रहा हूं कि हानि-लाभ तो पता ही नहीं चलता।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : वैसे सिद्धान्त तो यह होता है कि बिना लाभ-हानि के यह संस्थाएं चलती हैं। जहां तक कताई केन्द्र की बात है तो कताई केन्द्र जालौर और कोटवाड़ा, इसरायल, नौखा, आहोर, चौथा डोगांव (रानीवाड़ा), पांचवां भादीव (रानीवाड़ा) छठा मीरपुरा (रानीवाड़ा), सातवां गुंडाउ (रानीवाड़ा) और इसके विक्रय केन्द्र हैं जालौर, भीनमाल, आहोर, सांचौर। इस तरह इसके 4 विक्रय केन्द्र हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह आगे पूछ रहे हैं विकास के बारे में पूछ रहे हैं कि इसकी योजना क्यों नहीं बना रहे हैं?

श्री श्रीकिशन सोनगरा : जो विकास की योजनाओं के लिए माननीय सदस्य ने पूछा है, उसके सम्बन्ध में निवेदन यह है कि

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

खादी ग्रामोद्योग में जो भी संस्था अपना आवेदन करती है, एक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड विचार करता है, फिर उसके लिये आवश्यक ऋण आवश्यकता ....

श्री अध्यक्ष : आपकी तैयारी है यदि कोई एप्लाई करे ?

श्री श्रीकिशन सोनगरा : हां, वह तो है ही (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, इसके विस्तार के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि और अधिक कताई और बुनाई के केन्द्र और विक्रय के....

श्री अध्यक्ष : वह तो तैयार हैं, आप तो एप्लाई करवाइये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मेरा दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से यह है कि खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं के माध्यम से सरकार बहुत सारे उद्देश्यों के लिये व्यक्तिगत योजनाओं में भी ऋण वितरित करती है, उसमें अभी जालौर में कितनी योजनाएं चल रही हैं ? किस-किस मद में ऋण कितना दिया गया है और उसमें जिनको ऋण दिया गया है, जिन साधनों के लिए, वे साधन मौके पर उपलब्ध हैं या नहीं ? उसकी कोई जांच हुई है या नहीं ? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, अधिकतर लोन इसमें केवल कागजों में होते हैं, असेट्स की खरीद भी नहीं होती है और किसी मामले में खरीद होती है तो वह हाथों-हाथ, एक फार्मेलिटी होती है, या तो बिक जाती है या केवल खरीद शो होती है तो उसके फिजीकल वेरीफिकेशन के लिये हमारे पास क्या व्यवस्था है ? (व्यवधान) और उस सम्बन्ध में, मंत्री महोदय, आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री हरीसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को चैम्बर में बुलाकर सब बातें समझा दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। आप बाद में बता दीजिये। नैक्स्ट, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर स्थित बाईजी का तालाब का सौन्दर्यीकरण

46. **श्रीमती सूर्यकांता व्यास** (जोधपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर शहर में स्थित 'बाईजी का तालाब' को भूमिगत बाजार या सुन्दर उद्यान में बदलने का पूर्व में कोई प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजा गया था ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

(2) सरकार एवं नगर निगम द्वारा इस बारे में आगे क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

(3) क्या सरकार इसके लिए वित्तीय अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जी नहीं।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(2) प्रश्न ही नही उठता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो कोई उठा ही नहीं, इसका मतलब यह हुआ, माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया कि यह प्रश्न ही नहीं, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी चाह रही हू कि 26 अगस्त, 1977 को मुख्य मंत्री कार्यालय से एक पत्र प्रशासक, नगर परिषद, जोधपुर को इस आशय का भेजा गया था कि जोधपुर में "बाईजी के तालाब" को विकसित कर उसे पर्यटन महत्व का स्थल बनाया जाये अथवा परिषद् द्वारा कोई सुन्दर उद्यान लगा दिया जाये, पहला प्रश्न मेरा यह है। मुख्य मंत्री कार्यालय से पत्र गया है और ये कहते हैं कि कोई प्रश्न ही नहीं उठता (व्यवधान) उलटा कैसे पूछा है (व्यवधान)

दूसरा प्रश्न है, जिलाधीश, जोधपुर द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 15-3-69 में यह निर्णय लिया गया नगर परिषद द्वारा कि इस स्थान को उद्यान के रूप में विकसित करेगी, फिर भी ये कहते हैं कि प्रश्न ही नहीं उठता।

तीसरा प्रश्न है, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 10769 दिनांक 18-6-69 द्वारा प्रशासक, नगर परिषद् जोधपुर से यह अनुरोध किया कि उपरोक्त कथनानुसार कार्यवाही करने हेतु नगर परिषद् प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को स्वीकृति के लिये भेजे।

चौथा प्रश्न है, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग ने अपने अर्द्ध-शासकीय पत्र दिनांक 18-6 81 द्वारा प्रशासक, नगर परिषद्, जोधपुर से उक्त क्षेत्र को विकसित करने के बारे में प्रस्ताव मांगे, परन्तु इस पर भी सरकार कहती है, कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मुझे यह समझ में नहीं आया, आप इसकी जो कोई भी जानकारी चाहें, मैं सदन के सामने रख सकती हूं, मेरे पास इसकी सारी जानकारी है। इनका मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं, मगर अधिकारी लोग इनको क्या मालूम क्यों गुमराह कर देते हैं। इनको गलत-सलत जवाब लिखवा देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक तालाब ऐसा है जिससे जोधपुर शहर को पानी दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को बोलने दीजिये आप। आप बाद में बोल लेना, पहले ये बोल लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न किया, वह बिल्कुल इससे भिन्न है जो अब आप सवाल कर रही हैं। आपने तो यह पूछा था कि मुख्य मंत्रीजी के यहां से कोई प्रस्ताव है क्या? उसका उत्तर मैंने दिया है। लेकिन आपकी समस्या का समाधान मैं इस तरह करना चाहता हूं, वह आप सुन लें। यह प्रश्न आपका है, जोधपुर शहर में स्थित "बाईजी का तालाब", इस पर आप विकास का काम करना चाहती हैं। सन् 1984-85 में जब बोर्ड था, तो उन्होंने निर्णय लिया कि उसका कुछ विकास किया जाये। इस तरह का निर्णय कर लिया तो कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गये और हाई कोर्ट का स्टे ले लिया कि बोर्ड ने जो

72

(श्री भंवरलाल शर्मा)

निर्णय लिया है उसकी पालना नहीं की जाये। मेरी जानकारी अभी तक यह है कि अभी तक हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। आप क्लियर करें कि हाई कोर्ट का स्टे है कि नहीं अगर आपको जानकारी है तो? मेरी जानकारी है कि आज भी हाई कोर्ट ने उसको रोका हुआ है। साथ ही 3 लाख रुपया कलक्टर साहब ने इस बात का स्वीकृत किया था कि जो गन्दगी है उसको साफ किया जाय, और उसको समतल किया जाय। जो आप कहना चाहती हैं वह योजना इसमें नहीं है और 3 लाख रुपया केवल उसी के लिए सैंक्शन किया था। उसका भी नगर निगम वहां पर उपयोग कर पाया या नहीं लेकिन कोई सौंदर्यीकरण की योजना वह नहीं थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुझे अलग से बता दें क्या आपका प्रस्ताव है, क्या सौंदर्यीकरण कराना चाहती हैं. (व्यवधान).... या तो आप मुझे बता दें या कोई नगर निगम से पूछकर, (व्यवधान) आप बात सुन लें, उसकी कोई योजना बनायें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जितना पैसा उपलब्ध होगा उसके आधार पर कोई योजना वहां सौंदर्यीकरण की है और हाई कोर्ट का स्टे वहां पर नहीं हो तो इसके बाद इसमें कार्यवाही जरूर की जा सकती है। आप मुझे अलग से बता दें या चाहें तो हाउस में बता दें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि हाई कोर्ट से स्टे है। स्टे किस बात का है यह थोड़ी जानकारी दे दें और कोर्ट से क्या जबाब आया, इसकी मुझे जानकारी दे दें। आपने कह दिया कि स्टे है लेकिन स्टे किस बात का है, यह बताने की कृपा करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्या, हाई कोर्ट से स्टे लाने की जानकारी मुझे यह है कि आप स्वयं हाई कोर्ट में गयी हों....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं भी बता दूंगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने स्वयं ही हाई कोर्ट में जाकर स्टे कराया है। मुझसे ज्यादा जानकारी तो आपको होगी कि किस बात का स्टे कराया है। फिर भी मैं बता दूं कि बोर्ड ने जो निर्णय विकास करने का लिया था उस पर स्टे है। फिर आप बता दें कि क्या स्टे है?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : स्टे किस बात का है, मैं यह पूछना चाहती हूं। मैंने स्टे लिया है लेकिन किस परपज के लिए स्टे लिया है, यह तो आप सदन को जानकारी दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बताओ ना क्यों लिया आपने? आप बताओ, मैं क्या बताऊं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूं.... (व्यवधान).... मेरी बात सुन लें, बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट के अन्दर जाने का मतलब यह था कि कांग्रेस का बोर्ड था और मैं भी नगर पार्षद थी, वहां बोर्ड में चार-पांच कांग्रेस के लोगों ने बैठकर यह तय किया कि यहां पर पार्क नहीं बनना चाहिए जबकि मास्टर प्लान के अन्दर पार्क दिया हुआ है। पार्क के स्थान पर उन्होंने कहा कि मार्केट बनायेंगे। मैंने

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कोर्ट से स्टे इस बात का लिया है कि हम मार्केट नहीं बनने देंगे, इससे तो मास्टर प्लान का महत्व ही खत्म हो जायेगा। सरकार ने लाखों रुपये खर्च करके मास्टर प्लान बनाया और सन् 1971 में कांग्रेस सरकार थी उस समय मास्टर प्लान बना था और 1977 में जब भैरोंसिहजी की सरकार आयी तो उसको मान्यता दी। वह 7 साल तक ऐसे ही पड़ा था उस मास्टर प्लान का कुछ नहीं हुआ। यहां पार्क बनना था लेकिन कांग्रेस वालों ने मार्केट बनाने का तय किया इसलिए मैं स्टे लायी। आप स्टे की जानकारी सदन को देते। मैं उसका विकास चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने कह दिया, आप बना देना इनको। नैक्स्ट, श्रीमती उजला अरोड़ा।

ग्राम साहू (जमवारामगढ़) सड़क के मध्य नालों पर पुल/रपट निर्माण

47 **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम साहू, ग्राम पंचायत पापड़, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर की सड़क कुल कितनी लम्बी है ? अब तक कुल कितनी लम्बाई दूरी में सड़क बन चुकी है, शेष सड़क कब तक बना दी जावेगी ?

(2) क्या उक्त सड़क के मध्य में पड़ने वाले नालों पर पुल या रपट बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें। नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) ग्राम पंचायत साऊ, (आबादी 919/1971) सड़क की दूरी जयपुर-रामगढ़ सड़क से 9 कि. मी. है। अब तक केवल तीन कि. मी. की लम्बाई में (जयपुर-रामगढ़ सड़क से) डामर की सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष भाग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर सम्भावित होगा।

(2) जी हां। प्रथम 3 किमी. की निर्माणाधीन लम्बाई में छोटी रपटों का निर्माण करवाया जावेगा। रोड़ा नदी एवं अन्य पुलियाओं के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगी कि क्या मंत्री महोदय के द्वारा 21-5-92 को इस सड़क का शुभारम्भ किया गया था। आपको स्मरण होगा कि उस समय इस सड़क पर ग्रामवासियों ने श्रमदान से पूरी लम्बाई में अर्थ वर्क कर दिया था। यदि हां, तो अब तक विभाग ने इस पर अन्य कार्यवाही क्यों नहीं की ?

नम्बर दो, मैं मंत्री महोदय की जानकारी में यह भी लाना चाहूंगी कि यह सही नहीं है कि उक्त सड़क की 3 किमी. लम्बाई पर डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है। एक इंच की लम्बाई में भी डामरीकरण नहीं किया गया है। मंत्री महोदय से मैं यह भी जानकारी चाहूंगी कि मैंने सी. बी. वर्क निर्माण के सम्बन्ध में अपना प्रश्न किया था, यह रोड़ा नदी का पुल इसमें विभाग के अधिकारियों की चतुरता से किस प्रकार शामिल हो गया है ? मैं यह भी जानकारी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

देना चाहूंगी कि रोड़ा नदी पर वर्तमान में पुल बना हुआ है उसको बनाये जाने की आपके विभाग को आवश्यकता ही नहीं है। माननीय मंत्री महोदय मुझे उत्तर दें कि 12 लाख रुपये आपके द्वारा दिये गये, 5 लाख रुपये विधायक फण्ड में से दिये गये, इसका यूटिलाइजेशन अब तक क्यों नहीं किया गया ? क्या यह सच है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय यह बात सच है कि 21-5-92 को माननीय सदस्य महोदया के साथ मैं उस सड़क को देखने के लिए गया था और जीप से मैं उस किनारे से उस किनारे तक गया था ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें रोड़ा नदी कहां से आ गयी ? प्रश्न में तो नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय 12 लाख रुपया स्वीकृत किया गया था। माननीय सदस्या ने जो कहा कि डामर नहीं है, सचमुच एक जगह नहीं है परन्तु वह 3 किमी. की पूरी सड़क मैटल की बन गयी है केवल 180 मीटर को छोड़कर जिस पर कोई स्टे किसी ने लिया हुआ है। मैं माननीय सदस्या को यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय यह तय हुआ था कि उनको जो 10 लाख रुपया मिलता है वह 10 लाख रुपया इसमें देंगी तब आगे 3 किमी. का काम प्रारम्भ किया जायेगा। जिस 5 लाख रुपए की आप चर्चा कर रही हैं वह 5 लाख रुपया विभाग को नहीं मिला। अब भी मेरा कहना है कि जो कमिटमेंट मेरा उस समय था. 3 किमी. तो जून, 1994 तक डामर की बन जायेगी, बात नम्बर एक।

रोड़ा नदी पर पुल की जो चर्चा आपने की है वह पुल जो बना हुआ है अगर उसी को बने रहने देना चाहती है तो हमको कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि वह जिस प्रकार से रोड़ के सिक्वेंस में बना हुआ है वह ठीक प्रकार से नहीं आता और उसको ठीक बनाने के लिए 6 लाख रुपया चाहिए। उसी प्रकार 3 किमी. से लेकर 9 किमी. तक की सड़क बनाने के लिए 36 लाख रुपया और चाहिए। 3 किमी. से 9 किमी. करने में कुछ और काम करने में 12 लाख रुपये और चाहिए। कुल 54 लाख रुपया चाहिए। फिर भी मैं कहना चाहता हूं क्योंकि उस समय भी कमिटमेंट किया था इस 12 लाख का काम तो 3 किमी. में हो जायेगा। अगर माननीय सदस्या 10 लाख रुपया अपने फण्ड में से दें जैसा उस समय उन्होंने कहा था वह देंगी तो आगे काम करने की व्यवस्था की जा सकेगी क्योंकि यह गांव एक हजार की आबादी से कम है इसलिए हमारी किसी योजना में नहीं आता। किन्तु उस समय जाना हुआ था, देखना हुआ था इसलिए इतना करने की स्थिति में मैं हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सड़क का निर्माण होता है उसमें जनसंख्या की कमी होते हुए भी उस रोड को विचित्र परिस्थिति में, एक ओर पहाड़, बीच में नदी, तीसरी ओर टीला, इस समस्या से निवासियों को उबारने के लिए सड़क बनाने का आदेश दिया था।

नम्बर दो, सड़क और पुलिया में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लगभग डेढ़ किलोमीटर का अन्तर है इसलिए रोड़ा नदी के पुल को अलग ही माना जाये और इसके विकास की योजना अगर आप बनायें तो अलग से ही बनायें। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि रोड़ा नदी, जिसको आपने इसमें चलाकर शामिल किया है, मैं मुख्य मंत्रीजी की गाड़ी भी एक बार फम गयी थी। वहां के गांव वालों को जब बरसात आती है तब बस या अन्य साधनों से जाने-आने में मुश्किल पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी की गाड़ी फंस गयी थी इसलिए उन्होंने आपको स्पेशल कंशेशन दिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब ही पुल डलवाया था।

श्री अध्यक्ष : देखिए, यह मामला हाउस का नहीं है। आपके और मंत्रीजी के बीच में कोई बात हुई है, आप बाद में करिये, यह अभी छोड़िये। श्री रामस्वरूप मीणा। (व्यवधान) बैठिए, नहीं, यह हाउस का मामला नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मेरे प्रश्न से सम्बन्धित बात करती हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं है यह प्रश्न सम्बन्धी हो गयी बात क्लियर कि आपके और मंत्री जी के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं। आप आपस में बात करिऐ।

नैक्स्ट, श्री रामस्वरूप मीणा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे मेरा यह प्रश्न करने दीजिए।

प्रश्न संख्या 48

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप। नैक्स्ट श्री रामस्वरूप मीणा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री परसादीलाल मीणा।

पंचायत समिति लालसोट के ग्रामों की पेयजल योजनायें

49. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति लालसोट के ग्राम खेडला-खुर्द, महारिया, किशोरपुरा, दौलतपुरा, गुदामली की सामूहिक पेयजल योजनाऐं स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा ?

(2) क्या सामूहिक पेयजल वितरण योजनाओं के स्थान पर इच्छित लोगों की पाइप लाइन डालकर घरों में पानी के कनेक्शन देने से ज्यादा लाभ मिल सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जी. एल. आर के स्थान पर उक्त व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है ?

(3) क्या शिवसिंहपुरा-तलाब गांव पेयजल योजना से तलाब गांव को अब तक नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अब इस ग्राम को कब तक उक्त पेयजल से जोड़ दिया जायेगा ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) ग्राम खेडला खुर्द,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दौलतपुरा एवं होदायली हेतु क्षेत्रीय पेयजल योजना निर्धारित मापदण्डों के अनुसार न होने के कारण प्रस्तावित नहीं है। ग्रामों में मापदण्डों के अनुसार हैण्डपम्प कार्यरत हैं। ग्राम महारिया किशोरपुरा हेतु एक क्षेत्रीय पेयजल योजना बनायी गयी है, जिसकी स्वीकृति धन उपलब्धता के अनुसार की जानी सम्भव होगी।

(2) वर्तमान में मूलतः क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं में वितरण पाइप लाइन डालकर घरों में जल सम्बन्ध दिये जाने की नीति नहीं है एवं तकनीकी कारणों से भी सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। प्रक्रिया जारी है। इस ग्राम को मार्च, 1974 तक जोड़ा जाना लक्षित है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जैसा प्रश्न के खण्ड एक में बताया कि यह निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं है, हैण्डपम्प कार्यरत हैं, मंत्रीजी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शिवसिंहपुरा और खेड़ला में एक भी हैण्डपम्प जिस दिन नहीं था, आपने केवल एक या दो हैण्डपम्प यह कह कर लगाये थे कि जब तक योजना वहां पर क्रियान्वित नहीं होगी तब तक यह टेम्प्रेरी व्यवस्था कर रहे हैं और इसकी पूर्णतः व्यवस्था के लिये अपने विभाग को निर्देश देकर वहां की योजना को बनाने के लिये कहा था। वह योजना बनकर आपके विभाग में विचाराधीन है दो साल से। तो मैं आपसे यह कहूंगा कि आज क्या बात हो गयी कि वह मापदण्डों के अनुसार नहीं है। आप स्वयं याद करिये, जब आपने जिलेवार विधायकों की मीटिंग बुलायी थी, आपने स्वयं इस योजना को बनाने के लिये विभाग को निर्देश दिया था।

दूसरी, मेरी किशोरपुरा और महारिया की योजना के लिये दो साल से क्या धन नहीं मिला? क्या कारण है उनको स्वीकृत नहीं करने का और आप उसको अब कब तक स्वीकृत कर देंगे? जो आपकी यह शिवसिंहपुरा और तलाब गांव की योजना है कब सैंक्शन की थी? आपको याद होना चाहिए कि दो साल पहले इसकी स्वीकृति जारी हुई थी। आज तक आपने तलाब गांव, शिवसिंहपुरा को तो जोड़ दिया पर आज तक ...

श्री अध्यक्ष : अब यह तो मार्च में हो ही रही है।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या, साहब?

श्री अध्यक्ष : मार्च, 94 तक हो जायेगी।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं साहब, दो साल से अब तक यह लम्बित हैं। एक शिवसिंहपुरा से तलाब गांव के लिए.... (व्यवधान)....अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : देखिये आप, जो काम हो रहा है उस पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, ऊपर का ठीक है आपका प्रश्न।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं-नहीं, मेरा, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से....

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कहा है कि मार्च, 94 में हो रहा है यह कम्प्लीट।

श्री परसादीलाल मीणा : 94 में, दो

(श्री परसादीलाल मीणा)

मार्च निकल गये, उसके बाद भी आज तक वहां पाइप लाइनें नहीं डाली हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब निकल गये, उसका एक प्लेनेशन अलग से काल करिये । वह 94 में मार्च के पहले हो रही है इसलिए ऊपर वाला प्रश्न ठीक है आपका । अब यह तो हो गया ।

श्री परसादीलाल मीणा : हां, तो ऊपर वाले का जबाव दिलवाइये । खेड़ला के लिये तो आपने स्वयं निर्देश दिया था ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम महारिया और किशोरपुरा, इधर तो क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बन गयी है....

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, उसकी सैंक्शन कब तक होगी ? कब से बनी हुई पड़ी है । दो साल से बनी हुई पड़ी है । खेड़ला की भी दो साल से आपके निर्देशानुसार बनी हुई पड़ी है और आज आप कह रहे हैं कि धन उपलब्ध होगा जब करेंगे । दो साल से धन नहीं मिला इनके लिये ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगा मैं । अब यह विचाराधीन एडीशनल चीफ तक आ गयी है, इसकी प्रक्रिया पूरी करके जल्दी पूरी करा देंगे ।

श्री परसादीलाल मीणा : इस साल गर्मियों के पहले क्या आप सैंक्शन करके वहां पर पानी उपलब्ध करा देंगे ? मेरा तो यही निवेदन है आपसे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे प्रयत्न करने दें आप । Let me try.

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है, ठीक है । श्री जुबेर खान, नैक्स्ट ।

ग्राम बाम्बोली (रामगढ़) बाईपास सड़क मार्ग

50. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार के द्वारा ग्राम बाम्बोली तहसील रामगढ़ (अलवर) में बाई-पास सड़क निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ?

(2) क्या उक्त कार्य के लिए भूमि अवाप्त की गयी थी ? यदि हां, तो क्या किसानों को मुआवजा दिया गया ?

(3) उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) ग्राम बाम्बोली तह-सील रामगढ़ (अलवर) में बाईपास नाम से कोई स्वीकृति नहीं है । किन्तु ग्राम बाम्बोली से खूंटेटा ग्राम तक सड़क बनाने की नौ लाख रुपये की स्वीकृति है । यह सड़क ग्राम बाम्बोली के बाहर होकर खूंटेटा ग्राम तक जावेगी । इसकी लम्बाई 4 5 किलोमीटर है । (2) जी हां, उपरोक्त बाम्बोली खूंटेटा सड़क की भूमि अवाप्ति का अवार्ड दिनांक 28.11.88 को रुपये 2,47,790/- का

(18)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

किया गया था। अब तक 73 काश्तकारों को 2 18,393/- रुपये का भुगतान कर दिया गया है तथा 21 काश्तकारों को 11,293/- रुपये का भुगतान उत्तराधिकारी का प्रमाण-पत्र पेश नहीं करने के कारण नहीं किया जा सका। शेष 3 काश्तकारों द्वारा रुपये 18,104 का भुगतान लेने से मना कर दिया गया तथा कोर्ट द्वारा स्टे ले लिया गया तथा जमीन पर सड़क निर्माण कार्य नहीं करने दिया गया।

(3) एक किलोमीटर सड़क ग्राम बाम्बोली के पास भूमि उपलब्ध नहीं होने से तथा काश्तकारों के स्टे ले लेने के कारण नहीं बन सकी थी। 3·5 किलोमीटर डामर सड़क बनकर तैयार है। अब शेष एक किलोमीटर सड़क वर्ष 94 में बन जावेगी।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्स ई एन. ने गांव में जाकर जिन लोगों ने स्टे लिया था उनसे बात की कि भाई आप तीन लोगों की वजह से इस सड़क का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और उसके बाद में क्या आपकी यह जानकारी में है कि उन लोगों ने लिख कर देकर अपना स्टे कोर्ट से विथड्रा कर लिया है? अगर विथड्रा करा लिया है तो फिर आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग इस सड़क पर कार्य क्यों नहीं शुरू कर रहा है? एक तो मैं यह जानना चाहूंगा।

दूसरा, अगर आप यह मानते हैं कि यह बातचीत हो गयी है और लोगों ने विथड्रा कर लिया और पैसे लेने को तैयार हैं तो कब तक उनको पैसे देकर जमीन अवाप्त करके सड़क बना देंगे आप? आपने 94 का लिखा है 94 का तो दिसम्बर भी, एक साल है, अध्यक्ष महोदय, और दूरी थोड़ी सी है। अब फसल कटने जा रही है सरसों वगैरह, तो मेरा आपसे यह निवेदन होगा कि गर्मियों में फसल कट जायेगी ताकि लोगों को नुकसान नहीं हो तब तक इसको कम्पलीट करा देंगे?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आफिशियल प्रयास के कारण 3-5-93 को वह स्टे वैकेट करा लिया गया है और इसमें टेण्डर इनवाइट कर लिये गये हैं। 16 12 93 को निविदाएं प्राप्त हो गयी है। अब भी मुझे लगता है कि उन किसानों का रेजिस्टेंस रहेगा स्टे वैकेट होने के बाद भी, अगर माननीय सदस्य मुझे सहयोग करेंगे उन किसानों को मनाने के लिये, तो जून, 1994 में आपकी वह एक किलोमीटर सड़क मैं बना दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्रीमती तारा भण्डारी।

शिवगंज नगर (सिरोही) की पेयजल विस्तार योजनायें

51. **श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही विधान सभा क्षेत्र के शिवगंज नगर के लिये

(श्रीमती तारा भण्डारी)

पेयजल विस्तार की योजनाएं बनायी गयी थीं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी लागत की ?

(2) उपरोक्त योजनाओं की क्या स्थिति है तथा सरकार उन्हें कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

(3) अब तक इन योजनाओं पर कितना काम हो चुका है ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1 जी हां। उल्लेखित शिवगंज शहर हेतु पूर्व में 153·98 लाख रुपये की योजना बनायी गयी थी जिसे तकनीकी कारणों से संशोधित कर 234.43 लाख रुपये एवं पुन: संशोधित कर 188.57 लाख रुपये की योजना बनायी गयी तथा वर्तमान में इसमें और संशोधन किया जाकर अब यह 23.33 लाख रुपये की योजना विचाराधीन है।

(2) संशोधित 23.33 लाख रुपये की राशि की उक्त योजना का तकनीकी अनुमोदन होना अभी शेष है।

(3) तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के अभाव में इस योजना पर अभी कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, सिरोही एवं शिवगंज नगर की पेयजल योजनाएं लागू किये हुए चालीस साल से अधिक हो गये। वहां पर खपत ज्यादा होने, आबादी बढ़ जाने से पानी की भयंकर समस्या हो गयी है। पाइप लाइनें पुरानी हैं और उस पर कनेक्शन बहुत ज्यादा हो गये। इन सब समस्याओं का विचार करके दोनों शहरों की पेयजल योजनाएं बनी थीं और हुडको के यहां विचाराधीन भेजी गयी थीं। मैं मंत्री महोदय से एक ही सवाल पूछना चाहती हूं, जो उन्होंने जवाब दिया है, पुन: संशोधन, पुन: संशोधन, पुन: संशोधन, इसका मतलब क्या है ? विभाग इस पर कब तक संशोधन करता रहेगा और इस योजना को तोड़-मरोड़ कर अब कहां पहुंचा दिया है ? अध्यक्ष महोदय, सिरोही की योजना तो बिल्कुल ही तोड़ कर रख दी। अभी पिछले राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत इन दोनों योजनाओं का कोई पता नहीं है और अब फिर नये सिरे में योजना बनकर विचाराधीन है और सिरोही की योजना का तो आज तक कोई पता नहीं चला। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूं कि विभाग ने यह योजनाएं किस परपज से कब बनायी थीं और इन्हें बार-बार संशोधित करने का क्या कारण है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी चिन्ता बिल्कुल सही है और इसमें विलम्ब भी हुआ है। इसमें सबसे बड़ा जो एक बिन्दु रहा, यह रहा कि सोर्स कौन सा लिया जाय। शायद वहां के प्रतिनिधियों का या लोगों का दबाव यह रहा कि यह जो जवाई बांध है उससे सोर्स रखा जाय। विभाग का यह सोचना था कि वहां जो कुएं हैं जवाई बांध के पास, उनसे लिया जाय। इस विवाद में यह काफी देर तक चलता रहा और स्कीम भी काफी लम्बी इसलिए बनी कि यदि जो सोर्स उपलब्ध है उनसे सीधा पानी लेते हैं तो पैसा कम लगेगा और जवाई बांध से लाते हैं तो पैसा ज्यादा लगेगा। अन्त में यह निर्णय हुआ कि जो कुए हैं, जो जवाई बांध के पास हैं, उनका

(श्री भंवरलाल शर्मा)

स्तर भी उतना ही रहता है जितना जवाई बाध में रहता है, करीब-करीब, इसलिए पानी वहां ज्यादा उपलब्ध होगा तो उसके कारण अब इसकी लागत घटकर 23.33 लाख आ गयी है। आपको इस बात से प्रसन्नता होनी चाहिए कि यह जो बड़ी योजना थी बड़े पैसे की, यह हुडको से जाकर सैंक्शन करानी पड़ती और उसमें बड़ा लम्बा समय लगता। अब यह इतनी कम होने के कारण अगले वर्ष में जो बजट आयेगा उसमें राज्य सरकार ही इसको लेने की स्थिति में आ जायेगी। इसलिए अब इसके जल्दी होने की सम्भावना आपको माननी चाहिए। अगले बजट में हम इसको ले लेंगे।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, प्रसन्नता तो तब होती जब यह योजनाएं मंजूर हो जातीं।

श्री अध्यक्ष : आपकी योजना को मंजूर करने के लिये ही तो किया है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनें। यह पेयजल पहुंचाना कोई प्रयोगशाला का काम नहीं है जो बार-बार संशोधन, संशोधन किये जा रहे हैं या कोई एक्सपेरीमेंट किये जा रहे हैं। जनता पानी चाहती है और पानी देना हमारा फर्ज है। यह बार-बार संशोधन किस बात के हो रहे हैं? इस योजना को अगले वित्तीय वर्ष में लेंगे, अभी क्यों नहीं?

श्री अध्यक्ष : बता दिया। श्री अमराराम चौधरी।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब नहीं आया। सिरोही की योजना का तो कहीं पता ही नहीं है। सिरोही की भी 1 करोड़ 51 लाख की योजना बनी थी उसका कहीं पता नहीं है। मंत्री महोदय से जवाब दिलवाइये कि इन योजनाओं का क्या होने वाला है।

श्री अध्यक्ष मंत्रीजी ने संशोधन के कारण बताकर आपकी...

श्रीमती तारा भण्डारी : अगले वित्तीय वर्ष तक जनता क्या करेगी?

श्री अध्यक्ष : वहां 23 लाख रुपए लगने वाले हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, वहां दस-दस फीट गहरे खड्डे खुदे हैं शिवगंज नगर में। रोज एक्सीडेंट होते हैं। जनता पेयजल को तरसती है। कुछ न कुछ तो मंत्री महोदय से कहलवाइये कि अगले बजट तक, कब तक इन्तजार करें?

श्री अध्यक्ष : कह दिया ना अगले बजट में आपकी 23 लाख की योजना मंजूर करवा देंगे।

श्रीमती तारा भण्डारी सिरोही की योजना का तो बताया ही नहीं। 1 करोड़ 19 लाख की सिरोही की योजना है यह राष्ट्रपति शासन में गुम हो गयी। पता तो चले कि वह कहां गुम हुई, क्यो हुई?.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल तो शिवगंज का है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

प्रश्न में आपने शिवगंज की जानकारी चाही है।

श्रीमती तारा भण्डारी : साहब, मेरा तो पूरा ही क्षेत्र है। शिवगंज अलग है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप सवाल अलग से कर लीजिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : जब पेयजल योजना बनी थी तो विभाग को चाहिए पूरा जवाब दे।

श्री अध्यक्ष : आपने सवाल शिवगंज का ही पूछा है।

श्रीमती तारा भण्डारी : तो शिवगंज ही सही, यह बार-बार क्यों बदली कर रहे हैं और क्यों इस पर एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं ? कितने संशोधन बताये हैं. आप देख लें प्रश्न का उत्तर। संशोधन क्या इस योजना को लिगर आन करने का षडयंत्र नहीं है ? काहे के संशोधन कर रहे हैं बार-बार ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्या, मैंने यह निवेदन किया कि संशोधन होने के बाद अब जो वर्तमान में स्थिति है वह यह है कि यह कुल मिलाकर 23.33 लाख की स्कीम बन चुकी है और अगला जो बजट आयेगा, जो 1 अप्रेल, 1994 के बाद शुरू होगा....

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : I am addressing the Chair.

श्री जगदीप धनखड़ : आप इतने सीनियर मिनिस्टर हैं आप लगातार अपने सदस्यों की ओर देखते हैं। हमारी तरफ कभी नहीं देखते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बैठते ही ऐसी जगह हो जहां अपने आप ही देखना पड़ता है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, भीषण अकाल है। मेरा तो कोई परपज पूरा हुआ नहीं। कुछ पाइप लाइनें ही बदल दें और कुछ पानी की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

बालोतरा-लूणी नदी पर पुल निर्माण

52. **श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बालोतरा-लूणी नदी पर पुल का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो पुल बनकर कब तक तैयार हो जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : जी नहीं।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो लूणी नदी पर पुल है, कब स्वीकृत किया गया था ? क्या उसका कोई कार्य प्रारम्भ किया गया ? किया गया तो कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इस उच्च स्तरीय पुल की प्रशा-

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

सनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 150 लाख रुपये की दिनांक 14.6-84 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी थी उसमें से दस लाख रुपए पुल निगम को जमा कराये गये थे वर्ष 1984-85 में पुल के निर्माण के लिऐ जिसके तहत पुल निगम ने सर्वे, इन्वेस्टीगेशन का कार्य किया व साइट पर स्टोर आदि बनवाये। पुल निगम ने 315 लाख रुपए का पुल तथा 175 लाख का अप्रोच आफ गाइड बंध का तख्मीना बनाकर वित्तीय स्वीकृति हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित किया। स्वीकृति तो थी 150 की और यह टोटल हो गया सवा पांच करोड़। अभी तकनीकी पहलुओं पर विचार करने के लिए 19-8-89 को एक मीटिंग हुई उसमें यह तय किया गया कि साइट की आवश्यकता को देखते हुए सब्मर्सिबल पुल का तखमीना करवाया जाये, जो पुल निगम ने अपने पत्र क्रमांक 18-9-92 को सब्मर्सिबल पुल का तख्मीना 672 लाख का बनाकर प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति हेतु भिजवाया था।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सब्मर्सिबल पुल बने, हाई लेवल ब्रिज बने। सब्मर्सिबल पुल में तो लगेगा 672 लाख रुपया और हाई लेवल ब्रिज बनेगा तो उसमे लगेगा 16 करोड़ रुपया और पानी आता है दो दिन एक महीने में और रहता है तीन-तीन घण्टे। तो राजस्थान की स्थिति देखते हुए कौनसा पुल बनाया जाऐ यह विचार करने के कारण इस पर अभी कोई निर्णय नही हो सका।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 1990 के अन्दर कम से कम चार महीने लूणी नदी चली, 79 के अन्दर भी तीन महीने लूणी नहीं चली है। हजारो लोगों का वहां आना जाना है, नाकोड़ा जैसा तीर्थ है, बालोतरा है। दोनों तरफ बसा हुआ है। विद्यार्थी पढ़ने आते है और दो-दो, तीन-तीन महीने रास्ता बन्द हो जाता है। इसलिए क्या मंत्री महोदय इस पुल को बनाना आवश्यक समझते ही नहीं है? या तो यह कह दें कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता तो बहुत है, प्रश्न प्राथमिकता का है और प्राथमिकता में आता नहीं इसलिए मैंने निवेदन कर दिया।

श्री अध्यक्ष : यह जो बता रहे है यह फिगर्स देख लीजिए।

श्री अमराराम चौधरी : यह राशि तो बढ़ती जायेगी। जब तक आप जल्दी निर्माण नहीं करायेंगे तो यह राशि तो बढ़ती ही जायेगी। आपको पुल बनाना पड़ेगा, यह अति आवश्यक है। लोगों की जानें जाती हैं। हर बार हजारों करोड़ों रुपया सरकार का खर्चा होता है। उस समय हैलिकाप्टर मंगाये जाते हैं, नावें मंगायी जाती हैं। लोगों का राशन पानी सब बन्द हो जाता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी, जिन्होंने यह देखा है, वहां की घटना को देखा है वहां बाढ़ के समय पधारे हैं, यह पुल बहुत आवश्यक है, जल्दी ही योजना के अन्दर लेकर यह प्रारम्भ कराया जाऐ।

मेरा एक यह भी निवेदन था कि इस पुल का काम शुरू कर दिया गया था, शिला-

(श्री अमराराम चौधरी)

न्यास हो गया था, दस लाख रुपए तो इस पर लगा चुके।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत।

जोधपुर लिफ्ट कैनाल निर्माण पर व्यय

53. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर लिफ्ट कैनाल की अनुमानित लागत कुल कितनी आंकी गयी थी, अब तक इस पर कितना व्यय हो चुका है और भविष्य में कितना व्यय होना शेष है?

(2) जोधपुर लिफ्ट कैनाल के पम्प सिविल पर कुल कितना व्यय होना है कितने पम्प स्टेशनों का कार्य चल रहा है, कितने पूर्ण हो चुके हैं और कितने शेष हैं?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जोधपुर लिफ्ट पेय-जल परियोजना की वर्तमान में संशोधित अनुमानित लागत 256.80 करोड़ रुपए है। इस योजना पर नवम्बर 1993 तक लगभग 140.22 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं।

(2) योजना में पम्पिंग स्टेशनों के सिविल कार्यों हेतु 22.42 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। योजनान्तर्गत कुल आठ पम्पगृहों के निर्माण का प्रावधान है व उन सभी पर कार्य प्रगति में है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष जी, जोधपुर लिफ्ट कैनाल पर पिछले तीन वर्षों में माननीय मुख्य मन्त्री जी और जलदाय मन्त्री जी ने रुचि लेकर बहुत अच्छी प्रगति की है। पिछले एक वर्ष से जो मैकेनिकल पम्प...

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिए। दो सवाल रहे हैं और लोगों का नम्बर आ जाए। आपने जो पूछा है वह बता दिया है। बाकी बात बाद में कर लीजिए। आप जल्दी करने की बातें कहेंगे वह वैसे ही कह देना।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं जानना चाहूंगा मैकेनिकल पम्प जिनके टेण्डर एक वर्ष पूर्व हो चुके हैं, क्या वह स्वीकृत हो गये? उस फर्म को आदेश मिल गये क्या? यदि आदेश मिलने हैं तो कब तक आदेश मिल जायेंगे और मैकेनिकल पम्प कब मिल जायेंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा : इनमें टेण्डर आ चुके हैं और नेगोशियेशन के लिए रखे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेगोशियेशन के पम्प जल्दी आ जायें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण काम है, जोधपुर लिफ्ट कैनाल के टेण्डर इससे पहले एक बार हो चुके हैं और आज पांच-छः वर्ष हो गये हैं, इस विषय में इनका विभाग कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। इससे पहले जो टेण्डर हुए थे वह 1988 में हुए थे उसके बाद 92 में वापस टेण्डर हुए और होने के बाद आज एक वर्ष पूरा हो चुका है। किस समय तक वह फर्म को आदेश दे देंगे? किस फर्म को दे रहे हैं? मैकेनिकल पम्प पर कितना व्यय होने वाला है?

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि नेगोशियेशन

(124)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

होने के बाद ही किसी फर्म को आदेश मिलेगा। यह तो नेगोशियेशन के बाद ही तय होगा। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि मैं इसके पीछे लगकर इसको जल्दी से जल्दी कराऊंगा।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय गहलोत साहब यह डिबेट का विषय नहीं है। आप प्रश्न पूछ रहे हैं वह जवाब दे रहे हैं। आप एक सवाल और पूछ लें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : नहीं, सवाल यह है कि पीने का पानी जोधपुर को नहीं मिल रहा है।

(12.00 बजे)

वहां सोर्स इस प्रकार का नहीं है। यदि मैकेनिकल पम्प नहीं लगे तो जोधपुर को पूरा पानी नहीं मिल पायेगा।

श्री अध्यक्ष : वह जोधपुर के लिये पूछ रहे हैं। आप किसी को मौका नहीं देने देंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय मंत्रीजी ने जो ज़वाब बताया है कि हम इसको शीघ्र ही पूरा कर देंगे। कई बार इसके टेण्डर हो गये। इसके बारे में किसी तरह का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। हालांकि मुख्य मंत्री महोदय ने पिछली सरकार के समय में भी यह घोषणा की थी कि हम इस काम को सेना की मदद से भी करायेंगे और जोधपुर को पानी देंगे। परन्तु सेना की मदद छोड़ कर... (व्यवधान) वह जो इमरजेन्सी स्कीम बनायी थी 40 लाख गैलन की इसको भी यह पूरा नहीं कर सके। महामहिम राज्यपाल महोदय के शासनकाल में भी वह काम पूरा नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि इतना समय व्यतीत कर रहे हैं टेण्डर के ऊपर, काम नहीं कर रहे हैं, जो आ गये हैं, पता नहीं किस तरह से काम करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चर्चा तो नहीं करना चाहता कि राज्यपाल महोदय के शासन में हुआ, नहीं हुआ। वह सारी स्कीम हमारी थी और वह पूरी इस वक्त हुई है। कोई आदेश नया नहीं दिया गया। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने निवेदन किया कि इसमें जो विलम्ब हो रहा है वह नेगोशियेशन के कारण हो रहा है। यह 55 करोड़ रुपये की खरीद का मामला है....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : नेगोशियेशन में आखिर कितना टाइम लगेगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : ज्यादा समय नहीं लगना चाहिये। सीमा मैं नहीं बांध सकता, जब हो जाये तब ही ठीक है। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी पूरा होगा... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : जल्दी से जल्दी समय पर हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बोर्डर-होमगार्ड कर्मियों का पदस्थापन एवं भत्तों का भुगतान

40. डा. हरिसिंह (फुलेरा) : क्या नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बोर्डर होमगार्ड राजस्थान में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से किन-किन स्थानों पर कब से तैनात है ?

(2) इन्हें क्या-क्या वेतन एवं भत्ते दिये जा रहे हैं ?

(3) दिनांक 15-2-93 के पश्चात् विराम भत्ते (Halting Allowances) के भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) वर्तमान में सीमा गृह रक्षा की 20 कम्पनियां निम्न प्रकार विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु माह अक्टूबर, 1990 से तैनात है :—

क्र.सं.	नाम जिला	कम्पनियों की संख्या
1.	जयपुर	8
2.	कोटा	2
3.	जोधपुर	2
4.	भीलवाड़ा	2
5.	भरतपुर	1
6.	गंगानगर	5
		योग : 20 कम्पनियां

(2) ड्यूटी पर तैनात सीमा गृह रक्षा सदस्यों को निम्नांकित वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं :—

(अ) वेतन : रु. 1685/- प्रतिमाह

(ब) विराम भत्ता :—

(क) जयपुर शहर में तैनात कम्पनियों के सदस्यों को रु. 38/- प्रतिदिन

(ख) अन्य स्थानों पर तैनात कम्पनियों के सदस्यों को रु. 30/- प्रतिदिन ।

(स) धुलाई भत्ता :— रु. 1/- प्रति सदस्य प्रति सप्ताह ।

(3) दिनांक 16-2-93 से विराम भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राज. जयपुर से प्राप्त हुए । नियमानुसार एक माह से अधिक की अवधि के विराम भत्ते का भुगतान वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में महानिदेशक, पुलिस, राज. जयपुर से कुछ सूचनाएं मांगी गई है, जिनके प्राप्त होते ही वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करके भत्ते का भुगतान कर दिया जायेगा ।

टोडाभीम (सवाई माधोपुर) क्षेत्र के ग्रामों हेतु परिवहन व्यवस्था

48. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर के टोडाभीम क्षेत्र में राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस सेवा किन-किन ग्रामों में है ? यह बसें कहां-कहां ठहरती हैं व रात्रि विश्राम कहां है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(2) क्या सरकार टोडाभीम तहसील के ग्राम कमालपुरा को बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या नादौती तहसील के गढ़खेड़ा एवं गढ़मोरा ग्रामों के लिए बस सुविधा है ? यदि नहीं, तो कब तक बस सेवा सरकार उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार ग्रामों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर के टोडाभीम क्षेत्र में राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस सेवायें निम्न मार्गों पर संचालित है—

1. हिण्डौन-जयपुर वाया टोडाभीम
2. हिण्डौन-टोडाभीम वाया गाजीपुर
3. महुवा-टोडाभीम वाया गाजीपुर
4. जयपुर-कमालपुरा वाया दौसा-बालाजी-टोडाभीम
5. जयपुर-पदमपुरा वाया दौसा-बालाजी, टोडाभीम
6. हिण्डौन-खोहरा वाया गाजीपुर-टोडभीम
7. हिण्डौन-मोरडा वाया गाजीपुर-टोडाभीम
8. मोरडा से महुवा वाया टोडाभीम-गाजीपुर
9. हिण्डौन-नांगल-जयपुर वाया टोडाभीम
10. गंगापुर-दिल्ली वाया टोड भीम । इन बसों के ठहराव स्थल व रात्रि विश्राम स्थल दर्शाते हुए विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां, टोडाभीम तहसील के ग्राम कमालपुरा को पूर्व से ही निगम की बस सेवा से जोड़ा हुआ है । निजी बस सेवा हेतु ग्राम कमालपुरा को बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए मार्ग का सर्वेक्षण कराने व प्रस्ताव भेजने हेतु जिला परिवहन अधिकारी, सवाई माधोपुर को निर्देश दिये गये हैं । सर्वेक्षण व प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रकरण प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के समक्ष विचारार्थ रखा जावेगा ।

(3) इन ग्रामों के लिए निज वाहनों की सेवाएं पूर्व में ही उपलब्ध है ।

(4) निगम प्रमुखतया राष्ट्रीयकृत मार्गों पर ही यात्री परिवहन सेवाओं का संचालन करता है और राष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्थित सभी ग्राम निगम की बस सेवाओं से जुड़े हुए हैं । वर्तमान में निगम विद्यमान संचालन को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु प्रयत्नशील है, अतः सीमित ससाधनों को देखते हुये सभी ग्रामों को निगम की बस सेवाओं से जोड़ा जाना सम्भव नहीं है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र बामनवास (सवाई माधोपुर) के हैण्डपम्प

43. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हीरालाल)

(1) बामनवास विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने हैण्डपम्प हैं जिन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उनके स्थान पर नवीन हैण्डपम्प लगाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जावेगा ?

(3) क्या वर्तमान में बामनवास विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्प खराब हैं ? यदि हां, तो कितने तथा उन्हें कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

(4) बामनवास तहसील में जल-प्रदाय योजना के तहत पूर्व से प्रस्तावित कितनी योजनाएं हैं तथा उनकी क्रियान्विति की क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) उल्लिखित विधान सभा क्षेत्र में 31 दिसम्बर 1993 तक 185 हैण्डपम्प परित्यक्त घोषित किए जा चुके हैं।

(2) जी नहीं।

(3) हैण्डपम्पों का रख-रखाव पंचायत समितियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में उपलब्ध सूचना के आधार पर लगभग 550 हैण्डपम्प अस्थाई रूप से खराब हैं। वर्तमान नीति के अनुसार जिन ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक हैण्डपम्प परित्यक्त हो चुके हैं उनमें नये हैण्डपम्प लगाने को प्राथमिकता दी जाती है व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा समय-समय पर विशेष परिस्थितियों में हैण्डपम्प मरम्मत अभियान चलाया जाता है।

(4) बामनवास तहसील में वर्तमान में स्वीकृत 3 योजनाएं प्रगतिरत हैं जिनकी क्रियान्विति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'क' में अंकित है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 44
(स्थगित)

नगरपालिका नैनवां में निर्वाचित बोर्ड

45. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (नागपुर) एवं **श्री रामनारायण (नैनवां)** : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगरपालिका नैनवां में निर्वाचित बोर्ड कार्यरत है ? यदि हां, तो किस तारीख से ? बोर्ड के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बोर्ड के सदस्यों तथा अध्यक्ष के खिलाफ चुंगी चोरी के आरोप लगाए गए हैं ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मामले की जांच किसके द्वारा करवाई गई है ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निर्वाचित मण्डल दिनांक 29-8-90 से कार्यरत है। मण्डल के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अध्यक्ष के विरुद्ध श्री जी. एल. सैनी, नैनवां के द्वारा चुंगी चोरी का आरोप लगाया गया था। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) उक्त आरोपों की जांच जिला कलक्टर, बूंदी के माध्यम से उप जिला कलक्टर, नैनवां से करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री पुखराज ओसवाल, अध्यक्ष, नगरपालिका, नैनवां को दिनांक 20-9-93 को निलम्बित कर न्यायिक जांच हेतु प्रकरण संयुक्त विधि परामर्शी को भिजवा दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर में कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण

46. श्री हरिसिंह (कुम्हेर): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नगर सुधार न्यास, भरतपुर ने न्यास के धन से भरतपुर शहर में कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण कराया है? यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई है?

(2) नगर सुधार न्यास राजकीय भवनों पर किन प्रावधानों के अन्तर्गत धनराशि व्यय कर सकती है?

(3) नगर सुधार न्यास, भरतपुर द्वारा उक्त भवन पर व्यय की गई राशि को सरकार कब तक वापिस प्राप्त करेगी?

उत्तर

(1) यह सही है कि नगर सुधार न्यास, भरतपुर द्वारा अपने धन से भरतपुर शहर में नवीन कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण करवाया गया है। इस निर्माण पर न्यास द्वारा रु. 81·85 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

(2) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास नियम, 1961 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत न्यास संविदा करने हेतु सक्षम है। नगर सुधार न्यास, भरतपुर द्वारा नवीन कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत संविदा से किया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर/अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के अन्तर्गत उपरोक्त प्रकरण न्यास की बैठक में दिनांक 14 जनवरी, 1983 को विचारार्थ एवं न्यास निर्णय के वास्ते रखा गया। न्यास द्वारा सर्व-सम्मति से तय किया गया कि इस भवन का निर्माण न्यास अपने आर्थिक श्रोतों से करेगा। सामान्य प्रशासन विभाग राज. सरकार द्वारा पत्र क्रमांक एफ. 5(2) सा प्र./2/83, दिनांक 16-3-83 द्वारा इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई जिसके तहत इस भवन के बदले नगर विकास न्यास को वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु पुराना कलेक्ट्रेट भवन स्थानांतरित किया जाना था जिसमें 11 × 30 वर्गफुट की 184 दुकानों

(नगरीय विकास मंत्री)

से अनुमानित 1000/- प्रति वर्गगज की दर से होने वाली आय एवं छत का अधिकार रखते हुए पहली व दो मंजिलें संभावित निर्माण से पुन: होने वाली आय को ध्यान में रखा गया था।

(3) दिनांक 4-8-88 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पुन: नगर विकास न्यास को इस भवन पर होने वाले निर्माण कार्य के बदले 8 लाख रुपये की नजुल फण्ड्स, मथुरा में स्थित सम्पत्तियों व पुराना कलेक्ट्रेट भवन दिये जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी।

पुराने कलेक्ट्रेट भवन में आर. ए. सी. बैठी हुई है व सरकार के कुछ कार्यालय हैं जिसके कारण पुराने कलेक्ट्रेट भवन को नीलामी अभी हो नहीं सकी है। न्यास द्वारा पुराने कलेक्ट्रेट भवन में स्थित किरायेदारों से भवन खाली कराकर नीलामी में विक्रय कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

नगर पालिका कानोड़ (उदयपुर) के हैण्डपम्प

47. श्री कुबेर सिंह (फलासियां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगरपालिका, कानोड़, जिला उदयपुर द्वारा 1 जनवरी, 1993 से 30 नवम्बर, 1993 तक नगर में हैण्डपम्प लगाने हेतु कोई आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आदेशानुसार निश्चित स्थान पर ही हैण्डपम्प लगाये गये? यदि नहीं, तो अन्यत्र लगाने के क्या कारण रहे? स्थान के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या एक हैण्डपम्प से दूसरे हैण्डपम्प के बीच निश्चित दूरी रखना अनिवार्य है, यदि हां, तो कितनी? क्या उक्त मापदण्ड का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) कानोड़-बड़ी सादड़ी सड़क मार्ग पर बस स्टेण्ड से ब्रह्मपुरी मध्य हैण्डपम्प किस-किस स्थान पर, कितनी-कितनी दूरी पर, किस-किस आदेशानुसार लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार प्रश्न के भाग (4) में हैण्डपम्प आदेशानुसार निश्चित स्थान एवं निश्चित दूरी के मापदण्ड के अनुसार नहीं लगाने में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उल्लेखित अवधि में नगरपालिका कानोड़ द्वारा चिन्हित 8 स्थानों पर हैण्डपम्प लगाये जाने संबंधी आवेदन की वांछित प्रतियां प्रपत्र क, ख, ग पर संलग्न हैं।

(2) सात हैण्डपम्प निर्णयानुसार निश्चित स्थानों पर स्थापित किए गए। एक हैण्डपम्प अन्यत्र लगाये जाने के कारण सहित वांछित विवरण प्रपत्र-घ पर संलग्न है।

(3) शहरी क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगाये जाने का स्थान, लाभान्वित जनसंख्या, स्थान की उपलब्धता एवं स्थानीय मांग को ध्यान

(स्वायत्त शासन मंत्री)

में रखते हुए किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में सामान्यतया कोई निश्चित दूरी निर्धारित नहीं है।

(4) उल्लेखित स्थानों के मध्य 3 हैण्डपम्प स्थापित है एवं इनके मध्य औसत दूरी 150 मीटर है। ये हैण्डपम्प उत्तर संख्या 3 में उल्लेखित कारणों को ध्यान में रखते हुए लगाये गये। विवरण प्रपत्र 'च' पर संलग्न है।

(5) हैण्डपम्प उत्तर संख्या 3 में उल्लेखित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए लगाये गये हैं। अतः कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

राज्य की सड़क निर्माण योजनाएं

48. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राज्य में सड़कों के निर्माण के लिए कोई बीस वर्षीय योजना बनाई है ? यदि हां तो कब ? नागौर जिले की योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त योजना बनाने का क्या उद्देश्य था और उसमें कहां तक सफलता मिली तथा उसमें क्या-क्या कठिनाइयां आ रही है ? उनके निवारण के लिए क्या-क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की जा रही है ?

(3) कितनी-कितनी आबादी तक के गांव कब-कब पक्की सड़कों से जोड़ने थे, उनमें से कितनी आबादी तक के गांव पक्की सड़कों से इस वर्ष तक जोड़ दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा कोई बीस वर्षीय योजना तैयार नहीं की गई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत मानदण्डानुसार गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना बनाई गई थी।

(2) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क कार्यों का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

(3) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1971 में 1500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से जोड़ना था जिनमें ग्रेवल सड़कों से जुड़े हुए गांवों को सड़क से जुड़ा हुआ मान लिया गया था। इनमें से नागौर जिले में पक्की सड़कों से जोड़े जाने वाले गांवों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

विधायकों को टोल टैक्स से मुक्ति

49. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आगरा-जयपुर राष्ट्रीय मार्ग पर ढूंढ नदी पर पुल कब बना और उस पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

(2) इस पुल पर निकलने वाले वाहनों से टोल टैक्स के रूप में अब तक कितनी धन

(श्री हरि सिंह)

राशि राजकीय कोष में जमा हो चुकी है ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) किन वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाता ?

(4) विधान सभा सत्र में या विधान सभा कार्य हेतु आने जाने वाले विधायकों से टोल टैक्स लेने का क्या औचित्य है, जब कि राजकीय वाहन टोल टैक्स से मुक्त है ? इस संबंध में सरकार क्या विधायकों के वाहनों को इस टैक्स से मुक्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ढूंढ नदी पर पुल का निर्माण अप्रेल, 1985 में हुआ । उपरोक्त पुल पर कुल निर्माण व्यय रुपये 169.61 लाख हुआ ।

(2) इस पुल पर से निकलने वाले वाहनों से टोल टैक्स के रूप में अप्रेल, 1985 से दिसम्बर, 1993 तक कुल राशि 3,87,36,352/- रुपये प्राप्त हो चुके है । वर्षवार विवरण संलग्न सूची "क" में अंकित है ।

(3) राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेशों के अनुसार जिन वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त किया गया है उनका विवरण संलग्न सूची "ख" में अंकित है ।

(4) राजकीय वाहनों से यात्रा करने पर विधायक महोदय से टोल टैक्स देय नहीं है । माननीय विधायकों के वाहनों को टोल टैक्स मुक्त करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम (सवाई माधोपुर) में सड़कों की स्वीकृति

50. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1992-93 में कितनी नई सड़कों को स्वीकृति दी गई और उनमें से कितनी सड़कें पूर्ण हो गई एवं कितनी अपूर्ण हैं ? अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं, विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) तहसील नादौती में अब तक कितनी सड़कें बनी एवं कितनी अधूरी हैं ? उनके अधूरी रहने के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1992-93 में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल 9 नई सड़कें विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत की गई । इनमें से 3 सड़कों का कार्य स्वीकृत राशि तक पूर्ण हो गया है, शेष 6 सड़कें अधूरी है । शेष कार्य विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के तहत करवाये जाने हैं, जिनकी स्वीकृति 21-1-93 तथा 20-3-93 को की गई तथा विश्व बैंक के निर्देशानुसार निविदायें आदि करने के कारण अधूरी है ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) नादौती तहसील में अब तक 2 सड़कें बनी है व 12 सड़कें अधूरी हैं जो आर. एल. ई जी पी. व एन. आर. ई. पी. योजना के अन्तर्गत थीं तथा केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजनायें बन्द कर दिये जाने के कारण ये सड़कें अधूरी हैं। उक्त सड़कों को पूर्ण करना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा (सूची सलंग्न है)

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

पुल निर्माण के मानदण्ड

51. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग द्वारा नालों, नदियों तथा अन्य स्थानों पर आवागमन की सुविधा हेतु पुलियाओं के निर्माण हेतु प्राथमिकताएं एवं मानदण्ड निर्धारित किए हुए हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम पंचायत मुख्यालय, लालपुरा को आवागमन की दृष्टि से जिला एवं तहसील मुख्यालय, बून्दी से सीधा जोड़ने हेतु मांगली नदी पर ग्राम बागदा एवं लालपुरा के आसपास पुलिया निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या उक्त स्थानों पर पुलिया निर्माण करवाये जाने पर उक्त ग्रामों सहित क्षेत्र के 15 ग्रामों को आवागमन हेतु सुविधा मिल सकेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

मेहन्दीपुर बालाजी की बाईपास सड़क का निर्माण

52. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या मेंहदीपुर बालाजी के बाईपास सड़क की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या व इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं। मेहन्दीपुर बालाजी के बाईपास सड़क की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तहसील भीम एवं देवगढ़ में सड़क निर्माण

53. **श्री लक्ष्मणसिंह** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ तहसील के किन-किन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़क से सम्पर्क सड़क बनाकर जोड़ा जाना बाकी है ?

(2) उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को कब तक पक्की सड़क से सम्पर्क सड़क बनाकर जोड़ दिया जावेगा ?

33

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले की भीम तहसील में कुल 30 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, जिनमें से 20 पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से जुड़े हुए हैं तथा शेष 10 निम्नांकित पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ना शेष है :– खेमाखेड़ा, डूंगरखेड़ा, लगेत खेड़ा, लसाड़िया, शेखावास, बरजाल, जेतगढ़, कालागुमान, सारोठ, कुशलपुरा।

राजसमन्द जिले की देवगढ़ तहसील में कुल 19 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, जिनमें से 13 पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से, 1 पंचायत मुख्यालय मेटल सड़क से तथा शेष 5 पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ना शेष है :—काकरोद, नराना दौलपुरा, माद, कालेमरिया।

(2) उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जिला राजसमन्द में सड़कों का निर्माण

54. श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजसमन्द जिले में किस-किस तहसील में कौन-कौन सी सड़क का निर्माण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक किस-किस योजना के अन्तर्गत किया गया है?

(2) वर्ष 1993-94 में राजसमन्द जिले की किस-किस तहसील में कौन-कौन सी सड़क किस-किस योजना के अन्तर्गत बनाना प्रस्तावित थी?

(3) उक्त प्रस्तावित सड़कों में से कौन-कौन सी सड़क पर कितनी-कितनी राशि खर्च की जानी थी तथा अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले की 7 तहसीलों में वर्ष 1990-91 से वर्ष 1992-93 तक विभिन्न योजनाओं में करवाये गये निर्माण कार्य सूची क-1 से क-7 संलग्न है।

(2) राजसमन्द जिले की 7 तहसीलों में विभिन्न योजनाओं में वर्ष 1993-94 प्रस्तावित कार्यों की सूची ख-1 से ख-7 में संलग्न है।

(3) उक्त सड़कों पर की जाने वाली राशि तथा उन पर किये गये खर्च की राशि ख-1 से ख-7 में संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

महिला पोलीटेक्नीक एवं खेतान पोलीटेक्नीक, जयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियां

55. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या तकनीकी शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) महिला पोलीटेक्नीक एवं खेतान पोलीटेक्नीक, जयपुर में गत तीन वर्षों से कौन-कौन से वर्ग के पद कब से रिक्त हैं?

(श्री कुबेरसिंह)

(2) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध गत तीन वर्षों में किस-किस ने, कितने-कितने समय के लिए दैनिक वेतन-भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य किया, अवधि एवं नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर गत दिनों कोई नियुक्ति संस्था प्रधान द्वारा की गई है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए सम्भागीय आयुक्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र लिया गया ? यदि हां, तो अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार दैनिक वेतन-भोगी कर्मचारियों को जो पूर्व में उक्त संस्था में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य कर चुके हैं, नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार रिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर अनुचित तरीके से की गई नियुक्तियों को निरस्त कर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) महिला पोलीटेक्नीक, जयपुर एवं राजकीय रामचन्द्र खेतान पोलीटेक्नीक जयपुर में गत तीन वर्षों से रिक्त पदों का विवरण संलग्न है।

(2) उपरोक्त दोनों संस्थानों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में किसी को भी नियुक्ति नहीं दी गई।

(3) जी, हां। (अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र की प्रतियां संलग्न हैं।)

(4) जी, नहीं, क्योंकि इन संस्थानों में कोई भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त नहीं है।

(5) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को जो शिकायत प्राप्त हुई थी, उसकी विस्तृत जांच के आदेश दे दिये गये है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राज्य के महाविद्यालय

56 श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कुल कितने महाविद्यालय हैं तथा उनमें 01 नवम्बर, 1993 को कितने विद्यार्थी अध्ययनरत थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे उपखण्ड मुख्यालय पर जहां से महाविद्यालय 30 कि. मी. या इससे अधिक दूरी पर स्थित है, वहां पर महाविद्यालय खोले जाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

(श्री रामनारायण)

(3) क्या नैनवां जिला बूंदी में महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में सामान्य शिक्षा से सम्बन्धी 171 राजकीय अनुदानित एवं अनुदानित महाविद्यालय कार्यरत हैं। चालू सत्र में इन महाविद्यालयों में लगभग 98 हजार छात्र अध्ययनरत हैं। निश्चित संख्या पूरक परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा के पश्चात् प्रवेश कार्य को अन्तिम रूप देने के बाद उपलब्ध हो सकेगी।

(2) जी नहीं। चालू वित्तीय वर्ष में महाविद्यालय खोलने हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई प्रकरण विचारधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। नये महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु बजट में प्रावधान उपलब्ध होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ निर्धारित मानदण्डों के आधार पर एवं स्थान विशेष के गुणावगुणों के आधार पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

जयपुर से चूरू वाया सरदारशहर सड़क मार्ग पर बसों का संचालन

57. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर से चूरू होते हुए सरदार शहर मार्ग पर कौन-कौन सी एक्सप्रेस बसें चलती हैं ? इन बसों का कहां-कहां व किस-किस समय व कितनी-कितनी देर का ठहराव है ?

(2) सीकर आगार के अलावा किस-किस आगार की एक्सप्रेस बस जयपुर से चूरू होते हुए सरदार शहर मार्ग पर चलती है ? क्या इन बसों का ग्राम पंचायत खोटिया (तहसील फतेहपुर, जिला सीकर) में स्टोपेज है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) जयपुर से चूरू के लिए अन्तिम एक्सप्रेस बस कब रवाना होती है ? इस बस का कहां-कहां पर स्टोपेज है ? क्या ईस का स्टोपेज ग्राम पंचायत खोटियां (तहसील फतेहपुर, जिला सीकर) में है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर से चूरू होते हुए सरदार शहर मार्ग पर निगम द्वारा वर्तमान में उपलब्ध यात्री भार के अनुरूप 3 द्रुतगामी वाहन संचालित की जा रही हैं जिनकी समय सारणी एवं ठहरावस्थल निम्नानुसार है :—

जयपुर	सीकर	लक्ष्मणगढ़
0645	0915	0945
1400	1630	1700
1630	1915	1945

फतेहपुर	चूरू	सरदार शहर
1015	1130	1300
1745	1830	2000
2030	2130	2300

(यातायात राज्य मंत्री)

(2) जयपुर से चूरू होते हुए सरदार शहर मार्ग पर केवल सरदार शहर आगार द्वारा ही द्रुतगामी सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। इन द्रुतगामी वाहनों का ग्राम पंचायत खोटिया पर ठहराव स्थल नही है, क्योंकि द्रुतगामी वाहनों का ठहराव स्थल साधारणतया 40 कि. मी. से पूर्व नहीं रखा जाता हैं। वैसे भी ग्राम खोटिया से जयपुर एवं सरदार शहर के लिये सीधा यात्री भार उपलब्ध नहीं होता है, अतः इन सेवाओं को ग्राम खोटिया पर रोकने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता। सीकर से चूरू के बीच पर्याप्त मात्रा में साधारण एवं द्रुतगामी वाहनें संचालित है जिनका ठहराव स्थल ग्राम खोटिया पर है और ग्राम खोटिया से अधिकतम यात्री चूरू व सीकर के लिये ही उपलब्ध होते हैं। जयपुर से चूरू के लिये अन्तिम द्रुतगामी बस जयपुर से रात्रि में 09.00 बजे रवाना होती है जो चूरू होते हुए सांगरिया जाती है। इस बस सेवा के ठहराव स्थल निम्नानुसार है :—

जयपुर–सीकर–फतेहपुर–चूरू–तारानगर–साहवा–नोहर – रावतसर–हनुमानगढ़–सांगरिया।

(3) इस बस का भी ग्राम खोटिया पर ठहराव स्थल नहीं है जिसके कारण प्रश्न के भाग–2 के उत्तर में अंकितानुसार हैं।

राज्य के बेरोजगारों को रोजगार

58. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या श्रम व नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में वर्ष 1992-93 में कितने बेरोजगारों के नाम पंजीकृत किये गये, और उनमें से कितनों को रोजगार उक्तावधि में दिया गया ?

(2) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितने बेरोजगारों ने नाम पंजीकृत करवाया और कितनों को रोजगार दिया गया ?

(3) क्या सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या और इसे कब तक लागू करने का विचार है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्ष 1992-93 में राज्य के रोजगार कार्यालयों में 1,87,789 बेरोजगारों के नाम पंजीकृत किये गये तथा उक्त अवधि में 12248 को रोजगार दिलवाया गया।

(2) उक्त अवधि में टोडाभीम तहसील क्षेत्र के कुल 1231 बेरोजगारों ने नाम पंजीकृत करवाया और 35 को रोजगार दिलवाया गया।

(3) नियोजन विभाग केवल बेरोजगारों का पंजीकरण व रिक्त स्थानों के लिये आवेदकों के नाम सम्प्रेषण करता है।

राज्य के आयुर्वेद औषधालय

59. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामस्वरूप)

राजस्थान में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत हैं ? उनमें वैद्य कितने हैं एवं कितने स्थान रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भरने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

राज्य में वर्तमान में 3497 आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत हैं उनके लिये विभाग में कुल 3705 आयुर्वेद चिकित्सकों के स्वीकृत पद हैं उनके विरुद्ध 3606 चिकित्सक कार्यरत हैं । वर्तमान में 99 आयुर्वेद चिकित्सकों के पद रिक्त हैं जिन्हें शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री अचलाराम, सदस्य को सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री अचलाराम, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थता के कारण दिनांक 1 जनवरी, 1994 से सत्रावसान तक विधान सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है ।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामनारायण, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समितियों द्वारा आम जनता के हितों की अनदेखी करने तथा बैठकों में जन-प्रतिनिधियों को आमंत्रित न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(2) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में अपर्याप्त व अनियमित वर्षा के कारण अकाल की उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सूचनाएं

(1) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में व जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में टिड्डियों के अचानक आक्रमण से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(2) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से खेतड़ी तांबा परियोजना द्वारा उदयपुरवाटी तहसील के कतिपय गांवों का भू-जल निर्धारित मापदण्ड के अनुसार न लेने से किसानों को सिंचाई में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में ।

(3) श्री उगमराज मेहता, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से भूमि एवं भवन कर से मुक्ति की सीमा बढ़ाने अथवा उसे समाप्त करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से बेगूं तहसील की नहरों की मरम्मत हेतु अलग से धनराशि का प्रावधान करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जहाजपुरा विधान सभा क्षेत्र की कतिपय पेयजल योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति कर पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(6) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिंचित क्षेत्र खाजूवाला की नहरों में अनियमित जल सप्लाई होने तथा सफाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना क्षेत्र के देशी मदिरा के ठेकेदार द्वारा अनधिकृत मदिरा की दुकानें चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री हीरालाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति बौंली तहसील बामनवास के गांवों में बिजली की भारी अव्यवस्था होने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(9) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के केशवरायपाटन, बूंदी एवं नैनवां के चम्बल सिंचित क्षेत्र में नहरी अव्यवस्था के कारण कृषकों में भारी असन्तोष व्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) डा. शंकर लाल सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 27-12-93 को भीलवाड़ा जिले के भिकेजी चौराहा स्थित एक पैट्रोल पम्प द्वारा कम डीजल दिये जाने की एक घटना की एफ. आई. आर. दर्ज होने के बावजूद समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती कमला, सदस्य, विधान सभा की ओर से बैराठ विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति शाहपुरा एवं विराट नगर क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से पानी का संकट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल की समुचित एवं नियमित व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्रीमती मीना अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर शहर में पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं एक-एक को बुला रहा हूं। आप विराजिये। मैं एक-एक का नाम पुकार रहा हूं। श्री कन्हैयालाल पाटीदार। बोलिये आप।....(व्यवधान) बिराजिये आप। मैं एक-एक का नाम बोल करके सबको मौका दूंगा। आप बैठिये। एक साथ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव है। बिराजिये। मैं एक-एक को बुला रहा हूं। फिर आपको भी बुला लूंगा। एक-एक करके बोलेंगे तो कुछ समझ में आयेगा। एक साथ बोलने से क्या होगा।....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप 295 लें, जीरो आवर की जगह तो फिर आपका बिजनैस शुरू हो रहा है। लेकिन यह जीरो आवर की जो महत्ता है उसमें आप ...

श्री अध्यक्ष : मैं उसी में बुला रहा हूं। ये 295 पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की पिड़ावा तहसील में 2-3 वर्ष पूर्व से डार्क जोन लगाया हुआ है जिसकी वजह से इस क्षेत्र के सारे किसानों को किसी प्रकार के लोन की राहत नहीं मिल पा रही है। इससे किसानों की हालत दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि डार्क जोन हटाया जाय। साथ ही अभी 31 दिसम्बर को डग और पिडावा विधान सभा क्षेत्रों में ओलावृष्टि से किसानों का काफी नुकसान हुआ है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां तुरन्त प्रभाव से किसानों को कोई राहत पहुंचायी जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने 30 तारीख को काल अटेन्शन दिया था और उसमें ऐसी कोई फैक्चुअल बात भी नहीं थी लेकिन उस पर आज तक सरकार का जबाब नहीं आया। अगर आपको जवाब नहीं दिया तो आप कम से कम इस सत्र में उस पर वक्तव्य दिलायें। स्थिति यह बनी कि किशनगढ़ में झगड़ा होता है और जिन लोगों की मोटर साइकिल जलायी गयी वह लोग थाने में रिपोर्ट लिखवाने गये और थाने में जो रिपोर्ट लिखवाने गये, इस तरह की लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन हो जाये कि थाने के अन्दर यह पता नहीं कि जो आदमी रिपोर्ट लिखवाने जायेगा तो उसी को बन्द कर दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह गम्भीर बात है।

दूसरा, मैंने बिजली के लिये और अकाल के लिये दो एडजोर्नमेंट मोशन दिये हैं। अगर यह इस सत्र में निकल जायेंगे जिस तरह से बिजली के ऊपर अभिभाषण में जितनी इम्पार्टेन्स दी है....

श्री अध्यक्ष : अभी दो दिन हैं। आप चिन्ता मत करिये।

श्री विष्णु मोदी : आप उसमें कुछ करिये। दूसरी महत्वपूर्ण बात शार्ट नोटिस के बारे में है कि यमुना के समझौते में....

श्री अध्यक्ष : वह तो आप कर लीजिये मंत्रीजी से।

श्री विष्णु मोदी : मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने उसमें समय के लिये कहा है मंत्रीजी से।

श्री विष्णु मोदी : दूसरा, डंकल के लिये राजस्थान के अन्दर सारे किसानों में इतनी अनिश्चितता का वातावरण बन गया है कि डंकल समझौते से इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। इस सत्र के बाद में उसके ऊपर कई सारी कार्यवाही होगी और एक विचित्र स्थिति इसलिए पैदा हो गयी है कि विधान सभा सचिवालय ने डंकल के ऊपर के एक सवाल को रिजेक्ट कर दिया है। ऐसी विचित्र परिस्थिति पैदा हो गयी है इसमें ...

श्री अध्यक्ष : हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, इसके बारे में सदन में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये। प्रश्न जो रिजेक्ट होता है वह अलग से बात करिये, सदन में इसका उल्लेख मत करिये।

श्री विष्णु मोदी : क्षमा चाहता हूं। लेकिन जहां तक डंकल के महत्व का सवाल है मुख्य मंत्री जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है जो अखबारों में छपी है। गवर्नर का अभिभाषण हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डंकल प्रस्ताव के कुप्रभाव बता रहे हैं किसानों को।

श्री विष्णु मोदी : "डंकल प्रस्तावों पर भारत सरकार की स्वीकृति होने के कारण देश के किसानों को चिन्ता उत्पन्न हुई है। वर्तमान सरकार प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि डंकल प्रस्ताव के कुप्रभावों से प्रदेश के किसानों के हितों को सुरक्षित बनाये रखने का हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा।" यह तो गवर्नर का अभिभाषण है। दूसरी तरफ चिट्ठी छपती है, मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है कि राज्य सरकारों को आप बुलायें और उन्होंने बड़ा अध्ययन किया है और वह इस बात को कह रहे हैं कि हम इसमें किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी भारी अनिश्चितता का वातावरण बन गया है। इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो रही है इसलिये आप इस बात पर यहां भी चर्चा करायें और माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि डंकल से क्या हमारे किसानों को नुकसान होगा और किस तरह से उनकी सरकार उस नुकसान को रोकने वाली है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल बहुत देर तक आपका लम्बा-चौड़ा भाषण हुआ। किसानों का दर्द होता तो कल भी थोड़ी एक-दो लाइन बोल जाते। उस समय तो बोले नहीं।

श्री विष्णु मोदी : मैंने कल भी बोला है। आप प्रोसिडिंग्स मंगा कर देख लें। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि वह सीरियस बातों को नॉन-सीरियस करने की कोशिश नहीं करें।

(41)

श्री अध्यक्ष : अभिभाषण पर बहस चल रही है ?

श्री विष्णु मोदी : पूरे में डंकल पर आपने जिक्र किया। आपने चिट्ठी लिखकर किसानों के भले की बात कोई नहीं की और जो सीरियस बात है, जो महत्वपूर्ण बात है उसको आप उड़ाने की कोशिश नहीं करें। आपने डंकल के मामले में....

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी। अब आप अधिक समय मत लीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, विष्णुजी मोदी अगर चाहें तो डकल प्रस्ताव पर बहस करा लें। डंकल प्रस्ताव पर पालियामेण्ट में तो बहस नहीं करायी, पालियामेण्ट में तो स्वीकृति नहीं करायी आपकी सरकार ने और आप यहां पर डकल प्रस्ताव की बात करना चाहते हैं। .. (व्यवधान) बहस करा कर स्वीकृत करा लो संसद में विपक्ष ने यह कहा कि....

श्री विष्णु मोदी : मैंने जो लिख कर दिया है कि क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी ने डंकल प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिख कर यह मांग की है कि डंकल प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार से विचार किया जाना चाहिए। डंकल प्रस्ताव के सम्बन्ध में जहां तक कृषि व्यवस्था और किसानों के हितों का प्रश्न है, राज्य सरकार की क्या राय है, कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें। मैं डंकल प्रस्तावों की बहस की बात नहीं कर रहा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी यह बतायें कि डंकल प्रस्तावों से राजस्थान के किसानों का क्या अहित होने वाला है और उनकी सरकार ने जो अभिभाषण में कहलाया है कि उनके हितों की रक्षा की जायेगी ... (व्यवधान)........(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप। श्री रामनारायणजी....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, डंकल प्रस्ताव के बारे में धन्यवाद प्रस्ताव में उल्लेख है। कांग्रेस के माननीय सदस्य बतायें अभिभाषण पर कि डंकल से किसानों को क्या फायदा होने वाला है ? हमारी पार्टी और हमारी सरकार बार-बार कहती है कि डंकल प्रस्ताव किसानों के खिलाफ है और राजस्थान की सरकार किसानों पर यह अत्याचार नहीं होने देगी....(व्यवधान)....

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, गुलामी का प्रस्ताव है यह, इस देश के किसानों के लिये, व्यापारियों के लिये, उद्योगपतियों के लिये, सबके लिये।

श्री अध्यक्ष : रामनारायणजी, बोलिये आप.... व्यवधान)....मोदीजी, आइन्दा मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा। I will not give you any chance. नहीं, नहीं, यह आप मेरी इजाजत का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने केवल आपको मेन्शन करने के लिये कहा है and you started the debate which is not desirable. शून्यकाल में डिबेट नहीं होती है इसलिए now, please keep yourself under restraint. आप रेस्ट्रेण्ट में रहिये, जो आपको मैंने उल्लेख का कहा है आपने डिबेट शुरू कर दी। इसका मतलब आप अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देना नहीं चाहते। आप बोलिये।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आजकल हॉस्पिटल में दवाइयों से जिस तरह से मरीज मरते हैं उनका कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। आये दिन किसी न किसी हॉस्पिटल में या तो गलत दवाई हो तो रि-एक्शन हो जाता है या दूसरी तरह की दवाइयां, जिनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, उपयोग में लायी जाती हैं। यह 10 हजार रुपये तक की खरीद का जो अधिकार दिया गया है, ज्यादातर दवाइयां उनके द्वारा वह हॉस्पिटल में खरीदी जाती हैं जो 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 60 प्रतिशत कमीशन की होती हैं। अभी तीन दिन पहले बारां में इस मामले में ड्रग्स इंस्पेक्टर वगैहर ने छापा मारा है और उस मामले को दबाया जा रहा है और उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कुछ दिनों पहले बूंदी में भी इस तरह से एक मौत हुई है। तो जो दवाइयां रि-एक्शन करती हैं उनको एक को भी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, थर्मा ट्रेड्स और दूसरी महाराष्ट्र एण्टीबायोटिक्स है, इस तरह की कम्पनियां दवाई दे रही हैं। महाराष्ट्र एण्टीबायोटिक्स में तो क्रिस्टल आयोडीन वाले मामले में लाखों रुपये का घोटाला पकड़ा गया है। कोटा में 12 लाख रुपये की यह इस तरह की परचेज जो बिना अखबारों में विज्ञापित किये हुए की गयी है उसकी किसी तरह की कोई जांच नहीं की जा रही है। हर हॉस्पिटल में इस तरह की बात है। आप कोटा में, बारां में, झालावाड़ में इसकी जांच करवाइये।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री रामनारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे मामले में यदि सरकार ध्यान नहीं देगी तो यह मौतें जो हो रही हैं अप्राकृतिक तरह से, यह बढ़ती जायेंगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी ध्यान दें।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मुद्दे को मैं आज आपकी इजाजत से उठा रहा हूं, मैं समझता हूं इस सदन में कोई विवाद नहीं होगा। जनप्रतिनिधि और सरकार के बीच की खाई कम हो, इसके लिए आवश्यक रहेगा। जो पहले भी सुझाव आपके समक्ष दिया गया है कि इस सदन की जो क्वेश्चन आवर की कार्यवाही है उसको दूरदर्शन पर दिखाने की व्यवस्था करें। मान्यवर, इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं केन्द्र में मंत्री था, सबसे पहले मैंने लाइव टेली-कास्ट की बात की। आंशिक रूप से वह बात स्वीकार हुई। राज्य सभा और लोक सभा की क्वेश्चन आवर की कार्यवाही दूसरे दिन दिखायी जाती है। जनता की इसमें भारी दिलचस्पी है जनता अपने प्रतिनिधि पर इस माध्यम से नजर रख सकती है और, मान्यवर, यह बात आपके लिये भी सहायक होगी, जो थोड़ी-बहुत अव्यवस्था हाउस में होती है और आप व्यवस्था कायम करने का प्रयास करते हैं। जनता भी अपने प्रतिनिधि पर असर रखेगी कि विकास कार्य में ज्यादा से ज्यादा रुचि हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस विषय में शीघ्र कोई कार्यवाही की जावे ताकि इस सत्र का जो शेष भाग है उसके क्वेश्चन आवर को दूरदर्शन पर दिखाया जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बुडानिया जी, आप कुछ बोल रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों ने बताया है कि वहां पर ग्रामीणों से जो ऋण वसूली की जा रही है उसमें बहुत जोर-जबरदस्ती की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी, और माननीय मंत्री महोदय भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में भयकर अकाल पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जबकि रोजगार मिलना ग्रामीणों के लिये जरूरी है, विशेष तौर से हरिजन भाई हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अपने रोजगार की व्यवस्था में लगे हुए हैं और चूंकि पीने के पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है, दिनभर परिवार के अधिकांश लोग पानी की व्यवस्था में लगे हुए हैं, मैं यह नहीं कहता कि उनकी वसूली आप तुरन्त रोक दें लेकिन जो नार्म्स बने हैं, कानून है कि अकाल के अन्दर वसूली तुरन्त रोक दी जाये। मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा भी की है कि जनवरी में राहत कार्य शुरू कर रहे हैं, 10 तारीख की मीटिंग का भी इन्होंने अनाउंस किया है, तो मेरा निवेदन है आपसे कि चाहे वह को-आपरेटिव की वसूली हो, चाहे अन्य वसूलियां हों, आप तुरन्त प्रभाव से अधिकारियों को निर्देश दें कि वह गांव में जा करके गरीब लोगों के साथ जोर-जबरदस्ती नहीं करें, उनकी बेइज्जती नहीं करें। हालत यह हो रही है कि वह इस प्रकार से गाड़ियां लेकर घुसते हैं टेरर फैलाने के लिये और गरीबों को घर छोड़कर कोसों दूर भागना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि आप सदन में तुरन्त बतायें कि वह इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : 10 तारीख को।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये।

श्री भीमराज (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी चार-पांच दिन पहले मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पाली शहर के पास नया गांव में यह जो....

श्री अध्यक्ष : हां, आप इसके बारे में मेरे से मिल लेना।

श्री भीमराज : नहीं सर, उसमें अनुसूचित जाति के एक आदमी की हत्या कर दी गयी....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप मेरे से मिल लें।

श्री भीमराज : हत्या कर दी गयी....

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से मिल लेना। यह अंकित नहीं होगा।

श्री भीमराज : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह अंकित नहीं होगा।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

जब तक मैं व्यवस्था नहीं दूंगा कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री भीमराज : × × ×

श्री अध्यक्ष : कुछ अंकित नहीं होगा जब तक आप मेरे से व्यवस्था नहीं लेंगे। स्थगन प्रस्ताव के बारे में व्यवस्था के लिये मेरे से अलग से मिल लीजिए।

श्री भीमराज : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से मिल लीजिए, मैं व्यवस्था दे दूंगा।

श्री भीमराज : अच्छा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ आप देखते ही नहीं हैं। हमने तो तीन बार इशारा कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आपने चिट नहीं भेजी है। कृपया चिट भेजिये। कल मैं बोलने का मौका दूंगा, अभी मौका नहीं दूंगा आपको। आपका बहुत लेट आया, आप अनुपस्थित थे, आपके दो प्रश्न चले गये। दो प्रश्न आपकी वजह से चले गये। आज आपने अनुपस्थित रह करके हजारों रुपये सरकार के गवा दिये। आप अनुपस्थित थे। नहीं, आप बोलिये, मोहनजी मोदी। (व्यवधान) आप चिट भेजिये। अब जो व्यवस्था है उसे तोड़िये मत, आप मुझे पहले चिट भेज दीजिये।

श्री रिछपाल सिंह : आपने सब को बुलवा दिया. साहब. फिर हमारे को क्यों नहीं बोलने दिया जाता।

श्री अध्यक्ष नहीं सब ने चिट भेजी है, सब की चिट मेरे पास है, लिखित में है। मेरे पास पड़ी हुई हैं उन्हीं को बुलवाया है मैंने। आप बोलिये।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

नीम का थाना में शराब की अनधिकृत दुकानें

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में विदेशी मदिरा का ठेका कुरुक्षेत्र मे श्रीमती शकुन्तला पार्टी को दिया गया है जिसकी स्वीकृत दुकानें 15 हैं और 17 उनके उप केन्द्र हैं। वहां उन्होंने एक सौ के करीब अनधिकृत दुकानें चला रखी हैं। गांव में लोगों में इसका बड़ा असंतोष है। इस बात की सारी जगह उन्होंने शिकायतें भी की, सारे उच्च अधिकारियों के पास में शिकायतें भेजीं लेकिन आज तक वह दुकानें नहीं उठायी गयीं। 27 तारीख को डाबला पचायत के गांव के लोगों ने ठेकेदार से इस बात का निवेदन किया कि यह जो ढाणी के अन्दर दुकान कर रखी है इसको हटा दें। इस पर ठेकेदार ने पुलिस से मिलकर उन लोगों के खिलाफ इस बात का मुकदमा बना दिया कि इन्होंने मेरी दुकान, खोके को–जिसको दुकान कहते हैं, गुड़ा दिया, बोतलें फोड़ दीं, उसमें से पैसे निकाल कर ले गये। डकैती का 7 आदमियों पर केस बनवा करके उनमें से 2 आदमियों को अरेस्ट करवा दिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज अंकित न हो।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं ?

श्री मोहनलाल मोदी : मैं उसी का सारांश बोल रहा हूं साहब।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। वरबेटम पढ़िए। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। जो आपने लिखित में दिया है वही अंकित होगा, उसी का पढ़िये। वह भाषण नहीं है। उसी को पढ़ दीजिये।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं उसको पढ़ देता हूं।

महोदय, नीमकाथाना में देशी मदिरा का ठेका ग्रुप क्षेत्र में श्रीमती शकुन्तला पार्टी को स्वीकृत किया गया है जिसमें 15 दुकानें व 18 उप दुकानें स्वीकृत हैं। इस ग्रुप के संचालक ने स्वीकृत दुकानों के अलावा 51 अनधिकृत दुकानें चालू कर रखी हैं जिससे जनता में असन्तोष व्याप्त है। समय-समय पर ग्रामीण जनता द्वारा अनधिकृत दुकानों को बन्द कराने के लिए उच्च अधिकारियों को आवेदन किया लेकिन ग्रामीण जनता के बार-बार आवेदन करने पर भी अनधिकृत दुकानें बन्द नहीं करायी गयीं।

इसी सन्दर्भ में ग्राम पंचायत डाबला की ढाणियों की ग्रामीण जनता ने मोका वाली ढाणी के पास अनधिकृत रूप से रखी हुई दुकान को उठाने की आवाज उठायी कि यहां असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्रता करने से ग्रामीण महिलाओं का खेती में काम करना दुश्वार हो गया। महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। ठेकेदार को इस दुकान को उठाने का अनुरोध किया। इस पर ठेकेदार ने पुलिस से सांठगांठ कर ग्रामीण जनता के 7 व्यक्तियों पर झूठा मुकदमा बनाकर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया और दूसरा मुकदमा महिलाओं पर पुलिस का सामना करने का बनवाकर आतंक फैला रखा है। इस क्षेत्र की जनता में भारी असन्तोष व्याप्त हो रहा है और धीरे-धीरे असन्तोष की आग बढ़ रही है जो कभी भी भयंकर रूप धारण कर सकती है। इस दुकान को पुलिस रिकार्ड में अचला की ढाणी के नाम से स्वीकृत दुकान बताने की कोशिश की गयी है जबकि इस ग्राम पंचायत डाबला व आसपास भी इस नाम की कोई ढाणी नहीं है। यह एक्साइज विभाग की मिलीभगत से किया गया है।

अतः मैं यह मांग करना चाहता हूं कि तुरन्त अनधिकृत दुकानों को बन्द किया जावे तथा क्षेत्र की पूरी ग्रामीण जनता जिस दुकान को बन्द करवाना चाहे उनको बन्द करवायी जावे और असामाजिक तत्वों के कृत्यों पर रोक लगाई जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल (बामनवास) अनुपस्थित।

श्री मांगीलाल मेघवाल।

चम्बल सिंचित क्षेत्र में नहरी अव्यवस्था

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से हमारे बूंदी जिले के

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

चम्बल कमाण्ड के बायीं मुख्य नहर से जो व्यवस्थाओं के कारण किसानों को भारी परेशानी हो रही है उसके बारे में आपके माध्यम से, सरकार का ध्यान और सी. ए. डी. मंत्री महोदय का विशेष ध्यान आकर्षित करूंगा।

मान्यवर, चम्बल सिंचित क्षेत्र कोटा परियोजना के तहत हमारे जिले बूंदी में केशवरायपाटन, बूंदी एवं नैनवा विधान सभा क्षेत्र के सिंचित क्षत्रो में नहरी अव्यवस्था के कारण कृषक वर्ग एवं आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहरी अव्यस्था एव बजट के अभाव से दिनो दिन समस्याओं में बढ़ोतरी हो रही है वे इस प्रकार हैं:-

वर्ष 1960 में खोदी गयी नहरों, नहरों पर बने पक्के फाल, पुलियाएं साइफन एवं काजवे आदि आज क्षतिग्रस्त हो गये हैं। साथ ही नहरों में मिट्टी जमा हो जाने से पानी इधर उधर फैल जाता है जिससे पानी के भराव की स्थिति पैदा हो गयी है इससे हजारों हैक्टेयर में पानी भरा है। फसलें नहीं हो सकतीं और कृषकों की बहुमूल्य भूमि बरबाद हो जाने से इनके भूखों मरने की स्थिति हो गयी है।

दूसरा, जब पानी हैड रीच में ही फैलकर भराव की स्थिति हो गयी है जिससे टेल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचता है। इससे हमारी बायीं मुख्य नहर के बूंदी ब्रांच के 50 से 60 गांव अजेता, खटकड़, रायथल, जखाड़ा, बम्बोटी आदि. कापरेन ब्रांच के मायजा भासीजी का बाराना, नोताड़ा, रेबारपुरा, डगरिया एवं बोरदा काछिकार ग्राम पंचायतों के 50 ग्राम एवं केशवरायपाटन ब्रांच दढ़ू-खेड़ा घाट का बाराना, लबान, माखीदा, बड़ाखेड़ा, पापड़ी एवं बसवाड़ा आदि ग्राम पचायतों के 40 गांव सदैव पानी के अभाव में सूखे रहते हैं। कमाण्ड क्षेत्र होते हुए भी हजारों हैक्टेयर वाले हजारो कृषक भारी परेशानी उठाते हैं।

तीसरा, नहरों के क्षतिग्रस्त होने एवं पानी फैलने से आम राजस्व रास्ते पानी से भर जाते हैं आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ती है, जीप कार तो दूर की बात किसान की बैलगाड़ी और व्यक्ति पैदल तक भी नहीं चल सकता है।

अतः नहरी क्षेत्र में पानी के भराव की स्थिति, टेल क्षेत्रों में पानी न मिलने की स्थिति के समाधान हेतु निम्न कार्य किये जाकर समाधान किया जावे।

एक, चम्बल सिंचित क्षेत्र में नहरों की मरम्मत, पक्के फाल, पुलिया एवं साइफन आदि के लिये वर्ष 94-95 के बजट में कम से कम 2 करोड़ रुपयों का विशेष बजट दिया जावे।

दूसरा, नहरों में मिट्टी जमा हो जाने से नहरों से पानी फैलकर आम रास्ते खराब करता है साथ ही भराव की स्थिति पैदा करता है। इसके समाधान हेतु नहरों एवं ड्रेनों की योजनाबद्ध सफाई मशीनों द्वारा करवायी जावे। अभी इस क्षेत्र में जो भी मशीनें काम में ली जा रही हैं वे 30 वर्ष पुरानी हैं जो कभी भी चार घन्टे लगातार नहीं चलतीं। साथ ही इनका नियन्त्रण कोटा में बैठे अधिकारियों के हाथ है। वर्ष

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

1992 जुलाई में कोटा में सी. ए. डी मंत्री महोदय, सिचाई सचिव महोदय, मुख्य अभियन्ता, सिचाई, संभागीय आयुक्त कोटा एवं जनप्रतिनिधि के रूप में मैं स्वय उपस्थित था जिसमें तीन नयी इडर मशीन एक करोड़ की खरीदने के प्रस्ताव थे, वे मशीनें खरीदी जावें। खराब पुरानी मशीनों को राइट आफ किया जाकर इनकी जगह दूसरी मशीनें लगायी जावें ताकि नहरो एवं ड्रेनों में जमी मिट्टी खरपतवार एवं टूट-फूट को सुधारा जाने से पानी टेल तक पहुंचाया जा सके।

आम राजस्व रास्तों को विशेष बजट आदि दिलाया जाकर सुधारा जावे जिससे जनता को राहत मिल सके।

अधिकारी वर्ग आम तौर से अपने मुख्यालयों पर नहीं रहते हैं उन्हें भी पाबन्द किया जावे ताकि समय समय पर किसानों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो सके।

अत: मैं अपने इस लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाकर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की सारी समस्याओं का तुरन्त समाधान हो।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

टिड्डियों के आक्रमण से फसल को क्षति

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर पहले था; खैर, आपकी आज्ञा।

मैं विधान सभा के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य में और जयपुर ग्रामीण में टिड्डियों के अचानक हुए आक्रमण से हुये खराबे की पूर्ति किये जाने बाबत अपनी बात कहना चाहूंगी।

मान्यवर, गत दो माह पूर्व राज्य में टिड्डियों का दल आया और अनेक जगह फसलें खराब करता हुआ जयपुर जिले की तहसील पंचायत समिति जमवारामगढ़ में एकाएक पन्द्रह किलोमीटर लम्बा दल तीव्र गति से 10 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता हुआ भानपुर कलां, वासना, इन्द्रगढ़ पर आया व छा गया, बैठ गया। टिड्डी दल के आक्रमण से न केवल फसलें खराब हुई बल्कि घाटा, जलधारी, वासना में पेड़ टूटे, नांगल तुलसीदास में खराबा हुआ, ग्राम निम्बी में खराबा हुआ, बिजूरी जिन्हवास आदि भानपुर कलां नटाटा की ढाणियों व इन्द्रगढ़ गांव ढाणियों से लेकर पापड़, सायपुरा, जमवारामगढ़. लांगड़ीवास, राहोरी, नायला होकर यह दूसरे दिन जब दल लौटा, आगे बढ़ा रास्ते में उक्त व और गांवों, ढाणियों में खराबा करता हुआ गया। राष्ट्रपति का शासन था, उक्त मामले में ना तो कोई गिरदावरी करायी गयी, जैसी मेरी जानकारी है। चूंकि उस रात मैं स्वयं उन गांवों में घूमी और लोगों को बुलाकर आवाजें करायीं टिड्डियों को विरत करने का प्रयास करते रहे, गांव के लोग सारी रात भाग-दौड़ करते रहे, मेरे सारे प्रयत्नों से, गांव वालों के प्रयत्नों से कुछ कट्टे ही इस क्षेत्र में रासायनिक पदार्थों के प्राप्त हुए, जिन्हें छिड़कने से कोई खास लाभ नहीं हुआ। वह बहुत नाकाफी था। मैंने उसी दिन जितना भयानक खराबा देखा था जिला

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

प्रशासन को लिखकर दिया ग्रामीण जन अब सरकार से आशा लगाऐ बैठे हैं कि उक्त खराबे का मुआवजा दिलाला जावे जिससे किसानों को राहत मिल सके तथा नही दिये जाने से हो रही देरी से जनता में असन्तोष है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यहां सरकार बैठी है, माननीय मुख्य मन्त्री जी हैं, वह इस सब पर क्या सुविधा, राहत दिलाने वाली है, इस सम्बन्ध में बतलायें, जिससे ग्रामीणजनों में कुछ सन्तोष हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

खेतड़ी तांबा परियोजना द्वारा पानी लेने के निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत से मैं नियम 295 के अधीन नीचे लिखे अनुसार विशेष उल्लेख के द्वारा महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं।

झुंझनूं जिले में स्थापित खेतड़ी तांबा परियोजना के लिये उदयपुरवाटी तहसील के बागोली-गुडा-चंवरा-मैनपुरा आदि गांवों में कुएं बनाकर पानी लिया जा रहा है। यह योजना शुरु की गयी तब तांबा परियोजना पर यह पाबन्दी लगायी गयी थी कि पानी इतनी गहराई से लिया जावे ताकि काश्त के कुओं को मिलने वाले पानी पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े और किसानों को फसल की पिलाई के लिये पर्याप्त पानी मिलता रहे। खेतड़ी परियोजना इस शर्त को मान नहीं रही है तथा निर्धारित गहराई से पानी नहीं लेकर ऊपर से पानी ले रही है। कुएं का निर्माण इस प्रकार से किया जा रहा है कि बीच-बीच में जाली लगा दी जाती है जिससे निश्चित गहराई वाली शर्त का उल्लंघन होता है तथा ऊपर की सतह का पानी भी वे कुएं खींच लेते हैं जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है फसलें बरबाद हो रही हैं पूरा कृषि क्षेत्र सूखा होता जा रहा है। राजस्थान सरकार, भूजल मंत्रालय तथा अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड सब इसमें सम्मिलित हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था करायें कि एक निश्चित निर्धारित गहराई से ऊपर का पानी नही लिया जावे, जिससे किसानों को बरबादी से बचाया जा सके। पहले भी इस सम्बन्ध में आन्दोलन हो चुके हैं, किसानों पर मुकदमें बन चुके हैं और कुओं के नये निर्माण का कार्य ठप्प पड़ा है इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसका कोई समाधान किया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता।

भूमि एवं भवन कर सीमा का पुनर्निर्धारण

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। भूमि एवं भवन कर से मुक्ति की सीमा में एक लाख रुपये मकान की कीमत व एक लाख की आबादी वाला शहर नियमों में होने से आम जनता को जो छोटे-छोटे कस्बों में रहती हैं, काफी

(श्री उगमराज मेहता)

कष्ट हो रहा है, जिसके तहत ब्यावर जैसा छोटा-सा शहर भी इस सीमा में ऊपर निकल गया है। इन सीमाओं का निर्धारण सन् 1973 में किया गया था। आज 20 वर्ष अर्थात् दो दशक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इस सीमा को बढ़ाया नहीं गया है जबकि इस अवधि में कीमतें आसमान को छूने लगी हैं और आबादी भी दिन-दुगनी व रात-चौगुनी गति से बढ़ गयी है।

सन् 1977 में जनता सरकार, माननीय मुख्य मंत्रीजी, भैरोंसिंह शेखावत के समय में भूमि एवं भवन कर को समाप्त कर दिया था जिसे बाद की सरकार ने पुनः चालू कर दिया। यह सरकार इस कर प्रणाली को पुनः समाप्त करे तो स्वागत योग्य है और यदि इसे समाप्त किया जाना वर्तमान परिस्थितियों में सम्भव न हो तो कम से कम छोटे-छोटे मकान-मालिकों व कम जनसंख्या वाले कस्बों के लोगों को राहत दिये जाने के प्रयोजन से कर मुक्ति की सीमा एक लाख रुपये के स्थान पर पांच लाख रुपये व एक लाख की आबादी की सीमा को दो लाख किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है जिससे गरीब एवं छोटे कस्बों के निवासियों को उचित राहत मिल सके।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

बेगूं तहसील की नहरों की मरम्मत

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत बेगूं तहसील की नहरों की मरम्मत हेतु अलग से धनराशि का प्रावधान निर्धारण करने हेतु निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से।

मैं राज्य सरकार का ध्यान उक्त विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बेगूं क्षेत्र में औराई बांध, राजगढ़, तालाब, मानसरोवर तालाब, कालादेह, उमरन्दा आदि तालाबों की नहरों की हालत बहुत ही खराब है। काफी पुरानी हो जाने से टूटी-फूटी हालत में है जिससे बहुत-सा पानी बेकार बहकर रास्तों, नालों-वालों में चला जाता है और सिंचाई के काम नहीं आता, बल्कि खेतों को खराब कर देता है। कई दिनों तक खेत गीले रहने से फसलें समय पर बो नहीं सकते। नहर के आसपास लगने वाले खेतों में गीला रहने से, पानी भरा रहने से फसलों का बढ़ाव भी रुक जाता है जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। जब हम नहरों की मरम्मत की मांग करते हैं तो सिंचाई विभाग के अधिकारी बताते हैं कि मरम्मत के लिये कोई अलग से बजट नहीं है। नहरों की देखभाल के लिये जो राशि निर्धारित की जाती है उसी राशि में से कर्मचारियों का वेतन भी चुकाया जाता है। अतः अधिकांश राशि वेतन चुकाने में ही खर्च हो जाती है और नहरों की मरम्मत हो ही नहीं पाती है। अतः राज्य सरकार से मेरा अनुरोध है कि वेतन और नहरों की देखभाल की राशि शामिल न रखकर अलग-अलग निर्धारित की जाय ताकि नहरों की मरम्मत हो सके। नहरों की मरम्मत हो जाने से पानी का दुरुपयोग रुकेगा, जिन खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, पानी पहुंचेगा, जिन किसानों के खेत बरबाद हो रहे हैं, फसलें पैदा नहीं कर पा रहे हैं, फसलें ले सकेंगे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी। (अनुपस्थित) श्री भीमसेन चौधरी।

खाजूवाला की नहरों में अनियमित जल वितरण

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र के सिंचित इलाकों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र खाजूवाला इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की अनूपगढ शाखा के अन्तिम छोर पर है जहां आमतौर पर नहरों में अनियमित पानी सप्लाई की शिकायत रहती है। इस वर्ष तो पौंग बांध में वर्षा की कमी से पानी की समस्या गंभीर है मुख्यतः के. जे. डी. व के. वाई. डी. व बी. डी. नहरों के आर. डी. 28 के बाद के काश्तकारों की समस्या हमेशा ही बनी रहती है। नहरों की सफाई भी नियमित नहीं होती है अतः उपरोक्त नहरों की सफाई नियमित तौर पर करायी जावे और आर. डी. 28 के बाद काश्तकारों को नियमित पानी दिए जाने की सुचारू व्यवस्था की जावे।

श्री अध्यक्ष : डॉ. शंकरलाल।

पैट्रोल पम्प भिकेजी चौराहा की घटना

श्री शंकरलाल (कपासन) : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस सदन में माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 27-12-93 को भीलवाड़ा जिले के भिकेजी चौराहे पर स्थित नेशनल फिलिंग स्टेशन से एक ट्रक मॉडल 407 में डीजल भराया। इस ट्रक के डीजल टैंक की क्षमता 85 लीटर है फिर भी उसमें 88 लीटर डीजल मीटर की रीडिंग के अनुसार भरा गया। जबकि टैंक में पहले भी कुछ डीजल था। इस पर मोटर-मालिक व अन्य व्यक्तियों ने मिलकर इसकी शिकायत एस डी ओ. माण्डलगढ़ को की, तथा उक्त बिल भी डीजल का पेश किया जिस पर एस डी एम माण्डलगढ़ ने इस शिकायत पर एक एफ. आई. आर. माण्डलगढ़ थाने में दर्ज करायी। थाना अधिकारी की जांच से पम्प से तेल कम नाप कर देना साबित हुआ, जिस पर पम्प पर कार्यरत कर्मचारी गजपत व बालूसिंह को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और पम्प के मैनेजर जाकिर हुसैन, जो कि भीलवाड़ा के भूतपूर्व जिला प्रमुख व कांग्रेस (आई) के नेता श्री हफीज मोहम्मद के सुपुत्र हैं को थाने में ले जाकर छोड़ दिया और पुलिस ने यह कहा कि पम्प का मालिक कौन है इसका पता नहीं लग पा रहा है। मालिक का नाम मालूम होने के नाम पर पुलिस वाले जयपुर आकर बैरंग लौट गये और 5 दिन मालिक का पता लगाने में लगाते रहे जबकि पम्प के लाइसेंस पर ही मालिक का नाम लिखा हुआ होता है और गिरफ्तार कर्मचारियों ने भी नाम बताया फिर भी राजनैतिक प्रभाव में आकर पुलिस प्रशासन ने जान बूझकर 5 दिन का समय पम्प के मालिक श्री हफीज मोहम्मद व मैनेजर जाकिर हुसैन को दिया जिससे अग्रिम जमानत कराने का अवसर मिला।

(श्री शंकरलाल)

पुलिस थाना, माण्डलगढ़, एस डी. ओ., माण्डलगढ़ तथा एस. पी., भीलवाड़ा का यह कार्य कांग्रेस पार्टी के प्रभावी नेता होने के कारण श्री हफीज मोहम्मद को उनके प्रभाव में आकर उनको बचाने का रहा है जबकि रसद विभाग द्वारा जांच करने पर पाया कि हर पन्द्रह लीटर तेल में एक लीटर तेल कम दिया जा रहा है और इस प्रकार तेल कम देने तथा जनता को धोखा देने, अनुचित लाभ उठाने वालों की गिरफ्तारी होनी चाहिये थी।

अतः मैं माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि वे इस प्रकार की पत्रावली संख्या 217/93 दिनांक 27-12-93 थाना माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा से मंगा कर अवलोकन करावें और दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करें तथा राज्य के समस्त पैट्रोल पम्पों की स्पेशल चैकिंग तत्काल करावें।

धन्यवाद।

श्री रामनारायण (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। यह माननीय सदस्य व्यक्तिगत नाम ले करके सदन में....

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर नहीं है। बीच में होता नहीं है पाइंट आफ आर्डर।

श्री रामनारायण : व्यक्तिगत नाम ले करके बोल रहे हैं। व्यक्तिगत नाम....

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

एक माननीय सदस्य : आप भी नाम ले करके कई बार बोले हो, माननीय सदस्य महोदय। आपके कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने कई लाखों रुपये का घोटाला किया है, माननीय सदस्य महोदय।

श्री रामनारायण : व्यक्तिगत नाम लिया है, सदन की कार्यवाही से निकाला जावे, सदन की कार्यवाही से निकलवाया जाय। यह परिपाटी सदन की.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : व्यक्तिगत नाम वापस निकलवाना चाहिये, नहीं तो कल को हम भी.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण : मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। व्यक्तिगत नाम ले करके सदन में इस तरह की परिपाटी नहीं पड़नी चाहिये।

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) : एफ. आई. आर. में जो नाम कोट हैं वो ही पढ़े हैं, व्यक्तिगत कोई नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : समझ में आ गयी बात। ठीक है, मैं देख लूंगा।

श्री नाथूसिंह : माननीय सदस्य ने तो जो एफ. आई. आर. में नाम कोट हैं वो ही पढ़े हैं।.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण : मैं सिरोही की माननीय सदस्या से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि उनके परिवार का नाम भी आ सकता है कल को। यह सारा प्रोसीडिंग्स से निकलवाने की व्यवस्था दी जाये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला।

राज्य में पेयजल का संकट

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पेयजल की व्याप्त गम्भीर और व्यापक समस्या एवं कुओं के तेजी से गिरते हुए जल स्तर के सम्बन्ध में मैंने बैराठ विधान सभा क्षेत्र के बाबत और आम तौर पर राजस्थान की समस्या के बाबत भी यह विशेष उल्लेख आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बैराठ विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति शाहपुरा एवं विराटनगर में पिछले कुछ वर्षों से पीने के पानी एवं कृषि कुओं में पानी की कमी के गम्भीर संकट से उत्पन्न हो रही स्थिति के बाबत में आप सभी महानुभाव अपने-अपने इलाकों के सन्दर्भ में चिन्तित हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय इस क्षेत्र के अनेक गांवों की पेयजल योजनाएं प्रस्तावित होकर काफी समय से प्रशासन में उच्चस्थ स्तर पर लम्बित हैं और उनकी स्वीकृति न होने के कारण से ग्रामवासियों, नगरवासियों को भारी परेशानी हो रही है । कस्बा विराटनगर की पानी की टंकी क्रेक हो चुकी है और शीघ्र ही उसे तिलांजलि दी जाने वाली है और उसका दूसरा कोई प्रावधान भी नहीं किया गया है । जिस तरह से सीधा सोर्स से जुड़ जाने के बाद कस्बे की स्थिति बहुत शोचनीय होने वाली है, अनेक मोहल्ले अभी भी पाइप लाइन से नहीं जुड़े हैं । इसी प्रकार कस्बा मनोहरपुर की टंकी अनेक वर्षों पहले बनी थी, आज आबादी उससे चौगुनी हो चुकी है लेकिन दूसरी टंकी का प्रस्ताव काफी समय से लम्बित है, कई मोहल्ले भी पानी से वंचित पड़े हुए हैं । इसी प्रकार से शाहपुरा कस्बे में भी नयी टंकी बनाने के प्रस्ताव काफी समय से विभाग में लम्बित है लेकिन उनकी स्वीकृति नहीं हो पायी है । ग्राम जार्जकला, भाभरु, ढाणी गैसकान, बागावास चौरासी, कुहाड़ा, सूरजपुरा, निठारा, छोरी, करीरी, नायन, धानोता, बिलान्दरपुर, धोली, ग्रामलोदा, म्हार खुर्द, बिशनगढ़, घासीपुरा आदि अनेक गांवों की और योजनाएं ऐसी हैं जो काफी समय से स्वीकृति के लिए विभाग में लम्बित पड़ी हुई हैं लेकिन उनकी स्वीकृति अभी तक भी नहीं हो पायी है ।

इसके अलावा ग्राम जवानपुरा सोठ्याणा, राजपुरा, बिदारा, अमरपुरा, नाथावाला, रघुनाथपुरा, बाड़ीजोड़ी की मांग भी काफी तकाजे से की जा रही हैं । उनके शीघ्र प्रस्ताव बनाये जाकर उनकी स्वीकृति भी अपेक्षित है । माननीय अध्यक्ष महोदय कई जलदाय योजनाएं जो बनी हुई हैं, वहां के कई मौहल्लों के अन्दर अभी तक भी पाइप लाइन नहीं चालू की गई है तथा कई घरों में कनेक्शन भी नहीं दिये गये हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार इस क्षेत्र में पुराने लगे हुए 50 पर्सेण्ट हैण्डपम्प करीब खराब पड़े हुए हैं और उनकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है । अनेक गांवों में तो एक हैण्ड पम्प भी चालू नहीं है और ग्रामवासी बहुत कष्ट में हैं । नये हैण्डपम्प तो पिछले 4 वर्षों में कोई इक्के-दुक्के लगे होंगे जबकि आज इस क्षेत्र के कस्बों, गांवों और ढाणियों में लगभग 400 हैण्डपम्पों की बहुत सख्त जरूरत है और उसकी मांग करते चले आ रहे हैं जिसकी ग्रामवार सूचना मैं माननीय मंत्रीजी को भी पेश कर दूंगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार

(श्रीमती कमला)

द्वारा इन समस्याओं पर उनकी गम्भीरता एवं व्यापकता के अनुसार कोई तवोज्जह नहीं दिये जाने से यह समस्या और भी गम्भीर होती जा रही है और उसका एक कारण यह है कि जयपुर जिला, जिसमें 13 पंचायत समितियां हैं, म सिर्फ 180 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि एक पंचायत समिति के लिये भी यह 180 हैण्डपम्प पर्याप्त नहीं हैं जबकि पूरे जिले के लिये उन्होंने इतने मन्जूर कर रखे हैं। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं सम्बन्धित मंत्री महोदय से यह मांग और राजस्थान के व्यापक हित में कुछ यह सुझाव हैं :—

(1) लम्बित योजनाओं की अति शीघ्र स्वीकृति जारी करवायें और अन्य जो योजनाएं प्रस्तावित हैं उनकी भी योजना बना कर स्वीकृति के लिए भेजी जायें।

(2) जिन गांवों में पीने के पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है अथवा अपर्याप्त हैं वहां अविलम्ब जनसंख्या के अनुपात में हैण्डपम्प तुरन्त मंजूर किये जायें।

(3) जो हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं उनकी मरम्मत होनी है तथा जिन गांवों की टी. एस. एस. योजनाओं का, जलदाय योजनाओं का पंचायतों को भार सौंपा हुआ है वह अविलम्ब विभाग अपने जिम्मे लेकर उन्हें तुरन्त ठीक कर उनका संचालन करें।

(4) पीने के पानी की समस्या एवं जल स्तर के निरन्तर नीचे जाने की चिन्ता को देखते हुए राज्य सरकार विश्व बैंक या किसी अंतरराष्ट्रीय एजेन्सी से सहयोग करके राज्य के लिए एक व्यापक और प्रभावी योजना तैयार करें और उसके तहत में इस गहरी समस्या का समाधान करने की व्यवस्था करें। इसके तहत यह भी आवश्यक है कि ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा पूर्व में जो नलकूप लगाने के पाइंट आइडेण्टीफाई किये हुए हैं उन तमाम पाइंट्स को राज्य सरकार अपनी निगाह में ले, वहां पर नलकूप लगाये और उन्हें सर्वे और भी अगर करना हो तो नया सर्वे करवा कर वहां पर नलकूप कायम करके इन नलकूपों का एक नेटवर्क तैयार करे। कम से कम पूर्वी राजस्थान में इसकी बहुत अच्छी सम्भावनाएं हैं। वह नेटवर्क तैयार करके इस जलदाय की समस्या का समाधान करने के लिए स्थायी और व्यापक हल कायम करें।

(5) कुओं के गिरते जल स्तर की चिन्ता के सन्दर्भ में यह सुझाव है कि परम्परागत बांधों के अलावा अधिक से अधिक एनीकट बनाये जावें जिससे कि आसपास के कुओं में जल स्तर बढ़े और इलाकों में जल स्तर कायम रहे तथा नलकूपों की सिंचाई की व्यापक योजना बनायी जाय जैसा कि हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश आदि में यह व्यवस्था कायम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नलकूप व्यवस्था सरकार बनायें और कृषकों से सिंचाई का सिंचाई कर वसूल कर ले जिस प्रकार से नहरी क्षेत्रों में किया जाता है। पूर्वी राजस्थान के लिये इसके अलावा और कोई प्रस्ताव मुझे नजर नहीं आता।

(6) जलदाय विभाग के द्वारा तुरन्त तीन माह का एक अभियान चला कर खराब पड़े हुए हैण्डपम्पों को तुरन्त सुधारा जाये।

(श्रीमती कमला)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करती हूं कि सरकार इन बिन्दुओं पर तत्परता से कार्यवाही करेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ।

जोधपुर शहर की पेयजल व्यवस्था

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर शहर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल की समुचित एवं नियमित व्यवस्था न कर सकने पर नियम प्रक्रिया-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिऐ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ।

मान्यवर, जोधपुर शहर पेयजल की गम्भीर समस्या से ग्रसित है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग शहर में समुचित मात्रा में एवं उचित दबाव से पानी की व्यवस्था करने में नाकामयाब रहा है। शहर की अभी कुल आवश्यकता 2 लाख 50 हजार गैलन पानी के एवज में सत्तर प्रतिशत पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इससे शहर की आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग तो इस उपलब्ध पानी की समुचित वितरण व्यवस्था करने में भी नाकाम रहा है। अभी हाल ही में एक गंगलाव तालाब क्षेत्र में 18 इन्च व्यास की पानी की लाइन लीक हो गयी थी, जिसे मेरे द्वारा विभाग के कई अधिकारियों को मौके पर ले जाकर बताया गया था परन्तु जो लाइन लीकेज है, उसका उस अधिकारियों को कुछ पता नहीं है, उस पानी से गंगलाव का तालाब पूरा भर गया है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र के कुछ ऐसे इलाके हैं. इसके बारे में उल्लेख करना चाहूंगी। इसके पहले कई दिन पता ही नहीं चल पाया।

शहर के भीतरी भागों जैसे कबूतरों का चौक, सिटी पुलिस, हरदेव कॉलोनी, धावियों का मोहल्ला माणक चौक, गुलाब सागर क्षेत्र, मोती चौके, थलियों का बास; हनुमान जी की बावरी, शान्तीपुरा, फतहसागर, केमरबाड़ी. चतानियों की गली, खुटों की पोल रूखड़ों की घाटी, मण्डारियों की पोल भईयों की पोल. दीवानों की गली, धाचियों की गली डोडीदारों का मोहल्ला, आदि क्षेत्रों में पानी नही के बराबर आ रहा है और विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जोधपुर लिफ्ट कैनाल का कार्य पिछले एक वर्ष से ठप्प पड़ा है। 70 लाख गैलन की योजना के एवज में अभी केवल 40 लाख गैलन पानी केनाल द्वारा शहर को दिया जा रहा है और वह भी अनियमित रूप से।

मेरा माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री महोदय से यह अनुरोध है कि इस विषय में तुरन्त ही कार्यवाही कर शहर में पेयजल उपलब्धता की मात्रा को बढ़ाया जाय एवं वितरण की व्यवस्था में सुधार किया जाये। पुराने पड़े पम्पों और पाइप लाइनों को बदला जाये एवं जहां जरूरत हो, बड़े व्यास की पाइप लाइनों को लगाया जाये। इसके साथ ही लिफ्ट कैनाल को पूरा करने का कार्य युद्ध स्तर पर कर, इसकी क्षमता के अनुरूप पानी लाकर जोधपुर शहर के निवासियों को दिया जाये ताकि आम जनता की परेशानियां दूर हो सकें।

इसके बारे में अब तक की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत कराया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल। (अनुपस्थित) श्री भैरोंसिंह शेखावत।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त (ग्रुप-4) विभाग की पांच अधिसूचनाएं, एक से लेकर पांच नम्बर तक की सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय मैं ऊर्जा विभाग की दो अधिसूचनाएं, क्रमांक एक और दो सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथू सिंह (राज्य मन्त्री ग्रामीण विकास एवं पचायती राज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग की दो अधिसूचनाएं, नम्बर-वन व नम्बर-टू सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रोहिताश्व।

श्री रोहिताश्व (राज्य मन्त्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से परिवहन विभाग की I से II अधिसूचनाए सदन की मेज पर रखता हूं।

(अधिसूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

याचिका का उपस्थापन

ग्राम सूरली (बूंदी) में सिंचाई हेतु बांध का निर्माण

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिला बूंदी, तहसील नैनवां, ग्राम पंचायत जैतपुर के ग्राम सूरली में सिंचाई हेतु बांध निर्माण करवाने बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

धन्यवाद।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हमारे माननीय सदस्य श्री राजपाल शेखावत के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सदन को यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की 1990 में जो सरकार बनी थी, इसके मुख्य मन्त्री माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत थे, जनता ने पांच साल के लिए जनादेश दिया था और उस जनादेश के अन्तर्गत पांच साल के समयबद्ध कार्यक्रम बने थे, उस समयबद्ध कार्यक्रम के तहत जनता के विकास में एक निरन्तर प्रगति हो रही थी लेकिन केन्द्र की सरकार ने राजस्थान की इस जनता के द्वारा चुनी गयी सरकार को 15 दिसम्बर को भंग कर दिया और हमारे प्रान्त में राष्ट्रपति शासन लागू किया

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

गया। लोकतंत्र में पहली बार राजस्थान में इतना लम्बा राष्ट्रपति शासन रहा।

(12.56)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

जनता के बीच में गये। जनता ने विकास के जो अधूरे कार्य थे, किसान, गरीब, जनजाति शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और ऐसे पिछड़े हुए लोगों के जो समयबद्ध कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर पुन: सरकार में यहां बैठाया है। 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये, वनवासी बन्धुओं के लिये जो कार्य किये हैं, वास्तव में इतिहास में लिखाने योग्य हैं। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। कांग्रेस केन्द्र में और देश के विभिन्न राज्यों में सत्ता पक्ष में लम्बे समय तक रही। जनजाति वर्ग जो गुलामी के समय में हमेशा शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा रहा, उसे दूसरे दर्जे का इन्सान समझा गया उसकी आजादी के बाद एक अपेक्षा जागी थी कि इस पिछड़े हुए वर्ग को, इस वनवासी वर्ग को शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के वर्ग को एक नया जीवन मिलेगा, एक नयी जिन्दगी जीने का मौका मिलेगा। लेकिन इतने लम्बे अन्तराल के बाद में वास्तव में हमारे वनवासी बंधुओं की, जनजाति क्षेत्र का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था, अपेक्षित प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हो पायी। 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उनके लिये योजनाबद्ध कार्यक्रम बने। विशेष रूप से जो उदयपुर का दक्षिणाचंल है, यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी शिक्षा की दृष्टि से, उनके छोटे-छोटे पाकेट्स जमीन के हैं उनकी सिंचाई के लिये छोटी-छोटी योजनाएं बनायीं। विशेष रूप से मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है जहां माही और कडाना का बैंक-वाटर था, वह बैंक वाटर पहले भी था, वह आज से 15 वर्ष पहले भी था लेकिन हमारी पूर्व की सरकार ने उस पानी का सदुपयोग इस वनवासी क्षेत्रों के लिए कैसे किया जाये कभी इस तरह के कार्यक्रम नहीं बनाये, कभी इस तरह की योजना नहीं बनायी। 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस बैंक वाटर के आस-पास जो बस्तियां थीं, आस-पास के जो गांव थे, उनके लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाकर लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की। 11 करोड़ की योजना बनी, माही और कडाना के बैंक वाटर के ऊपर और आज वास्तव में वहां का क्षेत्र हरा-भरा है। आज आस-पास के लोग रहते हैं, वनवासी क्षेत्र के लोग गुजरात पलायन न करके उन्होंने भी इस समय उस सिंचाई के पानी का लाभ लेकर रबी की फसल बो करके अपना नया जीवन शुरू किया है।

माननीय सभापति महोदय मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि वास्तव में हमें आवश्यकता है कि जनजाति क्षेत्र, इतने लम्बे समय तक उपेक्षित रहा है, को वास्तविक रूप से कैसे उठाया जाय और विशेष रूप से शिक्षा की दृष्टि से और उनके पास जो फिक्स असेट्स हैं, छोटे-छोटे जो दो बीघा, चार

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

बीघा जमीन है, उनके विकास के लिये एक अलग से योजना बने, जिस तरह की योजना भारतीय जनता पार्टी ने ढाई साल में बनायी।

(13.00)

इस समय वापस जनता ने उनको समर्थन दिया है। वहां सिचाई के जो साधन हैं उन सिचाई के साधनों का कैसे उपयोग किया जाये ताकि जनजाति क्षेत्र जो आज इतना उपेक्षित रहा है उसका आर्थिक उत्थान हो, आर्थिक रूप से ऊपर उठायें ताकि शिक्षा की दृष्टि से भी वह अपने बच्चों को पढ़ा सकें क्योंकि कहावत है जब तक पेट में रोटी नहीं होगी वह शिक्षा या अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति कभी नहीं सोचेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पहले उसका आर्थिक स्तर कैसे उठाया जाये। पिछले ढाई साल के शासन में हमने जो कार्य किये उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि सिचाई के क्षेत्र में आसपास का जो पानी है, चाहे वह लिफ्ट के माध्यम से हो, चाहे छोटे-छोटे सामूहिक कुओं के माध्यम से हो, उनको सिचाई की सुविधा मुहैया करायी जाये ताकि सिचाई की सुविधा प्राप्त करके हम जनजाति क्षेत्र में विकास कर सकें। आज बड़े गर्व के साथ मैं कहूंगा कि चालीस साल के भुलावे में जो कांग्रेस के साथ जनजाति क्षेत्र रहा है, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग रहे है, वह आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और जुड़ने का एक ही कारण है कि हमने उनको आत्मीयता से गले लगाया है, कथनी और करनी में अन्तर नहीं रखा है जो कहा है वह हमने किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो मौका दिया है जनता ने आने वाले समय में उस का सदुपयोग करते हुए उस क्षेत्र में पर्टीकुलरली जो जनजाति क्षेत्र है उसका विकास हम क्रमबद्ध और समयबद्ध कार्यक्रम लेकर करें।

साथ ही, माननीय सभापति महोदय, यह भी कहना चाहूंगा कि उदयपुर क्षेत्र राजस्थान में आज भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। विशेष रूप से उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह खेती की दृष्टि से उतना उपजाऊ नहीं है जितना पश्चिमी राजस्थान का भाग है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदूषण के नाम से वहां की खानें बंद करने का केन्द्र सरकार ने आदेश निकाला था, वहां जो फैक्ट्रीज चल रहीं थी उनको बन्द करने का आदेश निकाला था। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति शासन में मेरे ही क्षेत्र में चलने वाली एक फैक्ट्री जो बिछड़ी नाम के गांव में चलती है, शहर से 20 किलोमीटर दूर है, राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों ने हर तरह के क्लेम दिये, हर तरह के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये लेकिन पता नहीं क्या कारण बने कि राष्ट्रपति शासन में जब चुनाव हो रहे थे उसके पूर्व उस फैक्ट्री को बन्द कर दिया गया। एक हजार मजदूर जो काम कर रहे थे वहां, आज बेरोजगार हो गये और उनके साथ जो परिवार के लोग थे, अगर पांच का अनुमान लगाया जाये तो कम से कम पांच हजार लोग आज भुखमरी की हालत में हैं। मैं सदन के माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस फैक्ट्री को बन्द करने के पीछे कोई कानूनी कारण नहीं थे, इसके पीछे वेस्टेड इन्ट्रेस्ट था। मैं चाहूंगा कि

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

सदन के माध्यम से, सभापति महोदय, आप सरकार तक मेरी बात पहुंचाने का कष्ट करें। इस फैक्ट्री को अविलम्ब शुरू करें और जांच करवायें कि वास्तव में इसके बन्द करने के क्या कारण थे। क्योंकि इस फैक्ट्री वालों ने मुझे लिख कर ज्ञापन दिया है उसमें इस तरह के कारण बताये गये हैं जो विश्वास योग्य नहीं माने जाते हैं कि वास्तव में इस तरह से फैक्ट्री बन्द की जा सकती है।

सभापति महोदय, उदयपुर संभाग में वास्तव में खानों की भरमार है। आज मार्बल की वहां इतनी खानें हैं जहां से वनवासी क्षेत्र के लोग अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था करते हैं। राष्ट्रपति शासन में इन खानों को बन्द करने के लिये भी एक अध्यादेश जारी हुआ था। मानव को पहले रोटी चाहिए उसके बाद प्रदूषण की बात पैदा की जाये। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं कि एनवायरनमेंट को खराब नहीं किया जाये लेकिन इसके साथ यह भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हमारे इस प्रदेश में, इस भू-भाग में रहने वाले जो मजदूर हैं, जो वनवासी भाई हैं, उनकी रोटी की व्यवस्था करें। और रोटी की व्यवस्था सरकार करती है। लेकिन सरकार के पास इतने स्रोत नहीं होते हैं तो इस तरह की इण्डस्ट्रीज, खानें हैं जहां पर आस-पास के लोग मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का पालन करते हैं तो इस तरह की जो माइन्स चल रही हैं उनको व्यावहारिक रूप से देखकर, जांच करवाकर प्रोत्साहन दिया जाये। साथ ही वनवासी क्षेत्र में जो इस तरह की खानें चल रही हैं, सरकार से आह्वान करना चाहूंगा कि वनवासी क्षेत्र के बन्धुओं को भी उसमें प्रोत्साहन दिया जाये, यह मेरा, माननीय सभापति महोदय, निवेदन है। वनवासी क्षेत्र में चलने वाले विभिन्न उद्योग हैं उन उद्योगों को भी सरकार अधिक से अधिक सब्सिडी दे, अधिक से अधिक प्रोत्साहन दे ताकि अधिक से अधिक उद्योग इस क्षेत्र में आयें और वहां के जो अनएम्प्लायड हैं वहां के जो मजदूर बेकार हैं, उन मजदूरों को वहां रोजगार मिले।

मैं पुनः राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण यहां हुआ है और जो प्रान्त की सरकार है, आने वाले समय में जो विकास के कार्यों को प्रारम्भ करने वाली है, उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

जय भारत।

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, 31 दिसम्बर को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये तो उनके पधारने का मैं स्वागत करता हूं परन्तु बनीपार्क से आये हुए माननीय सदस्य ने जो यहां पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है अभिभाषण पर, उसका मैं विरोध करता हूं।

माननीय सदस्य ने धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बातें कही हैं और शेखावत साहब की तारीफ की है। वह यह भूल गये और जनादेश की बात कर रहे हैं, जैसा कि अभिभाषण के अन्दर कहा गया कि पहले की राजनीतिक परिदृश्य को बहाल कर दिया गया है। यह बात तो सही है कि पहले का राजनीतिक परिदृश्य यही था कि न तो पहले

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

भारतीय जनता पार्टी को बहुमत था और न इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। पिछली बार भी जोड़-तोड़ से सत्ता को उन्होंने बनाये रखा और अभी भी सत्ता को उन्होंने बनाये रखा है। इसके लिये तो मुख्य मन्त्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं हैं कि उन्होंने किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की साख को बचाये रखा।

जहां तक इसमें यह उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का प्रतिशत बहुत है और ज्यादा लोग हमारे साथ जीत कर आये हैं। जीत कर आये हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जनता ने फैसला दिया है। परन्तु यह सरकार यह कहती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अन्दर जो चेतना ज्यादा हुई है, हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको बरकरार रखें। तो, सभापति महोदय, यह सरकार ऐसी पहली गठित हुई है जिसके अन्दर अनुसूचित जाति का कोई भी केबिनेट स्तर का मन्त्री शामिल नहीं हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि यह सरकार कैसी है। विश्वास मत प्रस्ताव के ऊपर कैलाश मेघवाल जी को खड़ा किया बोलने के लिये। कैलाश मेघवाल जी ने काफी तारीफ की बातें कही कि शायद उनका नम्बर आ जाये और केबिनेट मन्त्री शायद वह बन जायें। पर इससे यह जाहिर होता है कि एक पार्टी जो कि यह कहती है कि हमारे साथ इतने लोग हैं, आप भी इसको समझ लें कि उनका... (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : इधर ही आयेगा उधर नहीं आयेगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपके लिये नहीं कह रहा हूं। आप थोड़ा धीरज रखो। आपका नम्बर आ जायेगा।

श्रीमती तारा भण्डारी : इधर ही आयेगा, उधर नहीं आयेगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : तो इस तरह की सरकार जिसके अन्दर अनुसूचित जाति और जनजाति की बात कही गयी हो कि इतना बहुमत मिला और उसके प्रतिनिधि को केबिनेट में भी शामिल नहीं किया गया ? इससे पता चलता है कि सरकार का चिन्तन क्या है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : सिफारिश के लिए धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अच्छा आप भी बैठे हैं क्या ? कैलाश जी, मैंने आपके लिये कह दिया है। आपने विश्वास मत प्रस्ताव के ऊपर जिस तरह से तारीफ की, जो कसीदे पढ़े सरकार के लिये, मैं उम्मीद करता हूं आपका नम्बर आ जाना चाहिए केबिनेट के अन्दर।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : बड़ी गहराई में चोट की है आपने।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। चौधरी जी, जब बाज कबूतरों पर झपटेंगे तो शिकारी को पेश करेंगे अपने आप। आप क्यों चिन्ता करे रहे हो।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जहां तक यह उल्लेख किया गया अभिभाषण में कि पिछली

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

सरकार की जो योजनाएं चालू थीं विकास की योजनाएं, उनको पुनः गति देकर चालू किया जाऐगा। कौनसी योजनाएं? सभापति महोदय, एक योजना तो यह थी कि तमाम जो 6 हजार स्कूल खोले गये उनको बंद कर दिया गया। एक तो यह योजना थी पिछली सरकार की। नयी सरकार वापस आकर जो स्कूल बचे हैं उनको और बन्द करेगी। जो पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गयी थीं उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या उसके ऊपर भी आगे इसी तरह का काम किया जायेगा कि आगे भी कार्यवाही नहीं की जाऐ। महोदय, जिस तरह से जनादेश की बात इसमें कही गयी है, पिछली सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं को जिस तरह से समाप्त किया, कारण यह बताया कि हम पुनर्गठन करना चाहते हैं पंचायतों का। बात बिल्कुल ठीक है, पुनर्गठन तो आप करना चाहते हैं पर पुनर्गठन का, सभापति महोदय, आधार क्या रखा? पुनर्गठन का आधार राजनैतिक भेदभाव रखा। उसका कारण है कि कहीं पर भी जो नये गांव बनाये गये, उसमें न तो जनसख्या का आधार रखा गया कि पंचायत मुख्यालय होगा, न दूरी को कोई मापदण्ड बनाया गया कि इतनी दूरी तक कोई भी जो गांव आयेगा उसको मापदण्ड रखा जायेगा। केवल स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में आ करके इस तरह के फैसले किये गये। क्योंकि आप यह देख सकते हैं कि जो भी पुनर्गठन हुआ है उसके अन्दर कोई समान नीति कहीं पर लागू नहीं है। यद्यपि हमने कई बार इस बात के लिये कहा भी आपको कि कौनसा आधार आपनें दिया है, कितनी कम संख्या यहां पर है. यह केवल 7 सौ, 8 सौ हजार व्यक्तियों, घरों का ही गांव है और यह 2 हजार ढाई हजार घरों का गांव है. इसको आपने मुख्यालय क्यों नहीं रखा? कि आप तो जानते हैं यह तो पार्टी का दबाव है, आप विरोधी पार्टी के हैं इसलिये हम कह नहीं सकते, हम को तो यह करना पड़ेगा। इस तरह से पंचायतों के पुनर्गठन के नाम के ऊपर अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने की कोशिश की गयी जो कि बिल्कुल गलत है। मैं यह चाहूंगा कि अभी अपना जो नया बिल पंचायत राज का आया है हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री राजीव गांधीजी की जो भावना थी, जिस तरह से पंचायत बिल बना और आज आया और हम असेम्बली में डिस्कस करेंगे, मैं चाहूंगा कि जो पुनर्गठन हुआ है पंचायतों का, उसके ऊपर नये सिरे से विचार होना चाहिये। माननीय सदस्य, जो इस सदन के सदस्य हैं, मेरी भावना से जरूर सहमत होंगे।

तीसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य के अन्दर आज अकाल की स्थिति है, सभापति महोदय, आपके इलाके के अन्दर तो अकाल की स्थिति नहीं है जैसा अभी आप कल कह रहे थे कि अब की बार अकाल पड़ गया है, हम जिस इलाके से चुन कर आते हैं, पश्चिमी राजस्थान से, वहां पर हर दूसरे, तीसरे साल अकाल पड़ जाता है। जब यह सरकार शेखावत साहब के शासन में थी तब भयंकर बाढ़ आयी थी और बालोतरा से आने वाले सदस्य अभी अपनी बात कह रहे थे, प्रश्नकाल के अन्दर, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वहां पर घोषणा की थी कि वहां पर पुलिया बना देंगे भयंकर बाढ़ आयी जालौर जिले के गांवों में बाढ़

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

आयी, जोधपुर जिले में बाढ़ आयी और हमारी सरकार ने क्या किया ? सरकार ने हैलीकॉप्टर किराये पर लिये और वे केवल हेलीकॉप्टर से घूमते रहे। माननीय सभापति महोदय, सैंकड़ों लोग बाढ़ के अन्दर बह गये, पेड़ों पर बैठकर इन्तजार करते रहे कि हेलीकॉप्टर ऊपर घूमते हैं, हमको बचायेंगे। एक व्यक्ति को भी नहीं बचाया गया, यह सरकार की उपलब्धि है उस बाढ़ के समय के अन्दर, इस बात का जो उल्लेख कर रहा हूं यह सत्य से परे नहीं है जिस तरह से सरकार ने उस समय काम किया। सरकार की भावना अभी भी जो हैं, अकाल के बारे में मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि 10 तारीख को मीटिंग करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे तो महोदय, जलदाय मंत्रीजी ने तो जरूर अपनी कार्यवाही शुरू की है और वे एम. एल. एज. के साथ जिला लेवल पर मीटिंग कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे पहले से इस बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। और खाली तालों मत बजाइये आप, आप यह देखें कि पहले जो कार्यवाही हुई, मंत्री महोदय को मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पेयजल योजनाएं हमारी ऑलरेडी बनी हुई हैं और जो चल नहीं रही हैं, मंत्रीजी, आपने सुना, मैंने आपको धन्यवाद दिया आप जो कार्यवाही कर रहे हैं ...

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : बड़ी कृपा, साहब।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैंने आपको सुना।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप मत लो, आपको तो टाइम लगेगा अभी, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वास्तव में अभी सर्दी का समय है और हम तेजी से, जो समस्याएँ हैं पेयजल की उनको हाथ में लेते हैं तो उन समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। और जो बहुत बड़ी योजना है, मैं कहना चाहूंगा, जोधपुर से सम्बन्धित मारवाड़ से सम्बन्धित है, जोधपुर लिफ्ट कैनाल की योजना। जैसा मंत्री महोदय ने प्रश्नकाल के अन्दर जब मैंने प्रश्न किया था, यह बताया कि यह तो हमारे समय की योजना है। यह तो सदन को गुमराह करने वाली बात है। राजीव गांधी जी ने इस योजना को शुरू किया था और इस योजना के बारे में मुख्य मंत्रीजी जोधपुर पधारे थे तब उन्होंने यह आश्वासन जरूर किया था कि मैं इस योजना को प्राथमिकता से पूरा कराऊंगा। जोधपुर शहर से आने वाली माननीय सदस्या, अभी चली गयी, पानी का जिक्र कर रही थीं, मुख्य मंत्री ने कहा, इस तरह से जो समस्याएं हैं, सेना की मदद से मैं उस काम को कराऊंगा। सेना छोड़ कर वे खुद भी मौके के ऊपर उस लिफ्ट के काम को देखने नहीं पधारे। तो मैं यह चाहूंगा, मंत्रीजी कि आप उस मौके पर पधारें और व्यक्तिगत रूप से देखें क्योंकि जनता का ऐसा मसला है जिसमें हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। हर स्तर पर इस काम को प्राथमिकता से पूरा किया जाना चाहिये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जोधपुर की पेयजल से सम्बन्धित योजना है।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य, भीमराजजी बैठें हैं, जोधपुर में जो पानी आता है पीने का, वह पानी पाली से आता

(62)

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

है और रणसी गांव, जो मेरे क्षेत्र का इलाका है, से पानी आता है, जो ओझा क्षेत्र का इलाका है वहां से पानी जोधपुर को दिया जा रहा है। तो पानी की बहुत भयंकर दिक्कत है। यदि इस पेयजल योजना को जल्दी पूरा करा देंगे तो इसके अन्दर काफी वहां मदद मिलेगी, किसानों को भी काफी राहत मिलेगी।

जहां तक बिजली की समस्या का सम्बन्ध है, सभापति महोदय, आप भी इसके ऊपर काफी बोले हैं मैं बिजली के सन्दर्भ में कहना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड किस तरह से काम कर रहा है यह अपने आप में स्पष्ट है कि चेयरमैन साहब के बाद से आज घाटा एक हजार करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। किस तरह से बिजली की जो आपूर्ति है उसके अन्दर कोई सामंजस्य नहीं है और जैसा अभिभाषण के अन्दर भी कहा गया है कि 41.7% जो है, उस कमी को माना गया है और 94-95 के अन्दर 44% से ज्यादा कमी पड़ जायेगी। इसी तरह से यह बात कही गयी है लाइन लॉसेज को लेकर कि बिजली जो हमारी पहले से ही उपलब्ध है उसके अन्दर हमारा जो आंकड़ा है वह 30% है। माननीय सभापति महोदय, जो लॉसेज है यह 30% है और बोर्ड जो आंकड़े दे रहा है 21% के, वह गुमराह करने की बात कर रहा है। वह जो सारा जिस तरह से उपलब्ध है उससे साफ जाहिर होता है, जो नेशनल एवरेज है लॉसेज का वह 20% है और हम अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं वह है 30% के करीब। इसी तरह से जो ट्रांसफार्मर्स जल जाते है, ट्रांसफार्मर्स में भी सभापति महोदय, हमारा रिकार्ड है 15 से 20% ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं हर साल। यह हमारी स्थिति है। इसी तरह से कोटा के अन्दर लोड फैक्टर बढ़ाने की बात को जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, कोटा के अन्दर हमारी यूनिट चल रही है, लोड फैक्टर बढ़ गया है, सभापति महोदय, वह गुमराह करने की बात है। एक्चुयली बात यह है कि जो बिजली हम वहां पर बनाते है वह बहुत महंगी पड़ती है। आप यह पता कर सकते हैं कि जो लोड डिस्पेचिंग हमारी आर. एस. ई. बी. की वहां है, हमको दूसरी स्टेट्स से जो बिजली मिलती है कई बार उनके पास बिजली सरप्लस होती है और वे हमको टेलीग्राम देते हैं कि आप बिजली खरीदना चाहते हैं तो आप बिजली ले सकते हैं तो वह हमें 50 पैसे यूनिट बिजली देना चाहते हैं और हम एक रुपया तीस पैसा एक रुपया बीस पैसा यूनिट की बिजली बनाते हैं। लेकिन हम उसको बंद नहीं करना चाहते हैं। हमारा तारतम्य नहीं है इस बात का। खाली हम दिखाने के लिये यह बात करना चाहते हैं। उसको भी आप जांच करके देख सकते हैं। इससे भी हम घाटे की पूर्ति कर सकते हैं। इसी तरह से रेट्स को बढ़ाया गया बार-बार टैरिफ को बढ़ाया गया उसके बावजूद घाटा पूरा नहीं हुआ है। मैं इसलिये आप से निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली जैसा महत्वपूर्ण मामला है, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, इसके अन्दर मैं चाहूंगा कि सदन पूरा शामिल रहे।

दो-एक बातें, सभापति महोदय, मैं कहूंगा राजस्थान के अन्दर विश्वविद्यालयों में और प्रयोगशालाओं में राजस्थान की

(63)

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

प्रकृति, साधन और विकास के नये क्षेत्रों के लिये विशेष शोध अनुसंधान का कार्य होना चाहिये। सभी विश्वविद्यालयों में अध्ययन केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिये। दूसरा मेरा सुझाव है, सभापति महोदय, कि राज्य को पिछड़ेपन की स्थिति से उभारने के लिए हमारी योजना निर्माण के लिये राज्य में योजना आयोग का निर्माण किया जाये और विशेषज्ञों को शामिल किया जाये जिसमें हम आगे आने वाली 21 वीं सदी में कैसे राजस्थान में विकास कर सकें इसको लिया जाये। तीसरी बात, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राज्य में संस्कृति और साहित्य के प्रति उपेक्षा का जो भाव है उसे त्याग कर समन्वित प्रयास किये जाने चाहिये। अभिभाषण के अन्दर कला, संस्कृति, साहित्य के लिये एक लाइन का जिक्र नहीं किया है यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं यह चाहूंगा कि इस दिशा में राज्य की सभी भाषा, साहित्य, संस्कृति और अकादमियों के लिये 35 साल के कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिये और उन्हें समाज की बेहतरी के लिये अधिक सहायता और सहयोग दिया जाना चाहिये। चौथी बात कहना चाहूंगा कि राज्य में शिक्षा और ज्ञान को बढ़ाने के लिये दूसरे राज्यों की तरह पुस्तकालय अधिनियम को लागू करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं मेरी बात यहीं समाप्त करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है उसको मंजूर नहीं किया जाये।

धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री विजयेन्द्रपाल सिंह।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : सभापति महोदय, अभिभाषण पर जो प्रस्ताव बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है उसके समर्थन में मैं भी कुछ मेरी बात आपके द्वारा हाउस में रखना चाहता हूं।

जो माननीय सदस्य दो-तीन जा रहे हैं, धनखड़ साहब से भी कहूंगा–आइये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जो प्रतिपक्ष में बिराजे हैं उन्होंने काफी चर्चा की वह क्रिटिसिज्म फार दी सेक आफ क्रिटिसिज्म है न कि कन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। यही बातें विष्णु मोदी जी ने रखी, यही बात धनखड़ जी ने रखी। मेरे मित्र हैं परन्तु मैं यह बातें उनके सामने रखना चाहता हूं। अभी जो मोदी साहब ने इतनी बड़ी बात कह डाली कि बिजली की समस्या के निराकरण हेतु भारतीय जनता पार्टी के राज में ढाई साल 77 से 80 तक और 90 से 92 जो थोड़ा ज्यादा था उसमें, कुछ नहीं किया। हमारे सदन के नेता ने कुछ नहीं किया। उसके बारे में मैं उनको बताना चाहता हूं कि 77 से 80 के अन्दर ही एक तो पलाना बरसिंगसर वाली जमीन को लेकर लिग्नाइट की बात भैरोंसिंह जी ने उठायी थी उससे पहले शायद लोग लिग्नाइट के बारे में नहीं जानते थे। यह भी नहीं जानते थे कि लिग्नाइट हमारे घर की खेती है जो आज भी चार सौ रुपये टन के हिसाब से....

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, आपकी सूचना के लिए....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री हरिसिंह : आप तो स्वयं जानते हैं कि इन योजनाओं का शिवचरणजी माथुर ने राजस्थान में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कराया था उस समय यह बात आयी थी कि लिग्नाइट से बिजली उत्पादन की जा सकती है। माननीय सदस्य, उस समय की यह प्रस्तावित योजना है उसका सारा श्रेय माननीय सदस्य लेना चाहते हैं।

श्री सभापति : क्या आप अपने आप पर संयम नहीं रख सकते हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप आराम से जवाब दे देना। कोटा में जो आज एक्सटेंशन 210 का आ रहा है उसके लिए मोदी साहब ने यह कहा कि यह हमारे टाइम में एक्सटेंशन हुआ है। यह सही है पर जो ओरिजिनल था 77 से 80 के अन्दर ही आइडिया मूव किया था और कमीशन हुआ 84-85 में एक्सटेंशन 210 का बाद में आ रहा है। माही हाइडल भी 77 से 80 के अन्दर ही आइडिया मूव किया था और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई। कमीशन बाद में हुआ था। पर वह खाली एक पीकिंग स्टेशन है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ वाले की 77-80 के अन्दर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी उसके बाद उसको अच्छी तरह पेश नहीं किया इसलिए ड्राप हो गयी। हमारे जिले के मुख्य मंत्री थे शिवचरणजी उन्होंने सोचा कि चित्तौड़गढ़ की जगह माण्डलगढ़ में ही क्यों न लगा दें। लेकिन फासले की कमी के कारण वायबिलिटी नहीं बनती थी उसके कारण सी. ई. ए. ने उसको भी ड्राप कर दिया था। 77-80 के अन्दर इतनी स्कीम शुरू हुई थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं अब लिग्नाइट की बात-यह एक ब्लेसिंग इन डिसगाइस है लिग्नाइट का कोलमैन से होने वाला था, नेवेली से एम ओ यू साइन कर दिया था उसको कमीशन अवार्ड नहीं मिला और उन्होंने आगे पेशकश नहीं की। यह एक ब्लेसिंग इन डिसगाइस है। परन्तु आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को और ट्रेजरी बैंचेज को सुझाव देना चाहता हूं कि लिग्नाइट है उसकी टेक्नालॉजी जी. डी आर., हंगरी, आस्ट्रेलिया के अन्दर कितने ही प्लाण्ट लिग्नाइट पर चल रहे हैं। यह जरूर है कि कोल इतना बर्निंग फ्युअल नहीं है पर चार सौ रुपये टन के हिसाब से आज भी मिल सकता है और कोल की व्यवस्था बिहार से करनी पड़ती है बड़ी लाइन लगानी पड़ेगी, कब लगेगी, कोल मिलेगा या नहीं मिलेगा कोल इण्डिया पर भी पूरा हक हम नहीं रखते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज टेक्नालॉजी में 15 साल में बहुत चेन्ज हो गया है। लिग्नाइट का भण्डार जो पलाना, बरसिंगसर, गुढ़ा में है इसका एक प्रोजेक्ट बनाकर दो यूनिट पांच-पांच सौ की या तीन यूनिट पांच-पांच सौ मेगावाट की ही लगायें। आज इतना बढ़िया प्लाण्ट मिलता है कि 210 का प्लाण्ट है, 60 का प्लाण्ट है यह पुराने हो गये हैं। उन से इतनी व्यवस्था और इतना बढ़िया जनरेशन नहीं होगा, मैं यह निवेदन आपके सामने करना चाहता हूं और आब्सोलीट प्लाण्ट् कोलमैन देना चाहता है उसको नहीं लेना चाहिए और एक नयी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामने रखनी चाहिए। मोदी साहब ने कहा इतनी प्राइवेटाइजेशन बिट्स हो गयी हैं और हम पीछे रह गये इसका मैंने जवाब तो दे

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

दिया था, मैं फिर कहना चाहता हूं कि 1000–1000 के 500-500 के ही प्लाण्ट्स ध्राज आ रहे हैं इसलिए लिग्नाइट में भी पांच सौ का ही लेना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक सेण्ट्रल सैक्टर से जो ओवर ड्रा की बात है और अन्ता की जो हमारे टाइम के अन्दर शुरुआत की थी, स्टेज-2 के टाइम पर कांग्रेस का राज आ गया था, स्टेज-2 को डाइवर्ट करके दादरी में ले गये स्टेज 2 क्यों नहीं आयी उसके लिए मोदी साहब जवाब दें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अन्ता गैस पर बैस्ड थर्मल है। गैस पूरी मिलती नहीं है वह डाइवर्ट करके दादरी को दे दी जाती है क्योंकि दादरी दिल्ली को लुक आफ्टर करती है इसलिए वह स्टेज 2 दादरी ले गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ओवर ड्रा अन्ता से करना चाहें तो कर सकते हैं। एक तो इन्फ्रास्ट्रक्चर दे रखा है सेण्ट्रल सैक्टर के लिये, अन्ता के लिये उसमें 4 प्रतिशत मुफ्त बिजली हमें मिलती है. 9 प्रतिशत हमें और मिलती है उसके लिये पैसा देना पड़ता है पर पंजाब-हरियाणा को इस गैस बैस्ड थर्मल से पावर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यह महंगी पड़ती है। जहां भी सेण्ट्रल सेक्टर में है आप भी जानते हैं कि जब पंजाब-हरियाणा से हम गैस बैस्ड है यह करीब दो ढाई रुपये पड़ती है ओवर ड्रा करते हैं तो वह सबसे महंगी जनरेशन जो कहीं हो रही है वह पैसा हम से वसूल करते हैं इसलिए जी. ई. बी. हमारा लोस में चल रहा है। बहुत बार ऐसा करना पड़ता है कि महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पंजाब और हरियाणा से बिजली नहीं लें, अन्ता से लें चाहे कितनी ही, महंगी हो, लेनी चाहिए क्योंकि आज जो महाराष्ट्र में डील फाइनल हुई है वह 4 करोड़ पर थाउजेण्ड मेगावाट के हिसाब से हुई है और वहां जनरेशन कास्ट 4 रुपये पर यूनिट आयेगी। इसलिए यह तो फिर भी सस्ती है। जेस्टेशन पीरियड के लिए बात रखी है उसमें पांच-छह साल लगते हैं। मैं मोदी साहब और प्रतिपक्ष के नेता, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही, मैं कहना चाहता हूं, आज टेक्नालॉजी इतनी बढ़ गयी है कि मथा आज एक अवार्ड देओ और आपकी बिजली आने लग जायेगी, 42 से 45 मंथों में लिग्नाइट का अपन को यही पलाना और बरसिंगसर वाला मूव करना चाहिए। साल भर के अन्दर, जब से गवर्नर साहब का रूल था हमारे कांग्रेस के सब सम्माननीय भाई और सदस्य वहां तो ऐसे जाते थे जैसे कोई हम क्लब जा रहे हों। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उस टाइम बिजली की बात उन्होंने क्यों नहीं की। मैं अब बिजली की बात पर ज्यादा विचार नहीं रखकर दूसरी बात आपके सामने रखना चाहूंगा।

श्री विष्णु मोदी : मान्यवर, मैं आपको इण्टरप्ट तो नहीं करना चाहता, माननीय सदस्य ने अभी जो सुझाव दिये बहुत अच्छे सुझाव दिये, लेकिन पांच सौ मेगावाट और हजार मेगावाट के डिपाजिट्स हमारे लिग्नाइट के नहीं हैं। बरसिंगसर की जो स्थिति है वह 1/2 की 1/2 की है और जो एनवारनमेंटल क्लीयरेंस और सारी जितनी क्लीयरेंस हैं वे 1/20 की हैं। यह बात सही है कि 250 मेगावाट या 500 मेगावाट के....

श्री सभापति : आपका ज्ञान विपुल हो

(श्री सभापति)

सकता है परन्तु समय आने पर बताइयेगा, अभी तो माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जियालाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया डिपार्टमेण्ट ने कह दिया है, कम्बाइन किया जाये बिजनौर, गुढ़ा के अन्दर जो नये लिग्नाइट के भण्डार मिले है, उनको और पलाना और बरसिंगसर सबको। क्योंकि एक सड़क ही तो बीच में है पलाना और बरसिंगसर के। अपन अलग-अलग क्यों यूनिट लगायें? एक बार आपने 60 या 120 का लगा दिया तो यह पूरा भण्डार खराब हो जायेगा और फिर बड़ा पावर स्टेशन नहीं लगेगा। अब बिजली की बात छोड़कर....

श्री सभापति : अब कृपया कनक्लूड कीजिए बिजली की बात छोड़कर।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं पहली बार यह कहना चाहता हूं कि पहली बार एक पार्टी ने एक विश्वास मत, विश्वास मत नहीं विश्वास जाहिर किया है ब्यूरोक्रेसी पर, कभी किसी ने नहीं किया। आप भी उसके सदस्य रहे हैं इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि यह जो इंस्टीट्यूशन है इसकी लीगेसी तो ब्रिटिश राज की है। सही। पर यह बहुत ही अच्छी प्रणाली है, अच्छी लीगेसी हमें मिली है ब्रिटिश राज से। कितने भी पॉलिटिकल अपहीवल्स हों, कितनी भी प्राबलम्स आयें, कितनी भी इमरजेंसी आये यह एक इंस्टीट्यूशन है। यह एक काडर है आई. ए. एस., आई पी. एस. और आल इण्डिया सिविल सर्विसेज का, यूनिफिकेशन ग्राफ इण्डिया में जिसका बहुत योगदान है। इनमें, ठीक है, एस.सी., एस.टी. के भी हो सकते हैं, दूसरी कास्ट के भी हो सकते हैं पर मेरा जो सम्पर्क उनसे रहा है, मुझे तो वे चाहे एस.सी., एस.टी. के आई.ए.एस के ब्यूरोक्रेट हों या आई.पी एस. हों कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। जो विश्वास पहली बार एक पार्टी ने रखा है उसके लिए मैं सदन के नेता को बधाई देता हूं।

मैं यह बात तो जरूर कहूंगा, मजाक की बात नहीं लें कि राजस्थान में जब भी एक यंग आई. ए. एस. मसूरी से ट्रेनिंग करके आता है तो यहां की रूपरेखा देखकर एडजस्टमेण्ट करने की कोशिश करता है। इतने साल का फ्यूडल सिस्टम अब खत्म तो हो गया पर वह थोड़ा इन्फेक्शन्स अभी भी है। इन्फेक्शन्स इसलिए है कि सब, कोई ठाकुर साहब हैं, चौधरी साहब हैं, ये हैं, वो हैं और यह बात उनमें भी पहुंच जाती है। एक बहुत अच्छी बात हमारे मित्र जो एक सीनियर आई. ए. एस. आफिसर हैं, जब उनसे चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कही कि यह बात जरूरी है और यह सही है। आज भी हमारे यहां जब बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो वे कोई मंत्री महोदय से मिलने नहीं जाते हैं और कहते हैं, हमने सिटी पैलेस के अन्दर खाना खाया महाराज का। आज तो महाराज नहीं हैं आज तो राजा नहीं हैं। तो वह फ्यूडल सिस्टम अभी भी जो भी छोटा-मोटा है या नाममात्र का ही है, इन्फेक्शन्स हमारी इस आई. ए. एस. में भी हो गया है। एक जने ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पुराने जमाने में जब महाराज होते थे तो वे पदवी दे देते थे, उसने कहा है मैंने नहीं कहा, गलत नहीं लें, कि साहब, आप नाम ही बदल दो, सबको

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

खुशी हो जाएगी। जो जिलाधीश है, वह भी तो अपने ब्रिटिश राज से है। जिलाधीश, राजा जिले का। वैसे ही यह जो सैक्रेटरी एग्रीकल्चर है, सैक्रेटरी टूरिज्म है, सैक्रेटरी फाइनेंस है उनको ठाकुर साहब के नाम दे दो, ठाकुर साहब, एग्रीकल्चर, ठाकुर साहब एग्रीकल्चर, ठाकुर साहब फाइनेंस और ठाकुर साहब जो भी है। यह एनाक्रोनिज्म जरूर है पर एनाक्रोनिज्म होते हुए भी....।

मैं एक बात और कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा। आज हमारी मंत्री महोदया जो टूरिज्म की हैं वे यहां पर पधारी हुई नहीं हैं। टूरिज्म का नाम नहीं है इसके अन्दर। आज जो सबसे बड़ी इण्डस्ट्री है राजस्थान में वह टूरिज्म है। मैं बधाई देता हूं सदन के नेता को कि उन्होंने साम्प्रदायिक झगड़े नहीं होने दिये इसी कारण इतना प्रोत्साहन और प्रमोशन टूरिज्म का हुआ। मैं मैडम को एक ही बात आपकी मार्फत बताना चाहता हूं कि उनके डायरेक्टर साहब और सैक्रेटरी साहब या आज तो सभी कोई एक्सपर्ट बनते हैं कि, साहब, टूरिज्म में मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे चेयरमैन बना दो, मुझे यह कर दो। मैं तो यह कहूंगा आपको कि आपका योगदान इतना अच्छा रहेगा, टूरिज्म वर्ल्ड आपको याद रखेगा अगर आपने एक काम कर दिया। ठीक है, बहुत सारी हवेलियों को, गढ़ों को हैरीटेज होटल्स में दें, यह तो सब इन्फ्रास्ट्रक्चर होती है, पर अगर टूरिस्ट नहीं आयेंगे तो आप क्या कर सकोगे? टूरिस्ट यहां आता है, कम आता है या क्यों आता है उसके लिए एक ही बॉटल नेक है कि जो भी टूरिस्ट आता है वह दिल्ली होकर ही आता है राजस्थान में। दिल्ली उसको एक रात रहना पड़ता है। और फिर आई. ए. सी. को तो आप जानते ही हैं कि आई. ए. सी. में आपको जगह मिले नहीं मिले, जब उदयपुर जाना हो, जैसलमेर जाना हो, जोधपुर जाना हो, जयपुर जाना हो। वहां होटल की व्यवस्था भी नहीं होती बड़े आराम से। मैं तो कहता हूं आपको टूरिज्म वर्ल्ड याद रखेगा, आज ही आप फाइल मंगायें, डायरेक्टर साहब बैठे हैं उनसे मंगायें (सैक्रेटरी से मंगायें आपको पांच साल मिलेंगे, इण्टरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर में कर दिया तो यह सब गढ़, हवेलियां आप बना लेना, हैरीटेज होटल में सब कुछ हो जायेगा, पर यह जो बॉटलनेक है इसको आप रिमूव करें और इण्टरनेशनल एयरपोर्ट यहां कर दें। मैं नहीं कह रहा कि एयर इण्डिया को आना चाहिए या एयर फ्रांस को आना चाहिए या लुफ्थांसा को आना चाहिए। इनके आने की जरूरत नहीं है, ये आयेंगे भी नहीं, पर जो चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही हैं वे सीधे जयपुर आयेंगी। उनको जो 200-400 डालर दिल्ली में खर्च करने पड़ते हैं होटलों में, वे भी उनको नहीं करने पड़ेंगे।

मैं यह बात कहकर डंकल पर....

श्री सभापति : आपने 20 मिनट ले लिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : डंकल के बारे में बहुत सारी बातें कही गयीं किसान बहुत भयभीत हैं कि क्या चीज आ गयी। मेरे को तो एक ने कहा कि यह कोई टिड्डी है या नील गाय है, यह तो बता दो आप, एम.एल.ए. साहब। मैंने कहा यह टिड्डी भी नहीं है, नील गाय भी नहीं है यह तो उससे भी खतरनाक है। मेरे कांग्रेसी भाईयों ने कहा कि हमारी मजबूरी थी इसलिए हमने "गैट"

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

का समझौता किया और ये डंकल प्रस्ताव हमने मंजूर किये । मैं आपको एक बात बता दूं कि हम आइसोलेट जरूर हो गये थे पर हमारा साथ किसने दिया, आप जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे साथ, जो हमें मिला है 5 और 10 साल का जो ब्रीडिंग स्पेस मिला है कि यह एकदम हमारे सिर पर नहीं आयेगा । वह आपके कहने से नहीं, आपने तो हाथ ऊपर उठा दिये थे । आपके लिये तो कोई वहां पर मजबूरी थी साइन करने के लिये, पाकिस्तान हमारे साथ है । पाकिस्तान और हिन्दुस्तान ने साथ में नेगोशियेट किया है और उसी के कारण हमें एक ट्रांजिटरी टाइम मिला है टू एडजेस्ट आवरसेल्वज और वह 5 और 10 साल का मिला है इसके लिए मैं धन्यवाद पाकिस्तान को दूंगा, कांग्रेस को नहीं दूंगा । यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : धन्यवाद । माननीय श्री जगदीप धनखड़ ।

एक माननीय सदस्य : ताली ही नहीं बजी ।

श्री जगदीश धनखड़ (किशनगढ़) : आपके भी तो दो हाथ हैं । किसी ने बांध रखे हैं क्या ? अब तो पूरी तरह स्वतंत्र हैं जरा बजाइये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और कोई बजाये या न बजाये मैं तो बजाता हूं ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापतिजी, मेरे मित्र ने अभी अभी भाषण दिया है इण्टरनेशनल टूरिज्म, चार्टर्ड फ्लाइट, हैरीटेज होटल्स, 200-400 डालर बचाये । मान्यवर, झटका लग सकता है मैं सीधा उस गांव में ले जाऊंगा जिसका आज के दिन कितनी दयनीय स्थिति हैं । किसान परेशान है, बिजली की भारी समस्या है । आप सब लोग अपने इलाकों में गये हुए हैं, पेयजल की गम्भीर समस्या है । विकास के नाम पर जितना कुछ हुआ है सब आपने देखा है । ऐसी स्थिति के अन्दर जब इस अभिभाषण को पढ़ते हैं तो एक बड़ा जबरदस्त झटका लगता है । इससे भी ज्यादा झटका लगा, बनीपार्क से जो सदस्य आये हैं टेलेण्टेड हैं, उत्साही हैं, बड़ी मेहनत की है, कई मुद्दों पर उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित किया है पर कुछ मुद्दों पर वे बिलकुल बहक गये । कहते हैं मिनी जनरल इलेक्शन था और 4 4 राज्य सरकारों को बरखास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने को नकार दिया है । अब, मान्यवर, मानिये मिनी जनरल इलेक्शन था इसका नतीजा क्या हुआ ? छटपटाहट है वह स्वाभाविक है राष्ट्रपति शासन के खिलाफ क्योंकि झटका कोई साधारण नहीं लगा है । 4-4 मुख्य मंत्री थे, 4 में से 3 की स्पष्ट नीतियां थीं तीनों आर.एस.एस. से सम्बन्धित थे, एक राजनीतिक विचारधारा को चला रहे थे, बख्शा तो, खैर, भैरोंसिंहजी को भी जनता ने पूरा नहीं है और उन तीन को तो घर बैठा दिया । इस मिनी जनरल इलेक्शन के अन्दर एक राजनीतिक भावना ऊपर उठी है और वह है आर.एस.एस. का कट्टरवाद नहीं चलेगा । आर.एस.एस. के कट्टरवाद के खिलाफ जनता ने जो भावना व्यक्त की है, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने उसको नजरन्दाज

(श्री जगदीप धनखड़)

कर दिया। हमारे प्रधान मंत्री नरसिम्हारावजी ने संसद के अन्दर एक प्रस्ताव रखा था, विधेयक लाये थे रिलीजन और पालिटिक्स को डीलिंग करने का। निश्चित रूप से चाहते थे कि राजनीति के अन्दर धर्म की दखलंदाजी नहीं रहे। आपके दल ने नहीं होने दिया पर जनता ने ऐसा कर दिया। इस मिनी जनरल इलेक्शन में भारतीय जनता ने रिलीजन को पालिटिक्स से डीलिंक कर दिया और राजस्थान के अन्दर स्थिति यह कर दी (व्यवधान) दो महिलाएँ और डाक्टर साहब बैठे हैं गुरजंट सिंहजी हैं। इण्डिपेंडेण्ट जो लोग हैं इन्होंने कुछ भी किया हो, जनता की हालत को न समझा हो, उधर सत्ता बनाने में मदद की हो पर उन्होंने एक घोर पाजिटिव कण्ट्रीब्यूशन किया है और उसके लिये I congertulate them. पाजिटिव कण्ट्रीब्यूशन अपने यह किया है। अभी तो आप भी अन्दाज लगा रहे हैं कि क्या किया है। यदि आप उधर नहीं होते तो आर एस एस के ज्यादा लोग मंत्री बनते राजनीति में कट्टरवाद बढ़ता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी तरफ होते तो क्या होता ?

श्री जगदीप धनखड़ : जनता को इस बात से राहत मिली है। मान्यवर, चतुर्वेदीजी होते तो मैं पूछता कि क्या आर एस.एस. में कोई चुनाव होते हैं ? सभापति महोदय, क्या वह सिस्टम वह संस्था डेमोक्रेटिक हो सकती है जिसमें चुनाव नहीं होते ? क्या पालियामेण्ट्री डेमोक्रेसी में ऐसी संस्था का कोई स्थान है ? भारत की जनता का अभिवादन आप और हम सब को मिलकर करना चाहिये कि इस चुनाव के माध्यम से आर. एस. एस. को उन्होंने करारा जवाब दिया।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया। आई कांग्रेचुलेट, वे चाहते तो आपके भाषण के कुछ हिस्से नहीं पढ़ते। आप लोगों पर यह राष्ट्रपति शासन का भूत कब तक छाया रहेगा। अगर मैं पूछूं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि एक महीने में आप की कौनसी उपलब्धि है, आप कह सकते हैं हमने तो भ्रष्टाचार के कुछ मामलों पर पहले मुकदमे दर्ज किये थे। आपने तो कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया। कितनी बंदिश मुख्य मंत्री महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के अन्दर यमुना वाटर के सिलसिले में, भाटीजी तो स्वस्थ थे, सिचाई मंत्री को नहीं ले गये और पूर्व सिंचाई मंत्री को ले गये। पूर्व सिंचाई मंत्री मेरे मित्र हैं, योग्य आदमी हैं ले गये बड़ा अच्छा काम किया।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : मैं अस्वस्थ था।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरे को जानकारी नहीं थी पर पूर्व सिंचाई मंत्री को ले गये। मान्यवर, अगर पूर्व मंत्रियों को इस प्रकार काम मिलने लग गया तो पता नहीं दिल्ली से मेरे लिये कब बुलावा आ जाये और आप पर तो कोई बन्धन नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : यह आप दिन में सपने देख रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आप समझते हैं कि दिन में सपने उधर बैठकर ही देखे जा सकते हैं।

श्रीमती शशी दत्ता (विधि राज्य मंत्री) : सदन में बैठकर देखो आप तो।

(70)

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर, जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है इसमें कुछ बातें ऐसी कही गयी हैं जो बड़ी गम्भीर चिन्ता का विषय हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अभिभाषण के पृष्ठ 14 पर, "डंकल प्रस्तावों पर भारत सरकार की स्वीकृति होने के कारण देश के किसानों में चिन्ता उत्पन्न हुई है।" आगे मैं नहीं जाता। कितनी गलत बात लिखी हुई है। भारत सरकार ने स्वीकृति अभी तक दी कहां है? अधिकारी स्तर पर बातचीत हुई थी मंत्री स्तर पर होनी बाकी है। फिर गवर्नमेण्ट रेटिफिकेशन होगा और 1 जनवरी, 1995 से लागू होगा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में जब यह प्रश्न उठा तो कामर्स मिनिस्टर प्रणव मुखर्जी ने साफ तौर पर कहा। उन्होंने जो 17 दिसम्बर, को राज्यसभा में कहा, and I quote: "First I would like to mention in respect of the format which we are discussing as I mentioned earlier I am repeating the position is not that we have signed something." He did not sign anything. यह तो एक इनिशियल चीज है और आपके अभिभाषण के अन्दर अधिकारियों ने, और आपके मंत्रिमण्डल; मंत्रिमण्डल के बारे में तो मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि देश के अन्दर पहला मंत्रिमण्डल है जिसमें कृषि मंत्री राज्य मंत्री है, पंचायत राज मंत्री राज्य मंत्री है। आपने क्या कृषि को दर्जा दिया है, क्या पंचायत को दिया है, क्या ग्रामीण विकास को दिया है? आपने किसी को केबिनेट रेंक का नहीं रखा। स्वतंत्र चार्ज दिया, अच्छी बात है, पर कम से कम कृषि को तो दर्जा दें। और ऐसी स्थिति के अन्दर मैं इसको गलत नहीं मानता। बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे परसादी लालजी के टोकने के बावजूद पंचायत राज के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री रोहिताश्व (यातायात राज्य मन्त्री) : ट्रेनिंग है।

श्री जगदीप धनखड़ : कितने समय को? सभापति महोदय, डंकल प्रस्ताव के ऊपर इतना ही नहीं है इससे आगे देखिये, क्या कहा गया है। "वर्तमान सरकार प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि डंकल प्रस्ताव के कुप्रभावों से प्रदेश के किसानों के हितों को सुरक्षित रखने का हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा।" माननीय मुख्य मन्त्रीजी विचार-विमर्श करें, अधिकारियों से। मैं कहूंगा, मुख्य मंत्रीजी, कम से कम कुप्रभाव का जिक्र तो कीजिये। अपने कृषि राज्य मंत्री को कहिये कि इस सदन में आज बता सकें कि जिस डंकल प्रस्ताव का इतना बड़ा भूत आपने कर रखा है, जिस डंकल प्रस्ताव को किसान विरोधी कह रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सोवरीनटी खतम हो जायेगी उस डंकल प्रस्ताव का कौनसा कुप्रभाव है जिसके बारे में यह सरकार चिन्तित है। आश्चर्य है और यह चिन्ता का विषय है। क्या सरकार के पास डंकल प्रपोजल्स हैं? मान्यवर, मैं सरकार को भी एक कापी अवेलेबल कराऊंगा। तो मेरा, मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना है कि मुख्य मंत्रीजी जवाब देते समय इस बात को निश्चित रूप से कहें कि डंकल प्रपोजल्स की वजह से कौन से ऐसे कुप्रभाव राज्य के किसानों पर पड़ रहे हैं जिनसे सरकार चिन्तित है और सरकार बचायेगी? मैंने पहले भी कहा था कि मुख्य

(श्री जगदीप धनखड़)

मंत्रीजी ने अपने भाषणों में चुनाव के दौरान कहा था कि डंकल बहुत खतरनाक है। वह आदमी जीवित है डायरेक्टर जनरल ऑफ गैट, आर्थर डंकल। (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : वे अब रिटायर हो गये।

श्री जगदीप धनखड़ : यदि डंकल आ गया तो नीम का दतून नहीं कर पायेंगे। मैं कह सकता हूं प्रस्तावों के अध्ययन के पश्चात् कि इस प्रकार का कोई कुप्रभाव नहीं है। मान्यवर, जो चीज 7 वर्ष के बाद शुरू हुई, 7 वर्ष लग गए इस ट्रीटी के फाइनेलाइजेशन में, इस ग्रेप में आने में, 117 देश लगे हुए हैं, 1986 में जिसकी शुरूआत हुई, थोड़ी समस्या हुई, एक साल पहले तो गैट के डायरेक्टर जनरल ने कुछ प्रपोजल्स बनाये वह प्रपोजल्स मल्टी-नेशनल, इण्टरनेशनल ट्रेड के तहत हैं उसमें कितना जबरदस्त फायदा हिन्दुस्तान को हो सकता है, पता नहीं इस सरकार ने इसका अन्दाज क्यों नहीं लगाया ?

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि डंकल प्रपोजल्स की वजह से भारत को भारी फायदा होने वाला है We are a member of 177 countries. जो एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशनंस का स्टेटस देंगे और नार्मल डवलपमेण्ट से देखने के अलावा हर साल डंकल की वजह से हमारे ट्रेड में जो बढ़ोतरी होगी वह यू. एस. 1.5 से 2 बिलियन डालर की है। यह कोई साधारण बात नहीं है। साधारण प्रगति के अलावा 7 लाख लोगों को हर साल डंकल से एम्प्लायमेण्ट मिलेगा। कहते हैं कि डंकल की वजह से हमारा सीड हम काम में नहीं ले पायेंगे, डंकल की वजह से सब्सिडी नहीं दे पायेंगे। आप किसी आदमी से कहो कि 200 साल के बाद आप जी नहीं सकोगे और आप तूफान खड़ा कर दो, कौन जीता है 200 साल ? जितनी सब्सिडी दे रहे हैं उसमें कहां कटौती होगी ? कामर्स मिनिस्टर ने कहा कि डंकल प्रस्ताव मंजूर करने के पश्चात् जितनी सब्सिडी हम दे सकते हैं उतनी सब्सिडी हमने आज तक कभी दी नहीं है, उस लेवल तक ही नहीं पहुंच पायेंगे। फिर भी राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर डंकल के कुप्रभाव से किसानों को बचाने के लिए कहा गया है। किसानों को बचाइऐ, माननीय मत्रीजी, बिजली के संकट से, पेयजल की समस्या से, गांव में सड़क बनाकर। किसानों को, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप और आपके अधिकारी मिल कर डंकल प्रस्तावों के कुप्रभावों से बचाने की आवश्यकता नहीं है। किसानों के विकास में डंकल एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। समझ में नहीं आता, मान्यवर, चुनाव के समय जनता के समक्ष भाषण दिये जायें पर राज्यपाल के पद की गरिमा को कितनी ठेस पहुंचाई इस बात को लिख कर और राज्यपाल के अभिभाषण में यह बात तब लिखी गयी जब कि भारत की संसद में इस बात के ऊपर विचार विमर्श हो चुका, आपकी पार्टी के दिग्गज नेता श्री जसवन्तसिंह उस पर व्यापक विचार-विमर्श कर चुके।

मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सरकार इस बारे में पूरा खेद प्रकट करें। इस सदन को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, बरगलाने की चेष्टा की

(श्री जगदीप धनखड़)

गयी है । मान्यवर, दूसरे विषय पर जाते हुए....(व्यवधान) ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो बहकावे में नहीं आये ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : आ जाएंगे ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): अगले वर्ष आ जाएंगे ।

श्री रोहिताश्व : एण्टी डिफेक्शन....

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि इनका सरनेम धनखड़ की बजाय डंकल रख दिया जाये ।

श्री जगदीप धनखड़ : मुझे पता है, आप मेरी छुट्टी देश से करके कहीं न कहीं गैट में भेजेंगे । श्री रामनिवासजी मिर्धा युनाइटेड नेशन में चले गये मुझे क्यों भेजते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी इच्छा तो है ।

श्री जगदीप धनखड़ : एक दूसरी बात, इन्होंने जो व्यवस्था की है और बड़ी जबरदस्त व्यवस्था की है पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में । पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मान्यवर, मैंने मेरे नेता से पूछा और उन्होंने कहा कि समय दे सकते हैं ।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, पीछे वाले रह जाएंगे । केरी आन ।

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर, पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत एक जबरदस्त कान्स्टीट्यूशनल डवलपमेण्ट हुआ, 73वां कान्स्टीट्यूशन अमेण्डमेण्ट । लेट राजीव गांधी का सपना साकार हुआ । पंचायत चुनाव में राज्य स्तर के ऊपर जो बिखराव होता है पंचायत चुनाओं के साथ खिलवाड़ होता है उसे रोकने के लिए 73वां कान्स्टीट्यूशन अमेण्डमेण्ट के अन्दर व्यवस्था है और उसमें प्रतिपादित है कि उस निश्चित अवधि में चुनाव आवश्यक हैं । मिड 1994 में निश्चित है पर यह सरकार, मान्यवर, क्या कहती है ? पेज 11, लास्ट थ्री लाइन्स —

"1992 में संशोधन भी किये गये परन्तु दिसम्बर, 1992 में चुनी हुई सरकार को भंग कर दिये जाने के कारण इनके चुनाव नहीं हो सके ।"

आगे देखिये क्या कहते हैं—

"संविधान में हुए संशोधन के कारण पंचायती राज संस्थाओं के लिये नये सिरे से चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना पड़ेगा और उसके पश्चात् ही चुनाव संभव हो सकेंगे । हमारी सरकार यह चाहेगी कि यह प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र पूरी हो ।"

मान्यवर, दो वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं । आपकी मर्जी पर नहीं है । यह 73वां कान्स्टीट्यूशन अमेण्डमेन्ट आपको यह अधिकार नहीं देता है । आप अपनी मर्जी पर चलें । आप पानी पहुचाने में अपनी मर्जी से चल सकते हैं उसमें कान्स्टीट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, सड़क के लिये चल सकते हैं, बिजली के मामले में चल सकते हैं पर यह चुनाव आपको निश्चित रूप से 73वें

(श्री जगदीप धनखड़)

कान्स्टीट्यूशन अमेण्डमेण्ट के तहत करने पड़ेंगे और ये मिड 1994 में होने अति आवश्यक हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, it will be constiiutional failure. यह माना जायेगा कि आपकी सरकार कान्स्टीट्यूशनल प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं चल रही है। और आप अगले पैरा में क्या कहते हैं—

"राज्यपाल के समक्ष जन-प्रतिनिधियों की जगह किसी को लाने की बात थी, तो हम ऐसा कर लें...."

The cat is out of the bag. चुनाव तो करवाना नहीं चाहते, किसी को वहां स्थापित करना चाहते हैं। समय कितना है?

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि पंचायत संस्थाएं वह माध्यम हैं, जहां गरीब आदमी सत्ता में अपनी भागीदारी समझता है, गरीब आदमी अपनी छोटी-मोटी समस्याओं को लेकर सत्ता तक पहुंचने की चेष्टा कर सकता है। आप सत्ता में आये, पंचायतों के साथ खिलवाड़ किया, पूरी व्यवस्था को चरमरा दिया। ऐसी हालत को देखते हुए 73वां कान्स्टीट्यूशन अमेण्डमेंट आया कि कोई भी राज्य स्तर पर ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सके। इसमें कुछ चीजें निश्चित हैं, 5 साल की अवधि, एक चुनाव आयोग चुनाव करवायेगा, पंचायतों को कुछ अधिकार दिये जाएंगे, 30 प्रतिशत महिलाओं का, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन होगा....(व्यवधान)....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री): 33 प्रतिशत है।

श्री जगदीप धनखड़: क्या, 33 प्रतिशत है, मान्यवर।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही): आप महिला विरोधी हैं क्या?

श्री जगदीप धनखड़: मान्यवर, I am subject to correction. यदि 33 प्रतिशत है तो बड़ा खुश होऊंगा। 30 प्रतिशत है, आप दुबारा पढ़ लीजिए।

मान्यवर, पंचायती राज के साथ यह सरकार अपनी पुरानी परम्पराओं को दोहराना चाहती है, उस खिलवाड़ को जारी रखना चाहती है और ऐसा क्यों न हो। धन्यवाद प्रस्ताव के समय मैंने कहा, श्री परसादी लालजी मीणा ने इण्टरप्ट किया और इन्टरविन करते हुए कहा कि पंचायती राज का क्या हो रहा है? सब कुछ कहा बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने पर पचायती राज के बारे में कुछ नहीं कहा।

मान्यवर, दूसरी गम्भीर समस्या है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बड़ी एक्सप्लोजिव सिच्युएशन जिसके बारे में यह सरकार बिलकुल सो रही है और वह है शिक्षित बेरोजगारों की जिसके बारे में कुछ नहीं है, एक शब्द तक नहीं है. चलते रास्ते कोई बात कह दी गयी है। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इस सरकार ने सरकारी तंत्र पर जबरदस्त आघात किया है।

(14.00)

आधे से ज्यादा अधिकारियों को इस सरकार ने बन्द कर रखा है, ऐसी अनसर्टेनटी सिचु-

(श्री जगदीप धनखड़)

एशन क्रिएट कर रखी है ।...(व्यवधान)... मान्यवर, यदि मैं कोई और एक्सप्रेशन यूज कर दूंगा और उसका लिटरल मीनिंग ले लेंगे तो आप तो You are quite a senior minister. मान्यवर, ब्यूरोक्रेसी परमानेंट है, आप और हम टेम्प्रेरी हैं । इस चीज को आप और हम भूल नहीं सकते । जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ आप इतना जबरदस्त खिलवाड़ कर रहे है जिसका कोई अन्दाज नहीं है । पहले भी जब भैरोंसिंह जी मुख्य मन्त्री थे उनके सैक्रेटरी को मिनी चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, यह सर्व विदित है पर अब तो जबरदस्त हालात कर दिये और उसमें देखिये, मान्यवर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार की बात कैसे आ गयी राज्यपाल के अभिभाषण में ? पेज 13 पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, थर्ड पैरा में अंकित है, 'किन्हीं कारणों से इन परम्पराओं में विगत अरसे से जो विसंगतियां आ गयी थीं उनके निराकरण हेतु वर्तमान सरकार जहां एक ओर सुयोग्य एवं ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित करेगी, वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करेगी कि जनआकांक्षाओं के अनुरूप कार्य न कर निजी स्वार्थ में लिप्त रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय ।"....(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : ठीक है, इसमें क्या बुरा है ।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, सुनिये, थोड़ा सुनिये, मान्यवर, थ्यांवस रखिये, उधर आप नये-नये बैठे हैं ऐसा लगता है । बिना ब्यूरोक्रेसी के काम नहीं चलेगा, हमें तो चिन्ता आपके राज की नहीं है, विकास की है । राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी ने देश में नाम कमाया है । पिछले 2-4 साल में अपने दो केबिनेट सैक्रेटरी रहे हैं । मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि राज्यपाल के अभिभाषण में इस प्रकार का रेफरेंस आये, मुख्य मंत्री महोदय अनुपस्थित हैं आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वह अपने जवाब में इस बात का पूरा खुलासा करें, 'किन्हीं कारणों से ?' हमसे क्यों छिपाया जा रहा है बताइये, कौन से कारण हैं ? आगे, 'विगत अरसे से,' कहिये न, राष्ट्रपति शासन । पहले तो आपका ही राज था, फिर आ गये । "जो विसंगतियां आ गयी हैं और उनके निराकरण," तो उनको कह दीजिये कि आपका मकान मदीना के अन्दर चैक कराइये । कह दीजिये, आर. एस. एस. कल्चर को सब्सक्राइब करें । कह दीजिये, बी. जे. पी. के मेनीफेस्टो को ही गवर्नमेंट का कोड आफ कंडक्ट मानें । मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जनता के सामने बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं, जनता परेशान है । शिक्षित बेरोजगार के सामने जबरदस्त साइकोलाजिकल प्रोब्लम्स हैं क्योंकि यह सरकार उनको एम्प्लायमेंट देने के बारे में कुछ नहीं सोच रही है । सरकार को अचीव करने के लिए जरूरी है कि ब्यूरोक्रेसी के मोरल को इस प्रकार से नीचे नहीं आने दें, ऐसा खिलवाड़ ब्यूरोक्रेसी के मोरल से वह नहीं करे ।

मान्यवर, आज की स्थिति यह है कि राज्य के अन्दर कुछ हो नहीं रहा है । पिछली बार जब भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री बने थे, वहीं बात इस बार हो रही है । पहले जो कार्य किये, अब भी वही कार्य किये । मन्त्री मण्डल बनाने में देरी बाहर जो

(श्री जगदीप धनखड़)

कार्यक्रम गये, वे पहले एक बार रद्द हो गये थे इस बार भी हो गये। पिछली बार भी हो गये थे। कहने को तो कोई प्रोग्रेस नहीं है। हां, एक काम है, भैरोंसिंह जी का फाइनेन्शियल मैनेजमेंट। मेरे को यह तो समझ में आता है कि किसी पार्टी का कोई मेनीफेस्टो हो, एक व्यक्ति का फाइनेन्शियल मैनेजमेंट। बड़ी चर्चा की गयी है, वेरीगुड, लीडर को ट्रिब्यूट पे करना कोई गलत बात नहीं है पर कम से कम हमें पता तो लगे कि वह फाइनेन्शियल मैनेजमेंट क्या है? उस फाइनेन्शियल मैनेजमेंट की जो भी करामात है वह जनता तक तो नहीं पहुंच पायी। उसको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कहीं कंसील कर रखा है।

मान्यवर, राज्य में विकास की बात की गयी। सब कुछ दिल्ली पर डाल दिया और कहते हैं सरकारिया कमीशन ऐसा कहता है। इंकल को तो इन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा, सरकारिया कमीशन को तो they are taking very casually. सब कुछ राज्यों को दे दो, मेजर मिनरल्स भी हमें दे दो। एक जगह कहा गया हैं, मैंने देखा, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ा लरनेड भाषण दिया है पर ऐसा लगता है कि अपने भाषण को राज्यपाल के अभिभाषण से सब्स्टिट्यूट कराना चाहते हैं। एक नये प्रपोजल्स उसके अन्दर हैं और वह यह है कि हमें देते जाओ। एक पुरानी कहावत है 'आओगे तो क्या लाओगे, जाओगे तो क्या देकर जाओगे।' ऐसा सिस्टम इन्होंने चालू कर रखा है। आप और हम सबको भारत के संविधान के अधीन रह कर कार्य करना पड़ता है। फेडरल करेक्टर जो अपने देश में आया है, इसके तहत अपने को कार्य करना पड़ता है। राज्य सरकार मात्र यह कहती रही है कि राष्ट्रपति शासन ने सब कुछ बरबाद कर दिया और केन्द्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। They cannot find scapegoat in the Central Government or President Rule. Do not look for alibis. अब यह मौका है कि जनता की समस्याओं को हल करने के लिये कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण में ही नहीं, मुख्य मंत्री महोदय ने; I am at the cost of repetition, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी केबिनेट बनाते समय गांवों के साथ अहित किया। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश, राजस्थान जैसे कृषि प्रधान प्रान्त में कृषि मंत्री राज्य मंत्री है पंचायती और ग्रामीण विकास मंत्री राज्य मंत्री है। यह इस सरकार की मानसिकता को आगे लाती है।

मान्यवर, औद्योगिक विकास के बारे में कुछ नहीं कहा कि हम औद्योगिक विकास कैसे करेंगे, लोगों को कैसे लायेंगे। एक ही काम किया है अभिभाषण में, जो पहले की लेक आफ परफार्मेन्स थी, पहले का जो ट्रेक रिकार्ड गड़बड़ था, पहले जो विकास नहीं कर पाये। पहले के समय के बारे में यदि इनसे कोई प्रश्न करें कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर किस हद तक आपने एक्सटेंड किया तो पता लगेगा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरी तरह विफल रहे। इसमें सबसे पहले आता है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के मामले में मुख्य मंत्री ने जो ट्रेक रिकार्ड तैयार है वह राजस्थानियों के लिए भयानक स्थिति प्रस्तुत करता है।

(श्री जगदीप धनखड़)

जैसी स्थिति पावर जनरेशन की कर रखी है उसमें आप मानकर चलो कि राजस्थान का विकास बिलकुल सम्भव नहीं है।

मान्यवर, चर्चा हुई कि लिग्नाइट के सम्बन्ध में क्या हो सकता है। यह अवसर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन के अन्दर होटल का कितनी जल्दी लाइसेंस दे दिया गया और आप किस तरीके से एक विदेशी कम्पनी को बुलाकर किसी इन्टरमीडियेटर के माध्यम से कन्क्लूजन्स करना चाहते हैं। There will have to be an atmosphere of trust. यह सरकार ऐसा नहीं करने जा रही है। मान्यवर, सहकारिता, ग्रामीण विकास औद्योगिक विकास, शिक्षित बेरोजगारों के लिये नौकरी; ऐसा लगता है कि इन मुद्दों पर सरकार का ध्यान जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता ? इसके लिये भी ज्यादा दूर आप और हमको सोचने की आवश्यकता नहीं....

एक माननीय सदस्य : महिला का नाम नहीं लिया।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरे मित्र ने कहा महिला का नाम नहीं लिया और कमला जी अभी आयी है, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के जरिये समाज को बांटने की चेष्टा की, सोसायटी को नेरो कंसीडरेशन, सेक्टेरियन कंसीडरेशन के ऊपर बांटने की कोशिश की गयी है। आगे क्या कहा है शुरू में देखिये, मान्यवर, 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं ने विधान सभा के 57 आरक्षित क्षेत्रों में से वर्तमान सरकार में अपने 33 विधायक भेज कर ...।" मान्यवर, क्या यह राज्यपाल के अभिभाषण में आने लायक है ? क्या इसका अर्थ यह लगाया जाये कि आपकी तरफ माइनोरिटी का एक भी सदस्य नहीं है तो माइनोरिटी आपको अपना दुश्मन मानेगी। इस प्रकार की बात नहीं आनी चाहिये। राज्यपाल के पद को इन्होंने इतनी जबरदस्त रूप से ठेस पहुंचाई है nd the Rajyapal,bou and by the Constitution, he read it. वह एक स्थिति क्रिएट कर सकते हैं उससे कि इस प्रकार की बात नहीं आये। आपने चुनावों में समाज को सेक्टेरियन कंसीडरेशन के ऊपर बांटने की चेष्टा की, उसमें आप असफल रहे तो यहां करने की कोशिश की। कहते हैं, हमारे को बहुत बड़ा मेण्डेट मिला है। मान्यवर, इन चुनावों में कांग्रेस को मात्र 0.31 प्रतिशत वोट कम मिले हैं। मान्यवर, देखिये, एक स्थिति जिस पर यह ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये क्यों देंगे ? 1991 के लोक सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिले आपको इन चुनावों में 2 प्रतिशत कम मिले जबकि कांग्रेस को गत विधान सभा चुनावों से 5 प्रतिशत ज्यादा वोट हासिल हुए।

मान्यवर, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमें कुल मिला कर इतने वोट मिले, कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले। मैं पूछना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सीटें भी कम मिलीं और वोट भी कम मिले। मध्य प्रदेश में आपको सीटें भी कम मिलीं और वोट भी कम मिले। राजस्थान में मार्जिनल रहा। Do not play with figures.

श्री कालीचरण सराफ : फिगर्स आप देख लीजिए, पांचों स्टेट्स में मिला करके। एक करोड़ वोट ज्यादा मिले हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय कालीचरण जी, जो मैं कह रहा हूं उसे आप सुनिये। मैं कह रहा हूं, गत विधान सभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले सीटें भी ज्यादा मिलीं और वोट भी ज्यादा मिले। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को सीटें भी ज्यादा मिलीं और वोट भी ज्यादा मिले और राजस्थान के अंदर 0.31 पर्सेन्ट कम रहा।

श्रीमती तारा भण्डारी : यू. पी. में क्या हुआ ? यू. पी. में तो आप साफ हो गये।

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर, उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि अयोध्या के आस-पास आपकी सिर्फ एक सीट बची और जनता ने कल्याण सिंह की जगह मुलायम सिंह को बैठा दिया। जनता ने अपना निर्णय दे दिया।

श्री कालीचरण सराफ : यू. पी. में कांग्रेस का क्या हुआ ? हम तो एक नम्बर पर हैं।....(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार को यह कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई आर्थिक नीति विकास के मामले पर नहीं रखी। यदि विकास के मामले पर कोई आर्थिक नीति रखते तो उसका हवाला निश्चित रूप से धन्यवाद प्रस्ताव रखते समय किया जाता। इस पार्टी के अंदर जबरदस्त बिखराव है, इस पार्टी के अंदर कंफिलक्ट्स है। जसवंत सिंहजी एक बात कहते है तो डा. मुरली मनोहर जोशी दूसरे दिन कहते हैं यह तो उनकी व्यक्तिगत राय है, वे तो लिबरल हैं। अब ले दे करके जो इस पार्टी में बचे हैं वे लिबरल हैं। कट्टरवाद को जनता ने नकार दिया। मान्यवर, मैं महज अपोज करने के लिए अपोज नहीं करना चाहता। हमारी पार्टी और मैं, दोनों कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट में विश्वास रखते हैं, पर क्या किया जाय ? अब कसाई के सामने बकरी रख दो तो बचेगी ? मान्यवर, जागे हुए को कोई जगा सकता है सोते हुए को तो फिर भी जगा दे।

मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इस सरकार ने कुछ ऐसे काम किये हैं कि इसका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में जाने लायक है। नम्बर एक, राज्यपाल के पद की गरिमा को इन्होंने भारी चोट पहुंचाई है और यह चोट जान-बूझकर पहुंचाई है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इन्होंने जबरदस्त आघात किया है और पुरानी परम्परा है कि अधिकारियों के ऊपर तलवार लटकायी रखी, विकास नहीं करना चाहिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : "भय बिनु प्रीत न होई।"

श्री जगदीप धनखड़ : Thank you Madam, thank you for good suggestion. मान्यवर, मैं कन्क्लूड करते समय एक बात और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेस्ट पालिटिकल गेम खेल लिया है, बेस्ट प्लेइंग कार्ड प्ले कर लिया है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते थे, उसका नतीजा आपके सामने आ

(श्री जगदीप धनखड़)

गया है। राजस्थान के अंदर आप बच गये। राजस्थान अकेला प्रान्त है जहां बी.जे.पी. की सरकार है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : दो हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : हैण्डीकेप्ड है, दिल्ली को प्रान्त मत मानिये।

श्री शांतिलाल चपलोत पहले बी. जे. पी. के 2 आये उसके बाद हमने 85 सीटें प्राप्त की हैं। अबकी बार दो राज्य आये हैं और अब पूरे हिन्दुस्तान पर कब्जा होगा।

श्री जगदीप धनखड़ : They are not prepared to be reasonable. ये राइटिंग आन दी वाल नहीं देखना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग चिन्तन क्यों नहीं करते ? पूरी केबिनेट नहीं बनी है। मुख्य मंत्रीजी अपने आपको फँस में पा रहे हैं। जनता परेशान हो रही है, शिक्षित बेरोजगारों की समस्याएं जबरदस्त हैं उनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। राजस्थान का क्या बुरा हाल है, सोच नहीं रहे हैं और आपके पास सिर्फ एक ही उत्तर है, बस, केन्द्र सरकार।

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है और बिफोर कन्क्लूडिंग मैं कहना चाहूंगा फोर दी सेक ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन में विश्वास नहीं है। हम चाहेंगे गरीब के साथ न्याय हो, किसान के हित को देखा जाये, शिक्षित बेरोजगार को नौकरी दिलायी जाये, राज्य की समस्याओं के निराकरण की ओर बढ़ें, इन्फ्रास्ट्रक्चर सीन्सियरली क्रिएट करें, ब्यूरोक्रेसी के अन्दर अनिश्चितता की भावना को समाप्त करें और शुद्ध रूप से विकास की ओर आगे चलें। ऐसा नहीं है कोई प्राइवेट अरेंजमेंट से विकास की ओर बढ़ने की चेष्टा करें। यह कहते हुए निवेदन करूंगा यदि यह सरकार ऐसा नहीं करती है, यदि यह सरकार ग्रामीण विकास की ओर ध्यान नहीं देती है, गरीब-किसान, मजदूर, शिक्षित बेरोजगार की समस्याओं के निराकरण के लिये नहीं सोचती है तो, मान्यवर हमारे प्रतिपक्ष के नेता पहले कह चुके हैं कि हम 50 के नहीं हैं, We are 76 and our friends are there. यह तो फारमिडेबल अपोजिशन है, यह आपके लिये सहायक भी है और यह फारमिडेबल अपोजिशन इस सिचुएशन में भी है कि आपको जनता की समस्याओं के निराकरण करने के लिये बाध्य करे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बनीपार्क क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य राज्यपाल सिंहजी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसके लिये उन्हें धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय, पिछली सरकार द्वारा जनोपयोगी योजनाएँ बनाने, कल्याणकारी कार्यक्रम हाथ में लेने और समयबद्ध कार्यक्रम करने के कारण, योजनाओं की सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के कारण जनता ने हमें पुनः सरकार बनाने के लिये आशीर्वाद दिया है। सभापति महोदय, यह गरीब को गणेश मानकर कार्यक्रम चलाने का नतीजा

(श्रीमती तारा भण्डारी)

है. ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित विकास की योजनाएं बनाने का नतीजा है और यह नतीजा है जनता के विश्वास के अनुरूप कार्य चलाने का कि आज हम माननीय मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के नेतृत्व में सरकार में बैठे हैं।

मुझे सामने बैठने वाले माननीय सदस्यों पर तरस आता है जो इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को मात्र 'पीत-पत्रिका' कहते हैं। यह पीत-पत्रिका नहीं, इस दस्तावेज में राजस्थान के काश्तकारों की बहबूदी भरी हुई है। इस दस्तावेज में राजस्थान के सर्वांगीण विकास, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की योजनाएं हैं। सभापति महोदय, यह पीत वर्ण नहीं, यह तो फूली हुई सरसों का रंग है, यह तो शौर्य के दीवानों का बसन्ती रंग है। पीत वर्ण तो सामने वाले सदस्यों का है। इस सुन्दर और योजनाबद्ध कार्यक्रम को देखकर इनके हौसले पस्त हो गये हैं और इनके मुंह का रंग पीत हो गया है।

सभापति महोदय, गवर्नर साहब ने एक बार नहीं अनेक बार कहा, मैं पूर्व महामहिम राज्यपाल महोदय की बात कर रही हूं जिन्होंने सार्वजनिक मंचों पर भाजपा सरकार की कार्यविधि की प्रशंसा की थी। उन्होंने कई बार भाजपा सरकार द्वारा चलाये जा रहे समयबद्ध कार्यक्रम, कानून और व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था और इन सबसे खुश होकर, प्रसन्न होकर सार्वजनिक मंचों पर यह कहा था कि भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है। परन्तु, सभापति महोदय, 15 दिसम्बर को बिना यह सोचे-समझे कि भाजपा राजस्थान में किस प्रकार की बहबूदी लाना चाहती है, कैसी सुन्दर योजनाएं हैं, हमारी सरकार को बरखास्त कर दिया। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहती हूं, जो कांग्रेस पार्टी के भी प्रतिनिधि हैं, क्या गुजरात और महाराष्ट्र में भीषण नरसंहार नहीं हुआ ? क्या गुजरात के दंगे और महाराष्ट्र के दंगे आप भूल गये हैं ? उन सरकारों को केन्द्र सरकार ने क्यों बरखास्त नहीं किया ? यदि आपके पास जवाब हो तो सदन में देने का कष्ट करें। सभापति महोदय, यह राजस्थान तो केन्द्र सरकार की आंख की किरकिरी बन गया था। केन्द्र सरकार, जो दिल्ली में बैठी है उसके नजदीक राजस्थान अच्छी तरह राज कर रहा था, सरकार दंगा और भयमुक्त राज चला रही थी, ऐसी सरकार को बिना किसी बात पर, बिना सोचे-समझे बरखास्त कर दिया लेकिन मैं आज राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूं जिसने इस बरखास्तगी का प्रतिकार किया और इस प्रतिकार के रूप में पुनः भाजपा शासन को स्थापित कर दिया।

सभापति महोदय, पूर्व में जो भी कार्यक्रम चलाये, जो भी योजनाएं बनायीं, तीस जिले-तीस कार्य योजना चलायी, अन्त्योदय योजना चलायी, उस अन्त्योदय योजना से किसी वर्ग विशेष का फायदा नहीं हुआ। अपितु सारे ही वर्गों में जो सबसे गरीब था उस गरीब का फायदा हुआ। उस गरीब का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का उस अन्त्योदय योजना में प्रयास किया गया। सभापति महोदय, उस अन्त्योदय योजना की केवल राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी सराहना की गयी। ऐसी थी यह अन्त्योदय योजना। अपना गांव अपना काम

(श्रीमती तारा भण्डारी)

योजना, तीस जिले तीस काम, भागीरथ योजना, विधायकों को अपनी स्वीकृति के अनुसार दस-दस लाख रुपये खर्च करवाने के जो अधिकार थे इन सबने मिलकर राजस्थान में एक कीर्तिमान कायम किया, गांवों में अनेकानेक रचनात्मक काम हुए, निर्माण के काम हुए और अनेक ऐसे कार्य हुए जिनका ग्रामीण जनता वर्षों से इन्तजार कर रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय को, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से राजस्थान की प्यासी जनता को ज्यादा से ज्यादा पेयजल पहुंचाने का प्रयास किया।.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सिरोही के लिये सुबह ही तो आपने....

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुरा) : सब जगह, पूरे राजस्थान में सारे वाटर वर्क्स तो टूटे पड़े हैं, सारी व्यवस्था खराब हुई पड़ी है।

श्रीमती तारा भण्डारी : वह तो आपके समय की बात थी। आप सुनें। सिरोही की मैं बात कहूंगी, सिरोही मेरे साथ है....

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप क्यों एक राजी करने के लिये बात कर रही हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : सिरोही में तो इसलिये गड़बड़ी हुई कि राष्ट्रपति शासन में सिरोही की योजना गुम हो गयी, वह बात थी।

श्री परसादीलाल मीणा : ढाई साल में क्या हुआ ?

श्रीमती तारा भण्डारी : वरना तो ढाई साल में....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : सुबह तो आप पानी के लिए + + + रही थीं।

श्री सभापति : कृपया शांत रहें माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : तीसों गांवों में पानी है ...

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, इनको सुनने की जरा ट्रेनिंग दीजिये, हम भी सुन रहे थे जब धनखड़ साहब बोल रहे थे।... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : सुबह तो आप पानी के लिए + + + रही थीं....

श्रीमती तारा भण्डारी : हमने बड़े प्रेम से सुनी है धनखड़ साहब की सारी बातें, आप भी सुनने का कुछ माद्दा बनाइये। सिरोही की बात भी कहूंगी। मैं सिरोही की भी कहूंगी, मैं जयपुर की भी कहूंगी, मैं पूरे राजस्थान की कहूंगी।....

श्री परसादीलाल मीणा : सुबह क्या शाम को क्या।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं आपको यह दावे के साथ कह सकती हूं कि सिरोही क्या, राजस्थान भर में गांव-गांव में पेयजल संवर्धन के लिये अनेक टंकियां बनीं, अनेक जगह

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

पाइप लाइनों का विस्तार हुआ, नये ट्यूब वैल खोद गये, नये कुए खोदे गये.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया डिस्टर्ब न करें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हमारे टाइम में जो वाटर वर्क्स बने थे.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपके टाइम का तो चुल्लू भर पानी भी नहीं बचा, क्या बात करते हैं आप। आप याद करिये वह दिन, जब मैंने स्वर्गीय राजीव गांधीजी....

एक माननीय सदस्य : सीमेंट तो सारी खा गयीं आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैंने स्वर्गीय राजीव गांधीजी को सिरोही का पानी प्रस्तुत किया था।.... (व्यवधान) सभापति महोदय, यह सुनें जरा। और मैंने वह पानी राजीव गांधीजी को यह कह कर प्रस्तुत किया था, राजीव गांधीजी, मेरे क्षेत्र में परमात्मा अगर किसी को पीड़ित करता तो माना जा सकता है, परमात्मा विकलांग बनाये तो सोचा और माना जा सकता है, लेकिन राजीव गांधीजी, चालीस वर्षों से राज कर रही इस कांग्रेस के राज में मेरे इलाके के लोग फ्लोरिसिस का पानी पी-पी कर विकलांग हुए चौपाये जानवरों की तरह चलते हैं। यह देन है मान्यवर, कांग्रेस की यह देन है। इस बार बूटासिंहजी को भी यह सामना करना पड़ गया जब मैंने पब्लिक मीटिंग में कहा कि बूटासिंहजी आप कहते हैं- करोड़ों रुपये खर्च हो जायें, मेरा लवली जीतना चाहिए। तो मैंने कहा, यह सिरोही के बच्चे आपके प्यारे नहीं हैं क्या? चालीस वर्षों से जहां पर पानी पीकर लोग विकलांग हो रहे हैं? आप हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं, दिल्ली में बैठे हैं और केन्द्र के पास अरबों रुपया पानी के लिये है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया डिस्टर्ब न करें। कृपया बिराजें। माननीय सदस्या को सुनें। कृपया बिराजें.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या वह पानी यह नहीं पीती हैं? क्या इनको अलग पानी पीना पड़ रहा है? इनको अलग पानी पीना पड़ रहा है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कृपया बिराजें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : असत्य आरोप तो नहीं लगाना चाहिए कम से कम, इतना तो आप ध्यान रखिये।

श्री सभापति : आप बता देना।.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, इनको दौरा पड़ गया है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, यह सुन नहीं सकते। मैंने बार-बार बूटासिंहजी को सामने कहा था, पब्लिक मीटिंग में कहा था, अजी, बूटासिंहजी, लवली आपका इतना प्यारा है तो हम भी सिरोही के बच्चे हैं। सिरोही के एक सौ और कुछ ऊपर गांव हैं जहां के लोग पानी पी-पी कर

(श्रीमती तारा भण्डारी)

चौपाये जानवरों की तरह चलते हैं, कमर से टेढ़े हो गये हैं, बच्चे जन्मते ही विकलांगता की ओर बढ़ते हैं। कम से कम आप हमारे एम. पी. हैं, दो-दो बार एम. पी. बने हैं, दिल्ली में बैठे हैं और केन्द्र सरकार द्वारा अरबों रुपया....

श्री परसादीलाल मीणा : ढाई साल में आपने क्या किया ?

श्रीमती तारा भण्डारी : जल संसाधन के माध्यम से दिया जा सकता है। मैंने कहा, बूटासिहजी, आपके यह लाखों बच्चे जो प्रतिवर्ष विकलांग होते हैं, इनकी विकलांगता बंद करने का प्रयास तो करते।

एक माननीय सदस्य : यह सरकार ही विकलांग थी।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह सरकार विकलांग थी। इसीलिये....

श्री हीरालाल इन्दौरा : पैसा लाने की सारी मशीनरी तो आपके पास थी फिर क्यों नहीं आपने भारत सरकार से पैसा मांगा ?

श्रीमती तारा भण्डारी : मान्यवर, सुनिये। इसीलिये सिरोही की जनता ने नकार दिया आप लोगों को। तीन की तीन सीट भाजपा के खाते में देकर बूटासिहजी को करारा जवाब दिया है कि सिरोही के बच्चों को बच्चे नहीं मानने का फल क्या होता है।

एक माननीय सदस्य : वह लवली तक सीमित थे।

श्रीमती तारा भण्डारी : वह लवली तक सीमित थे तो दूसरों के बच्चे क्या उनको प्यारे नहीं थे। यह जवाब सिरोही की जनता ने दिया है और यह जवाब, यह समर्थन भाजपा को देकर उन्होने हमारे मुख्य मंत्री और हमारी मंत्री परिषद् में विश्वास भी जताया है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : मानते हैं, सिरोही वाले सभी लवली हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : मान लिया, चलो अच्छा हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो यह मानते हैं, वे थोड़े ही मानते हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : मान गये। सभापति महोदय, न केवल पेयजल, शिक्षा के मामले में भी ...

श्री सभापति : कृपया बिराजें, माननीय सदस्या बिराजें।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : भारत सरकार एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम में जो ग्रांट दे रही है वह ग्रांट इस वक्त में, इस साल मुझे मालूम नहीं है, शायद होगी 80-90 करोड़ के आसपास। शायद देश भर में सबसे ज्यादा इस हैड के अन्दर ग्रांट मिल रही है वह राजस्थान को मिल रही है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : वह तो खर्च ही नहीं कर पाये।....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, हमारी सरकार ने बजट का 62 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया और

(श्रीमती तारा भण्डारी)

उसी का नतीजा है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, वह ग्रांट है। वह प्लान की बात नहीं है।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं तो साहब, बजट की बात कर रही हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं ग्रांट की बात कर रहा हूं। आप प्लान के 60 प्रतिशत की बात कर रही हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह मैं बजट की बात कर रही हूं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, अनुदान है। बिलकुल अनुदान मिल रहा है, कोई मैचिंग कान्टीब्यूशन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का, टोटल ग्रांट है।

श्रीमती तारा भण्डारी : वह बात तो आपकी हमने सुन ली, साहब, लेकिन अब हमारी भी सुन लें।... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय परसादीलाल जी, आप बिराजें।

श्रीमती तारा भण्डारी : अजी साहब, आपने कुछ अच्छे कर्म किये होते तो आप यहां क्यों नहीं होते।....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें, उनको बोलने दें।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, माननीय सदस्या बहुत अच्छा बोल रही हैं....

श्री सभापति : आप कृपया डिस्टर्ब नहीं करें, यह अच्छी परम्परा नहीं है। बोलने दीजिए उनको, उसके बाद में आपका नम्बर आ जाये तो आप बता दीजिएगा अपनी बात।

श्री परसादीलाल मीणा : गलत या असत्य बात सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। शहरों में और गांवों में....

श्री सभापति : अपने ऊपर थोड़ा संयम रखिये।

श्री परसादीलाल मीणा : उसमें गांवों से ज्यादा शहरों के लिये इन्होंने पैसा रखा था, आपको ध्यान होना चाहिए, आपके बजट में देखिये।

श्री सभापति : ठीक है।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह आप अपनी बारी आये तब बात रखना, हम मना नहीं करते आपकी बात।

श्री किशनाराम नाई : बिलकुल सत्य कहा है, हम भी तो सुन रहे थे न।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या सुन रहे थे, आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, पिछली भाजपा सरकार ने बजट का 62 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च किया उसी का नतीजा है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों पक्के काम हुए, निर्माण के काम हुए, स्कूलें खोलीं, कितनी स्कूलें खोलीं ?....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : 6 हजार स्कूलें। ...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह परम्परा ठीक नहीं है। आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। माननीय सदस्या को अपनी बात कहने का अधिकार है। कृपया बिराजें आप।....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : गलतबयानी कर रही हैं, यह सही नहीं है।

श्री सभापति : आप बिराज जाइये, कृपया डिस्टर्ब नहीं करें। (व्यवधान)... इसको डिबेट मत बनाइये, उनको बोलने दीजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय यह सच्चाई सुन नहीं सकते।

श्री परसादीलाल मीणा : आप सच्चाई बोल नहीं सकती।

श्रीमती तारा भण्डारी : जो शिक्षा केन्द्र बंद किये वह शिक्षा केन्द्र नहीं भ्रष्टाचार के अड्डे थे।

श्री परसादीलाल मीणा : आपको पाठ ही असत्य बोलने का पढ़ाया जाता है।

श्री सभापति : माननीय परसादी लाल जी, आप थोड़ा संयम रखिये। कोई बात आप सही नहीं बोलते हैं, कोई वह सही नहीं बोलती है, यह उचित नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप उनको यह कहो कि उधर मुंह करके बोलें।

श्रीमती तारा भण्डारी : नेता महोदय, थोड़ा अंकुश रखिये। इनके स्प्रिंग लगी हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्या, आप आसन की तरफ देखो। आप देख इधर रही हैं इसलिए व्यवधान हो रहा है। आपको आसन की तरफ देखना चाहिए। रूल्स में इस बात का प्रावधान है कि जो पजेशन आफ दी फ्लोर है उसको आसन की तरफ सम्बोधित करना चाहिए, उन्हीं की तरफ देखना चाहिए।

श्रीमती कमला (बैराठ) : सभापति महोदय, माननीय सदस्या से मैं एक निवेदन कर रही हूं कि आप अति न कहें और गलत न कहें। आप यह अति कह रही हैं कि सर्वांगीण विकास की पुस्तिका है जिसमें वन फोर्थ सब्जेक्ट्स का सिर्फ उद्धरण है। उसमें बिजली क्यों नहीं आ रही न उसका कारण है, न शिक्षा का है, न सिंचाई का है, न कृषि का है।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपकी बारी आये तब बोलिये ना आप।

श्रीमती कमला : दूसरा, स्कूलें खोलने में क्या भ्रष्टाचार हुआ? अगर विद्यालय के नाम के बजाय हमने शिक्षा केन्द्र खोले और उसके अन्दर ज्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिये कम खर्चे में काम किया तो इसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ? ऐसी बातें तो आप भी न बोलें। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। उनको सुनें, उनका बहुत समय बरबाद कर दिया आप सब लोगों ने।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, उन स्कूलों में क्या भ्रष्टाचार था यह माननीय सदस्या को मालूम नहीं है। वह स्कूलें सिर्फ कागजों में चलती थीं, बालकों की उपस्थिति नहीं थी, मास्टर कभी जाते नहीं थे।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, यह बिल्कुल गलत है। मैं उनको चुनौती देती हूं। हो सकता है एक दो पर्सेन्ट चालू नहीं हुए हों बाकी मैंने लिख-लिख कर दिया है गवर्नर को भी, मुख्य मंत्रीजी को भी, स्कूलें चल रही थीं लेकिन चलती हुई को इन्होंने बन्द किया।

श्रीमती तारा भण्डारी : अच्छा आप ही थीं क्या शिक्षा मंत्री। तब तो ठीक है आप अपनी सेफ्टी कर लीजिये।

सभापति महोदय बढ़ चढ़ कर बात करते थे, महिला, महिला, महिला और जब महिला बोलने को खड़ी हो गयी तो इन्हें बरदाश्त ही नहीं हो रहा है। सब एक से बढ़ कर एक महिला की खिलाफत करने के लिये खड़े हो गये।

श्रीमती कमला : थोड़ा आप भी मर्यादा रखो।

श्रीमती तारा भण्डारी : देखिये, जब आपकी बारी आयेगी तब यह पाठ हम आप से सीख लेंगे।

सभापति महोदय, बहुत व्यवधान डाल दिया इन लोगों ने। अब आप अंकुश लगायें तो मैं अपनी बात कह सकूं। हमारी सरकार ने जो अन्यान्य क्षेत्रों में कार्य किये थे और जो उसका आज नतीजा है गांवों में इतने स्कूल खुल गये....

श्री परसादीलाल मीणा : बन्द हो गये।

श्री सभापति : यह बहुत बुरी बात है। कृपया शांत रहें, बोलने दीजिए माननीय सदस्या को।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के ढाई वर्ष और कांग्रेस के पांच वर्षों का आज कम्पेरीजन करवा लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है। इतने स्कूल खोलें, इतने अस्पताल खोलें। डाक्टरों की पोस्ट चालीस वर्षों में चार हजार...।

श्री हीरालाल इन्दौरा : सभापति महोदय, यह तो डाक्यूमेन्टरी प्रूफ है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह अच्छी बात नहीं है। माननीय धनखड़ जी 35 मिनट तक बोले, इधर से एक शब्द नहीं बोला गया। आप इनको सुन नहीं सकते, यह अच्छी बात नहीं है। कृपया शांत रहें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह बिल्कुल विपरीत बात कह रही हैं उसको कौन सहन करेगा।

श्री सभापति : आप अपना टाइम आये तब अपनी बात बता दीजिऐगा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : कौन-सी स्कूलें खोल दीं, कौन से हास्पिटल खोल दिये....।

श्री सभापति : कोई बात नहीं है, क्या

(श्री सभापति)

हो गया। आप अपने पर संयम रखिये। आपको बहुत समय मिलेगा। आपके मैम्बर बोल रहे हैं उनको बता दीजिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, आंकड़े कागजों में हैं, रिकार्ड में विद्यमान हैं। चालीस वर्षों में चार हजार डाक्टरों को नियुक्ति दी होगी तो पता नहीं, यहां ढाई वर्षों में चार हजार से अधिक डाक्टरों की नियुक्ति की है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध करवायी। इस एक साल में उन अस्पतालों का क्या हाल हुआ है वह भी, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहती हूं। उसका अध्ययन करवायें कि आज ग्रामीण क्षेत्रों की क्या हालत है। मास्टर जाना नहीं चाहते, डाक्टर जाना नहीं चाहते, महिला डाक्टर जाना नहीं चाहती। यह सब सुनने की हमको सहन शक्ति बनानी चाहिए। आप भी जायेंगे अपने क्षेत्रों में तो जनता पूछेगी कि विकास की बात आती थी तब तो आप विरोध करते थे अब आप किसलिये आये हो। मैं समझती हूं आपको, हमको मिल-जुलकर राजस्थान के विकास की गंगा में अपनी भागीदारी बनानी चाहिये।

सभापति महोदय, बार बार जिक्र किया जा रहा था कि राष्ट्रपति शासन में कौनसी योजनाएं बंद कर दीं। दो-चार तो मैं ही बता दूं। मेरे यहां सूकड़ी इनंनडेशन नाम से एक योजना मंजूर हुई। वह योजना या तो भरतपुर में चलती है या यह हमारे इलाके में पहली बार चालू हुई। यह सूकड़ी इनंनडेशन योजना दो करोड़ रुपये में दो हजार से ज्यादा हैक्टेयर में सिंचाई करने वाली थी। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की समझ में यह बात आयी कि यह काश्तकारों के लिये अच्छी योजना है, यह उनके विकास को गति देने वाली है और खेती के लिये बहुत ही फलदायक योजना है। उन्होंने इस योजना की मंजूरी दी। उस योजना के तहत साठ लाख रुपये खर्च हुए। आठ कंटूर बने। आज एक वर्ष हो गया, राष्ट्रपति शासन में उस योजना का पता नहीं, यह फिर उचकेंगे इनके स्प्रिंग लगी हुई है, परन्तु, सभापति महोदय मैं बताती हूं आपको कि उस योजना का मुख्य डिजाइन बार-बार मंजूर होता रहा, बार-बार अस्वीकृत होता रहा। टेण्डर मांगते हैं टेण्डर केन्सिल करते हैं। लगता है कि टेण्डर अभियंताओं की समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात है और क्या नहीं है। आज एक वर्ष से मेरी वह योजना बन्द पड़ी हुई है। कंटूर टूटने शुरू हो गये हैं और पूछते हैं पेयजल योजना बनायी थी सिरोही जिले में। पेयजल संवर्द्धन की सिरोही की एक करोड़, 19 लाख की योजना थी, शिवगंज की एक करोड़ 51 लाख की योजना थी जिसकी सुबह मैं चर्चा कर चुकी हूं। दोनों योजनाएं राष्ट्रपति शासन में तोड़-मरोड़ दी गयी और आज सिरोही की योजना का तो कहीं पता भी नहीं है कि योजना है कहां। वर्षों से जो लोग पेयजल के लिए तड़प रहे थे, आज उन योजनाओं को समाप्त कर देने के कारण हमारी स्थिति यह हो रही है। इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ कहेंगे तो आप उसको वो नहीं करेंगे।

बार-बार पंचायतों को भंग करने की बात बतायी। 1986 में नगरपालिकाएं भंग की थीं। चुनी हुई नगरपालिकाएं कांग्रेस

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सरकार ने भंग की थीं और 1990 तक कांग्रेस सरकार रही। 1986 से 1990 तक उन नगरपालिकाओं के चुनाव क्यों नहीं कराये गये ? सभापति महोदय, बात बहुत लम्बी है, समय नहीं है परन्तु इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो सूकड़ी इननडेशन योजना हमारी खतम करने की साजिश चल रही है, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगी कि यह योजना दिनोंदिन महंगी होती जा रही है कृपया यह कहां तक आ गयी है इसके बारे में जानकारी लेकर उसे मंजूरी दी जाये और उसका काम पुनः शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाये।

सभापति महोदय, मेरे यहां रावी-व्यास का पानी नहीं है यमुना का जल भी नहीं है लेकिन सिरोही जिला चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है उसमें कैचमेंट एरिया बहुत है। वहां पर आप छोटे-छोटे बांध बना सकते हैं. वहां पर छोटे-छोटे एनीकट बना सकते हैं। वहां पर छोटी-छोटी लिफ्ट सिंचाई योजनाएं बन सकती हैं। सभापति महोदय, मुझे कहने मे बड़ा दर्द होता है कि एक बार मेरे यहां फेमिली प्लानिंग की एक मीटिंग हुई, कलेक्टोरेट में मीटिंग चल रही थी, सी एम. एच. ओ. को जब यह पूछा गया कि सिरोही की जनसंख्या बराबर की बराबर क्यों आती है तो हमारे सी. एम. एच. ओ. बोले कि यहां पर ग्रोथ नहीं है। सभापति महोदय, ग्रोथ तो है लेकिन 16 वर्ष का बच्चा अपने धंधे की तलाश में माइग्रेट कर जाता है। हमारे किसान समृद्ध नहीं, मण्डी व्यापार समृद्ध नहीं और किसी भी तरह के रोजगार की वहां पर गुंजाइश नहीं। इस कारण से हमारे बालक 16-17 वर्ष के होते ही गुजरात पलायन कर जाते हैं, साउथ इण्डिया में चले जाते हैं, अन्य-अन्य प्रान्तों में चले जाते हैं। मेरा आज सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सिंचाई के साधनों को सुदृढ़ बना कर हमारे काश्तकारों की बहबूदी लायी जाये और कुछ रोजगार के साधन जुटा करके हमारे नौजवानों को एंगेज किया जाये ताकि सिरोही जिले से माइग्रेशन बन्द हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, सारा समय मेरा इन्होंने ले लिया और आपने घंटी बजा दी। दो बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी।

अभिभाषण में हैण्डपम्प संधारण की बात कही है कि दोहरी व्यवस्था को खतम करेंगे। यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है। पर इसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि दोहरी व्यवस्था तो आप जरूर समाप्त करें लेकिन हैण्डपम्प संधारण का काम पी. एच. ई. डी. को सुपुर्द कर दें ताकि जनता को पेयजल मिलता रहे।

इसी तरीके से इस अभिभाषण में ग्रामीण आवासीय योजना बनाने की बात कही है। सभापति महोदय, ग्रामीण आवासीय योजना की बात वास्तव में धन्यवाद के लायक है और बहुत प्रशंसनीय है। परन्तु एक बात कहना चाहूंगी, पहले भी एक योजना बनी थी 'इन्दिरा आवास योजना' उसकी आज क्या हालत है ? इन्दिरा आवास में कोई रहना नहीं चाहता। आधे तो गिर

(श्रीमती तारा भण्डारी)

गये, आधे टूट गये। सारे के सारे इन्दिरा आवास खाली पड़े हैं। मेरा सदन के माध्यम से मंत्री परिषद् को निवेदन है कि योजना ऐसी बनायें जहां ग्रामीण जाकर बस सकें। सरकार का चूना, पत्थर, पैसा खराब करके जो इन्दिरा आवास बनाये गये हैं उनकी दुर्गति हो रही है। ऐसे आवास ना बनाकर कुछ अच्छी योजनाएं बनायें जिससे ग्रामीण अपने पशुधन के साथ उन घरों में रह सकें।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगी। पंचायतों में सचिव लगा रखे हैं। कहीं तीन पंचायतों पर एक सचिव है, कहीं चार पंचायतों पर एक सचिव है। कहीं-कहीं तो पचायतें इतनी बड़ी हैं सभापति महोदय, जो नगरपालिका के लायक हो गयी हैं, उनके साथ तीन-तीन पंचायतें जोड़ी हुई हैं। सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि जितनी भी बड़ी पंचायतें हैं वहां एक पंचायत पर एक सचिव लगाया जाये और अगर सचिव की कमी है तो दो पंचायत पर एक सचिव लगाया जाये। ग्राम पंचायतों के पास आज बहुत काम है और सारी की सारी विकास योजनाएं जो गांवों में चलती हैं वह ग्राम पंचायतों के माध्यमों से चलती हैं। एक सचिव तीन-तीन (पंचायतों) का होता है। किसी को आवश्यकता हो और सचिव को ढूंढें तो एक्स नहीं वाई होगा। वाई वहां नहीं उसमें होगा। सचिव कहीं मिलता नहीं और लोगों के काम समय पर नहीं होते। इसलिये जनता का काम समयबद्ध हो, सरकार की योजनाओं का अच्छा सफलतापूर्वक परिपालन हो जाये इसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी पंचायतों में एक सचिव, छोटी पंचायतों में दो सचिव लगायें।

सभापति महोदय, महिलाओं का रिजर्वेशन तो आपने तय कर लिया है मंजूर कर लिया है। नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों में आज महिलाओं का रिजर्वेशन रख दिया है। महिलाओं के मामले में हमारी सरकार ने पिछली बार भी बहुत काम किया था। छात्राओं को बड़ी रियायतें दी थीं। छात्रवृत्ति के अन्य-अन्य साधन जुटाये थे। मेरा इतना आग्रह है, जिसे कहना चाहिये सुझाव है कि जब आपने रिजर्वेशन को मान लिया है तो लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभा के चुनावों में भी महिलाओं को रिजर्वेशन देने की व्यवस्था के लिये राजस्थान पहल करें।

सभापति महोदय, मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये तो धन्यवाद करती हूं साथ ही, सारे सदन से, इधर बैठे और उधर बैठे सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर एक सहमति करके धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदय, मैं इस सदन में पहली बार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। गये तीन-चार दिनों से तीन शब्द सुनने को मिले संवेदनशीलता, स्वच्छ प्रशासन और विकास की गंगा। मेरा तीनों के बारे में बारी-बारी से कहना है कि विकास की गंगा की जगह माननीय मुख्य मंत्रीजी पानी की गंगा बहा देंगे तो समझ

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

लेंगे कि राजस्थान का पूरा विकास कर दिया। लेकिन पानी की गंगा बहाने के लिये कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसके द्वारा यह कहा जा सके कि सिंचित क्षेत्र की बात कही गयी है या पेयजल की बात कही गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि यह संवेदनशील सरकार है। संवेदनशील और स्वच्छ सरकार बारे में मैं दो भ्रष्टाचार के नमूने अभी प्रस्तुत करता हूं। पहला यह कि भारतीय जनता पार्टी के गत शासनकाल में गम्भीर अनियमितताएं प्रशासनिक देखी-अनदेखी से हुई और मनमाने ढंग से गरीब जनता पर जुल्म किये गये। भारतीय जनता पार्टी के काल में जो भूमि हड़पने के गिरोह हैं, जो अच्छी से अच्छी जमीन लेने के लिये गिरोह बने हुए हैं उनके द्वारा साजिश की गयी। राजस्थान के जाने-माने विधायक, जो इस विधान सभा में 10 साल से विधायक रहे, स्वतन्त्रता सेनानी, श्री पी. के. चौधरी जी की विधवा श्रीमती रेवा चौधरी को भी नहीं बख्शा गया। उनके साथ यह हालत हुई कि श्रीमती रेवा चौधरी की कुक्कुटशाला जो मैन अजमेर रोड पर स्थित है, जिसके लिये 1962 में 10 बीघा जमीन लीज पर दी गयी थी उस कुक्कुटशाला की जमीन का मामला माननीय राजस्व मंत्रीजी की सुनवाई में चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी का जो गत सालों का शासन रहा था उसी की स्वच्छ प्रशासन और संवेदनशीलता की बात आपको नंगे सत्य के रूप में बता रहा हूं, इसमें तारीख पेशी पड़नी थी माननीय राजस्व मंत्रीजी के यहां लेकिन अचानक एक दिन मालूम हुआ कि मुख्य मंत्रीजी के यहां उस पत्रावली को कुछ लैण्ड ग्रेबर्स, जो इस जमीन पर निगाह रखते थे, कहने पर मंगा लिया गया और सारे कानूनों को ताक में रख कर उस लीज को केन्सिल कर दिया गया और श्रीमती रेवा चौधरी को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। एक विधवा के साथ में आपके भारतीय जनता पार्टी के राज में यह हुआ जो कि एक नंगा सत्य है। इतना ही नहीं उस भूमि का कब्जा लेने के लिये आदेश भी दे दिये गये। यही नहीं श्रीमती रेवा चौधरी, जो कि विधवा है, इस फैसले की नकल भी नहीं दी गयी जिसका कि हलफनामा भी उन्होंने दिया। इसके अतिरिक्त उस पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके कार्यवाही की और उस भूमि को नीलाम कर दिया गया। क्या ऐसा व्यवहार + + + नहीं है? यह संवेदनशील सरकार है, सेन्सिटिव गवर्नमेंट है? यदि आपकी संवेदनशीलता की यही परिभाषा है तो धन्य है। आशा है सरकार इस कार्य की पूर्ण जांच करवा कर सदन के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

दूसरा, आपकी स्वच्छता, संवेदनशीलता और भ्रष्टाचार का नमूना मैं पेश कर रहा हूं। यह आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस दिसम्बर के महीने में बनी उसी के भ्रष्टाचार का दूसरा नमूना प्रस्तुत कर रहा हूं। भूमि के रूपान्तरण के बिना ही रिहायशी परिसर का नक्शा पास। यह अखबार 23 दिसम्बर की राजस्थान पत्रिका है। इसमें लिखा हुआ है, माननीय सभापति महोदय, कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने अजमेर रोड पर एक भवन निर्माण

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

को कृषि भूमि से आबादी में रूपान्तरित किये बगैर रिहायशी परिसर बनाने की इजाजत देकर नक्शा पास कर दिया और उस पर 92 फ्लैट बन गये हैं जिनकी कीमत करोड़ों नहीं हैं बल्कि करोड़ों से ज्यादा है। उसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने यह भी कहा, एक संस्था मोहन एन्टरप्राइजेज के नाम से नक्शे पास किये गये और यह भी कहा गया कि आप इसकी रूपान्तरण राशि भी जमा करवा दें, जबकि रूपान्तरण राशि जमा नहीं करवायी गयी है।

एक तरफ तो जयपुर की जनता ने, राजस्थान की जनता ने 1982 में रूपान्तरण शुल्क जमा करा दिया, वह आज तक कृषि भूमि है उनकी। क्या वजह है कि आज एक गरीब, एक छोटा-सा व्यवसायी, एक छोटा सा कर्मचारी मकान बनाता है तो उसके मकान बनाते समय इन्सपेक्टर चले जाते हैं जे डी. ए. के और पांच दस हजार रुपये लेकर आते हैं। आपके संवेदनशील प्रशासन का नंगा सबूत साबित करने के लिये दूसरा तर्क इस तरह का है कि भूमि रूपान्तरण के बिना ही इस तरह से यह नक्शा पास होता है, यह अपने आप में विसगति है।

इसके अलावा मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा। सांगानेरी गेट के बाहर एक बहुमंजिला होटल है उस होटल की बालकनी से, उस होटल के अन्दर खाना खाते हुए आदमी के हाथ से अगर चम्मच गिर जाये तो सड़क पर चलते हुए आदमी के ऊपर आकर वह चम्मच गिरेगा। ऐसी स्थिति है यहां के जयपुर विकास प्राधिकरण के मान्यता देने की, अनुमति देने की। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं ? यह आपकी सरकार के नमूने हैं इसको स्वच्छ प्रशासन आप मानते हैं तो आपकी परिभाषा आपको मुबारक।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं जिस जिले से आया हूं उस दौसा जिले से 80 प्रतिशत सीटें कांग्रेस को मिली हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की नीति को नकारा गया है। आपकी जो 85 सीटें थीं, माननीय सभापति महोदय, उसकी जगह 95 ही सीटें मिली हैं। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो प्रस्तुत किया गया है वह पीले रंग से इसलिये ग्रस्त है कि इस सरकार की स्थिति स्वस्थ नहीं है। यह पीलिया से ग्रस्त है इसलिए यह पीले रंग का ही पत्र है। इसमें राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें शिक्षा के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, जुडिशियरी जो कि राजस्थान का एक अभिन्न अंग है उसके बारे में इसमें कोई मेन्शन नहीं किया गया है। साथ ही मेडिकल एण्ड हैल्थ के बारे में भी इसमें कुछ नहीं कहा गया है और रोजगार के बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यह सरकार की नीति, घोषणा, जो आगे सरकार करना चाहती है उसको क्रियान्वित करने का दस्तावेज आता है। इस दस्तावेज में इन बातों का वर्णन नहीं होना यह बताता है कि सरकार ने सर्वांगीण दृष्टिकोण से, समुचित दृष्टिकोण से कोई योजना नहीं बनायी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें पूर्वी राजस्थान में सिंचाई के लिये और पेयजल के साधनों के विकास के बारे में कोई योजना नहीं बतायी गयी है और इससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होता है। पूर्वी राजस्थान के साथ

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

हमेशा ही पक्षपात होता रहा है और इस अभिभाषण के द्वारा भी पक्षपात ही दिखाई देता है, क्योंकि हमारे यहां कोई मेजर योजना नहीं बनायी गयी है।

इसके अलावा अवैध खनन का कार्य. माननीय सभापति महोदय जगह-जगह हो रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं और प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। शिक्षा की स्थिति यह है कि आज स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। अध्यापक नहीं जा रहे हैं और आपकी सरकार ने पांच हजार स्कूल बंद कर दिये। यह एक स्वच्छ प्रशासन और संवेदनशीलता का पांचवा नमूना है। इसके अलावा यह भी बात है कि स्कूल में बच्चों के पेयजल के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। बोर्ड की परीक्षाओं में विद्यार्थियों को 50 और 60 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है जबकि आपका यह कानून भी है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 है, उसका भी ख्याल नहीं किया गया। एक तरफ आपने कानून बनाया है दूसरी तरफ बांदीकुई के परीक्षार्थियों को, जो दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्र हैं उनको 52 किलोमीटर दूर दौसा भेजा जा रहा है।

इसके अलावा जुडिशियरी के बारे में इस अभिभाषण में ये सारी बातें गायब कर दी गयी हैं।

(14.53)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके समक्ष यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय में 32 में से मात्र 18 जज ही नियुक्त हैं और ऐसी स्थिति में न्याय जो कि त्वरित मिलना चाहिए उसमें भी बड़ा व्यवधान आ रहा है। इसके अलावा राजस्थान जुडिशियरी सर्विस रूल्स, 1962 के तहत पांच साल का अनुभव रखने वाला व्यक्ति ही राजस्थान जुडिशियरी सर्विस में आ सकता था, वह बात अब लागू नहीं की गयी है। यह प्रोविजन वापस लागू किया जाये। इसके अलावा एक यह भी स्थिति है कि कांग्रेस की सरकार ने वकीलों के लिये नीति नगर की घोषणा की थी और नीति नगर की घोषणा के बाद पूरे राजस्थान भर में वकीलों से पैसे तो लिये पर यह दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद नीति नगर की घोषणा की कार्यवाही को बंद कर दिया गया और वकीलों को नोटिस दे दिये गये कि वे पैसे लेने चाहें तो रिफण्ड करा लें। इस तरह से नीति नगर की योजना जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बंद की गयी वह अपने आप में एक गलत बात है और वकीलों की देखी-अनदेखी करना है। यह सब संवेदनशील सरकार की बात नहीं है।

इसके अलावा मैं मेडिकल और हैल्थ के क्षेत्र में यह कहना चाहूंगा कि कौन नहीं जानता है कि राजस्थान में गये चार साल में आपका शासन रहा उसमें सेल्फोस की गोली खाने से करीब हजार आदमी मरे। एक हजार आदमी, माननीय सभापति महोदया, गये चार साल में सेल्फोस की गोली, जो एल्यूमिनियम फास्फेट होता है, उसको खाने से मर गये जिसका इस संवेदनशील सरकार ने कुछ नहीं किया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

आज एक छोटा सा बच्चा जाता है और चूहे मारने की दवा के नाम पर, अनाज में रखने की दवा के नाम पर सेल्फोस की गोली लेकर आ जाता है और नतीजा यह निकलता है कि वह आत्महत्या कर लेता है। आजकल तरह-तरह के खाद्य पदार्थों में मिला कर भी इसको जीवन का अन्त करने के लिये भी षड़यंत्रकारी गिरोह काम में ले रहे हैं। यह संवेदनशील सरकार क्या इस तरह के जो पदार्थ हैं उनको बेचने पर कोई रोक लगायेगी? इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि डाक्टर्स टाइम पर नहीं बैठते हैं और ज्यादतर डाक्टर्स को आपके शासन-काल में, भारतीय जनता पार्टी के शासन-काल में गांवों में भेजा गया वे डेली बड़े शहरों के लिये अप डाउन करते हैं और अपना काम अंजाम नहीं देते हैं। शाम के समय चिकित्सालय में कोई भी डाक्टर नहीं बैठता है। कहीं कोई सर्जन है तो सामान नहीं है और सामान है तो स्पेशलिस्ट नहीं है।

यही स्थिति सड़क यातायात की है। पंचायतों में सम्पर्क सड़क की बात कही गयी लेकिन पंचायतों में सम्पर्क सड़क की कोई बात नहीं है।

रोजगार के बारे में अभिभाषण में कुछ भी नहीं बताया गया है कि किस तरह आने वाली सरकार युवकों को रोजगार दिलाने के अवसर प्रदान करेगी।

इसके अलावा बिजली के बारे में मेरा यह कहना है कि बिजली के बारे में बहुत-कुछ बढ़ा-चढ़ा करके कहा गया। आंकडों की इस दुनिया में, भूल-भुलैया में जनता को रखना चाहते हैं उससे कोई भी मकसद नहीं निकलेगा। जनसाधारण आंकड़ों की दुनिया में नहीं जाना चाहता। जन साधारण यह चाहता है कि सरकार उसको क्या देने वाली है, क्या करने वाली है। मैं आपको एक निवेदन करूं कि यदि ट्रांसमिशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज अगर घटा लिये जाते हैं, जो कि राजस्थान में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में चार या पांच प्रतिशत है तो ऐसी स्थिति में हमें करीब 20 करोड़ रुपये का फायदा होगा। बिजली के बारे में हमारी राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। बिजली की चोरी और लॉसेज हो रहा है इसके लिये कोई भी कारगर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। हां, कारगर कदम इस सरकार के द्वारा जरूर उठाये जा रहे हैं, माननीय सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि संवेदनशील सरकार का नमूना है कि दवे साहब का एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथी बार समय बढ़ा दिया गया है। यह संवेदनशीलता और स्वच्छ प्रशासन की ही देन है। अगर ऐसा ही आपका संवेदनशील प्रशासन है ऐसा ही स्वच्छ प्रशासन है कि एक आदमी जो रिटायर हो गया है उसके बाद भी उसका समय निरन्तर बढ़ाया जाये तो मैं समझता हूं कि यह किसी भी तरह स्वच्छ प्रशासन नहीं कहा जा सकता है और इसमें बायस्ड अपोजिटनेस झलकती है।

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये कुछ भी नहीं किया गया है। कृषकों को जो बिजली दी जा रही है वह, सभापति महोदया, रात को 12 बजे आती है। जब कृषक खेत में

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

जाता है और क्यारी में बैठता है तो मालूम पड़ता है कि पानी बंद हो गया, तो वह वापस मुरझाया हुआ चेहरा लेकर आ जाता है और फिर 3 घण्टे तक बैठा रहता है और इस प्रशासन के द्वारा जो बिजली दी जाती है उसकी यह स्थिति है कि फिर 2 घण्टे बाद बिजली आती है पांच मिनट के लिये। इस तरह से बिजली एक-एक कर समय-समय पर आती है। किसान की साल भर की कमाई इन दिनों में राज्य सरकार के द्वारा दी गयी बिजली पर आश्रित है जिस पर किसी भी तरह कोई गौर नहीं किया गया है। इस प्रशासन ने अभी तक ऐसी कोई उत्तरदायित्वपूर्ण घोषणा नहीं की है। इस सदन के सामने आज बिजली की भयंकर समस्या है और बिजली की समस्या इतनी भयंकर है कि आने वाले दिनों में, मैं समझता हूं, राजस्थान में जनद्रोह, जो कि कृषकों में जगह-जगह व्याप्त है, उभर कर आयेगा और आपकी संवेदनशील सरकार इसके लिये कुछ भी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको देखी-अनदेखी कर रही है, यह किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। बिजली की चोरी को सतर्कता विभाग नहीं रोक पा रहा है।

इसके अलावा उद्योगों को जो बिजली दी जा रही है वह तत्काल बंद कर दी जानी चाहिए। उद्योग 15-20 दिन बाद भी पनप सकते हैं लेकिन खेती अभी नष्ट हो गयी तो दुबारा पनप नहीं सकती। ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं, सरकार अपना रवैया बदलेगी। कृषकों को कम से कम 12 घण्टे बिजली निर्बाध रूप से दी जाय। बिजली के उच्च अधिकारी हैं वह बिजली सप्लाई के दौरान जगह-जगह ग्रिड स्टेशन पर बैठे रहें और देखते रहें चौकसी करते रहें। बिजली की सप्लाई के लिये सघन अभियान चलाया जाय यह मेरा निवेदन है।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हैण्डपम्प जगह-जगह खराब पड़े हैं। राजस्थान के हर गांव में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक लज्जाजनक स्थिति में, एक शर्मनाक स्थिति में इस तरह का कार्य कोई आदमी कर देता है तो उसको हर जगह शर्मिन्दा होना पड़ता है, उसी तरह से हर जगह हैण्डपम्प शर्माया हुआ अपना सैल्यूट डाउन करता हुआ हर गांव में मिल जायेगा। किसी में भी पानी नहीं आ रहा है। इसके रख-रखाव की स्थिति यह है, सभापति महोदया, आज की स्थिति में माननीय मंत्री महोदय भी यह नहीं बता सकते हैं कि इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी किस की है, पंचायत समिति की है या पी. एच. ई. डी. की है, यह दोहरी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। लेकिन यह व्यवस्था खत्म नहीं हो रही है। जब कृषक पंचायत समिति में जाते हैं तो वह कहते हैं कि हम माइनर डिफेक्ट दूर कर सकते हैं, मेजर डिफेक्ट दूर नहीं कर सकते। मेजर डिफेक्ट के लिये जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं हैं- आप पंचायत समिति में जाइये। इस तरह से भूल-भुलैया में कृषकों को, ग्रामीवासियों को धक्के खाने पड़ते हैं।

(15.00)

यही सरकार हैण्ड पम्पों की व्यवस्था कौन करेगा और कौन उसकी रिपेयरिंग का काम हाथ में लेगा, यह व्यवस्था नहीं कर पायी। तो मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

यह बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में हैण्ड पम्पों के बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है जब कि हैण्ड पम्प एकमात्र ग्रामीण जनता के लिये पेयजल का साधन बना हुआ है।

इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बांदीकुई निर्वाचन क्षेत्र जहां से मैं विजयी होकर आया हूं, में पानी की व्यवस्था बहुत क्षीण है और पानी की सप्लाई बहुत कम हो रही है। कई जगह टंकियां बन गयी हैं, दो जगह, हिंगोटा में और गुडलिया में भी हैं लेकिन विद्युत सम्बन्ध बिजली विभाग से नहीं मिल पा रहा है इसलिये पानी की सप्लाई बन्द हो रही है। जब यह सरकार इतनी संवेदनशील है तो क्या 6 और 8 महीने में बिजली विभाग से बिजली का कनेक्शन लेकर टंकी में पानी नहीं डलवा सकते? लेकिन यह सरकार कतई संवेदनशील नहीं है, यह सरकार बिलकुल उदासीन है, निष्क्रिय है।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज जल का स्तर नीचे जा रहा है। इस जल का स्तर नीचे न जाने के लिये कोई भी योजना स्थायी तौर पर नहीं बनायी जा रही है। यह समय आप लोगों को नहीं बख्शेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी मिलेगी। समय रहते जल का स्तर जो नीचे गिर रहा है इसको उठाने के लिये आपको चाहिए कि वर्षा का पानी जो बहकर चला जाता है, जो कि बहुत बड़े भू-भाग में चला जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है उसको जगह-जगह सरकार एनीकट बनाकर, मिनी डेम बनाकर रोके। उसको रोके रखने से सिंचाई के साधनों में और सिंचित क्षेत्र भी वृद्धि होगी। इसके अलावा, माननीया सभापति महोदया, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो जल का स्तर है वह भी सुधरेगा, हैण्ड पम्पों में भी पानी आ सकेगा और कुओं में भी पानी आ सकेगा। आज कुओं में पानी आने के तो दूर के दर्शन हो गये हैं। ऐसी स्थिति में एनीकट और छोटे-छोटे मिनीडेम के लिये इस अभिभाषण पत्र में कोई प्रस्तावना नहीं की गयी है। इसी कारण यह एक एकांगी अभिभाषण पत्र कहा जाना चाहिए और इसको सर्वांगीण अभिभाषण-पत्र कहना राजस्थान की जनता के साथ धोखा करना है।

हाउसिंग बोर्ड के लिये, आवासीय समस्या के लिये अभिभाषण-पत्र में कहा गया है लेकिन कौन नहीं जानता कि जिस आदमी को दो हजार रुपये मिलते हैं उससे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड 24 सौ और 28 सौ की किश्त मांगता है। क्या यह सत्य नहीं है? यदि यह नंगा सत्य है तो आज तक बी.जे.पी. की सरकार ने इसके बारे में क्या किया? आप गरीबों का भला ही नहीं करना चाहते हैं। जो दो हजार रुपये कमाता है उससे आप चाहते हैं कि वह दो हजार की जगह 20 हजार रुपये अनुचित साधनों से कमाये और फिर हाउसिंग बोर्ड भी एक अजूबा करके दिखाये कि दो हजार की सेलेरी और 2400 रुपये की किश्त अदा करे। मैं यह चाहूंगा आपके माध्यम से कि आवासीय मंत्री इस ओर ध्यान दें और वेतन से ज्यादा मासिक किश्तें जो कि गरीब जनता से मांगी जा रही हैं और उपभोक्ताओं

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

से मांगी जा रही हैं इसमें नयी प्रणाली बतायी जाय।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गत दिनों में जयपुर में क्या स्थिति कर दी है यह कहते हुए कि हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, रामनिवास बाग में आवागमन बन्द कर दिया गया है लेकिन उसका परिणाम क्या रहा ? परिणाम यह रहा कि पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, पैट्रोल ज्यादा खर्च हो रहा है, समय ज्यादा खर्च हो रहा है। खुद सरकार यह चाह रही है कि पर्यावरण में धुंआ बढ़े, सरकार यह चाह रही है कि पैट्रोल ज्यादा खर्च हो। सड़कें आपके पास उतनी ही चौड़ी हैं, उतनी ही लम्बी हैं इस सारे ट्रैफिक को आप किधर से निकालेंगे। कोई व्यवस्था नहीं, कोई विकल्प नहीं, संवेदनशीलता का नाम-निशान नहीं। आप यह मानते हुए कि रामनिवास बाग में चन्द लोग घूमने आते हैं, आज कितनी जनता के साथ यह एक तरह से गलत कार्य किया है। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि जयपुर को समस्याविहीन नगर बनाकर छोड़ेंगे। यह बहुत ही एक धन्यवाद की बात है माननीय मन्त्री महोदय के लिये कि वे जयपुर को समस्याविहीन नगर बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन काश यह घोषणा मुख्य मन्त्री महोदय पूरे राजस्थान के लिये करते कि पूरे राजस्थान को समस्याविहीन बनाया जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समस्या की जगह दुविधा ही बढ़ती जा रही है।

मेरा यह भी कहना है कि पंचायतों के चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं, न ही इस अभिभाषण में कोई निश्चित तिथि बतायी गयी है कि अमुक तारीख तक पंचायतों के चुनाव करा दिये जायेंगे। तो क्या ऐसी स्थिति थी कि पंचायतों के जो सरपंच जीते हुए थे जो वार्ड पंच थे उनको नहीं रखा जाये ? अभी भी सरकार पुनर्विचार करे और जो भूतपूर्व सरपंच और भूतपूर्व पंच हैं उनको पुनर्स्थापित करे जब तक कि चुनाव नहीं हों। यह स्वस्थ प्रजातान्त्रिक प्रणाली होगी। 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने उद्घाटन किया लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का, उसका गला घोंटा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतान्त्रिक स्तर पर चुनी हुई पंचायतों को निरस्त करके। इस तरह इस सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं वे किसी भी तरह से ठीक नहीं रही हैं।

लॉ-एण्ड-आर्डर की यह स्थिति है कि पंकज सिंघवी हत्याकाण्ड अपने आप में अजूबा है। उसकी जांच और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस जयपुर शहर, कैपिटल के अन्दर हुआ। जो इतने बड़े अधिकारी के पुत्र थे। इस सरकार का इतना रुपया प्रशासन पर खर्च होता है, इतना रुपया पुलिस पर खर्च होता है लेकिन, माननीया सभापति महोदया, उसके बारे में इस सरकार ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखायी।

इसी तरह जो साम्प्रदायिक दंगे हुए उनके पीछे किसका हाथ था ? आपने कहा कि जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आयी, दंगे नहीं हुए। दंगे होंगे क्यों ? ये दंगे करवाने वाले कौन हैं ? माननीया सभापति महोदया सब जानते हैं कि दंगे करवाने वाले कौन हैं। जब दंगे कराने वाले ही यहाँ बैठेंगे तो दंगे पीछे से करेगा

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कौन। ऐसी स्थिति में ... (व्यवधान) हमें विश्वास है कि जब तक आप सत्ता में रहेंगे, कोई दंगे नहीं होंगे।

इसके अलावा सबसे बड़ी घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 10-4-91 को की, दौसा को जिला बनाया गया लेकिन, माननीया सभापति महोदया, यह कितने दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक उप जिले की घोषणा नहीं की गयी है। आज ढाई साल हो गये हैं लेकिन बांदीकुई को उप जिला नहीं बनाया गया है जब कि सारे जो भी सब-डिवीजनल हैड-क्वार्टर्स के आफिस हैं वे बांदीकुई में हैं। उसके लिये काफी कार्यवाही हो रही है लेकिन उप जिला स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार दौसा जिले का उप जिला बांदीकुई को बनाने की शीघ्र घोषणा करें।

इसके साथ ही आज आपने मेरे को जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद देते हुए अन्त में यही निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है इसको मैं पूर्णतया अस्वीकार करता हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय ने जब समय का बंटवारा किया था तब इंडिपेंडेंट्स के लिये भी समय रखा था। हमने कल से नाम दे रखे हैं। अच्छा हो कि आपकी नजर हमारी तरफ भी पड़ती रहे और एक-एक को कल आपने नहीं बुलाया तो एक दो को आज बुला दीजिए, कल एक दो को बुला लीजिए। एक साथ हम बोलना चाहेंगे तो उचित नहीं रहेगा इसलिए इंडिपेंडेंट्स के लिये रिजर्व समय है उसमें हमारी लिस्ट के अनुसार हमको भी बुलाया जाये।

श्री सभापति : नहीं, इसमें नाम है।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं नाम है तो बुलाओगे जब है न। नाम तो बहुत होते हैं।

श्री सभापति : तो सूची के अनुसार ही बुलवाऊंगी।

श्री शिवनाथ सिंह : आपकी नजर पड़े जब है, साहब। क्या करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : सभापति महोदया, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और कुछेक बातें मैं कहना चाहूंगा। जितने भी वर्तमान सरकार ने पिछले तीन साल के कार्यकाल में विकास के कार्य चालू करवा रखे थे उनको राष्ट्रपति शासन के दौरान रोक दिया गया है। उदाहरण के तौर पर पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में सेम की समस्या का समाधान करने के लिये डिप्रेशन नम्बर 8 से एक स्केप का निर्माण कार्य चालू था जिसका 75 पर्सेंट काम पूरा हो गया और राष्ट्रपति शासन के दौरान उसका काम बन्द कर दिया। इसके अलावा सेम की समस्या का समाधान करने के लिये वर्तमान सरकार ने 87 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति दी थी और ग्राम मानकथेड़ा से लेकर भैंरूसीरी तक सेम नाला बना करके 4-5 जगह पर पम्प स्टेशन लगा

(श्री रामप्रताप कासनियां)

कर पानी उठाकर नहरों और डिप्रेशनों में डालने का प्रावधान था परन्तु राष्ट्रपति शासन के दौरान उस स्कीम को भी बस्ते के अन्दर बांधकर पता नहीं उस फाइल को ही कहां गुम कर दिया। इसके अलावा सिद्धमुख कैनाल और कई अन्य जो छोटी डिस्ट्रिब्यूट्रीज थीं जिनका काम चल रहा था वह भी रुक गया। इसके अलावा कांग्रेस के शासन में जितनी भी नहरें पक्की बनी थीं खाले पक्के बने थे उन सबकी आज यह हालत है, किसान आज उससे इतना परेशान है कि जितना पानी कच्ची नहरों, खालों में चलता था उससे आधा पानी हो गया। सारे के सारे खाले टूटे पड़े हैं, सारी की सारी नहरें जगह-जगह से टूटी पड़ी हैं। ईंटें तीन नम्बर, चार नम्बर की यूज की गयी है, सीमेण्ट बिलकुल ही नहीं लगायी गयी। अब इसकी सजा किसान को मिल रही है। जब खाले कच्चे थे उस टाइम अगर कहीं पर पानी टूट जाता तो कम से कम किसान उसको आसानी से बांध सकता था। आज हालत यह है कि न तो उसको मिट्टी उठाने के लिये जगह है और पक्के खाले के अन्दर एक बड़ी परेशानी है कि पानी टूटने के बाद बांधना बड़ा मुश्किल है।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी विकास के काम हुए हैं उनमें बड़ी धांधली हुई है। सारे के सारे जितने भी विकास के काम हुए हैं उनमें सीमेण्ट और ईंट, जो महत्वपूर्ण चीज है, बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी की यूज की गयी है।

इसके अलावा गंगानगर जिले की पिछले 40 वर्षों में उपेक्षा की गयी है। गंगानगर जिले का किसान लगातार कांग्रेस के शासन में आन्दोलन करता रहा है। गंगानगर जिले में आये दिन कोई न कोई नया कानून बना कर किसानों को परेशान किया और किसान बार-बार धरने पर बैठे, जेल गये पर कांग्रेस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वर्तमान सरकार ने अपने पिछले तीन साल के कार्यकाल में जितनी किसानों की समस्याओं का समाधान किया है। कांग्रेस ने अपने 40 साल में इससे डबल समस्या पैदा की है। जिन बातों को लेकर किसान आन्दोलन किया करते थे उन समस्याओं में से 80 पर्सेण्ट समस्याओं का समाधान माननीय मुख्य मन्त्रीजी भैरोंसिंहजी शेखावत ने किया है। मैं उसके लिये इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे जमीन बेचने पर पाबन्दी लगायी थी, किसान अपनी खातेदारी जमीन में से पेड़ नहीं काट सकता था, वह अपनी जरूरत के मुताबिक कोई हल बनाने के लिये या कोई कृषि का औजार बनाने या कोई घरेलू काम के लिये लकड़ी अपनी खातेदारी जमीन में से नहीं काट सकता था। भैरोंसिंहजी शेखावत ने आज किसानों को यह छूट दी है कि वह अपनी खातेदारी जमीन में से पेड़ काट सकता है।

इसके अलावा 5 बीघा नहरी और 10 बीघा बारानी जमीन बेचने पर पाबन्दी लगी हुई थी। सभापति महोदया, एक किसान की पांच बीघा जमीन थी और पांच ही बेटे थे और अगर कोई एक बेटा एक बीघा जमीन बेच कर कोई दूसरा धन्धा करना चाहे या दूसरी जगह सस्ती जमीन है वहां खरीदनी चाहे तो बड़ी परेशानी होती थी। उस परेशानी से भी किसान को मुक्त कर दिया। आज किसान अपनी मर्जी से

(श्री रामप्रताप कासनियां)

चाहे एक बीघा की रजिस्ट्री करवा सकता है। इसके अलावा 1955 से पूर्व की जो जमीन थी उसको दो दो, तीन-तीन बार अलाट किया। कभी 18 हजार रुपये किश्त के कर दिये कभी 20 हजार किये गये, कभी 35 हजार और एक ही जमीन को दो-दो, तीन-तीन बार अलाट कर दिया। माननीय मुख्य मन्त्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने इस काले कानून को समाप्त कर दिया और किसान को दो मुरब्बा जमीन फ्री, बिना किश्त के देने के आदेश दिये।

इसके अलावा जिन किसानों को किश्तों पर जमीन मिली हुई थी किसी किसान ने वक्त पर जमीन की किश्त नहीं चुकाई, फसल अच्छी नहीं हुई या अपनी फसल के पैसे कोई दूसरे काम में ले लिये और किश्त ड्यू हो गयी तो जैसे एक किसान की तरफ 40 हजार रुपये बाकी हैं और 5 हजार रुपये की किश्त ड्यू हुई तो पूरी की पूरी रकम पर 6 पर्सेण्ट एक्स्ट्रा ब्याज लगा कर और किसान के ऊपर बहुत बडा वजन लाद दिया था। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने नियम में परिवर्तन करके एक कानून बना दिया कि जितने पैसे, जैसे 5 हजार रुपये की किश्त ड्यू होती है तो 5 हजार रुपये पर ही ब्याज लगना चाहिये, पूरी रकम पर नहीं लगना चाहिये।

इसके अलावा नोहर फीडर और सिद्धमुख नहर, दोनों की दोनों नहरों का काम माननीय शेखावतजी ने चालू करवाया। एक गंग कैनाल लिंक है, जो वर्षों से अधरझूल में लटकी पड़ी थी और बार-बार किसान मांग करते थे। यह गंग कैनाल किसानों के लिये वरदान है। आज गंग कैनाल लिंक भी चालू करवा दी गयी। इसके अलावा जमीन से सम्बन्धित जो समस्याएं थीं सारी की सारी समस्याओं को, दो-चार बातों को छोड़कर, मांग पत्र में जितनी बातें थीं उनमें से 80 पर्सेण्ट समस्याओं का समाधान हो गया और दो-चार बातें विशेष रूप से रही हैं। मैं, माननीया सभापति महोदया, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपने गंगानगर जिले के किसानों को बहुत राहत दी है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): आपके नेता को हरा दिया।

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय सदस्य आपको ध्यान होना चाहिये कि गंगानगर जिले के अन्दर भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं था और आज हालत यह है कि तीन विधायक यहां पर जीत कर बैठे हैं आपकी सारी की सारी सीटें टक्कर से हारी हैं और आने वाले समय में मैं दावे के साथ कहता हूं....

श्री मोहनलाल मोदी : आपके नेता को हरा दिया आपने।

श्री रामप्रताप कासनियां : सारी की सारी सीटें वहां पर टक्कर में रही हैं और यह भैरोंसिंहजी शेखावत की करामात है कि उन्होंने ...

श्री मोहनलाल मोदी : वह तो तीसरे नम्बर पर गये ना।

श्री रामप्रताप कासनियां · किसानों के, गरीब के, सब काम किये हैं। तीसरे नम्बर पर आपके भी कई नेता हैं पहाड़ियाजी,

(श्री रामप्रताप कासनियां)

दिनेश जोशीजी या देवपुराजी, रमा पायलट, बड़े-बड़े आपके भी लोग ...

श्री मोहनलाल मोदी : बात गंगानगर जिले की हो रही है।

श्री रामप्रताप कासनियां : तो यह जो हारना जीतना है. मोटे रूप से आप यह देखें कि पब्लिक ने मेजोरिटी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चाहा है और गंगानगर जिला जहां पर 11 की 11 सीटें कांग्रेस की आया करती थीं आज जो हालत है वह आपके सामने है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर जिले की 2-4 समस्याएं बची हैं उनका समाधान अगर कर दें तो गंगानगर जिले का किसान जिन्दगी भर आपका अहसान नहीं भूलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पक्के खालों की किश्त माफ करने का निवेदन करूंगा। दूसरा, एक सेम की समस्या है, सैंकड़ों गांव सेम की चपेट में आ गये। आज वहां के किसानों की यह हालत है कि जिस किसान के घर हजारों मन अनाज पैदा होता था, आज उसको न रहने के लिये मकान है, न खाने के लिये अनाज है. न पशुओं के लिये चारा है और वह लोग दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। हालत यह है कि वहां पर, सभापति महोदया, 30-30, 40-40 वर्ष के लड़के कुंवारे ही फिर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई रिश्ता देने के लिये आता ही नहीं और पहले (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय मुख्य मंत्रीजी की बात करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : नहीं तो उस वक्त 14-14 15-15 वर्ष के लड़कों को लोग रिश्ते देने के लिये आते थे। आज तो उनके बाल सफेद हो गये हैं। हालत यह है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है, रिश्ते वाला तो कोई जिक्र ही नहीं करता।

श्री मोहनलाल मोदी : आपके भी हैं ये।

श्री रामप्रताप कासनियां : रिश्ते वाला तो जिक्र ही नहीं करते। तो यह समस्याएं जो हैं, बड़ी भयकर हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता कई बार मौका देखने तो जरूर गये, परन्तु समस्या का समाधान करने की कोई चेष्टा नहीं की। इसके अलावा एक बीमारी और है जो माली रकम लगती है, उस पर सरचार्ज लगता है हुई-बुई प्रणाली के मय सरचार्ज समाप्त की जाये।

एक माननीय सदस्य : आप बन्दोबस्त करेंगे क्या ?

एक माननीय सदस्य : कुंवारों की चर्चा चल रही है।

श्री रामप्रताप कासनियां : तीसरी बात, भाखड़ा प्रोजेक्ट के अन्दर वाटरमेण्ट टैक्स लगता है. वह भी समाप्त किया जाये। इसके अलावा फर्स्ट स्टेज के अन्दर कई नहरें ऐसी हैं जो अभी तक पक्की नहीं बनीं, कई खालें ऐसे हैं जो पक्के नहीं बने। तो मैं यह चाहूंगा कि गंगानगर जिले की बची-खुची जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान माननीय मुख्य मन्त्रीजी करेंगे।

एक बात और कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य बार-बार पंचायत

(श्री रामप्रताप कासनियां)

चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। पंचायत चुनाव आपके कार्यकाल में 13-13 वर्ष तक नहीं हुए और हमने तो यह चुनाव नही करवाये, इसका कारण है, पंचायतों का....

श्री मोहनलाल मोदी : सरपचों को बरखास्त नहीं किया, उनकी जगह ग्राम सेवक नहीं लगाये, उनकी जगह सरपंच ही कायम रहे। यह आपके ध्यान में है या नहीं।

श्री रामप्रताप कासनियां : हमने पंचायतों का पुनर्सीमांकन किया और पचायतों में महिलाओं के लिये....

श्री मोहनलाल मोदी : आप चाहते क्या हैं? ग्राम सेवक ही लगे रहें, वे लूटते रहें। ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदया, आपस में बातें कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : महिलाओं के लिये रिजर्वेशन किया, हरिजनों के लिये रिजर्वेशन किया और राजस्थान की नकल आपकी केन्द्र में सत्ता में विराजमान पार्टी ने की है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : इसके अलावा ...

एक माननीय सदस्य : बढ़िया बोल रहे हैं, बोलने दें।

श्री सभापति : दूसरों को भी अवसर देना है।

श्रीमती कमला (बैराठ) : सभापति महोदया, बड़ी गलती करना और उस पर अनुसरण करना, उसकी पैरवी करना, खुश होना, यह कोई अच्छी बात तो नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनियां : मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं। पंचायतों के चुनाव नहीं हुए, इसका कारण यह है कि हमने पंचायतों का पुनर्सीमांकन किया और महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, हरिजनों को रिजर्वेशन दिया। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदया.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय धनखड़ साहब तीन दिन पहले कह रहे थे कि जिस तरह से केन्द्र के अन्दर एक एम.पी. को अपने क्षेत्र में एक करोड़ रुपये खर्च करने के लिये प्रावधान रखा गया है इसी तरह का प्रावधान राजस्थान में भी होना चाहिए, विधायकों को भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए। तो, माननीय सभापति महोदया, राजस्थान के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले से ही एक विधायक को 10-10 लाख रुपये का निर्माण कार्य करवाने के आदेश दे दिये थे और इसकी नकल।

श्री भीमराज (पाली) : उससे काम थोड़े ही चलता है।

श्री रामप्रताप कासनियां : केन्द्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने नकल की और एक एक

(श्री रामप्रताप कासनियां)

एम.पी. के एरिया में 10-10 विधान सभा क्षेत्र हैं, मैं ज्यादा पढ़ा-लिखा तो नहीं पर दसू-दस सौ, एक करोड़ रुपये बनते हैं।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय सदस्य, आठ-आठ हैं और आप दस बता रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : आप जोड़ लीजिए। दस-दस विधान सभा क्षेत्र में एक...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपना भाषण समाप्त करें और आमने-सामने बात नहीं करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : मुझे तो मौका ही पहली बार मिला है।

श्री सभापति : दूसरों को भी मौका दें।

श्रीमती कमला : नकल की भारत सरकार ने एक करोड़ देकर के, अब आप उनकी नकल करिये। आठ लाख से पचास लाख करके, बहुत अच्छा होगा।

श्री रामप्रताप कासनियां : हमने नकल नहीं की। दिशा-निर्देश देने वालों में से हैं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी। नकल करेगी केन्द्र सरकार। अभी तो देखते जाओ और क्या-क्या होगा और आप नकल करते जाना।

श्रीमती कमला : नकल में भी अक्ल चाहिए।

श्री रामप्रताप कासनियां : इसके अलावा एक बात कांग्रेस के माननीय सदस्य....

श्री नरेन्द्र बुढानिया (सरदारशहर) : आप सही तो बोलो कम से कम।

श्री रामप्रताप कासनियां : कांग्रेस बार-बार कहती है धर्म को राजनीति से अलग करें। यह कोई जंचने वाली बात है? माननीय सभापति महोदया, धर्म के बिना मां-बेटे का रिश्ता खत्म हो जायेगा, बहन-भाई का रिश्ता खत्म हो जायेगा। सारी की सारी बात धर्म पर टिकी हुई है। स्त्री-पुरुष का कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

श्रीमती कमला : कैसे खत्म हो जायेगा?

श्री रामप्रताप कासनियां : धर्म पर सारी की सारी बात, मान-मर्यादा टिकी हुई है। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं....

श्रीमती कमला : सभापति महोदया, यह क्या बात हुई, अगर धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे तो रिश्ते ही खत्म हो जायेंगे।

श्री रामप्रताप कासनियां : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि....

श्रीमती कमला : कैसी अटपटी बात बोल रहे हैं?

श्री रामप्रताप कासनियां : धर्म के बिना....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती कमला : आप धर्म के बिना राजनीति नहीं करेंगे तो रिश्ते कैसे खत्म हो जायेंगे?

श्री रामप्रताप कासनियां : नहीं, आप कहते हो अलग करो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आपस में बात नहीं करें। सुनें।

श्रीमती कमला : धर्म को राजनीति में नहीं मिला लेंगे ?

श्री रामप्रताप कासनियां : आप तो कह रहे हैं कि राजनीति को धर्म से अलग करें। तो मेरा कहने का मतलब है, आज कोई भी व्यक्ति अदालत में जाये और गवाही के अंदर जब वह कटघरे में खड़ा होता है तो सर्वप्रथम उसको उसके मजहब के अनुसार गीता की सौगन्ध, कुरान की सौगन्ध और गुरुग्रंथ की सौगन्ध दिलाई जाती है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब इस तरह से कानून का प्रावधान है, धर्म के अन्दर जब आपने कानून बनाया तो उस वक्त ही कानून के अन्दर यह प्रावधान रख दिया था। फिर क्यों गीता की सौगन्ध, गुरुग्रंथ और कुरान की सौगन्ध खिलाते हो। तो यह जो बेस है, इसमें धर्म राजनीति से अलग नहीं हो सकता और मैं पुनः, माननीय सभापति महोदया....

श्रीमती कमला : शपथ ईश्वर के नाम से लो, पर वोट ईश्वर और धर्म के नाम पर मत लो, इसका अर्थ यह है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप निर्णय नहीं लें।

श्रीमती कमला : आप गलत व्यक्त कर रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : मैं तो सीधे-सीधे बात कह रहा हूं, ज्यादा इतना....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय....

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : हम दोमुंही बात नहीं करते। हम शपथ तो लें ईश्वर के नाम पर और वोट नहीं मागेंगे ईश्वर के नाम पर ?

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय सदस्या, मैं आपके जितना एक्सपर्ट नहीं हूं, अभी नया-नया हूं. जितनी मेरी समझ की बात है, वह मैं बोल रहा हूं फिर भी मैंने जाने-अनजाने में कोई गलत शब्द बोल दिये तो मैं उसके लिये माफी चाहूंगा। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर जिले की दो-चार बातें जो हैं बची-खुची, उनका आप समाधान कर लें तो हम सिर ऊंचा उठाकर चलेंगे और कांग्रेस वालों की अबकी बार गंगानगर जिले में छुट्टी कर देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मुझे तो आज पहली बार मौका मिला और आपने बार-बार घंटी बजाकर मेरे दिल में धड़कन पैदा कर दी। आपने समय दिया इसके लिये मैं आभारी हूं।

जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति : श्री बनवारी लाल शर्मा।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : माननीय सभापति महोदया, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री कालीचरण सराफ विरोध के लिये विरोध मत कीजिये ।... (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल शर्मा : ऐसी बात नहीं है कि विरोध के लिये विरोध कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं । यह एक आधारहीन भाषण है, निराधार है और राजनीतिक भाषण है । यहां पर किसी भी अभिभाषण, जो राज्य सरकार द्वारा तैयार कराया गया हो, में ऐसी झलक मिलनी चाहिए कि अगले वर्ष में विकास के कार्यों में क्या प्रगति होगी और या योजनाओं में क्या प्रगति होगी । इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी की शैली की झलक तो जरूर नजर आती है जो कि चिरपरिचित है । माननीय मुख्य मंत्रीजी विकास के कार्यों में तो कभी रुचि रखते ही नहीं हैं । क्योंकि उनकी हमेशा यह मंशा रहती है कि किसी प्रकार से दूसरे व्यक्तियों, उन्होंने विकास के कार्यों में रुचि नहीं रखी पर दोषारोपण करके लाद देते हैं और उन पर मढ़ देते हैं । माननीय मुख्य मंत्रीजी की विकास कार्यों में रुचि के बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पर जानकारी रखता हूं । नवी विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्रीजी धौलपुर विधान सभा क्षेत्र से ही चुनकर आये थे और वहां की जनता ने....

श्री कालीचरण सराफ : आपको हरा कर ।

श्री बनवारी लाल शर्मा : जी हां, मुझे हरा कर आये थे इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

श्री कालीचरण सराफ : दुःख होगा ।

श्री बनवारी लाल शर्मा : नहीं दुःख नहीं हो रहा है । दुःख यह जरूर हो रहा है कि वहां से भाग खड़े हुए हैं । मुख्य मंत्री होते हुए भी । वहां की जनता ने इतना बड़ा अहसान किया था, वहां से चुनाव जीतकर वे मुख्य मंत्री पद पर आसीन हुए । मुख्य मंत्रीजी ने वहां की जनता के सामने इस प्रकार के वादे किये, विकास की गंगा बहाने की बात कही. उनको लुभावने भाषण देकर, गुमराह करके पद हासिल कर लिया लेकिन तीन साल में मुख्य मंत्रीजी ने विकास कार्यों से तो वंचित रखा ही उस क्षेत्र की जनता को सांत्वना के दो शब्द कहने का भी उनको समय नहीं मिल सका । यह है उनकी विकास कार्यों में रुचि ? तो मैं यह निवेदन करना चाह रहा था, मुख्य मंत्रीजी, मेहरबानी करके केन्द्र पर या दूसरों पर दोषारोपण नहीं करें । क्योंकि जो आपकी योजना थी चाहे वह पानी की योजना थी, चाहे वह बिजली की योजना थी, सन् 90 में जो यहां पर थीं आज उनमें कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ । वहीं की वहीं वह विकास योजनाएं हैं क्योंकि आपने कभी प्रयास नहीं किया । केन्द्र सरकार के जरिये से, अगर जरूरत थी तो सुप्रीम कोर्ट में रेफर करा सकते थे । इतनी ही जरूरत थी तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे । लेकिन आपने उन योजनाओं को पूरा कराने के लिये कोई प्रयास नहीं किया । सन् 84 में धौलपुर थर्मल पावर प्लांट की योजना कांग्रेस सरकार ने प्रस्तावित की थी । आपने बड़े-बड़े वादे किये थे, बड़े बड़े आश्वासन दिये थे लेकिन उनमें आपके प्रयास सफल नहीं हो पाये । मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन जब आपके समर्थित केन्द्र में वी. पी. सिंह जी प्रधान मंत्री थे, चन्द्रशेखर जी आपके मित्र प्रधान मंत्री थे उस

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

समय पर्यावरण मंत्री श्रीमती मेनका गांधी थीं, उनसे आपने उसको क्यों नहीं क्लियर करा लिया। आपने कहा कि मैं अभी 24 तारीख को मिला हूं मैंने प्रयास किया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इस योजना को जितना ज्यादा लम्बा खीचेंगे उतनी ही इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। चार सौ करोड़ की यह योजना थी, आज करीब दो हजार करोड़ पर पहुंच गयी है। आपने कहा कि उन्होंने पोल्यूशन कण्ट्रोल के लिये ऐसे यन्त्र लगाने के लिये आपको आश्वासन दिया है और वह क्लियरेंस दे देंगे। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि ऐसे यंत्रों की कीमत बहुत ज्यादा है। पहले से ही इस प्रोजेक्ट की कीमत इतनी ज्यादा हो गयी हैं। आज एक प्रोजेक्ट में पोल्यूशन एनवायरमेंट कण्ट्रोल के लिये आप कोई यंत्र लगायेंगे उसकी तीस करोड़ की कीमत है और ऐसे तीन यंत्र आप लगायेंगे तब कहीं इसमें आप सफल हो पायेंगे। तो एक अरब रुपये की कीमत और बढ़ जायेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके इस योजना को क्रियान्वित कराने में ज्यादा समय न लेकर प्रयास यह करें कि जल्दी से जल्दी इसको मजूर करायें यदि आपको कांग्रेस पार्टी का कहीं सहयोग है। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हू कि आप पर धौलपुर की जनता का जो भी कर्जा है उसको चुकाने का अभी भी वक्त है। आपको मौका मिला है। जो वादे आपने किये थे उनको पूरा नहीं कर सके लेकिन जो विकास की गंगा बहाने का आपने वादा किया था, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है, आप उसको पूरा करें और वहां की जनता को, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसके विकास के कार्यों में अपना योगदान दे यह मेरा आपसे निवेदन है।

जहां तक पेयजल का सवाल है, मैं, मुख्य मंत्रीजी, निवेदन करना चाहूंगा, पेयजल के बारे में हालांकि आपके मंत्री महोदय प्रयास कर रहे हैं लेकिन पेयजल के बारे में आज गंभीर समस्या है। अभी जनवरी का महीना है, अभी भी पीने के पानी की समस्या है। पूरे धौलपुर क्षेत्र में ही नहीं पूरे राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है क्योंकि पानी का वाटर लेवल नीचे चला गया है। जितने भी हैण्डपम्प थे वह खराब हो चुके हैं। मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि गर्मी का मौसम आने को है, इस पर गंभीरतापूर्वक निर्णय लेकर इस प्रकार का प्रावधान करें जिससे क्षेत्र की जनता में पीने के पानी की समस्या नहीं रहे। शहरी क्षेत्र के लिये पिछले चालीस साल की योजना है। आपने कोई भी आग-मेन्टेशन के लिये शहरी क्षेत्र में पैसा नहीं दिया। जो योजना थी उस समय की पापूलेशन उस समय के हालात को देखकर सफल थी लेकिन चालीस साल हो गये और शहरों में आपने कहीं पैसा नही दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि उन शहरी क्षेत्र की योजनाओं के लिये पाइप पुराने पड़ गये हैं, आबादी बढ़ गयी है, एरिया बढ़ गया है, उनको सुविधापूर्वक पानी उपलब्ध कराने के लिये शहरी क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने की योजनाओं के लिये भी ज्यादा से ज्यादा धन-राशि उपलब्ध करायें।

दूसरा, मुख्य मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है, शायद आपकी जानकारी में आया या नहीं आया, इस समय अस्पतालों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गयी कि डाक्टर्स लोग अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं।

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

हालांकि कंसल्टेशन उनको अलाउड है लेकिन इस प्रकार का उनको अलाउड नहीं है कि वह अपने घर पर क्लीनिक खोल लें। धौलपुर में आपकी जानकारी में आया कि नहीं आया, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप जांच करा लें और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी भी बिराजे हुए हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह चाहे अपने अधिकारियों को भेजें. मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं आज धौलपुर अस्पताल में बीस डाक्टर्स होंगे शायद उनमें से पन्द्रह की खुद की क्लीनिक होगी। घर पर प्रेक्टिस कर रहे हैं. घर पर मरीजों को भर्ती करते हैं। अस्पताल में मरीजो को इस प्रकार से बाध्य करते हैं कि वह उनके घर आवें और उनको पैसा दें. उनके यहां भर्ती हों। तो मेरा, माननीय मुख्य मंत्रीजी, निवेदन है कि इस प्रकार की जो प्रवृत्ति वहां पर है, गरीब जनता को लूट रहे हैं. ऐसे डाक्टर्स के खिलाफ आप कार्यवाही करावें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : निश्चित तौर पर जांच करवायेंगे।

श्री बनवारी लाल शर्मा : धन्यवाद, आपने मेरी इस तकलीफ को सुना। वहां वास्तव में हालत इस प्रकार की हो रही है।

तीसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि धौलपुर में अगर कोई भी आप रोजगार नहीं ला सकते, मुख्य मन्त्रीजी, तो धौलपुर के डवलपमेण्ट के लिये मेहरबानी करके उसे इण्डस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया घोषित करा दें। जो आज पोल्यूशन की वजह से, एनवायर्नमेंट की वजह से आगरा से कारखानों को और जगह शिफ्ट कराने की बात की जा रही है. अगर धौलपुर को आप इण्डस्ट्रियल बैकवर्ड घोषित करा देते हैं तो निश्चित तौर पर वहां लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां की बेरोजगारी दूर होगी। इसी प्रकार से....।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : आपको तो रोजगार मिल गया।

श्री बनवारी लाल शर्मा : मुझे रोजगार मिल गया लेकिन आप बेरोजगार हो रहे हैं अभी इस समय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जब चुनाव घोषित नहीं हुआ था, आपने मुझे फोन पर कहा कि इतना तो करो भैरोंसिंहजी यहां से न लड़ें और आप आज कह रहे हो....

श्री बनवारी लाल शर्मा : यह आप उनकी वकालत कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी में कार्य करने की, विकास करने की भावना ही नहीं है। वरना बार-बार क्षेत्र नहीं बदलते अगर ऐसी बात होती। उनकी विकास कार्यों में इतनी रुचि होती तो हमारे नेता रह चुके हैं, मुख्य मंत्री रह चुके हैं जो एक ही क्षेत्र से दस बार चुनाव जीत कर आये हैं और एक आपके नेता महोदय हैं जो कि हर बार अपना क्षेत्र बदलते हैं। यह तो उनके विकास की बात है।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात): सर्वांगीण विकास के लिये बदलते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो अपनी अपनी विशेषता है।

श्री बनवारी लाल शर्मा : आपकी जानकारी के लिये उसमें विशेषता हो सकती है बाकी मैं यह समझता हूं कि यह उनके लिये शोभा की बात नहीं है क्योंकि वह विकास कार्यों में रुचि नहीं रखते हैं ।

श्री रोहिताश्व : इससे पूरे राजस्थान का विकास हो जाता है ।

श्री बनवारी लाल शर्मा : अच्छा है । अच्छा हुआ कि उनकी थोथी बातों में गंगानगर की जनता नहीं आयी और मैं गंगानगर की जनता का आभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उनके थोथे भाषणों में वहां की जनता नहीं आयी और उनकी असलियत को पहचान गयी कि वास्तव में यह क्षेत्र में रहते हैं वहां पर कार्य नहीं करते हैं और उसने इनको सबक सिखा दिया ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं । सभापति महोदया, जिस प्रकार से मेवात बोर्ड बनाया है जिस प्रकार से और बोर्ड बनाये हैं उसी प्रकार से एक डांग क्षेत्र का बोर्ड धौलपुर, अलवर सवाई-माधोपुर और कोटा क्षेत्र, जहां पर कि डांग सर्किल है, के डवलपमेण्ट के लिये, वहां की समस्याओं के समाधान के लिये गठित किया जाये । शिक्षा के मामले में जैसा कि बहुत से सदस्य कह रहे थे आप रुचि नहीं रखते, आपने स्कूल बन्द करा दिये, कालेज कोई खोले नहीं, मैं तो यही अर्ज करना चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में जिस प्रकार से मैंने अस्पतालों के बारे में कहा, इसी प्रकार से अध्यापकों की प्रवृत्ति भी ट्यूशन की होती जा रही है । उनके मन में भी यह भावना फैलती जा रही है कि बच्चों को बजाय इसके कि अपने स्कूल में शिक्षा दें उनको इस प्रकार से प्रेशराइज किया जाता है, इस प्रकार का मैनिपुलेशन किया जाता है कि वह उसके घर पर आकर ट्यूशन करें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी देखें ।

इसके अलावा यहां भ्रष्टाचार की बात है । मुख्य मंत्री जी, अर्ज करूं, आपका पुराना क्षेत्र रहा है, वहां पर नगरपालिका के जो अध्यक्ष हैं वह इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, अनियमितता कर रहे हैं, सृजित पद नहीं हैं उनको भर रहे हैं और करोड़ों रुपयों का घोटाला कर रहे हैं । इसकी आप जांच कराने की हिम्मत रख सकते हों तो जांच करायें और अगर वास्तव में सत्य हो और यह चार्ज सही हो तो उसके खिलाफ आप निलम्बन की कार्यवाही करें, मेरा आपसे ऐसा निवेदन है ।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं ।

धन्यवाद । जय हिन्द ।

श्री सभापति : श्री किशन गोपाल कोगटा । (अनुपस्थित) ।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : मेरे नाम का क्या हुआ ?

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है अभी ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इनसे पहले था मेरा नाम ।

श्री सभापति : ठीक है, आप बोल लें । हां, लिस्ट में इनका नाम है, इनके नाम की

(श्री सभापति)

जगह पहले कुछ चेंज किया हुआ था, इसलिये आप बोलें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदय ने कृपा करके जो अभिभाषण इस सदन के सम्मुख पढ़ा, उसके लिये धन्यवाद ज्ञापित करना इस सदन का कर्तव्य है और उस कर्तव्य की अनुपालना में बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं।

इस धन्यवाद प्रस्ताव के विरुद्ध भी बोलने वाले कई माननीय सदस्य यहां पर बिराजमान हैं। अब स्वाभाविक है, जो लोग किसी भी तरह से हर हाल में आसन के दाहिने तरफ बैठना चाहते थे, पर बिल्ली के भाग्य का छींका टूटा नहीं और उन्हें उधर बैठना पड़ गया, उनको पीड़ा तो होगी....

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : आपकी पीड़ा की, आपके दुःख की चिन्ता कीजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मेरे दुःख की चिन्ता मैं कर लूंगा....

श्री रतनलाल ताम्बी : हम तो सहानुभूति के लिये....

श्री जोगेश्वर गर्ग : सहानुभूति के लिये धन्यवाद। अब उस पीड़ा को किसी न किसी रूप में उजागर करना है, उसी की यह सारी कसरत हो रही है। बहुत ज्यादा जिस मुद्दे को उछाला गया वह था, पंचायतों को भंग करना। पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् उन्हें भंग किया गया। उस बात पर बावेला मचाने वाले लोग, इतने वरिष्ठ लोग इस बात को भूल गये कि उन्होंने चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को पौने तीन साल में ही भंग कर दिया था। उनका तो कार्यकाल पूरा हो गया था, उनकी समयावधि पूरी हो गयी थी, उन्हें तो जाना ही था, पर जिनकी समयावधि पूरी नहीं हुई थी उनको भंग करके आपने जो अलोकतांत्रिक काम किया है उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। अब मन में तो पीड़ा होगी पर बोल नहीं सकते, मजबूरी थी। इसके कारण राजस्थान का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई में फिर कई साल लगेंगे।

सभापति महोदया, राष्ट्रपति शासन, आलोचना करना, क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय का शासन था, उचित नहीं है पर मजबूरीवश मुझे कुछ बातें बोलनी पड़ रही हैं इसलिये कि प्रतिपक्ष की तरफ से यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में विकास के कार्य रुक गये थे और इन 10-11 महीने के कार्यकाल में वह काम ज्यादा हुए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितने काम हुए वह जगजाहिर है, उनके काम को आपके प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं। उसके बिना भी जनता जानती है उनको। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, पहले भी राजस्थान में बाढ़ आती थी, बरसात होती थी, जब कभी भी मामूली बरसात में सड़कों में छोटी-मोटी टूट-फूट होती थी वह ठीक नहीं हो पाती थी साल साल भर तक और वापस बरसात आ जाती थी। जालोर की जनता साक्षी है, 1990 की

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बाढ़ में जालोर की सड़कों की क्या हालत हुई थी, तहस-नहस हो गयी थीं इन सड़कों को तीन महीने के अन्दर-अन्दर न केवल पहले जैसी बल्कि उससे भी सुन्दर स्थिति में ला करके खड़ा किया था और केवल उस अकेले जालोर जिले में सवा छः करोड़ रुपये खर्च किये थे माननीय भैरोंसिंहजी की नेतृत्व वाली सरकार ने। 1992 में फिर बाढ़ आयी, वाटर वर्क्स में भी टूट-फूट हुई, सड़कों में भी टूट-फूट हुई, सिंचाई विभाग के जो बांध थे, उनमें भी टूट-फूट हुई। उनकी मरम्मत का पैसा लोकप्रिय सरकार रही होती तो तुरन्त मिल जाता। वह पैसा आज तक नहीं मिला।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : माननीय सदस्य, कौन-सा बांध बना ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : वह भी बताऊंगा, माननीय सदस्य, बहुत कुछ है हमारे पास काम के नाम पर गिनाने के लिये।

सभापति महोदया, अब मैं कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं, जो काम चलते-चलते रुक गये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक सड़क 10 किलोमीटर की मंजूर हुई थी, रेवत गांव से लेकर भाखरा रोड़ गांव तक। साढ़े सात किलोमीटर बन गयी और अचानक सरकार चली गयी तो सड़क जहां थी वहां रुक गयी ढकोतला गांव के पास, 11 महीने में वह ढाई किलोमीटर सड़क नहीं बन सकी और अब जब सरकार आयी तो वह काम शुरू हुआ है। ऐसा ही एक और उदाहरण दूंगा। जालोर 132 के. वी. स्टेशन पर साढ़े बारह एम. वी. ए. के दो ट्रांसफार्मर काम कर रहे थे, लोड ज्यादा था, तीसरे की आवश्यकता थी। मेरे द्वारा मांग की गयी थी, सरकार ने उसको स्वीकार किया और वह ट्रान्सफार्मर जून, 1993 में जालोर पहुंच गया था। दिसम्बर, 1993 के प्रथम सप्ताह तक उस ट्रान्सफार्मर के लिये न तो फाउंडेशन बनने की तैयारी की गयी और न उसके लिये आवश्यक साजो-सामान मंगवाया गया और न कोई कार्यवाही हुई। सरकार आने के बाद मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि तुरन्त उस पर कार्यवाही हुई है फाउंडेशन का काम शुरु हो गया है, उसके लिये सामान जितना भी आवश्यक था, सब आ चुका है। वहां पर एक स्पेशल टीम विशेषज्ञों की 20 लोगों की उस ट्रान्सफार्मर को चार्ज करने के लिये लगी हुई है। यह अन्तर है, उस 11 महीने के कार्यकाल में और उसके बाद के और उसके पहले के कार्यकाल में। इस प्रकार अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, पर यह दो उदाहरण ही उस स्थिति को समझने के लिये पर्याप्त हैं और अधिक उदाहरण देकर मैं सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहूंगा।

सभापति महोदया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में मैं बताना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी अपने आपको अनुसूचित जाति का मसीहा कहती रही और उन्हें लुभावने सपने दिखाकर उनके वोट 45 साल से लेती रही। इस बार उन सपनों का जादू टूट गया। इस बार वह जादू बिखर गया और जालोर में मेघवाल समाज ने सरेआम घोषणा की कि जालोर और सिरोही दोनों जिलों में हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। जालौर विधान सभा क्षेत्र में तो उनका

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बागी उम्मीदवार खड़ा हुआ और सरेआम गांव-गांव, गली-गली घूम-घूम कर कहा कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है. मुझे दें बहुत अच्छा है मुझे नहीं दें तो मत दें पर कांग्रेस को तो मत देना। तिलिस्म टूट गया। अब वह उन सपनों में आने वाले नहीं, अब आपकी लुभावनी बातों में उलझने वाले नहीं और उसका परिणाम यह निकला कि 33 एस. सी. की सीटें हैं, 33 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आयीं और सभापति महोदया उन 24 में से एक वह भी सीट है जहां से अनुसूचित जाति के अपने आपको मसीहा कहने वाले सांसद माननीय बूटासिंह के सुपुत्र लवली खड़े थे। उस लवली को रेवदर की जनता ने अगली बनाकर वहां से रवाना कर दिया। अनुसूचित जाति के मसीहा बनने वाले भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्रीमान् पहाड़िया साहब भी नजर नहीं आते इस सदन में। अब जितने भी स्थापित नेता थे।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री हार गये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : उन सारे लोगों का, उन सारे स्थापित नेताओं का जिन्होंने अब तक लुभावे में रखा, भुलावे में रखा, अनुसूचित जाति समाज ने, पूरे तबके ने बहिष्कार कर दिया, बहिष्कृत कर दिया। उसका बहुत बड़ा कारण था, यह मैसेज गया समाज में, तबके में, पंचायतों में जो आरक्षण हुआ अनुसूचित जाति के लोगों के लिये, जनजाति के लोगों के लिये, महिलाओं के लिये उस सबका यह चमत्कार है। उसको जितना समर्थन मिला राजस्थान प्रान्त में और उसके कारण जितनी वाहवाही मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी शेखावत की हुई उसके कारण समर्थन बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। मेरा दावा है कि इस बार तो 33 में से 24 आ गये, कांग्रेस के पास सिर्फ 6 बचे हैं, अगली बार यह 6 भी नहीं बचेंगे। एक नियम है सरकार का विकास के काम जितने भी होते हैं पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के जलदाय विभाग के सिंचाई विभाग के या और कोई, जनहित के कार्यों में 17 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति की बस्तियों में पर, खर्च होनी चाहिये। यह एक सिद्धांत है। मैं मेरे सामने बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, आज तक कब इस सिद्धांत का पालन किया गया? कभी नहीं। अनुसूचित जाति की बस्तियां जो वर्षों पहले आइडेण्टिफाई हो गयी थीं यदि इस सिद्धांत का पालन किया गया होता तो उनमें पानी बिजली की कोई शिकायत नहीं होती। दुर्भाग्य से आज भी वह शिकायत बाकी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया कि इसको कड़ाई से लागू करेंगे और वह लागू हो रहा है उसके कारण यह परिणाम आया कि इन बस्तियों में विकास के काम हुए हैं।

सभापति महोदय, नीतियों की बात चली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नीति और मापदण्ड निर्धारित किये और उससे पहले जो अनीति के मापदण्ड प्रचलित थे उनको समाप्त किया। मैं उदाहरण देना चाहूंगा चयन की, भर्ती की प्रक्रिया होती है। अध्यापकों की भर्ती, पटवारियों की भर्ती और कोई सरकारी कर्मचारियों की भर्ती का जो तरीका पहले था एक ही तरीका था, तगड़ी सिफारिश ले

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

आओ और नौकरी ले लो। भारतीय जनता पार्टी के शासन में पौने तीन साल के शासन में नीतियां निर्धारित हुई, प्रक्रिया निर्धारित हुई और उसके अनुसार रिक्रूटमेण्ट में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सका। पटवारियों की भर्ती हुई, हमारे शासन काल में हजारों मास्टरों की भर्ती हुई, डाक्टरों की, वैद्यों की कम्पाउण्डर्स की भर्ती हुई, पर्यवेक्षकों की भर्ती हुई, सैकड़ों-हजारों की सख्या में एम्प्लायमेंट मिला, सबको एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत मिला। किसी को सिफारिश की आवश्यकता नहीं, किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं। इस सब के कारण वास्तविक योग्य व्यक्ति जिसका हक है, जो हकदार था, को अपना हक मिला, उसको नौकरी मिली। बेरोजगारी के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे। बेरोजगारों को जो वास्तव में योग्य हैं, काबिल हैं जिनको सिफारिश तन्त्र के कारण काम नहीं मिलता था, लटकते रह जाते थे, कम अंक वाले लोग भी सिफारिश के कारण नौकरी पा लेते थे उस सिस्टम को, परम्परा को समाप्त किया। फर्जी डिग्रियों का प्रचलन किसके समय में हुआ? फर्जी डिग्री का प्रचलन हुआ, मास्टरों की नौकरियों में बहुमत फर्जी डिग्री वालों का आने लग गया और मैं याद दिलाना चाहूंगा सदन के रिकार्ड पर है, सभापति महोदया, 89 में यहां मामला उठा था, कांग्रेस की सरकार थी तो फर्जी डिग्री का प्रकरण उठा और फिस्स हो गया, दब गया और वही मामला भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भैरोंसिंहजी के मुख्यमंत्रित्वकाल में उठा मैं ही था उठाने वाला, उस पर कार्यवाही हुई, जो लोग फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पा गये थे उनको घर भेजा गया, उनके खिलाफ केस बने, भविष्य में नहीं आ पायें उसके लिये व्यवस्था हुई। आज सामान्य प्रक्रिया बन गयी कि जिस किसी की भी डिग्री राजस्थान के बाहर की हो, क्योंकि ज्यादातर फर्जी डिग्रियां उधर से ही आती हैं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से आती हैं उनकी जांच किये बिना यदि मेरिट में नाम आ जाता है तो भी पोस्टिंग लेटर नहीं दिया जाये। यह नियम माननीय भैरोंसिंहजी के शासनकाल में बना। उसके कारण आज स्थिति बनी है कि फर्जी डिग्री वाले लोग अब आने ही बन्द हो गये हैं। उसके बाद बहुत कम लोग फर्जी डिग्री के पाये जाते थे। वरना चार साल पहले यह स्थिति थी, मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है, अन्दाजन तीन हजार अध्यापक फर्जी डिग्री वाले नौकरी पा जाते थे। इस प्रकार की व्यवस्था पूरे शासन तंत्र में करने का प्रयास माननीय भैरोंसिंहजी के शासन में हुआ। 40-45 साल का पाप धोने के लिये 40-45 महीने तो चाहिए परन्तु हमारी सरकार को इतना भी मौका नहीं मिला। अकारण बीच में ही हटा दिया गया।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, जो अभी सदन में नहीं हैं उल्लेख कर रहे थे आर. एस. एस. के बारे में, आर. एस. एस. की कट्टरता के बारे में। मैं जवाब देना चाहूंगा। चूंकि उन्होंने आर. एस. एस. का जिक्र किया, मैं उनसे कहना चाहूंगा आर. एस. एस. को समझने के लिये आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो नहीं समझ सकते आप....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : अब भी नेकर पहन लो तो अभी समझा देते हैं।....(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : आप ही समझो । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक बार जो आ जाता है वह मोक्ष पा जाता है उसका दूसरा जन्म नहीं होता ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : आर. एस. एस. को कट्टरवादी इसलिये कहा जाता है कि वह अल्पसंख्यक को बहलाने के लिये, फुसलाने के लिये नाटकबाजी नहीं करता है । सीधी-सच्ची बात करता है । कभी कोई आपदा आये, अकाल की हो, बाढ़ की हो, भूकम्प की हो, अग्नि काण्ड होगा, दुर्घटना होती हो, हर मामले में आर. एस. एस. के कार्यकर्ता ने बिना किसी भेदभाव के उनकी मदद की है, बिना धर्म पूछे, बिना किसी की जाति पूछे । विश्वास नहीं हो तो गुजरात में मोरवी की बाढ़ आयी थी वहां के मुसलमानों से जाकर पूछ आयें । परन्तु उनको प्रसन्न करने के लिये नाटकबाजी नहीं कर सकते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिये अपनी टोपी अपनी वेशभूषा नहीं बदल सकते हैं, इसलिये हम पर कट्टरता का आरोप है तो इसका इलाज नहीं है ।

माननीय सभापति महोदया, जोधपुर लिफ्ट कैनाल की बात कही, बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने । उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मंजूर नहीं हुई, कांग्रेस के शासनकाल में मंजूर हुई । ठीक बात है, 83-84 में मंजूर हुई थी । 83-84 से 89-90 तक के 6 वर्ष के शासनकाल में उस योजना पर कुल खर्चा हुआ 3156 करोड़ और उसके दो साल बाद 91-92 और 92-93 म उस योजना पर खर्चा हुआ 7568 करोड़ । दुगुने से ज्यादा 6 साल में आपने जितना खर्च किया उसका दुगने से भी ज्यादा दो साल में खर्च किया प्रगति हमने की है या आपने की है, तुलना कर लीजिये । उस योजना पर काम हम करें सात हजार करोड़ योजना में....

(16 00)

श्री परसराम मदेरणा (नेता. प्रतिपक्ष) : दो साल में सात हजार करोड़ रुपये इस योजना में ? इस साल की योजना 1700 करोड़ की थी और पिछले साल की 1400 करोड़ की थी और आपने दो साल में जब प्लान नहीं था, प्लान होली डे था, सात हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिये । यह रेवेन्यू एक्सपेण्डीचर की बात कर रहे हैं आप ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : क्षमा चाहूंगा, करोड़ नहीं लाख है । पर गणित वहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : सात हजार लाख भी करोगे तो भी आंकड़ा गलत है ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इस अभिभाषण में लिखा है कि 1983-84 से 1989-90 तक कुल 3156 लाख रुपये खर्च हुए और 1991-92 में....

श्री परसराम मदेरणा : वह जो योजना थी वह तीन हजार करोड़ की थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना । लाख नहीं है । आप पांच साल की पूरी सातवीं पंचवर्षीय योजना बता रहे हैं । सातवीं योजना का जो आकार था वह तीन हजार करोड़ का था । इसलिए करोड़ और लाख में शायद मेरी समझ में

(112)

(श्री परसराम मदेरणा)

आप थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहे हैं। यह तो असम्भव है। असम्भव इसलिए है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का आकार साढ़े ग्यारह हजार करोड़ है, जिसकी आप डींग हांक रहे हैं। उनको पांच साल मे आप डिवाइड कर दीजिये, करीबन ढाई हजार करोड़ आती है। जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि इसका आकार हमने 280 प्रतिशत बढ़ा दिया है। जब प्लान होली डे था, जब योजना नहीं थी। आठवी पंचवर्षीय योजना लागू हुई है 1992-93 से। दो साल जब बी जे पी और जनता दल की सरकार थी उसमें सात हजार करोड़ आपने खर्च कर दिये। कहां कर दिये? क्या कर दिये? आपने एप्रोप्रियेशन बिल के आंकड़े रेवेन्यू और कैपीटल दोनों के साथ ले लिये लगते हैं, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैंने निवेदन किया 3156 लाख मतलब 31 करोड़।

श्री परसराम मदेरणा : वह भी गलत है। 31 करोड की कोई वार्षिक योजना होती है क्या? राजस्थान की कोई भी योजना हुई होगी तो 1100 करोड़....

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय विपक्ष के नेता, आप जोधपुर लिफ्ट कैनाल पर बोल रहे हैं, योजना पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं जोधपुर लिफ्ट कैनाल की चर्चा कर रहा था।

श्री रमाकान्त शर्मा (थाना गाजी) : लिफ्ट कैनाल पर जो खर्चा हुआ था, पिछले दो वर्षों में उसका डबल हुआ है यह बता रहे हैं। रुपयों में मत जाइये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने समाधि भी तोड़ी तो जोगेश्वर जी गर्ग के साथ। आप अगर समाधि तोड़ें तो जरा अपने....

श्री जोगेश्वर गर्ग : गनीमत है उन्होंने मुझे टक्कर के लायक माना।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पूरा करें अब।

श्री जोगेश्वर गर्ग : जोधपुर लिफ्ट कैनाल योजना में 1983-84 से लेकर 1989-90 तक कुल 3156 लाख मतलब 31 करोड़ 56 लाख का खर्चा हुआ है।

श्री सभापति : आंकड़ों के जाल में जाकर क्या करना है?

श्री जोगेश्वर गर्ग : उस तुलना में 1991-92 और 1992-93 दोनों वर्षों में मिलाकर 75 करोड़ 68 लाख का खर्चा हुआ। छह साल में जितना हुआ उससे दुगुना से अधिक रुपया केवल दो सालों में हमने खर्च किया। इतनी तेज गति से उसमें काम किया। उसके कारण आज यह दिन आया है कि वह लिफ्ट योजना है कि वह लिफ्ट योजना लगभग पूरी होने को है और बहुत जल्दी उसका पानी जोधपुर की जनता को नसीब होगा।

इससे जुड़ा हुआ एक मामला है जिसको मैं ध्यान में लाना चाहूंगा। जब यह लिफ्ट कैनाल का पानी जोधपुर को मिलेगा उस समय जवांई बांध का जो पानी जोधपुर जा रहा है यह सरप्लस हो जायेगा। जब भी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

वह पानी सरप्लस हो. जोधपुर को उसकी आवश्यकता न रहे तब वह पानी जालौर जिले को दिया जाये क्योंकि उस पर पहला अधिकार जालौर जिले का है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : बालोतरा को दिया जाये।

श्री सभापति : जालौर से सिरोही नजदीक है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सिरोही भले ही नजदीक होगा। सभापति महोदया, आप आसन पर विराजमान हैं, सिरोही की विधायक के रूप में इधर नहीं विराज रही है।

जवाई बांध बनने से नुकसान यदि किसी को हुआ है तो सिर्फ जालौर जिले को हुआ है। फायदा उसका सिरोही और पाली को हुआ होगा पर नुकसान में सिर्फ जालौर रहा है। जवाई बांध में पानी रुकता है तो जालौर को नुकसान।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : सबसे सीधा और सरल तरीका है कि उस पानी को समदड़ी के पास में बहने वाली नदी के अन्दर छोड़ दिया जाये, तो किसानों के कुएं चार्ज हो जायेंगे। यह बढ़ा हुआ पानी उस काम आ जायेगा।

श्री सभापति : अभी इसके सुझाव नहीं लिये जा रहे हैं. माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी : सरप्लस पानी को जो लूणी नदी चल रही है उससे पीने के लिये बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाके में पहुंचाया जाये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बाड़मेर के इलाके में पहुंचाने के लिये नरना कैनाल आ रही है।

श्री सभापति : अब पूरा करें। दूसरों का भी नम्बर है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इस पानी को नहरों के माध्यम से जालौर जिले को दिया जाये और जवाई नदी में भी पानी को अधिक बहने दिया जाये ताकि वहां जो कुएं सूख रहे हैं वे ठीक हो सकें, उनकी समस्या खत्म हो।

मैं एक निवेदन और करना चाहता था बिजली के बारे में।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें कृपया।

श्री जोगेश्वर गर्ग : जालौर में माननीय भैरोंसिंहजी के शासनकाल में बिजली में बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है। रानीवाड़ा का 132 के. वी. का जी.एस.एस. बनकर तैयार है।

श्री हीरालाल विश्नोई : सांचौर का रुका हुआ है चार साल से 132 के. वी. का। रानीवाड़ा से पहले हुआ था उसका उद्घाटन।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सांचौर का उद्घाटन नहीं हुआ था शिलान्यास हुआ था। उद्घाटन तो अब हम करेंगे 15 दिन के बाद।

(114)

श्री हीरालाल विश्नोई : हां, जो हुआ उसको चार साल हो गये। उसका क्या हुआ ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : सांचौर भी बनकर तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन बहुत जल्दी करेंगे। आपको भी बुलायेंगे। इधर सायला में 132 के. वी. का जी एस. एस. माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से स्वीकृत हुआ। उसके लिये मैं आभारी हूं। आहोर तहसील में उम्मेदपुर में भी 132 के. वी. का जी. एस. एस. स्वीकृत हुआ। हमारे शासन काल में ट्रांसफार्मर आ गया। एक साल से वह ट्रांसफार्मर पड़ा है, राष्ट्रपति शासन होने के कारण वह काम अटक गया था, उसको अब पूरा करेंगे।

श्री सभापति : रिपीट नहीं करें, कृपया।

श्री जोगेश्वर गर्ग : कुल मिलाकर माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के नेतृत्व में विकास के जितने काम हुए हैं वह एक माइलस्टोन है, एक उदाहरण है। मैं न केवल आशा करता हूं बल्कि मुझे विश्वास है कि भविष्य में इससे भी अधिक....

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आप काहे तारीफ कर रहे हो ? आपको तो मन्त्री पद से हटा दिया था इन्होंने।

श्री टीकमचन्द कान्त : इन्होंने खुद छोड़ा था।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैंने तो छोड़ा था और फिर भी मिल जायेगा, पर आपको तो उम्मीद ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अयोध्या गये थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय कम हो जायेगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इसके साथ ही मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति : श्री भरतसिंह हाडा।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : माननीय सभापति महोदया, इस सदन के लिये मैं नया हूं, मगर इसके पहले मैं पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में सरपंच और प्रधान के पद पर काम कर चुका हूं।

श्री कालीचरण सराफ : तब तो कोई बात भी है। नये तो नहीं हो।

श्री भरत सिंह : नया नहीं हूं, मेरा अनुभव बता रहा हूं जो मैं महसूस कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप तो बोलिये।

श्री भरत सिंह : नहीं, मैं बोलूंगा। इनके बोलने से रुकूंगा नहीं।

मुख्य मंत्रीजी के शब्द माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने माननीय राज्यपाल जी से कहलवाये, मैं यह महसूस करता हूं कि यह एक वो तीर है जो दिशाहीन है, जिससे राजस्थान की जनता को खासकर गांवों में बैठे हुए लोगों को किसी प्रकार की आशा पैदा नहीं होती। इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस सदन को एक साल तक राष्ट्रपति

(श्री भरत सिंह)

शासन की वजह से डिजोल्व कर दिया गया और वापस अब इसका गठन किया गया। अभिभाषण में यह कहा गया है कि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम हो। डेमोक्रेसी की बात कही गयी है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि चुनी हुई सरकार बैठे। मगर मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि केवल 200 विधायक और 25 सांसद पूरी राजस्थान की जनता की सही तरीके से आवाज नहीं उठा सकते।

श्री सभापति : विधान सभा बढ़वा दो।

श्री भरत सिंह : गांव की जनता की आवाज, सही रूप से डेमोक्रेटिक आवाज, जितनी भी डेमोक्रेटिक संस्था हैं जब तक वह जीवित नहीं होतीं, प्रजातांत्रिक तरीका इस देश में कायम नहीं हो सकता। आज हम इस सदन में जो कुछ करते हैं उसका परिणाम गांव वालों को क्या मिलता है? यह उसी बात पर निर्भर होता है कि सदन में क्या होता है। जब यहां से लौटकर गांव जाऊंगा और गांव वाले लोग-बाग पूछेंगे कि आप क्या करके आये। क्या जिन हैण्डपम्प में पानी नहीं आ रहा था, पानी चालू हो जायेगा? क्या पटवारी के पास जाने से नकल मिल जायेगी? वह आटा जो चक्की पर लेकर जाता है वह पिस जायेगा टाइम पर, 3-3 दिन तक नहीं पड़ा रहेगा? तभी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सही रूप से कसौटी है। बुखार थर्मामीटर से नापा जाता है मगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को नापने का सही तरीका यह है कि जो सबसे नीचे गांवों में झोंपड़ी में बैठा हुआ है वह आपके बारे में क्या सोचता है। यह अत्यन्त लज्जा की बात है कि जिस सदन का मैं सदस्य बना हूं उसकी शुरुआत ही असत्य से करनी पड़ती है और उस असत्य के लिये एफिडेविट देना पड़े तो वह भी देते हैं हम। गांव के लोगों को क्या मिलता है इस सदन में आने से? आज एक ही व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्रीजी कर दें, यह घोषित कर दें कि दो महीने के अन्दर हम पंचायत चुनाव करायेंगे। कालिदास बनकर उस डाल पर बैठकर उसी डाल को काट रहे हो जिससे पूरा प्रजातंत्र नीचे गिर जायेगा। आपने कहा कि पंचायत व्यवस्था जब खतम हो गयी तो हमने प्रशासक इसलिये बना दिया ताकि पुनर्गठन का काम सही प्रकार से हो सके। यह राजस्थान की जनता का अपमान है, उन चुने हुए लोगों का अपमान है, शब्द निकाला जाये इसमें से कि पंचायतें चुनी हुई व्यवस्था में पुनर्गठन के काम में रोड़ा अटकाती हैं। वे लोग-बाग गांवों के बारे में ज्यादा जानते हैं। ये प्रशासक आपने बैठा दिये हैं और आज उसी की वजह से यह हालत है कि आपका तो एक साल का रोना है मगर गांव के आदमी तो उस दिन से रो रहे हैं जिस दिन से पंचायतें भंग हुई थीं।

आज बिजली की बात करते हैं, बिजली की कमी है हमारे यहां पर। आपको जो बिजली मिल रही है उसमें से आधी बिजली भी आज आप दिला दें तो। 4-6 घण्टे दे रहे हैं वह भी नहीं मिल रही है और आज मैं आपको बोल रहा हूं कि आज भी जमीनें पड़त पड़ी हुई हैं। सामुदायिक सिंचाई योजनाएं लागू हों। छोटे-छोटे काश्तकारों को अपनी जमीन गिरवी रखकर डीजल के पम्प और सिंचाई के अन्य साधन ढूंढने पड़ते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हो नहीं

(श्री भरत सिंह)

तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था पुनः कायम नहीं हो पायेगी हम चाहे कितने भी निर्णय लें। निर्णय हम कुछ भी लें, जब तक उसका एक्जीक्यूशन नहीं होगा, सही निर्णय का कोई मतलब नहीं रहता है। आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दो व्यवस्थाएं हैं, एक तरफ तो है प्रशासन जिसको चलाने वाली सरकारी मशीनरी और दूसरी तरफ है आपके चुने हुए नुमाइंदे। अगर आप एक कलक्टर बैठा देते हैं और तहसील में वहां पर पटवारी नहीं होता, तहसीलदार नहीं होता, एस. डी. ओ. नहीं होता तो आपकी नीतियों का एक्जीक्यूशन कैसे होगा? इसी प्रकार से दो सौ एम. एल. ए. बैठ जाते हैं और नीचे के स्तर पर काम का एक्जीक्यूशन करने की कोई एजेन्सी नहीं है आपकी। तो कितने भी कार्यक्रम आप ले लें, जनता के हित के कितने ही कानून यहां पर पास कर दें, कितनी ही योजनाएं ले लें मगर उसका सीधा लाभ उन लोगों को नहीं मिलता जिनके लिये आप यह योजना चला रहे हैं। तो सब सदस्यगण से मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस बात पर जोर दें....(व्यवधान) जून तक कौन-सा जून 94, यह तो 95 में जा सकते हैं, जून 96 में भी आयेगा और यह चीजें होती आई हैं, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। मुझे खेद है कि यहां पर कोटा के मंत्रिगण और मुख्य मन्त्रीजी मौजूद नहीं हैं मगर मेरी भावना को उन तक पहुंचा दें। सड़कों की बात होती है, 1500 की आबादी वाले गांव को आप सड़क से जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं जिस सम्भाग से आता हूं उस सम्भाग की बात करता हूं कि आजादी से पहले, 50 साल पहले वहां पर नदी-नालों पर कम से कम दो सौ से अधिक पुलियाएं थीं, उन दो सौ पुलियाओं में आज नेशनल हाईवे पर जो पुलिया आती है वह भी पूरी नहीं हुई। कोटा में जब बारां जिला अलग नहीं बना था उस वक्त 12 तहसील आती थीं और बरसात के चार महीनों में, यहां कोई भी सदस्य यदि मैं गलत कह रहा हूं तो खड़ा होकर टोके, 12 में से 9 तहसीलें ऐसी थीं जहां पर तहसील मुख्यालय तक कोटा जिले से नहीं जाया जा सकता था, आज भी नहीं जा सकते। आज अगर कोटा से भोपाल जाना है नेशनल हाईवे के ऊपर तो बरसात के मौसम में वह रास्ता बन्द है। किसी को कोटा जिले से बारां जाना है वह रास्ता बन्द है। यहां सदन में हम 1500 की आबादी की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि 50 हजार की आबादी के भी बन्द हैं उससे हमारा समूचा विकास बिगड़ा हुआ है। स्कूल में मास्टर नहीं जाते, अस्पताल में डाक्टर नहीं जाता है, दफ्तरों में अधिकारी नहीं जाते हैं और इस प्रकार से हमारी पूरी व्यवस्था बिगड़ती है। आज कहने को है कि कोटा औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर चम्बल का पानी बह रहा है। चम्बल की बात कहूं, जब राजस्थान में पानी की बात कही जाती है तो कहते हैं कि चम्बल के अलावा नदियां नहीं हैं। मैं कहता हूं कोटा में नदियों का जाल बिछा हुआ है और सम्पूर्ण पानी बहकर जा रहा है उसको रोका नहीं जा रहा है। यह बात कोटा ही नहीं दक्षिणी राजस्थान के पूरे इलाके की बात है कि जिस प्रकार से पानी नदी में बह रहा है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। सोइल इरोजन की प्राब्लम हमारे बढ़ रही

(श्री भरत सिंह)

है। तो मैं यह आशा करता हूं कि इसको माननीय मुख्य मन्त्रीजी, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी इस दृष्टि से देखेंगे कि कोटा बिलकुल कटा हुआ है। वे नदी-नाले जिन पर पुलिया नहीं हैं और पूरा इलाका जो एक दूसरे से कट जाता है उसको जोड़ने के लिये इस योजना में शामिल करेंगे और पंचायत चुनाव जो टाले गये हैं उनको शीघ्र करायेंगे।

श्री सभापति : श्री समर्थलाल मीणा। (अनुपस्थित) श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : सभापति महोदया, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका समर्थन करता हुआ निवेदन करूंगा कि उनका प्रस्ताव माननीय भैरोंसिंहजी, मुख्य मन्त्री महोदय के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसके द्वारा भविष्य में जो कार्य होने वाले हैं विकास के, उसका दर्पण है, साथ ही जो पिछले 11 महीने का राज्यपाल शासन था उसका भी कुछ चित्रण है।

सबसे पहले तो, जो विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि पंचायत राज के चुनाव नहीं हुए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जब 1990 में चुनाव हुए, हमारे सामने विपक्ष में बैठे सदस्य उस टाइम सरकार से नीचे उतर कर विपक्ष में बैठे थे, उनको सहन नहीं हुआ और वे मौका ढूंढ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का राज बखूबी बढ़िया चल रहा था, गांवों के विकास के लिये तत्परता से कार्य हो रहे थे और बजट का 62 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये दिया जाने लगा वह सहन नहीं हुआ और दिसम्बर, 92 में एक मौका मिला और उसको माध्यम बनाते हुए सरकार गिरायी, प्रजातंत्र का गला घोंटा। कोई बहाना नहीं था। केवल गवर्नर शासन 6 महीने के लिये लगना चाहिये था और लगा और सर्वे कराया गया कि हम वापस आ सकते हैं या नहीं जब पता लगा कि जनता कांग्रेस को नहीं चाहती है तो फिर 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ाकर असली मायने में प्रजातंत्र का गला घोंटा। केन्द्र की नरसिम्हा राव सरकार और कांग्रेस ने घोंटा और उदाहरण दे रहे हैं पंचायत राज के चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं। अभी भी जो वास्तविकता है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और माननीय सदस्य, जो विपक्ष में बैठे हैं, हर बात में किसी न किसी बहाने अपना दुःख प्रदर्शित कर रहे हैं। पंचायत चुनावों का तो एक बहाना था। अगर आप प्रजातंत्र की इतनी ही इज्जत करते हैं तो आपने 13 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये थे। यह भी आपके कार्यकाल में हुआ है यह बात सही है कि पुनर्गठन के लिये चुनाव नही हुए पंचायतों के पुनर्गठन के लिए चुनाव स्थगित रखे गये। उस हिसाब से तो ठीक है कि एक ही सरपंच 13-13, 15-15 साल तक मठाधीश की तरह से बैठे रहे। जनता उनसे परेशान थी कि उन्हें कब हटाया जाय।

अकाल की बात भी आयी। यह बात सही है कि अकाल की स्थिति है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अकाल की स्थिति के बारे में सितम्बर-अक्टूबर में पता चल गया था। राज्यपाल महोदय का शासन था,

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

क्यों नहीं काम शुरू करवाये गये ? खास कर मैं अजमेर जिले की अकाल की स्थिति बताना चाहूंगा। इस साल अजमेर जिले में 40 प्रतिशत से भी कम बरसात हुई। गिरदावरी की रिपोर्ट सितम्बर में प्राप्त हो गयी थी। शासन का समय था तो निश्चित रूप से काम प्रारम्भ होने चाहिए थे। चारे की स्थिति ऐसी है कि जानवरों को मध्य-प्रदेश और कोटा की साइड में भेजा गया। उस समय गवर्नर का शासन था, तारीख भी तय हो गयी थी कि नवम्बर माह में अकाल राहत कार्य शुरू किये जायेंगे। यह घोषणा केवल वोटों का लाभ लेने के लिये और दुरुपयोग के लिये की गयी थी। वास्तविकता में कुछ नहीं था। मुख्य मंत्री महोदय ने तत्परता दिखाई और 10 तारीख को सारे राजस्थान के कलक्टर्स और अधिकारियों को बैठा कर निर्णय किया कि अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिये योजना क्रियान्वित करेंगे। चारे की स्थिति भी खराब है, यह बात सही है और इसके बारे में भी राज्य सरकार तत्पर है और व्यवस्था करेगी।

जहां तक पानी की समस्या है, वास्तविक स्थिति यह है कि आज जो स्थिति पानी की बिगड़ी है वह सारी देन कांग्रेस शासन की है। अगर 40 सालों में ठीक ढंग से प्लानिंग बनती और हैण्डपम्प वगैरह की ठीक ढंग से मानीटरिंग होती तो आज यह स्थिति नहीं होती। बहुत से हैण्डपम्प ऐसे हैं जो खुदे ही नहीं, 80-90 फीट है, पैसा पूरा दिया गया है, 1980 से 85 के वर्ष में, और उसमें पानी नहीं है। खास कर राज्यपाल महोदय के शासन में इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया और जो कुछ भी थोड़ा इस ओर ध्यान दिया गया तो कुछ निश्चित स्थानों पर। आज स्थिति यह है कि गांव में दो-दो किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चर्चा यह कर रहे हैं कि अभिभाषण में क्या है और क्या नहीं है।

मैं डंकल प्रस्ताव के बारे में भी बताना चाहूंगा। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने डंकल प्रस्तावों पर चर्चा की। सभी को जानकारी है कि इनसे देश को नुकसान होने वाला है और खास कर किसानों को, जो भारतीय संस्कृति में अपनी खेती-बाड़ी करते हैं और अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। उन्होंने बताया कि विकसित 107 देशों के साथ सदस्य बन जायेंगे, एक्सपोर्ट होगा और यह सब होगा....

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : डंकल प्रस्ताव क्या है ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : हां है, मैं ग्रामीण क्षेत्रों से आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि फायदा क्या होगा। यह तो ऐसा ही हुआ कि 4 बीघा जमीन वाले किसान को आप रोटरी और लायंस क्लब का सदस्य बना दें, उससे उसको क्या बेनीफिट होने वाला है ?

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : बाकी बात तो छोड़िए, Who was Dunkel ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय डाक्टर साहब, आप बैठिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सीधे सवाल नहीं करें।

डा. हरिसिंह : Mr. Dunkel was chairman of GATT. आप के चेयरमैन के पहले। आप डंकेल प्रस्ताव बता दें क्या है ? तो आपकी आगे चर्चा ठीक है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : बैठिये, बाद में बात कर लेंगे। अभी तो सुनिये आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : घाट गेट के चेयरमैन थे।

श्री किशन गोपाल कोगटा : इसके साथ साथ बिजली के बारे में भी बताना चाहूंगा। बिजली की आज जो स्थिति हो रही है उसके सम्बन्ध में आपको एक तुलनात्मक स्थिति बताना चाहूंगा कि 1985-90 में जिस प्रकार के ब्रेक फेल हुए, जिस प्रकार से लाइट कट हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी के पिछले ढाई साल के राज में जो इम्प्रवमैण्ट हुआ है वह आपके सामने है और एक साल के लिए गवर्नर साहब का शासन रहा उसी का परिणाम यह हुआ कि दिसम्बर माह में सारे राजस्थान में बिजली की ट्रबल हुई। वह भी आपके सामने है। लेकिन जिस प्रकार से राज सम्भालने के बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तत्परता दिखाई उसी का परिणाम है कि आज सारे राजस्थान में नार्मल स्थिति है. इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा।

इसके साथ-साथ शिक्षा के बारे में भी चर्चा हुई। बार बार यह कहा जाता है कि 6 हजार स्कूलें बन्द कर दीं, 6 हजार स्कूलें बन्द कर दीं। एक्चुअल में....(व्यवधान)

(16.26)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

स्कूलें नहीं थीं, केवल घोषणा थी और पार्टी विशेष का राजनैतिक अड्डा बनाकर हर गांव में यह खोली गयी थी और सेवादल के सदस्यों को शिक्षक के रूप में 4-4 सौ रुपये देकर ये केन्द्र खोले गये थे। स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ते नहीं थे, न उनकी शिक्षा के मामले में बोलते हैं। जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा था उसको समाप्त किया है। वास्तविकता में स्कूलें अब खुली हैं या प्राइमरी स्कूलें खुली हैं वह पिछले भारतीय जनता पार्टी के राज में खुली हैं। यह जो शिक्षा के राजनीतिकरण की कोशिश की गयी है उसको समाप्त किया गया है, न कि वास्तव में जो स्कूलें थीं उन्हें हटाया गया है।

अन्त में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री समर्थलाल मीणा।

श्री समर्थलाल मीणा (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो इस सदन के अन्दर अभिभाषण दिया उसके बारे में पिछले दो रोज से वाद-विवाद चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद चलते वक्त इस अभिभाषण को कई बार मुझे पढ़ने का अवसर मिला है। इसके अन्त में राज्यपाल महोदय ने यह लिखा है, यह संकेत दिया है—

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्।"

(श्री समर्थलाल मीणा)

जब इस प्रकार की कल्पना राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के समय हमारे बीच में की है तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि विरोध पक्ष के लिये विरोध करने की गुंजाइश कहां है ?

श्री अध्यक्ष : यह आपको सुखी देखना नहीं चाहते हैं।

श्री समर्थलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, 16 पृष्ठों के अभिभाषण के अन्दर राजस्थान की जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं उनका जिक्र किया गया है और उनके निराकरण के लिये राज्य सरकार कृत-संकल्प है इस बात का इससे आभास मिलता है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर आज जो ज्वलंत समस्या है बिजली की उसके बारे में इस अभिभाषण के अन्दर खुलासा बात कही गयी है। कई पृष्ठों के अन्दर उसका जिक्र किया गया है। इस बात का भी विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों को एतराज है। राजस्थान के किसानों की ज्वलंत समस्या है जिसका जिक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर किया जाये, मैं समझता हूं कि उसका विरोध नहीं होना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पीने के पानी की समस्या है, राजस्थान के अन्दर जो खेत सूखे पड़े हैं, आजादी के 47 वर्षों के बाद भी, उन सूखे खेत को पानी देने की बात है, प्यासी जनता को पानी पिलाने की बात है और इसके अलावा राजस्थान का विकास किस प्रकार से किया जायेगा इस सब का दर्शन इस अभिभाषण में मिलता है उसके लिये सदन को एकमत हो करके राज्यपाल महोदय को धन्यवाद प्रेषित करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसानों के बारे में, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के बारे में इस अभिभाषण के अन्दर महामहिम राज्यपाल महोदय ने राजस्थान सरकार का एक संकल्प दोहराया है उसको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। सदन के अन्दर यह बात कही गयी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ठेकेदार केवल कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, मैं समझता हूं, ठेकेदारी प्रथा अब खत्म हो गयी है। राजस्थान की जनता ने राजस्थान की 57 सीटों में से 33 अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिह्न पर जिता करके इस बात को सिद्ध कर दिया कि राजस्थान के अन्दर, कांग्रेस का अनुसूचित जाति-जनजाति के अन्दर अब कोई लेना-देना नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर जो जिक्र किया गया है, उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दशा सुधारने के बारे में, मैं इसके लिए राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति की जो दशा पिछले वर्षों से चली आ रही है, 40 वर्षों के कांग्रेस के शासन में उनके साथ एक प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, वह दुर्व्यवहार राजस्थान की जनता और राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति सहन नहीं कर पायी और उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के 33 सदस्यों के रूप में उन्होंने यहां बहुमत दिया है। मैं निवेदन करना चाहता

(श्री समर्थलाल मीणा)

हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति के बारे में सरकार जो बजट पास करती है वह पूरा उनके ऊपर खर्च नहीं हो पाता। मैं हमारी सरकार से निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में यहां पर विकास के कामों के अन्दर, पीने के पानी और शिक्षा के अन्दर जो बजट पास किया जाता है उसका पूरा लाभ इन लोगों को दिया जाना चाहिये। अब तक जिन विभागों ने इसके अन्दर कोताही की है उन विभागों का मूल्यांकन किया जाना चाहिये और मूल्यांकन करने के बाद जहां पर भी कोताही हुई है उसके बारे में कोई न कोई व्यवस्था राज्य सरकार को आवश्यक रूप से करनी चाहिये।

पीने के पानी की राजस्थान में विकट समस्या है। पहले तो केवल पश्चिमी राजस्थान में यह समस्या हुआ करती थी लेकिन अब यह समस्या पूरे राजस्थान के अन्दर है। मैं हमारी राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस समस्या को दूर करने के लिये कोई कारगर कदम उठाये जाने चाहिये, कोई योजना बनायी जानी चाहिये। जितने भी राजस्थान में पंचायत हैडक्वार्टर्स हैं उनको जलदाय योजना से आने वाले 5 वर्षों में जोड़ें। इस प्रकार की योजना बना करके यदि सरकार चलेगी तो निश्चित रूप से पीने के पानी की समस्या राजस्थान के अन्दर हल हो पायेगी।

जहां तक सिंचाई का मामला है, सिंचाई के लिये भी हमारे राजस्थान के अन्दर कोई कारगर योजना नहीं बन पायी। कुछ बड़ी योजनाओं के अन्दर राजस्थान सरकार का काफी पैसा खर्च हो रहा है और काफी लम्बे समय के बाद योजनाएं पूरी हो पा रही हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

काफी लम्बे समय के बाद जब पूरी होती हैं तब उन योजनाओं का हमको लाभ मिलता है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर जो पहाड़ी एरियाज हैं उन एरियाज के आसपास जब बरसात होती है तो वह पानी बहकर निकल जाता है। इस प्रकार के एरियाज के अन्दर छोटे-छोटे बांध, छोटे-छोटे एनीकट्स बनाने की योजना होनी चाहिये जिससे वह पानी रुक सके और हमारे कुओं का जल स्तर बढ़ सके। उसके आधार पर पीने के पानी की समस्या हल होगी और सिंचाई के लिये पानी रुक पायेगा। इस प्रकार से दोनों समस्याओं का हल हो पायेगा।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गांवों के अन्दर जो अनुसूचित जाति, जनजाति के एरियाज हैं उनके मिनी ब्लाक्स 1977 की सरकार ने 1978 के आसपास बनाये। करीब 40 मिनी ब्लाक्स राजस्थान में बने थे और वहां कुछ विकास के काम हो रहे हैं। ये मिनी ब्लाक्स अनुसूचित जाति, जनजाति के एरियाज में हैं। जो एक साथ लोग रहते हैं, काम्पेक्ट एरियाज के अन्दर उनको लाभ मिलना चाहिये और मिनी ब्लाक्स वहां पर बनाये जाने चाहिये। मिनी ब्लाक्स बनाने की सरकार की जो योजना है इस प्रकार की योजनाओं के अन्दर भारत सरकार से भी काफी पैसा मिलता है और राज्य सरकार भी शेयर करती है। तो इस प्रकार की योजना बना करके उन लोगों

(श्री समर्थलाल मीणा)

की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यह गांवों की समस्या भी है और अनुसूचित जाति-जनजाति की समस्या भी है, इस प्रकार से इस समस्या का हल किया जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय ने जो यहां अभिभाषण दिया उसके लिये राज्यपाल महोदय को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण डूडी।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिन से राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन में दिया उस पर वाद-विवाद चल रहा है। मैंने अभिभाषण की प्रतिलिपि पढ़ी। जैसा सदन के नेता ने कहा कि मैं एक साल की छुट्टी से वापस आया हूं, हमने सोचा कि इन्होने आराम फरमाया होगा, प्रदेश के लिये कुछ गहन चिन्तन किया होगा, कुछ नयी विचार-धारा राजस्थान के सामने लायेंगे पर हम सबने देखा कि ऐसी कोई बात नहीं है इस अभिभाषण में, न कोई दिशा-निर्देश है जिसके आधार पर राज्यपाल महोदय से इस प्रतिलिपि को पढ़वाया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो भी हालात हैं उस हालात में ये बराबर यह कहते हैं कि राष्ट्रपति का शासन था। करीब 1990 से लगातार आज तक आप लोगों की जो योजनाएं थीं वे योजनाएं ठीक क्रियान्वित हो रही थीं, आपके जो विचार थे, आपका जो चिन्तन था और आपका जो सोच था राजस्थान के प्रति, वह ही कार्य कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय, आज भी चाहे बिजली के क्षेत्र के अन्दर, चाहे पानी की समस्या के अन्दर, चाहे शिक्षा के अन्दर, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र के अन्दर जनहित के काम हैं, जिनका अटैचमेंट पब्लिक के साथ हमेशा रहता है, वे सब मृत-प्राय: अवस्था के अन्दर हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, बिजली के मामले में लम्बा-चौड़ा, तीन पृष्ठों के अन्दर राज्यपाल महोदय से यह भाषण पढ़वाया गया। अन्ततोगत्वा आपने इन सालों के अन्दर कितनी मेगावाट बिजली पैदा की, आपने कितने नये बिजलीघर की योजना बनायी, उसके अन्दर कुछ भी नहीं कहा। जैसाकि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने बताया, साढ़े आठ मेगावाट बिजली आपने पैदा की और कितने उद्योगों को आपने दी? जो डिमान्ड थी लोगों की, एग्रीकल्चर सैक्टर के अन्दर, औद्योगिक सैक्टर के अन्दर और जो डोमेस्टिक कनेक्शन के अन्दर विद्युतीकृत गांव हैं कितने गांवों को आपने विद्युतीकृत किया? कितने गांवों के घरों के अन्दर लाइट पहुंची? केवल इलेक्ट्रिफाइड करने का मतलब, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं कि गांव के बाहर चौराहे पर एक ट्रांसफार्मर लगा दिया गया और उस ट्रांसफार्मर लगाने के बाद में कह दें कि यह गांव इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। यदि यह ऐसी परिभाषा में आता है तो यह सोच आपका अलग है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपने ओ. टी. पी. स्कीम चलायी बिजली के अन्दर, नकद जमा राशि योजना और उस नकद जमा राशि योजना के तहत उन हजारों गरीब

(श्री रामनारायण डूडी)

लोगों के जो कनेक्शन पेण्डिंग थे, जो वरीयता की सूची के अन्दर थे वे आपने मारे और उनके बाद ओ टी पी. कनेक्शन आपने दिये दिये नहीं आपने लोगों से पैसे जमा कराये और पैसे भी एक नहीं, दस हजार नहीं, लाख लाख रुपये । मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं आपको आपकी जो स्कीम उस वक्त आपने लागू की आज तक वह ओ. टी. पी. के कनेक्शन पेण्डिंग पड़े हैं। आपके विभाग के अन्दर जाते हैं तो कहते हैं कि सामान नहीं है । आपने रोकड़ पैसे लिये हैं और टाइम बाउण्ड प्रोग्राम था आपका। आपने कहा, तीन महीने के अन्दर बिजली मुहैया करा देंगे । और इसी आधार पर लोगों ने देखा, अपना गहना गिरवी रख दें, जमीन का कोई टुकड़ा बेच दें और उसी आधार पर उन्होंने आपके बिजली के कनेक्शन हेतु फाइल भरी । उसका नतीजा यह हुआ कि दो साल से आज तक कई काश्तकार इन्तजार कर रहे हैं इस बिजली के लिये कितना खर्चा होता है एक काश्तकार का, जब पानी जाता है ? आपको रोकड़ पैसे के अन्दर जिनके 7-8 पोल लगते हैं और 25 के. वी. एम. का ट्रांसफार्मर हो, उनका लाख-सवा लाख रुपये तो वे होते हैं, लाख रुपये के मोटर पम्प, कुछ धोरी पानी, 3 लाख में क्यारी के अन्दर पानी पहुंचता है और उनको आप बिजली कितनी देते हैं आपने कहा, इस बार हम 8 घण्टे बिजली देंगे । जब काश्तकार ने बुवाई शुरू की आपने घोषणा की थी कि हम 8 घण्टे बिजली देंगे । काश्तकार ने अपनी मिर्ची भी बोयी, काश्तकार ने अपना रायड़ा भी बोया और काश्तकार ने अपना जीरा, जो एक कमर्शियल है, भी बोया । उनको जब आज हम बोते हैं तो नौ दिन के बाद पानी देना पड़ता है । ऐसे वक्त के अन्दर जब बी. जे. पी. गवर्नमेण्ट शासनरूढ़ हुई, अध्यक्ष महोदय होता क्या है ? आंख मिचौली हो गयी । पिछले 2 महीने से काश्तकार की फसल सूख रही है । आज मिर्ची, रायड़ा और जीरा इन तीनों की बुवाई काश्तकारों को एक साथ करनी पड़ती है । उस मामले के अन्दर कोई किसी प्रकार की इनके पास बिजली उपलब्ध नहीं है । 8 घण्टे के बजाय आज हालत यह हो गयी, मैं परसों गांव में जाकर आया, तीन और साढ़े तीन घण्टे बिजली देते हैं वह भी सिर्फ फ्लक्चुएशन के लिये बीच के अन्दर ट्रिप आ जाती है और इस ट्रिप और फ्लक्चुएशन से काश्तकार की मोटर जल जाती है । एक मोटर जलने पर, रि-वाइंडिंग होने का, वापस रोलिंग होने का जो खर्चा आता है, गरीब काश्तकार 5 हजार रुपये भुगत रहा है । यह हालत है । न इनके पास सिस्टम इम्प्रूवमेण्ट करने का कोई मामला है । सारी जी. एस. एस. की लाइनें ओवरलोडेड हैं, लाइनें इनकी खराब हैं । वोल्टेज आ नहीं रहा है । ऐसी हालत के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, यह जनादेश की बात करते हैं । लूली-लंगड़ी सरकार जो निर्दलियों की बैसाखियों पर तैरने वाली है, जिनके विचार, जिनका चिन्तन और जिनकी आइडियोलोजी एक नहीं हो, एक दक्षिण की तरफ जाता है, एक उत्तर की तरफ जाता है और काश्तकारों के लिये जिनका कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं और ग्रामीण जनता जो त्राहि-त्राहि कर रही है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार को यह आगाह करना चाहता हूं कि वह काश्तकार की जो स्थिति है, जो आज हालत पैदा हो गयी है

(124)

(श्री रामनारायण डूडी)

बिजली के मामले के अन्दर, वह हालत यदि समय पर दूर नहीं की गयी तो मैं समझता हूं कि काश्तकार को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मरता क्या न करता? आज लोगों को जनरेटर चलाने पड़ते हैं और आप भी यह सोच लीजिए, एक जनरेटर के एक घण्टे के कितने पैसे होते हैं। उनका यदि बच्चा बीमार पड़ जाय तो उसको दवाई न देकर एक बीघा जमीन बेचेगा जनरेटर से उसको ज्यादा महत्व समझेगा। हालत जब यह पैदा हो गयी और यह सरकार सो रही है। 8 घण्टे बिजली की बात करती है. तीन घण्टे बिजली नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय, आप यह विचार कीजिए, शाम को 6 बजे के बाद में गांव के अन्दर 12 बजे तक बिजली नहीं मिलती है। बंद कर देते हैं, सप्लाई बंद है। अब गांव के अन्दर पढ़ने वाला बच्चा, घर के अन्दर रात के अन्दर काम करने वाले, न तो अब चिमनी रही है क्योंकि घासलेट की व्यवस्था नहीं, न ही लैम्प रहे, न लालटेन रही है, अब बिजली भी बन्द कर दी है।

एक माननीय सदस्य : लालटेन तो है।

श्री रामनारायण डूडी : तो, मेरा इस सरकार से निवेदन है कम से कम मेहरबानी करके जी. एस. एस. लगाकर इनके डोमेस्टिक कनेक्शन की जो लाइटें हैं वे बन्द नहीं करें।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा, आज पानी की व्यवस्था में गांव के अन्दर त्राहि-त्राहि मची हुई है। मैं आपसे निवेदन करूं, पिछले डेढ़ महीने से गांव के अन्दर पानी नहीं मिल रहा है। मैं गलतबयानी नहीं कर रहा हूं। यदि सही नहीं है तो आप अपने अधिकारियों को भेज करके पता करवा लें। जो भी पाइप लाइन हैं उन पाइप लाइन पर बिजली नहीं मिल रही है। बिजली पानी दोनों का सम्बन्ध एक है और जो पुराने सिस्टम थे उन सिस्टम को भी बंद कर दिया। अध्यक्ष महोदय, उसका विस्तार करना होगा। आखिर जनता के नुमाइन्दे बनकर आये हैं यह लोग भी हम भी केवल हां पक्ष और ना-पक्ष से मामला नहीं चलेगा। काम करने के लिये इनकी जो शैली है, वे गांव और शहर को....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये, श्री भगवान दास डोसी।

श्री रामनारायण डूडी : मैं, अध्यक्ष महोदय, एक मामूली, एक थोड़ी-सी बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय यह गांव और शहर के अन्दर भेद बढ़ाना चाहते हैं। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, आज गांव के अन्दर एजूकेशन सिस्टम आपका + + + हो चुका है। स्कूलों के अन्दर लेक्चरर्स नहीं हैं। स्कूल में साइन्स मैथेमेटिक्स में यदि टीचर है. बॉयलोजी का टीचर है, फिजिक्स का टीचर है. इन 3 सबजेक्टों के अन्दर तो रिजल्ट रहेगा हण्ड्रेड पर्सेण्ट और 85 पर्सेण्ट और एक केमेस्ट्री का मान लीजिये उस स्कूल के अन्दर टीचर नहीं है तो वह पूरा का पूरा उनका रिजल्ट जीरो पर्सेण्ट हो गया। यह किसकी जिम्मेदारी है? कौन भेजेंगे टीचर? कौन खोलेंगे स्कूल? आपने 6 हजार स्कूलें बन्द कर दीं और इस विचार के लिये....

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अवलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : अब आप बंद करिये....

श्री रामनारायण डूडी : मैं पुनः अध्यक्ष महोदय. ...

श्री अध्यक्ष : आप ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा हो गया। जितने लोग बोले हैं, उतने ही और बोलने वाले हैं। आप लोगों को मौका दीजिए। आप बोल चुके हैं।

श्री रामनारायण डूडी : आपने वे स्कूल ढाणियों के अन्दर खोले।

श्री अध्यक्ष : यह बात हो चुकी है। भगवान दासजी।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, आप जब बीच में बैठाते हैं तो मैं आपको धन्यवाद देते हुए, इस अभिभाषण के प्रति तो नहीं, मगर आपको धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूं। आपने मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उस पर बनीपार्क के सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा उसका मैं समर्थन करता हूं।

दो दिन से बहस चल रही है। मैं कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में इस सरकार को आगाह करता हूं। मेरे चौहटन विधान सभा क्षेत्र में विशेष तौर से सड़कों की कमी है। 8-10 वर्ष पूर्व फेमिन में सड़कें बनती थीं और फिर सड़कें फेमिन में बनना बन्द हुई। 20-20, 25-25 किलोमीटर में भी कोई सड़क नहीं है। कोई बीमार भी पड़ता है तो सौ रुपये के बिना गाड़ी से किसी स्थान पर नहीं पहुंचाया जाता। कई पंचायत हैडक्वार्टस, करीब 15 पंचायत हैडक्वार्टस सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन चाहता है कि सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री भगवानदास डोसी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था मेरे क्षेत्र में 15 पंचायत हैडक्वार्टर अभी तक सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। सड़कें विकास का प्रथम बेस है। जहां सड़कें नहीं हैं वहां ड्रिलिंग की मशीनें भी नहीं जा सकतीं, कोई डॉक्टर नहीं जा सकता, कोई मास्टर भी नहीं जाता। इसलिये विकास का पहला कदम सड़कें होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि फेमिन में सड़कें बननी चाहिए। योजना में एक हजार किलोमीटर सड़कें राजस्थान में बनें तो एक विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा

(श्री भगवानदास डोसी)

5 किलोमीटर आता है तो 20 वर्षों में भी सड़कें नहीं बनेंगी। इसलिये मेरा सरकार से पुरजोर निवेदन है कि हमारे यहां की सड़कों की समस्या है, फेमिन में कुए और टांके बन गये हैं लेकिन सड़कों के लिये व्यवस्था की जाये तो ठीक रहेगा।

पानी की स्कीम्स भी अधूरी पड़ी हैं उनको भी गति दी जाये। बिजली की इस साल बहुत ही कमी है। सदन में इस बारे में खूब चर्चा हो गयी है। अकाल राहत कार्य खोल कर जैसा पहले काम करते थे उससे अब कोई फायदा नहीं है लेकिन सड़कें बननी चाहिए।

मैं पंचायत चुनाव के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कि पचायतों के चुनाव तुरन्त कराने चाहिए जो पिछली सरकार या राज्यपाल के समय में नहीं हो सके। जन-प्रतिनिधियों को फिर से अधिकार दिया जाये यह उचित नहीं है क्योंकि सरपंच जिन पर 17 (4) की कार्यवाही चल रही है उनके खिलाफ कई आरोप हैं और इसका बेस बनायेंगे तो सरपंच वापस आयेंगे। ग्राम सेवकों को तो बदला जा सकता है। मेरी राय है कि सरपंचों को पुन चार्ज नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि चुनाव जल्दी से जल्दी हों ताकि वापस प्रजातांत्रिक तरीका बहाल हो।

मैं यही निवेदन करता हुआ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : डा. जितेन्द्र।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में रखे गये प्रस्ताव के विपक्ष में कहना चाहूंगा।

आज राजस्थान की जो स्थिति हो रही है उसकी मैं शुरूआत पानी से करूंगा। मुकददस काबा के पैगम्बर ने हजारों साल पहले जो बात कही थी, पानी का महत्व उन्होंने बताया था लेकिन मुझे अफसोस है कि कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन सारी योजनाओं को एक तरफ रख दिया जाये और महज पानी की समस्या को एक तरफ कर लिया जाये तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की बहबूदी पूरी हो जायेगी। मान्यवर, आज पानी एक मौलिक अधिकार है। स्थिति यह है, मैं शुरुआत उसी से करता हूं, मैं आपके सामने मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के अन्दर रोज दिये जाने वाले पानी की एक बोतल आपके सामने पेश करता हूं, अगर हलक में एक बूंद भी उतर जाय तो मैं इसका दावा करता हूं। यह पानी तीन साल से दिया जा रहा है लेकिन एक बूंद पानी इसका कोई नही पी सकता। मैं इस पानी को आपके सामने पेश करता हूं, यह जांच के लिये रखा जाये।

श्री अध्यक्ष : आप बोलते जाइये, आपका समय चला जायेगा।.... (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं इस नमूने को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

(माननीय सदस्य डा. जितेन्द्र सिंह द्वारा पानी से भरी हुई बोतल सदन के पटल पर रखी गयी)

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये अपनी बात।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : 5 साल पुराना पानी है यह ।

डा. जितेन्द्र सिंह : माफ कीजियेगा, यह कोई कड़वी दवा नहीं है, यह रोज पीने का पानी है जो गत 3 सालों से खेतड़ी वालों को मुहैया कराया जा रहा है । जनाब, जरा इसको पीकर देखिये । सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि अगर एक नागरिक को उसकी रोजमर्रा की चीजों से महरूम किया जाये तो क्या होगा, मान्यवर, इस पर गौर कीजिए । मेरा क्रिटिसाइज करने का मकसद नहीं है । मैं मांग करता हूं इसकी जांच की जाये ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पानी मिले । यह तो सिर्फ खेतड़ी की बात है यहां पर चूरू के माननीय सदस्य बैठे हैं, राजस्थान में फ्लोराइड युक्त वाटर की यह स्थिति है, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि लोग क्रिपल्ड हो गये हैं, चला नहीं जा रहा है । It is a big problem, sir. इसका जितनी जल्दी हो सके आप निर्णय करने की कोशिश कीजियेगा । मैं तो यह कहता हूं कि जो तेल की लड़ाई अरब और ईरान के मध्य हुई थी, एक दिन ऐसा आयेगा जब पानी के लिये युद्ध होगा, यह मैं आपको बता रहा हूं । गांवों के अन्दर मैं रोज देखता हूं पीने का पानी दो हिस्सों में बंट गया है एक पीने के लिये तथा एक नहाने के लिये । गलती से नहाने का पानी पी लिया तो फिर डाक्टर के पास जाना पड़ेगा । यह स्थिति हो रही है कि लोग कनस्तर के कनस्तर भरकर बसों में ले जाते हैं । यह क्या माजरा है । मैं सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसको दुरुस्त किया जाय । पानी की समस्या का यह हाल है कि राजस्थान के अन्दर सैकड़ों पानी की टंकियां बनायी गयीं और सैकड़ों पानी के स्रोत भी मौजूद हैं लेकिन बड़े दुःख की बात है कि पानी की टंकियां पहाड़ों पर और पोलर्स पर खड़े-खड़े ही सूखकर फट गयीं । महज कुछ चंद हजारों रुपयों की खातिर लाखों की योजनाओं को धूल-धूसरित कर दिया गया । उन्हीं पानी की टंकियों को उनके सोर्सेज से नहीं जोड़ा गया । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा आप मेरी मांग को उन तक पहुंचा दें ।

पानी की बहुत समस्या है । हैण्डपम्प की योजना पंचायत समितियों के माध्यम से ठीक नहीं हो सकेगी । राजस्थान के डेढ़ लाख हैण्डपम्प्स में से एक लाख से ज्यादा हैण्डपम्प खराब पड़े हैं और किसान धक्के खा-खाकर आ जाता है । रोज जेब से पैसा देता है ठीक करने के लिये । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति से यह चार्ज वापस लिया जाये और पी. एच. ई डी. को दिया जाये जिसमें कि इसके अनुभवी डाक्टर हैं जो यह समझते हैं कि हैण्डपम्प में क्या खराबी है । पंचायत समिति के पास न तो स्टाफ है वह महज लोगों का समय खराब करती है । पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है । मेरा यही निवेदन है कि एनीकट्स बनाये जायें, बांध बनाये जायें ताकि पानी का स्तर बढ़े । एनीकट्स इस तरह के बांध जो सिंचाई के काम आयें और इस तरह के एनीकट्स जो वाटर रिजर्व का काम करें, बनाये जिससे कुंओं का जल स्तर बढ़ेगा । इस तरह की योजनाएँ बनानी चाहिए ।

महोदय, मुझे दुःख है कि इस अभिभाषण के अन्दर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को बिलकुल नजरन्दाज कर दिया गया है । आज

(डा. जितेन्द्र सिंह)

राजस्थान के सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के अन्दर तो उन्होंने बाईपास सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनायी है, उन्होंने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में नेफरोलॉजी डिपार्टमेंट अलग से बनाया है जहां वे किडनी ट्रांसप्लांट की योजना बना रहे हैं लेकिन मेरे गांव और ढाणियों के अन्दर ऐसे सैकड़ों सब-सेंटर्स पड़े है जहां नर्सेज की सुविधा नहीं है। मुझे इस पर सख्त दुःख और अफसोस है। मैं डाक्टर होने के नाते कह रहा हूं मैंने लड्ढों के अन्दर डिलीवरियां करायी हैं। मैं स्वयं इसका गवाह हूं। स्वास्थ्य मंत्री महोदय चले गये, आप मेरी भावना उन तक पहुंचा दीजिए। अभी पांच दिन पहले यह सिचुएशन हो गयी। गांवों की ग्रामीण महिला वहां तक पहुंच नहीं सकतीं सब-सेंटर्स जो गांवो के अन्दर हैं और उनके स्टाफ का यह एटीट्यूड है कि नहीं जाना चाहिए गांवों मे। मेरा निवेदन है कि जिन डॉक्टर्स ने, मैं मेरा उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैंने तो सन् 1968 में ही एम. बी बी. एस. कर लिया था और गांवों में जाकर अपना कैरियर स्टार्ट किया, सरकार यह करे कि जो डाक्टर्स 10 वर्ष तक गांवो के अन्दर प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे हैं उनके लिये पी. जी के अन्दर रिजर्वेशन दें जबकि आप सरकारी नौकरों को ही कर रहे हैं। हम सरकार से कुछ नहीं मांगते। मेरे साथ विपक्ष में बैठे हुए डॉक्टर्स हैं वे भी कुछ नहीं मांगते और बहुत से सैकडों डाक्टर्स हैं वे भी कुछ नहीं मांगते सरकार से। वे महज यह मांगते हैं कि आप पी. जी. कोर्सेज में, एम. एस. और एम. डी में 10 साल तक जिन्होंने गांवों में सर्विस की है उनका रिजर्वेशन करेंगे तो वे बेहतर सेवाएँ दे सकेंगे।

(1700)

अन्त में, मैं, अध्यक्ष महोदय, जो बात निहायत जरूरी है वह कहना चाहूंगा। आज सवाई जयसिंह का यह खूबसूरत ढाई सौ साल पुराना शहर जयपुर एक ऐसे कगार पर आकर खड़ा हो गया है, महोदय, मैंने अपनी आंखों से आज से दो साल पूर्व सवाई मानसिंह हास्पिटल के मुर्दाघर में जली हुई लाशें देखी थीं। वह इन्सानियत की लाशें थीं। मैं नहीं कह सकता कि वे किस मजहब के थे। लेकिन क्यों? यह भय का वातावरण क्यों? महोदय, जौहरी बाजार की गलियों के अन्दर सन्नाटा छा जाता है रात को आठ बजे के बाद। मेडिकल मैंने यहीं से पास किया है, मुझे याद है रात को दो-दो बजे निकल कर जाते थे, स्वच्छंद थे दो बजे के बाद। लेकिन आज रात के दस बजे मरघट का सा सन्नाटा छा जाने लगा है। क्यों? मेरे इस खूबसूरत जयपुर, इस राजधानी के साथ, जहां यह दो सौ माननीय सदस्य बैठे हैं, यह क्या होने जा रहा है? महोदय, पलायन कर रहे हैं लोग गांव, स्कूलें छोड़-छोड़ कर। यह गलियां छोड़-छोड़ कर लोग बाहर बसने की सोच रहे हैं। माननीय कालीचरणजी कहां बैठे हैं, पूछिये उनसे। कालीचरणजी, यह स्थिति है या नहीं?

श्री कालीचरण सराफ : अब ऐसा नहीं है।

डा जितेन्द्र सिंह : यह स्थिति हो रही है, कालीचरणजी, I am witness of it महोदय, मैं क्रिटिसाईज नहीं कर रहा,

(डा. जितेन्द्र सिंह)

मैं फैक्ट्स बता रहा हूं आपको। महोदय, इन चन्द अल्फाज में मैंने अपना नजरिया आपके सामने पेश किया। आपने जो सुना, साथियों ने सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट।

श्री कालीचरण सराफ : अब पूर्णतः सुख-शांति है, कोई गड़बड़ी नही है, आप चिन्ता मत करो। हम लोग बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट। श्री गोपीराम जाट—अनुपस्थित हैं क्या? आप नहीं बोल रहे है? अच्छा।

श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर यहां पिछले दो दिन से वाद-विवाद चल रहा है। उस वाद-विवाद में मुख्य मंत्री महोदय ने जो एक पीली पुस्तिका छापकर हमको दी है और राज्यपाल महोदय से जो बातें कहलवायी गयी हैं, ज्यादातर वही बातें हैं कि पिछले समय में मुख्य मंत्री जी ने यह किया, वह किया, यह करेंगे, वह करेंगे। इन्होंने जो वादे किये, योजनाए बनायीं, उनका कोई लेखा-जोखा इसमें नहीं है। बिजली की बातें इसमें कही गयीं पर कहीं भी ग्रामीण विद्युतीकरण की चर्चा इस अभिभाषण में नहीं की गयीं कि हम इतने गांवों का विद्युतीकरण करेंगे, गांवों में जहां लाइनें खींच दी गयीं हम वहां कनेक्शन देंगे या किसानों की जो पेंडिंग एप्लीकेशन्स हैं उनको हम कनेक्शन देंगे। इस तरह की इस अभिभाषण में कोई भी चर्चा कहीं नहीं की गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि क्या किसानों को मुख्य मन्त्रीजी बिल्कुल भूल गये, उनको कृषि कनेक्शन नहीं देंगे? मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाह रहा हूं, मैंने पिछले सैशन में भी विधान सभा में एक प्रश्न किया था कि राजस्थान में ऐसे कितने गांव हैं जहां पर लाइनें खींच दीं, ट्रांसफार्मर रख दिये पर एक भी कनेक्शन नहीं दिया। आपकी जानकारी के लिये, आप देख लीजिये आपके सचिवालय में, 3792 उस समय ऐसे गांव थे जहां इन्होंने एक भी कृषि कनेक्शन जारी नहीं किया। आज भी वही की वही स्थिति चली आ रही है। राष्ट्रपति शासन एक साल के लिये आया। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता पर मुख्य मंत्रीजी कम से कम यह तो कहते कि जिन गांवों में हमने कागजों में विद्युतीकरण कर दिया उन गांवों को कनेक्शन देंगे। इन्होंने एक तुरन्त प्राथमिकता योजना चलायी कि सारा किसान से खर्चा लेंगे और उद्योगपतियों के लिये इन्होंने उसी में एक प्रावधान किया, यदि उद्योगपति एडवांस स्कीम में कोई कनेक्शन लेगा तो हम उसके सारे पैसे का समायोजन बिलों में करेंगे। उद्योगपतियों और किसानों के बीच में कितना फर्क मुख्य मन्त्रीजी ने अपनी सरकार की रीति और नीति में किया है। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा और जो माननीय सदस्य बैठे हैं, ज्यादातर वह कहते हैं कि गांवों से आये हैं, किसान वर्ग के हैं, कहीं इस अभिभाषण में कृषि कनेक्शन की बात नहीं कही गयी। आज किसानों की हालत देख लीजिये। जब 85

(श्री परसादीलाल मीणा)

से 90 में सरकार में थी कांग्रेस, तब मुख्य मन्त्रीजी ने और विपक्ष के सदस्यों ने झुंझुनू में एक किसान की हत्या करवा दी, बीस-पच्चीस दिन तक राजस्थान बन्द करवा दिया, केवल दो पैसे बिजली के बढ़ाने पर। आज इकतीस से पैंतालीस पैसे तक सरकार ने बढ़ाये हैं। इन्होंने क्या नहीं बढ़ाया है? किसानों के लिये क्या सुविधाएं दी हैं? यह जब सारी बातें हैं, यह अभी तो राम-राम के नाम पर जीत कर आ गये पर मैं यह कहना चाहता हूं, अगली बार जब आओगे तो आपको किसानों के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा कि हमने किसानों के लिये यह किया। आज आपने गांवों का कागजों में विद्युतीकरण कर रखा है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में भी ऐसे हालात होंगे। उन गांवों को सबसे पहले आप दो-दो कनेक्शन की बात करते हैं, आज दो-दो कनेक्शन से कुछ नहीं होने वाला है। आप उस नीति को बदल कर दो की जगह पांच कनेक्शन की बात करें तो कोई समझ में आती है। पांच हजार की आबादी वाले गांव, दो हजार की आबादी वाले गांव, डेढ़ हजार की आबादी वाले गांव, आप उसमें पांच लाख रुपये खर्च करके उसका विद्युतीकरण करते हैं और परे जाकर दो कनेक्शन देते हैं। तो सरकार को चाहिए कि किसानों के भले के लिये काम करे। चालीस साल पहले तो हनुमान चालीसा होता था और आजकल हर माननीय सदस्य, भैरोंसिंहजी चालीसा का पाठ पढ़ रहा है। इनको कम से कम यह सोचना चाहिए कि हम किसानों के लिये क्या करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पांच ही कनेक्शन तक क्यों टिकते हैं? जो मांगे उनको दें कनेक्शन बिजली चली गयी तो। उसमें क्या आपत्ति है?

श्री परसादीलाल मीणा : वह तो, अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है अगर आप करा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : वही है, जब बिजली गयी है तो जो कनेक्शन मांगे उन्हें मिलें।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं-नहीं, वह करा सकते थे। पहली बार जब विद्युतीकरण करते हैं, यह केवल दो ही कनेक्शन दे रहे हैं, कम से कम उसको पांच तो करें आप जिसमे पांच किसानों का तो एक बार में ही भला हो। यह दो से आगे बढ़ाने की मंशा नहीं। दो भी कहां, यह एक भी देना नहीं चाहते।

दूसरी बात, मैं कहूंगा कि किसानों को जो बिजली आप रात को दे रहे हैं, वह भी दो घंटे-तीन घंटे दे रहे हैं। किसान को यह पता नहीं कि मेरी बारी बिजली की कब आयेगी, रात को आयेगी या दिन में आयेगी, सुबह आयेगी या आधी रात को आयेगी। इस तरह की व्यवस्था राजस्थान में चल रही है। आज यदि उसकी फसल सूख गयी तो फिर बाद में उसको बिजली देने से क्या फायदा है। कम से कम किसान को बारह घंटे बिजली आप लगातार दें और उसी समय दें। अगर बाद में आपने दी, एक महीने बाद, फसल सूखने के बाद आपने इन्तजाम किया बिजली का, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज की बात

(श्री परसादीलाल मीणा)

आयी। इन्होंने माननीय सदस्यों से सुझाव मांगे हैं कि हम प्रशासक मनोनीत करें तो उसका क्या आधार हो। अब यह हम क्या समझायें बात मुख्य मंत्रीजी को, राज्यपाल महोदय के मुंह से कहलवा लिया गया। आप चुनाव कराइये। हमारा तो यह सुझाव है, जल्दी से जल्दी चुनाव कराइये। आप अमेण्डमेंट की बात जो कर रहे हैं, क्यों नहीं इस सैशन को चाहे दो दिन, तीन दिन बढ़ाकर आपको लाना पड़े पर आपको गांवों की स्थिति सुधारनी है। जो सरकार में मंत्री बैठे हैं वह भी गांवों से आये हैं। आज पंचायतों की क्या हालत है? अध्यक्ष महोदय, आपके भी इलाके में पचायतें हैं। एक सैक्रेटरी के पास तीन और चार पंचायतें हैं। सैक्रेटरी अपनी जेब में पचायत को लेकर घूमता है। विकास कार्य को कोई देखने वाला नहीं है। जे. ई. एन., बी. डी. ओ. और सैक्रेटरी मिल गये, सारी एम बी. भर ली, सारा पेमेण्ट कर दिया, कोई काम को देखने वाला नहीं है क्योंकि बी. डी. ओ. ही तो वहां पर बॉस है उसका। कौन देखेगा आज उस काम को? जवाहर रोजगार योजना का पैसा भ्रष्टाचार मे जा रहा है। आज हर सैक्रेटरी के पास मोटर साईकल और जीपें कहां से हो गयीं दो-ढाई साल में? इस भारतीय जनता पार्टी के राज ने गांव-गांव में भ्रष्टाचार का जो अड्डा पंचायतों को भंग करने के बाद फैलाया है, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि यह जो सारे काम प्रशासकों के माध्यम से हुए हैं, उनकी एक-एक की जांच होनी चाहिये, एक-एक काम का तखमीना जो जे. ई. एन. ने बनाया है, उसका दूसरे विभाग से पी. डब्ल्यू. डी. से असेसमेंट होना चाहिए कि यह काम गांव में हुआ या नहीं हुआ है। इस तरह का आज भ्रष्टाचार गांवों में फैला हुआ है।

दूसरी बात जो पेयजल की है सारी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। कहीं पाइप नहीं है, कहीं कनेक्शन नहीं हैं तो कहीं पर टकी नहीं हैं। इस तरह की अव्यवस्था आज गांवों में फैली हुई है। अध्यक्ष महोदय, गर्मी आने वाली है, यह मार्च के बाद जाकर उसका प्लान बनायेंगे। कण्टिन्जेन्सी प्लान जब गर्मी आ जायेगी तब बनायेंगे और वह काम कब होंगे? बारिश के समय होंगे जब पानी की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों नहीं सरकार इमीजियेट अभी इस प्लान को बनाकर इसके लिये पैसा देकर उन कामों को शुरू कराये। जिसकी जरूरत आपको दो महीने बाद, तीन महीने बाद आने वाली है। अध्यक्ष महोदय, आज गांवों में पानी की हालत तो यह हो गयी कि पानी का स्तर प्रति वर्ष दस फीट नीचे जा रहा है और जो हमने पांच साल या छह साल पहले हैण्ड-पम्प लगाये थे वे आज बिल्कुल सूख गये हैं, और अबेन्डड घोषित हो गये हैं। आज गांव के लोगों को पीने के पानी के लिये कोई साधन नहीं है। यदि गांव में बिजली नहीं आये तो गांव के लोग सुबह से शाम तक बिजली की बाट जोहते रहते हैं, कब बिजली आये और कब पानी पीवें। इस तरह के गांवों में आज हालात हो गये हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्य के बारे में। 16 या 17 जिलों की रिपोर्ट आ गयी, मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हम एक जनवरी से या अभी कुछ कामों को शुरू करा देंगे, 31 दिसम्बर को यहां बहस हुई थी, आज तक न कोई

(श्री परसादीलाल मीणा)

अकाल राहत कमेटियां बनायी गयी हैं, न अकाल राहत कार्य शुरू करने की कोई बात है। आज कहीं भी एक भी काम शुरू नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं कि यह अकाल राहत कार्य जल्दी से जल्दी शुरू कराये जाने चाहिए।

शिक्षा के मामले में, मैं कहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे मंत्रीजी ने एक घोषणा की थी, अभी मैंने एक अखबार मे पढ़ा था कि हम ढाई सौ की आबादी के हर गांव मे स्कूल खोलेंगे। सिद्धान्ततः खोलने चाहिए। पिछली सरकार ने भी छह हजार स्कूल खोले थे। 250 की आबादी तक के गांवों में स्कूल थे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाक का सवाल बनाया कि यह 6 हजार स्कूलें कांग्रेस ने खोले हैं। वहां पर भवन भी बन गये थे, विद्यार्थी भी पढ़ रहे थे, सारी व्यवस्था ठीक चल रही थी पर उन स्कूलों को बन्द करने के बाद आज भी गांव वाले यह कहते हैं कि इस भवन में हम क्या करें, इसका उपयोग क्या करें, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिये कहां भेजें। आपसे मेरा अनुरोध है कि इस सरकार को चाहिए कि जो 6 हजार स्कूल खोले हैं उनको प्राथमिकता से चालू करें। सीनियर स्कूल खोलें। मैंने तो ढाई साल तक का राज देखा है, राजनीतिक आधार पर स्कूल खोले जाते हैं। हम कांग्रेस के पचास एम. एल. ए. पिछली बार थे, इस बार हम 76 हैं। हमारे किसी भी एम. एल. ए. की कांस्टीट्यूएन्सी में कोई सीनियर, कोई सैकण्डरी कोई मिडिल स्कूल एक भी नहीं खोली। इस तरह के द्वेष की भावना से यह सरकार काम करेगी? आज राजस्थान का सर्वांगीण विकास करने वाली सरकार इस तरह से काम करें कि जहां कांग्रेस के एम.एल.ए. हैं वहां काम नहीं करेंगे, इस तरह का भेदभाव आपको नहीं करना चाहिए।

मैं यह कहूंगा कि पंचायतों के चुनाव आप शीघ्र करवायें जिससे गांवों में जो अव्यवस्था हो गयी है और गांव के लोगों के शासन का जो अधिकार आप लोगों ने छीन लिया है उस अधिकार को गांव के लोगों को वापस दें। पंचायत राज के माध्यम से जो हमारी जवाहर रोजगार योजना है उससे गांवों का विकास हो। गांवों के विकास के लिये सरकार को सबसे पहले यदि कोई काम करना है तो भ्रष्टाचार मिटाना है। गांवों का विकास करना है तो आपको सबसे पहले पंचायतों के चुनाव करवाने चाहिए।

आपने समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर बनीपार्क से आने वाले विधायक श्री राजपाल सिंहजी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र के अन्दर चुनी हुई सरकारों को भंग करना एक अलोकतान्त्रिक कार्यवाही है।

राजस्थान प्रदेश की सरकार राजस्थान के विकास के लिये, राजस्थान की समस्याओं का समाधान करने के लिये जनता की आशाओं के अनुरूप कार्य कर रही थी परन्तु

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

15 दिसम्बर, 1992 को केन्द्रीय सरकार ने और प्रधान मंत्री माननीय श्री नरसिम्हा राव जी ने धारा 356 के आधार पर राजस्थान की सरकार को भंग किया, यह एक अलोकतान्त्रिक कार्यवाही थी। इस अलोकतान्त्रिक कार्यवाही के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के विकास के लिये राजस्थान में चुनाव लड़ा, चुनावों के अन्दर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया और उसके परिणामस्वरूप राजस्थान के मुख्य मंत्री, माननीय श्री भैरोंसिह जी शेखावत बने।

अध्यक्ष जी, राजस्थान का जिस तरह से विकास हो रहा था राष्ट्रपति शासन के अन्दर सारा विकास रुक गया। समस्या वहीं की वहीं रुक गयी। विपक्षी सदस्य अभी बिजली और पानी की चर्चा कर रहे थे। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि 11 महीनों में राजस्थान के अन्दर मात्र अधिकारी शाही रही, मात्र अफसरशाही रही, जनता की कोई सुनने वाला नहीं था जिसके कारण जो योजनाएं थीं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किसी ने नहीं किया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस अभिभाषण के अन्दर राज्यपाल महोदय ने जोधपुर की जल समस्या के समाधान के लिये सरकार का संकल्प दोहराया है। पिछले तीन वर्षों में जोधपुर शहर की पेयजल समस्या के समाधान के लिये माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिहजी शेखावत ने और जलदाय विभाग के मत्री माननीय भंवरलाल जी शर्मा ने जो कार्य किया है, उसको जोधपुर की जनता भूल नहीं सकती। 1984 में जोधपुर लिफ्ट कैनाल का कार्य शुरू हुआ था और 1990 तक उस कार्य को किसी भी प्रकार की गति नहीं मिली। जो जमीन किसानों की आ रही थी, न उसको मुआवजा मिला, न पाइप के लिये निर्णय किया गया और जो पम्प हाउस बनने वाले थे, उसके लिये भी कोई निर्णय नहीं किया। 1990 से 1993 तक जोधपुर के पेयजल की समस्या के समाधान के लिये मुख्य मंत्रीजी ने जो रुचि ली उसके कारण जोधपुर लिफ्ट कैनाल पर तीन वर्षों के अन्दर 115 करोड़ रुपये खर्च किये गये। उससे पहले जोधपुर लिफ्ट कैनाल का जो 6 वर्ष से कार्य चल रहा था, मात्र 50 किलोमीटर में काम चल रहा था, कुछ मिट्टी का काम चल रहा था और मात्र 17 किलोमीटर में टाइल्स का काम चल रहा था। उसके बाद आज जब भैरोंसिहजी की सरकार ने संकल्प लिया कि जोधपुर की पेयजल की समस्या का समाधान करना है तो उन्होंने 209 किलोमीटर जो लाइनिंग का काम था वह पूरा करवाया। उसमें उन्होंने देखा कि कैनाल के अन्दर पानी लाने में देरी हो सकती है। देरी होने के कारण इसके अन्दर अस्थायी पम्प स्टेशन लगाकर, आपातकालीन योजना बनाकर जोधपुर को पानी दिया। आज जोधपुर की जनता हिमालय का पानी पी रही है चाहे वह कम मात्रा में ही पी रही हो। जोधपुर लिफ्ट कैनाल में देरी होने का कारण राष्ट्रपति शासन ही है। जब नहर के अन्दर मिट्टी आ चुकी थी, मिट्टी हटाने के लिये बार बार ध्यान आकर्षित करने के बाद भी राष्ट्रपति शासन में उस मिट्टी को हटाया नहीं गया। मैकेनिकल पम्प जिसके टेण्डर एक साल पूर्व नवम्बर, 1992 में हो चुके थे, उसको एक साल हो चुका है, उसके

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

भी राष्ट्रपति शासन में आदेश नहीं दिये गये। इस प्रकार की समस्याओं की जो चर्चा करते हैं, आज जोधपुर का, पूरा पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र बिजली के कारण जी स्थिति भुगत रहा है वह 11 महीने के राष्ट्रपति शासन की देन है। 11 महीने के अन्दर जोधपुर की जो योजनाएं थीं 220 का जो ग्रिड स्टेशन जोधपुर में लगने वाला था, और लाइनें लगने वाली थीं, वह सारा का सारा काम ठप्प पड़ा रहा। इस कारण किसान को पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। इसका सारा दोष यदि कहा जाये तो राष्ट्रपति शासन की प्रणाली का है। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि चुनी हुई सरकारों को भंग करने की जो धारा 356 है, इसका विरोध करना चाहिए ताकि इस प्रकार की अलोकतान्त्रिक कार्यवाही करने का केन्द्र सरकार कभी भी साहस नहीं करे।

अध्यक्ष जी, पश्चिमी राजस्थान में पिछले 11 महीने में बहुत कम बरसात हुई है। कम बरसात होने के कारण आज अकाल की स्थिति होती जा रही है। राष्ट्रपति शासन के अन्दर इसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। न अकाल राहत कार्य खोले गये न पानी और चारे की व्यवस्था की गयी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जो अकाल की स्थिति है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ की जो स्थिति है, उसकी ओर ध्यान दें और पानी की जो स्थिति जोधपुर के अन्दर बनी हुई है उस पर ध्यान दें जिससे जोधपुर की जनता को पूरा पानी मिल सके।

आपने बोलने के लिये समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी (अनुपस्थित)। श्री शांतिलाल चोईवाल (अनुपस्थित)। श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के द्वारा जिस अभिभाषण का सदन के समक्ष पठन किया गया है, उस अभिभाषण का अध्ययन करने के बाद में उस पर धन्यवाद प्रस्ताव जो रखा गया है उसके पक्ष में इसलिये समर्थन नहीं कर सकता हूं क्योंकि उस अभिभाषण में न कोई दिशा है, न दृष्टि है, न कोई नीति है, न कोई कार्यक्रम है।

जैसा आप सबने अनुभव किया होगा कि उसमें शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, पेयजल की समस्या के समाधान के बारे में और सिंचाई सुविधाओं के बारे में किसी प्रकार की योजना का सही चित्रण प्रस्तुत नहीं हुआ है। जिससे यह अभिभाषण दल विशेष की विचारधाराओं से तैयार करके प्रस्तुत किया गया है वह किसी भी दृष्टि से स्वागत योग्य नहीं है। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि बार-बार यह कहा गया कि राजस्थान की जनता ने एक जनादेश दिया है और वह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर राजस्थान के मतदाताओं का जो रुझान है, वह मेरी यह मान्यता है कि 61.42 प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध रहा है। हकीकत में तो यह सरकार निर्दलीय सदस्यों की

(श्री रतनलाल ताम्बी)

बैशाखियों पर जोड़ तोड़ से बनी है जिससे न कोई जन आकांक्षा पूरी हो सकती है और न कोई जनता जो अपेक्षाएं उनसे कर रही थीं वह पूरी हो सकती है।

इस सरकार के द्वारा राजस्थान में 57 शिड्यूल्ड कास्ट, 16 शिड्यूल्ड ट्राइब्स की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिलने की बात कही जाती है पर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक भ्रमजाल, मायाजाल लगता है। जो राजस्थान की सरकार बनी है उस सरकार पर दृष्टिपात करें तो जिस पार्टी का एस.सी. और एस.टी. के लोगों ने इतना समर्थन किया, उस पार्टी की सरकार में इन जातियों का एक भी केबिनेट मंत्री नहीं है। मैं सोच रहा था कि हमारे जिले के प्रतिभाशाली अनुभवी व्यक्ति के रूप में कैलाश मेघवाल को समाविष्ट किया जायेगा। मैं समझता हूं ऐसे व्यक्ति इस मंत्रिमण्डल से बाहर हैं तो अनुभवहीन लोगों की सरकार जिस प्रकार राज चलायेगी। यह कहा गया कि कैलाश मेघवाल को कोई जिम्मेदारी दी गयी थी और उन्होंने इस जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया इसलिये उनको मंत्रिमण्डल में सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं आपके मार्फत अनुरोध करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की जिम्मेदारी और जो अपेक्षा उनसे की गयी थी वह वास्तव में पूरी होने के काबिल नहीं थीं। इसलिये हमारे जिले की जनता और हमारे एस.सी. के लोग जो उनके प्रति काफी आशाएं लगाये बैठे थे, उन पर कुठाराघात हुआ है। सदन के नेता महोदय यहां पर बिराजमान नहीं हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम इस तरीके के दायित्व का उन पर चार्ज लगा कर उनको महरूम करने की बात यदि सत्य है तो मैं समझता हूं इस बारे में विशेष तौर से सहानुभूति मेरी है, हमारे जिले की जनता की भी है और जिले के एस.सी. के लोगों की और राजस्थान की जनता की है। जब उस पर विचार किया जायेगा तब जाकर मैं मानूंगा कि एस.सी. के प्रति यह सरकार वास्तव में जो कहती है वही करती है।

मैं इस मौके पर आपके सामने यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मैंने इस सारे अभिभाषण को पढ़ा है, इसमें किसी योजना के बारे में स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं की गयी है। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में इस समय अकाल की स्थिति गम्भीर है, पेयजल की स्थिति गम्भीर है और इस गम्भीर स्थिति में किसी बात का मास्टर-प्लान अभी तक नहीं है। कौनसी योजना कब लागू होगी, पता नहीं लगता। 1989-90 में हमारे जिले और हमारे क्षेत्र की कई पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई थीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 वर्ष में यह योजनाएं क्रियान्वित नहीं हुई। इस सरकार से और क्या आशा की जाये? इस तरह की योजनाएं जहां काफी गम्भीर स्थिति थी, जहां जनता बहुत परेशान थी, आज भी क्रियान्वित नहीं हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, बड़ी चर्चा की जा रही थी प्रगति और विकास की, मैं आपकी मार्फत राजस्थान सरकार को जानकारी देना चाहता हूं कि 1989-90 में जो सिंचाई बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में प्रारम्भ हुए थे, वह आज ज्यों के त्यों पड़े हैं। किसी में 30 लाख रुपया खर्च हो गया, किसी में 25 लाख हो गया और केवल

(136)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

नहरों की खातिर वह योजनाएं जहां की तहां हैं।

इसी प्रकार शिक्षा के बारे में मेरा निवेदन है कि इस बारे में इस सरकार की कोई नीति स्पष्ट नजर नहीं आती। 1989-90 में लगभग 5-6 हजार के बीच में प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुए थे। आप प्रगति की बात करें तो उसके पहले उसके आधार की बात को भी स्पष्ट सामने लाना चाहिये। वह सब के सब स्कूल बन्द कर दिये गये, अस्पताल बन्द कर दिये गये, सड़कें अधूरी वहीं की वहीं छोड़ दी गयीं और पशु चिकित्सालय जो स्वीकृत हुए थे, वह आज तक चालू नहीं हुए। यह क्या प्रगति है, किस बात का धन्यवाद अभिभाषण के माध्यम से सरकार चाहती है? इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार ने जो अभिभाषण यहां प्रस्तुत किया है यह केवल दस्तावेज है। राजस्थान सरकार किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है? यह सही है कि हमारे मुख्य मंत्री आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहन लाल जी सुखाड़िया, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को बनाया, भूगोल को बदला, अनुसरण करने का काफी प्रयत्न करते हैं। मैं इस बात के लिये तो उनका धन्यवाद करना चाहता हू। राष्ट्रीय स्वयं सेवक जैसी संस्थाओं के चारों ओर से फसाने के बावजूद वह किसी तरह सरकार बना पाये परन्तु सरकार बना पाने के बाद प्रगति और विकास की बात के लिये उनको आज सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं राजस्थान के उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां चिकित्सा सुविधाओं की बड़ी आवश्यकता है, दो-दो वर्ष से डाक्टर नहीं हैं, कम्पाउण्डर नहीं हैं, नर्सें नहीं हैं, परन्तु इस सरकार ने इस दिशा में भी कोई नीति स्पष्ट नहीं की है।

मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल की विभीषिका है। जनवरी में आपने कहा कि हम काम आरम्भ करेंगे। जिला प्रशासन से मालूम किया कि कोई सरकार का नोटिस है, यहां तक कि अकालग्रस्त गाव जो घोषित किये जाते हैं सितम्बर में, गिरदावरी के बाद जनवरी महीने में, वह भी घोषित नहीं किये गये। कब अकाल की योजना बनायेंगे कब काम चलेंगे यह एक गम्भीर सवाल है और इस पर गम्भीरता से चिन्तन की आवश्यकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं बिजली के बारे में। 1952 में राजस्थान में करीब 8 मेगावाट बिजली जहां आती थी वहां बढ़ते-बढ़ते आज करीब-करीब, मैं समझता हूं, राजस्थान की जो स्थिति है उसके हिसाब से बिजली का बहुत अभाव है। अभाव की स्थिति यहां हो रही है। आज हम जयपुर में बैठे हुए विधान सभा में जगमगाती हुई बिजली देखते हैं और गांवों में हमारे क्षेत्रों में बिजली के बिना अंधेरा चारों ओर नजर आता है। किसानों को रात को कभी-कभी बिजली मिलती है, मीटर बहुत चलता है। किसान परेशान है परन्तु कोई सुनने वाला नहीं है। नये कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। उनकी दरें भी भारी मात्रा में बढ़ा दी गयीं। किसान उनको दे नहीं सकता है। तो सरकार की इस तरह की नीति है जिससे किसानों का हित नजर नहीं आता। मैं समझता हूं किसानों की बिजली के बारे में राजस्थान के आये हुए लोग बहुत गम्भीर चिन्तन करेंगे। आज किसान गांव-गांव इकट्ठे होकर सहायक

(श्री रतनलाल ताम्बी)

अभियन्ता और अभियन्ताओं के घरों पर चक्कर लगाता है और धक्के और गाली खाकर वापस लौटता है। निराशा का वातावरण चारों ओर बना हुआ है। इस आधार पर आज बिजली की समस्या पर चिन्तन करने की बड़ी आवश्यकता है। फसल खराब हो गयी तो राजस्थान आर्थिक दृष्टि से जहां आत्मनिर्भरता की बात की जाती है वहां बहुत पिछड़ जायेगा, यह मेरा निवेदन है।

मैं इस मौके पर थोड़ी-सा ध्यान पीने के पानी की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज सैकडों की तादाद में हैण्डपम्प बिल्कुल सूखे पड़े हैं। उनका संधारण नहीं हो रहा है। उनको कोई देखने वाला नहीं है। पानी का स्तर नीचे चला गया। पाइप खराब हो गये। उनको ठीक नहीं किया जाता है। यह कब किया जायेगा ? त्वरित योजनाएं कागजों में अभी आपने बना रखी होंगी लेकिन मौके पर हालात बहुत खराब हैं। इन सारी समस्याओं को इस अभिभाषण में आपने व्यक्त नहीं किया। अतः मैं इसका समर्थन करने में वास्तव में अपने आपको सक्षम नहीं मानता कि इस प्रकार के अभिभाषण का समर्थन किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजस्थान की मूलभूत समस्या है अकाल की, पानी की, बिजली की, इसके बारे में सरकार को इसी सदन में एक-दो दिन में स्पष्ट घोषणा करके कार्यक्रम देना चाहिये। हम लोग गांव में जायेंगे तब लोग पूछेंगे कि आपने 15 दिन जयपुर में रह कर क्या किया ? यह सरकार जो किसी भी तरह समस्या के प्रति जागरूक नहीं है, उसमें आप लोगों ने क्या चेतना पैदा की, क्या उनका ध्यान आकर्षित किया ? इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राजस्थान सरकार से अनुरोध करना चाहता चाहता हूं कि केवल कागजों में आपने राज्यपाल महोदय से कुछ लिखवा दिया उससे काम नहीं चलेगा, वास्तव में भौतिक दृष्टि से उपलब्धियां आपकी सामने आयेंगी तब जाकर काम चलेगा।

अन्त में मैं पंचायती राज के बारे में कुछ निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं परिचित हैं 1959 में राजस्थान में पंचायती राज स्थापित हुआ था, स्वर्गीय मोहनलालजी सुखाड़िया ने उस समय देश में सर्वप्रथम लागू किया और सारे देश ने उसका अनुसरण किया था। उस पचायती राज की आत्मा निकल गयी। बार-बार अमेंडमेण्ट होते-होते एक तरह से खोखला पंचायती राज हो गया और नौकरशाही के हाथों में कराह रहा है। मैं कहता हूं कि पंचायती राज का कानून बिल्कुल नये ढग का क्रांतिकारी बनाया जाये। पंचायतों के पुनर्गठन के नाम पर जो तमाशा पिछली बार हुआ, किन्हीं जिलों में कम जनसख्या होते हुए अधिक पंचायतें गठित कर दी गयीं, बड़े-बड़े जिलों में ज्यादा पंचायत अधिक जनसंख्या होते हुए गठित नहीं की गयीं। जनता की भावना के साथ उसमें बड़ा कुठाराघात किया। जनता से एतराज लिये गये, सैंकड़ों की तादाद में लोगों ने एतराज प्रस्तुत किये मगर नौकरशाही ने उन सारे एतराज को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि 1991 की जनसंख्या सामने आ चुकी है, नये मजरे और ढाणी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

काफी बदल गये, आबादी जगह-जगह इधर से उधर हो गयी. इन सब बातों को देखते हुए राजस्व मण्डल के एक सदस्य का अध्यक्षता में कमेटी बनाकर उसमें एस. डी. ओ. हों, तहसीलदार हों उसमें खण्ड अधिकारी हों, विधायक हों, उसकी मार्फत पंचायतों का पुनर्सीमांकन नयी जनसंख्या के आधार पर करके जल्दी से जल्दी इस पंचायती राज को बहाल किया जाये ताकि जन आकांक्षाओं के आधार पर विकास का कुछ काम हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

श्री भीमराज : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी दिया था. मैं सुबह से मेरी बारी का इन्तजार कर रहा था।

श्री अध्यक्ष : आ जायेगा। मैंने आपका नाम पुकारा था।

श्री भीमराज : हां, मैं बाहर चला गया था।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं, बोल लेना, फिर आ जायेगा।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन नहीं करता।

राज्यपाल ने जो यहां भाषण दिया उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन जो अभिभाषण के अन्दर बात बतायी गयी है, खास तौर से बिजली के बारे में, जब से यह सरकार बनी है तब से बिजली गायब है। आप स्वयं 13.12. से स्वयं मानते हो कि बिजली किसानों को पूरी नहीं मिल रही है। जब हमने बुवाई की थी उस समय बिजली 20 घण्टे, 15-15 घण्टे काश्तकारों को दी गयी। हमने उसके अनुसार बुवाई कर दी लेकिन ज्यों ही चुनाव समाप्त हुए, परिणाम घोषित हुए उसके बाद में दो-दो घण्टे ही बिजली मिलती है और उसमें भी दस बार ट्रिपिंग होते हैं। काश्तकार जब अपनी मोटर चालू करके अपने खेत में खड्डे में पानी पिलाने के लिये फसल में जाता है तो दो मिनट बाद फिर बिजली बंद हो जाती है। इस बिजली की बेचैनी के कारण हमारे किसान की आंख का आंसू नहीं टूट रहा। आज किसान बहुत परेशान है। किसान की हालत यह है कि वह कर्ज में ही पैदा होता है, कर्ज में ही रहता है और कर्ज में ही मरता है। आज बिजली के जो बिल दिये जा रहे हैं, आपकी जो आडिट होती है, वह तीन-तीन साल से होती है और किसानों से एवरेज चार्ज लिये जा रहे हैं। ज्यों ही यह सरकार बनी है, किसी के 10 हजार का बिल, किसी के 15 हजार का बिल, किसी के 7 हजार और किसी के 3 हजार का बिल आ रहा है इस प्रकार की गलत आडिट के आधार पर जहां खारे कुएं हैं और सिर्फ एक फसल होती है, उन पर भी एवरेज चार्ज लगाया गया है। बिजली एक महीने में एवरेज अगर 20 घण्टे मिली है, उसके आधार पर एवरेज चार्ज लगा करके तीन साल के बाद में बिल भेजा जाता है। काश्तकार की फसल पकी नहीं है और अभी उनसे बिल वसूल किया जा रहा है। इसको वसूल करने से रोका जाये और जो गलत आडिट हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए।

(श्री अमराराम चौधरी)

आज जो हमारी आर्थिक नीति है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। इसमें भ्रष्टाचार मिटाने की जो बात है उसके लिये क्या होना चाहिए, उसके बारे में अभिभाषण में कहीं नहीं बताया गया है। मेरा यह मानना है, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह सुझाव देता हूं कि आज जो भी बात की जाती है कि पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस के सिपाही ने पैसे ले लिये लेकिन बड़े-बड़े हमारे जो सफेद हाथी हैं, जो लाखों-करोड़ों रुपये डकारते हैं उनका कुछ नहीं होता। पुलिस के कर्मचारियों के लिये एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि कोई भी राज्य सरकार में भर्ती हो, 12 महीने के लिये उसको आधी तनख्वाह दी जाये और आधी फिक्स डिपोजिट की जाये और जब वह रिटायर होगा तो एक मामूली सिपाही को भी 10 लाख रुपये मिलेंगे। उससे वह कभी भी भ्रष्ट नहीं बनेगा। हर नौकरी के अन्दर हो। बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है और इसको लागू कर....

श्री अध्यक्ष : तब तक उसके परिवार के कितने लोग जिन्दा रहेंगे ?

श्री अमराराम चौधरी : मैं यह कह रहा हूं कि जब 22 साल का आदमी होता है तो नौकरी लग जाती है। एक साल के लिये उसको आधी तनख्वाह दीजिए। मान लीजिए, अगर आज उसको 24 हजार रुपये साल के मिलते हैं, उसको 12 हजार रुपये दीजिए और 12 हजार रुपये फिक्स डिपोजिट करवा दीजिए उसके बाद आप पूरी तनख्वाह देते रहें। यह जो 12 हजार हैं, 38 साल तक वह नौकरी करेगा तब तक 10 लाख से अधिक मिलेंगे, उसको इससे वह अपने बच्चों की पढ़ाई भी करवा सकेगा, बच्चों का विवाह भी कर सकता है और अपना मकान भी बना सकता है। इस प्रकार के सुझाव यदि सभी नौकरियों में लागू कर दें, कोई भी आई.ए.एस. अफसर हो, सिर्फ एक साल की आधी तनख्वाह ही है, तो उस पर भी कभी किसी प्रकार के लांछन नहीं लगेंगे। निज पर शासन फिर अनुशासन, यदि अपने आप कोई आदमी यह कन्ट्रोल करे कि मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना है, मुझे देश को अपना देश समझकर काम करना है जो भावना जब तक यह नहीं होगी तब तक यह देश नहीं सुधरेगा। इसलिए लोगों की भावना अपने आप बदलनी चाहिए।

गुजरात का एक डायरेक्टर जनरल था पुलिस का। मैंने यह पूछा, आप घर में इतने सादे क्यों रहते हैं, आपके सिपाही, आपके थानेदार, आपके डीवाई. एस.पी. ने बड़े-बड़े बंगले बनाये हैं और आप अभी डायरेक्टर जनरल बन गये फिर भी आप बड़े सादे हैं? उन्होंने कहा, भाई, यह तो मेरे अपने हाथ की बात है। मैं झोंपड़ी में रहने वाला था, मैं यहां तक आ गया, अब मुझे पैसों का क्या करना। इसी प्रकार से लोग जब मन में यह विचार कर लेंगे तो यह देश बहुत अच्छा बन सकता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर, जो मेरा क्षेत्र है पचपदरा, टेल एण्ड की डिस्ट्रिक्ट है अकेली, वहां पर बिजली बहुत ही कम मिल रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो इतने दिन तक आपने तीन या चार घण्टे बिजली दी है, उन काश्तकारों की क्षतिपूर्ति के लिये आप कम

(श्री अमराराम चौधरी)

से कम 12 घण्टे बिजली दें। मेरा निवेदन यह भी है कि जो उद्योग लगे हुए हैं आपके, उन उद्योगों के अन्दर महीने भर के लिये बिजली आप कम दीजिए। इनको 24 घण्टे दे रहे है, वहां 12 घण्टे दीजिए क्योंकि यह फसल है यह एक बार जब मर जायेगी, काश्तकार की फसल चौपट हो जायेगी तो यह वापस नहीं हो सकती। काश्तकार जो रो रहा है, आज जो इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है,

"श्वानों को दूध मिलता यहां,
भूखे बच्चे अकुलाते हैं,
मां की गोदी में ठिठुर-ठिठुर कर
जाड़ों की रात बिताते हैं।"

आज यह काश्तकार खेत के अन्दर इस जाड़े के अन्दर, ठण्ड के अन्दर बार-बार अपनी मोटर चालू करके खेत में जा रहा है। उसके पास पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं। वह गहना बेच रहा है। उसको यदि आप 12 घण्टे बिजली नहीं देंगे तो वह किस प्रकार से अपनी फसल को जीवित रख कर समय पर सरकार का कर्जा और अपना कर्जा चुका सकेगा और अपनी साहूकारी रख सकेगा? हमारे देश की जो इस प्रकार की आर्थिक नीति है, उसमें परिवर्तन....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

करना पड़ेगा। आज कुछ तो ऐसी औरतें हैं,

"पीली सूं गोरी लड़ालूम,
दबती चाले झूम-झूम।"

एक ऐसी औरतें हैं जिसके सोना ही सोना है और दूसरी के पहनने के लिये कतीर भी नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था है। इसमें जब तक आप परिवर्तन नहीं करोगे, इस प्रकार से काश्तकारों की गांव में जो हालत हो रही है उसको आप नहीं सुधारोगे तो यह आपका राज बहुत दिन नहीं चलेगा और काश्तकार, गांव की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आज गांव में खाने के लिये अनाज नहीं पीने के लिये पानी नहीं। मेरे क्षेत्र पचपदरा में....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

गांव के अन्दर पीने का जो पानी है वह बिल्कुल नहीं जा रहा है।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डा. शंकरलाल (अनुपस्थित)। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बनीपार्क से आये विधायक ने जो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा उसका मैं समर्थन करती हूं तथा भाजपा सरकार की उपलब्धियों एव निश्चयों के प्रति आस्था व्यक्त करती हूं।

1990 में श्री भैरोंसिंह जी शेखावत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन स्थापित किया, अपव्यय को रोका और राजस्व में होने वाली चोरी पर अंकुश लगाया जिसे योजना आयोग ने भी सराहा। इन कारणों से आठवीं पंचवर्षीय योजना के आकार में अन्य राज्यों की तुलना में 283 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक वर्ष के राष्ट्रपति शासनकाल के दौरान विकास क्रम थम गया,

(41)

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

अतिरिक्त ससाधन जुटाने हेतु निष्ठापूर्वक प्रयास नहीं किये गये। वस्तुत: राष्ट्रपति शासन कांग्रेस (ई) को जिताने की भूमिका बनाने में लगा रहा। सलाहकारों द्वारा माननीय संवेदनाओं को परे रखकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। सिंचाई के लिये उपलब्ध पानी के उपयोग हेतु बनाई जल वितरण समितियां निष्प्रभावी रहीं।

पेयजल समस्या की गम्भीरता को देखते हुए श्री भैरोंसिंह शेखावत सरकार के संवेदनशील प्रयास निस्सदेह सराहनीय हैं। वर्तमान सरकार द्वारा जोधपुर वृहद जलोत्थान योजना, बीसलपुर जल परियोजना को शीघ्र पूरा करने तथा बीकानेर में बीछवाल जलाशय का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का निश्चय स्वागतयोग्य है। प्रशासन चुनी गयी सरकार के प्रति उत्तरदायी है और भाजपा सरकार द्वारा वर्ष के आरंभ में विभागों, प्रशासनिक सचिवों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को लक्ष्य देकर अनेक कार्यों का मूल्यांकन करना सराहनीय प्रयास है। राज्यों में निरंतर बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के क्रम में नौकरियों पर लगी रोक को तुरन्त हटाया जाना चाहिए। राज्य में महिला शिक्षा को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिये निष्ठापूर्वक प्रयास करने चाहिए। राज्य के विकास को गति देकर अन्य विकसित राज्यों के बराबर लाने के लिये विकास व्यवस्था व विकास संरचना में परिवर्तन, व्यापक सहमति से योजनागत प्राथमिकताओं व कल्याणकारी कार्यक्रमों का पुन: निर्धारण करने के राज्य सरकार के दृढ़ निश्चय के प्रति मैं आस्था व्यक्त करती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति शासन के अन्दर कई ऐसे कार्य थे जो कि पूरे करने थे वे सारे कार्य अधूरे रह गये इसलिए आज जोधपुर शहर की जनता पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रही है। अगर साल भर और भैरोंसिंहजी की सरकार रहती, यह राष्ट्रपति शासन नहीं रहता तो जोधपुर के अन्दर पानी की समस्या का जल्दी ही हल हो जाता मगर राष्ट्रपति शासन के अन्दर यहां ऐसी अव्यवस्था हुई जिसका आज तक हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिर भी मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज। **(व्यवधान)**

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : आप ही इस बात के जिम्मेदार हो। आपकी ही चलती थी राष्ट्रपति शासन में।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीया सदस्या कह रही थीं कि पानी की अव्यवस्था हुई। जवाई डेम के गेट खोले गये दो दफे। जब जवाई डेम के पानी का फुल इम्पाउण्डमेंट होता है तो जोधपुर में जितना भी पानी केरी कर सकती है केरियर, कैनाल, बराबर बरसात का मीठा पानी मिल रहा था, यह तो सौभाग्य की बात है कि जवाई भर गया। लूनी नदी जो है वह स्पेट में नहीं आयी है, ट्रिब्यूटरीज दो दफा स्पेट में आ गयीं। भाखरा की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है, पोंग की चिन्ताजनक है, गांधीसागर की जो स्थिति है पिछले साल से बहुत ज्यादा चिन्ताजनक है और यह पन बिजली उत्पादन के ऊपर भी प्रतिकूल असर डालेगा, इसलिए माननीया सदस्या जिस अव्यवस्था की बात कर रही थी वह तो एक रिआर्गेनाइजेशन

(श्री परसराम मदेरणा)

और ऊंचे स्थानों पर पानी नहीं पहुंच रहा था, पानी तो बहुत अवेलेबल था।

श्री भीमराज (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण के लिये मैं व्यक्तिगत तौर पर तो उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन माननीय सदस्य श्री राजपाल सिंहजी शेखावत द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं कड़ा विरोध करता हूं।

बात तो, माननीय मुख्य मंत्रीजी, बहुत छोटी सी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटी सी बात है। आप तो तीन बार मुख्य मंत्री बन चुके हैं +++ लेकिन +++ आपने सरकारी मंत्रियों के लिये और दूसरे लोगों के लिये तो सारी व्यवस्थायें कर रखी हैं लेकिन +++ इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, ये +++ नहीं बोल सकते हैं। +++ किसको कहते हैं, इनको मालूम ही नहीं है, +++ क्या होते हैं।

श्री भीमराज : नहीं, अगर मैं कुछ गलत बोला हूं तो नया सदस्य हूं।

श्री अध्यक्ष : आप विधान सभा के बारे में न बोलें तो ही अच्छा है। आप अपने विषय पर ही बोलिए।

श्री भीमराज : मैं उसके लिये क्षमा चाहता हूं +++ मैंने कुछ कह दिया तो मैं उसके लिये क्षमा चाहता हूं लेकिन उनकी जो स्थिति है उसके बारे में मैं अध्यक्ष महोदय, का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। +++

श्री अध्यक्ष : देखिए, इस सम्बन्ध में आप मेरे से अलग से बात करिये। हाउस में यह सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए क्योंकि यहां के कर्मचारियों की जिम्मेदारी मुख्य मंत्रीजी की नहीं, मेरी है। इसलिए यहां उठाने की आवश्यकता नहीं है। वह अलग से बात करिए। विधान सभा के बारे में यह परम्परा रही है कि इस हाउस में नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए बता रहा हूं।

श्री भीमराज : माफी चाहता हू मैं।

श्री परसराम मदेरणा : +++ इसलिए इस पर चर्चा करने की आवश्यकता यहां नहीं है और आपके साथ बात होनी चाहिए। मुख्य मंत्रीजी उदारता दिखा रहे हैं और अभी....

श्री अध्यक्ष : लेकिन लीगलपोजिशन यह है....

श्री परसराम मदेरणा : उदारीकरण की इकानामिक पालिसी भी कन्ट्री में और वर्ल्ड ओवर ग्लोबल चल रही है। +++

श्री अध्यक्ष : आप बोलिए।

श्री भीमराज : दूसरा, मैं निवेदन कर रहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लोगों के बारे में और उनके समर्थन के बारे में बहुत जोर शोर से महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा गया है। 55 में से 33 आपके सदस्य जीतकर आये हैं लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आपकी सरकार बनने के बाद मुख्य मंत्री महोदय, मर्डर हुए हैं,

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भीमराज)

उन मर्डर्स को आपके पुलिस के लोग आत्म-हत्या का मामला बना रहे हैं। जो चश्मदीद गवाह हैं वे चश्मदीद गवाह पुलिस में जाते हैं तो उनको पीटकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या यही हालत रहेगी ? 55 में से 33 आप लोग जीतकर आये हैं, आपके भाई जो गांव में मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या यही रवैया रहेगा ? इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन है इस बारे में कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है या हत्या होती है या गम्भीर मारपीट उनके साथ होती है तो उसके लिये उस गांव के पटवारी को और जिस थाने के अन्तर्गत ऐसी घटनाएं होती हैं, उस थाने के थानेदार को जिम्मेदार ठहराया जाये। साम्प्रदायिक सद्भाव की और साम्प्रदायिक संवेदनशील सरकार की आप बात करते हैं तो जिस जिले में यह साम्प्रदायिक दंगा हो, उसके लिये निश्चित तौर पर उस जिले के कलक्टर को और एस.पी. को क्या जिम्मेदार ठहराने की स्थिति में हैं ? अगर इस तरह का आप सदन में आश्वासन दें तो जिस साम्प्रदायिक सद्भाव को आप कायम करना चाहते हैं, उस साम्प्रदायिक सद्भाव की तरफ एक निश्चित ठोस कदम होगा और यह आपकी सरकार को एक नयी दिशा देगा।

दूसरा, पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण में किसी भी तरह का कोई उल्लेख नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी जब पिछली बार.... (व्यवधान)....मैं वही निवेदन कर रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी जब पिछली बार मुख्य मंत्री के रूप में पाली पधारे थे तो वहां पाली पधार कर माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि मैं इन फैक्ट्रियों, जो प्रदूषण फैला रही हैं, के 6 महीने में ताला लगवा दूंगा। वह 6 महीने भी गये, 12 महीने भी गये, साल भी गया, दो साल भी गये और सब कुछ हो गया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी तो कुछ भी घोषणा किसी भी समय कर सकते हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी फैक्ट्री को कोई ताला लगे लेकिन जो जिन फैक्ट्रियों की वजह से हमारी बांडी नदी और लूनी नदी तक, बालोतरा और बाड़मेर तक जो पानी, नदी और कुएं खराब हो चुके हैं, उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी कोई निश्चित घोषणा करें। उस प्रदूषण से हमारे काश्तकार भाईयों की जो जमीनें खराब हुई हैं, अगर सरकार उन जमीनों का कोई मुआवजा दें तो बेहतर होगा। जैसा हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा है कि वित्तीय व्यवस्था में माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत माहिर हैं, अगर वित्तीय व्यवस्था की उस माहिरता को साबित कर दें, उनको मुआवजा दिलाकर तो बेहतर होगा। और अगर उनको मुआवजा नहीं दिला सकें तो अब जबकि जोधपुर में पीने के पानी की 40 लाख लीटर पानी की व्यवस्था हो चुकी है और अगले चार-छह महीने में शायद पूर्ण भी हो जाये अगर आपकी सरकार ने उस पर पूरा ध्यान दिया तो, हमारे जिले से जोधपुर जाने वाला पानी जवाई बांध और हेमावास से, वह 40 लाख लीटर पानी इन्दिरा गांधी कैनाल से जोधपुर पहुंच जाय। और हमारे लोगों की जो जमीनें फैक्टरीयां प्रदूषण से प्रभावित हुई हैं, उन जमीनों की तरफ उस पानी को मोड़

(श्री भीमराज)

दिया जाय तो कुछ व्यवस्था उन काश्तकार भाइयों, जिनकी जमीनें प्रदूषण से खराब हुई है, के लिये हो सकती है। मत दीजिये आप मुआवजा उस मुआवजे को अगर आप देने की स्थिति में नहीं है, तो वित्तीय व्यवस्था करने में तो आप बड़े माहिर हैं लेकिन वह नहीं कर सकते तो कम से कम जवाई बंधे के पानी को, हेमावास के बंधे के पानी को जो प्रदूषण से जो जमीनें खराब हुई हैं, उन को दिलाने की मेहरबानी करके व्यवस्था करवाइये।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, डार्क जोन के सम्बन्ध में।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हर डार्क जोन के बारे में बात की जाती है। डार्क जोन जहां हैं वहां पानी है, पूरी तरह से पानी है, पूरी तादाद में पानी है पर उस इलाके को डार्क जोन घोषित कर दिया जाता है। उस डार्क जोन के जो काश्तकार हैं वह अपने कुएं खुदवाने के लिये और उस कुएं पर पम्प सैट लगाने के लिये या विद्युत कनेक्शन लेने के लिये जाते हैं तो टालते रहते हैं, सरकार की तरफ से उस डार्क जोन को हटाने की कोई भी समय पर व्यवस्था नहीं होती है। डार्क जोन के बारे में जो लालफीताशाही है, सरकारी अधिकारियों की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को शार्ट करके उस डार्क जोन को कम से कम हटाने के बारे में एक निश्चित नीति इस नयी सरकार को बनानी चाहिये।

तीसरा मेरा आपसे यह निवेदन है कि हम जो निर्दलीय हैं, वह नील गाय की तरह यह मेरे माननीय सदस्य खंगारसिंहजी उधर विराजमान हैं, तो यह रोजड़ों की तरह से, हम तो जिस के खेत में घुस गये भाजपा के खेत में घुस गये तो भाजपा के खेत खा गये, कांग्रेस के खेत में घुस गये तो कांग्रेस के खेत खा गये लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रोजड़े हैं, नील गायें हैं, वह रात भर हम काश्तकारों को, माननीय सदस्य उधर विराजमान है, खंगारसिंहजी साहब, इनके खेत में इनकी खुद की फसल नहीं बोयी गयी है, वह खुद मेरे साथ थे, इतनी भयंकर समस्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री खंगार सिंह चौधरी (खाचरियावास) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री खंगार सिंह चौधरी : इनके पिताजी के पहले से मैं भाजपा में हूं और 62 में मैंने चुनाव लड़ा है सीकर से। यह मुझे रोजड़े कैसे बता रहे हैं ? यह रोजड़े हैं।

श्री भीमराज : नहीं, नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, नील गायों की बात कह रहा हूं। नहीं, माननीय सदस्य महोदय, मैं नील गायों की बात कह रहा हूं।

श्री खंगार सिंह चौधरी : मैं भाजपा में हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं भाजपा में बैठा हूं।

श्री भीमराज : मैं नील गायों की बात कर रहा हूं। उन नील गायों की वजह से जो तकलीफ हो रही है किसानों को, उन नील गायों का....

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, कृपया समाप्त करें।

श्री भीमराज : साहब, मेरे को कुछ मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आपको पूरे दस मिनट दिये हैं।

श्री भीमराज : दस मिनट कहां हो गये ?

श्री अध्यक्ष : दस मिनट हो गये।

श्री भीमराज : कुछ तो टाइम दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपने 5.45 पर शुरू किया था। अब समाप्त करिये, एक माननीय सदस्य अभी और हैं।

श्री भीमराज : इसलिए यहां जो रोजड़ों की समस्या है उसके बारे में केन्द्र सरकार से बात करके....

एक माननीय सदस्य : +++ है।

श्री भीमराज : +++ मैं नहीं कहता। नील गायों की जो समस्या है उसके बारे में केन्द्र सरकार से जो वन संरक्षण अधिनियम है, 2-सी और 3-सी है उसके तहत बात करें।

एक छोटी सी बात मैं और कहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत नैतिकता की दुहाई देते हैं। नैतिकता तो वह होती है कि किसी आप जैसे विधायक को या किसी और को, यह तो स्वयं गंगानगर से हार कर आये थे, उनके कई चहेते हारे, इनके साथ के कई साथी हारे परन्तु इन्होंने एक दिन भी शोक नहीं रखा, दो दिन का शोक नहीं रखा....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गये और नेता बन कर....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। डा. शंकरलाल।

श्री भीमराज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नया आदमी हूं, कुछ मौका तो दें।

श्री अध्यक्ष : छह बजे हाउस स्थगित हो जायेगा।

श्री भीमराज : मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का भाषण समाप्त हो तब तक का समय बढ़ाने का प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : यह क्या मतलब हुआ ? घंटे भर तक बोलते रहेंगे। नहीं, नहीं, मैं घंटी बजा दूंगा तब तक। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम (गंगानगर) :.... मेरी प्रार्थना आपने स्वीकार नहीं की थी।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री शंकरलाल (कपासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो अभी चर्चा हो रही है बनीपार्क के विधायक श्री राजपालसिंहजी शेखावत ने जो उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है और उदयपुर के सदस्य ने उसका समर्थन किया है, मैं उसका अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

जो अभिभाषण यहां महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रस्तुत किया है उसमें मुख्य रूप से तीन सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया गया है। पहला है तेजी से विकास, दूसरा स्वच्छ प्रशासन और तीसरा जनता की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति। इन तीन बातों पर इस डाकूमेंट में खास तौर से विचार किया गया है। साथ ही राज्यपाल महोदय ने अपनी लिमिटेशन भी इसमें बयान की है। उनके अनुसार बजट सत्र आने वाला है और बजट प्रस्ताव बनने वाले हैं इसलिए सरकार की जो रीति नीति होगी, वह सही रूप में आने वाले समय में जो बजट प्रस्ताव आयेंगे। उन्हीं आधार पर पूरे रूप से या सही रूप से प्रकट होगी, ऐसा उन्होंने आग्रह किया है।

साथ ही उन्होंने एक आनेस्ट एडमिशन भी इसमें किया है। उनके अनुसार राष्ट्रपति शासन के दौरान इकानामी में जो वृद्धि होनी चाहिये थी वैसी गति नहीं रह पायी। जो सरप्लस बजट था वह घाटे में बदल गया और घाटा बढ़ता गया और अभी जो फिस्कल ईयर है उसमें अनुमान लगाया कि 57 करोड़ रुपये तक का घाटा हो जायेगा। यह उनका आनेस्ट एडमिशन है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही इसके अन्दर जो डायरेक्शन सेट किये हैं, जो अभी प्रिलिमिनरी इन्होंने इसमें डायरेक्शन बनाने की कोशिश की है कि एस. सी., एस. टी. के जो हमारे लोग हैं, उन लोगों ने भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है और अपने विधायक भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को जिता कर यहां पर भेजे हैं इसलिए यह विशेष दायित्व हो जाता है कि इन समुदायों की तरफ, जो पिछड़े हुए गरीब हैं, जो विकास की दौड में पीछे रह गये हैं, जो सदियों से प्रताड़ित हैं ऐसे लोगों की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार विशेष रूप से ध्यान दें। इस अभिभाषण में इस ओर खास तौर से ध्यान दिलाया है, इसका मैं स्वागत करता हूं।

इसके अन्दर बिजली के संबंध में काफी विस्तार से चर्चा है और सदन में भी इस संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। सरकार इन सब का फायदा उठायेगी और तद्नुसार काम करने की कोशिश करेगी लेकिन मेरा निवेदन है कि जो कुछ चीज रहगयी उसी संबंध में मैं कुछ बोलना चाहता हूं। उसमें एक है बिजली कनेक्शन कृषि कार्यों के लिये दिये जाते हैं, उसमें वन पोल और निल पोल सिस्टम जो है, बीच-बीच में सक्यूंलर निकालते हैं और उस आधार पर कनेक्शन दिये जाते हैं। इसमें भारी भ्रष्टाचार होने की गुंजाइश रहती है। वन पोल, निल पोल का सक्यूंलर जब निकलता है, जैसे हमारे यहां 30-40 कनेक्शन अभी आये हुए हैं उसमें जब फिजिबलिटी की जाती है

(श्री शंकरलाल)

तो बताते हैं कि इस जगह ट्रान्सफार्मर फिट नहीं है, यहां पर कनेक्शन नहीं हो सकता या विभिन्न प्रकार के कारण बताये जाते हैं। इस वजह से कनेक्शन देने में देरी हुई है या देने में आना-कानी की जाती है और यहीं से भ्रष्टाचार का जन्म होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो एक पोल, निल पोल के कनेक्शन हैं, या तो एक मुश्त दे दिये जायें। आज दिन तक 85 के बाद जो कनेक्शन बाकी हैं उनमें जो वन पोल, निल पोल, जो भी कनेक्शन दिये जा सकते हैं उस सिस्टम से, उनको एक मुश्त दे दिये जायें। इससे बिजली बोर्ड को भी आय होगी क्योंकि....

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 6-1-94 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.00 बजे गुरूवार, 6 जनवरी, 94 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 43 की सूची

भीलवाड़ा जिले की तहसील रायपुर, सहाड़ा क्षेत्र में आठवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य

क्र. सं.	तहसील/ पं. सं.	सड़क का नाम	जोड़े जाने वाले गांव का नाम	जनसख्या (1971)	राशि (लाखों में)	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1.	सहाड़ा	सम्पर्क सड़क नान्दसा (2 किमी.)	नान्दसा (खातसा)	1675	6.10	डामर सड़क 2 कि. मी.	जोड़े जा चुके हैं।
2.	रायपुर	सम्पर्क सड़क नान्दसा जागीर (2 कि.मी.)	नान्दसा जागीर	1312	6.10	डामर 2 कि.मी.	„
3.	रायपुर	सम्पर्क सड़क थला (2 कि.मी.)	थला	1391	6.10	रोड़ी की सड़क 2 कि. मी.	जोड़े जाना शेष है।
4.	रायपुर	खेमाणा—पालरा (4 किमी.)	पालरा	1251	12.20	ग्रेवल सड़क 4 किमी.	„
5.	रायपुर	बोराणा से कोट (11 कि.मी.)	कोट	1129	33.55	ग्रेवल सड़क 11 कि मी	„
6.	सहाड़ा	सम्पर्क सड़क अड़सीपुरा (4 कि.मी.)	अड़सीपुरा	1094	12.20	ग्रेवल सड़क 4 कि मी.	„
7.	सहाड़ा	गंगापुर आमली सड़क से शिवरती (3 कि.मी.)	शिवरती	1197	13.00	ग्रेवल—3 कि.मी.	„
			7		89.25 लाख		

परिशिष्ट—2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के पंचायत मुख्यालयों हेतु सम्पर्क सड़कें

54. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पिछले 4 वर्षों में किस-किस पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ा गया ? अब किस-किस ग्राम को कब तक पंचायत मुख्यालय से जोड़ने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पिछले 5 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 7 पंचायत मुख्यालयों को ग्रेवल/मैटल सड़क से जोड़ा गया है। (सूची "अ" संलग्न है) अब 9 पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जाना शेष है। (सूची "ब" संलग्न है) जिनमें से रानोली गांव को कृषि विकास कार्यक्रम (विश्व बैंक परियोजना) के अन्तर्गत वर्ष 95 में डामर सड़क से जोड़े जाने की सम्भावना है। शेष 8 पंचायत मुख्यालयों को जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में ग्रेवल व मैटल सड़कों से जुड़े पंचायत मुख्यालयों की सूची

क्र. सं.	पंचायत मुख्यालय	जनसंख्या 1971	जनसंख्या 1981
1.	सांकरवाड़ा	973	1102
2.	मातासूला	1063	1330
3.	खेड़ी	1626	1911
4.	शहराकर	1161	1328
5.	शेखपुरा	1477	1759
6.	जीतकीपुर	771	889
7.	कुंजेला	1770	2011

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सड़कों से नहीं जुड़े हुए पंचायत मुख्यालयों की सूची

क्र. सं.	पंचायत मुख्यालय	जनसंख्या 1971	जनसंख्या 1981
1.	पाल	1212	1664
2.	चिरावड़ा	1791	2560
3.	दलपुरा	436	568
4.	भीलावाड़ा	764	903
5.	उरदेन	566	587
6.	अजीजपुर	995	1122
7.	बडा	398	506
8.	रानोली	1228	1602
9.	मेडे का पुरा	—	766

पंचायत मुख्यालयों हेतु यातायात व्यवस्था

55. श्री परसादी लाल (लालसोट) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार पंचायत मुख्यालयों को यातायात सुविधाओं से जोड़ने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लालसोट के ग्राम पंचायत मुख्यालय श्रीयातलाबगांव, दौलतपुरा, खटवा, श्याम-पुरा, महादिया, सवासा, कालूवास, कल्ला-वास में पक्की सड़कें होने के बाद भी यातायात के लिए बसों की सुविधा नहीं है ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को यातायात सुविधा से जोड़ने के लिए राज्य परिवहन निगम की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में ऐसी कोई योजना विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है। ग्राम श्रीमा व ग्राम खटवा को छोड़कर शेष सभी ग्रामों को बस सुविधा सुलभ है। ग्राम खटवा व श्रीमा को बस सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कार्रवाई मार्गों का सर्वेक्षण कराने के बाद ही की जा सकेगी : सर्वेक्षण कराने के सम्बन्ध में जिला परिवहन अधिकारी, दौसा को निर्देश दे दिये गये हैं।

(3) उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों के मार्गों का यातायात उपलब्धता की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण कराये जाने के बाद ही पर्याप्त यात्री उपलब्धता होने पर निगम की बस सेवा चलाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

राजस्व ग्राम नेवा (फलौदी) की पेयजल व्यवस्था

56. **श्री पूनम चन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नव गठित राजस्व ग्राम नेवा (कानासर) तहसील फलौदी जिला जोधपुर की आबादी 2500 से अधिक है और इनको लगभग 10 कि. मी. से पेयजल प्राप्त करना पड़ रहा है ?

(2) इस गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, उल्लिखित ग्राम नेवा की जनसख्या 1991 की जनगणनानुसार 1618 है। ग्रामवासी लगभग 7-8 किलो मीटर दूरी पर ग्राम कानासर अथवा जोधपुर लिफ्ट कैनाल से पेयजल प्राप्त करते हैं।

(2) क्षेत्रीय जलदाय योजना चिन्नू-बाप के संवर्धन के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं जिसमें इस ग्राम को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

जोधपुर-जैसलमेर मार्ग का निर्माण

57. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निमाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जैसलमेर सड़क 102 कि. मी. से 125 कि. मी. तक का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से यह सड़क ठेके की शर्तों के अनुसार नहीं बन रही है ?

(3) क्या यह सही है कि इस सड़क में गिट्टी, मुरम, मूंगिया आदि जो काम में लिया गया है वह बहुत ही घटिया किस्म का है ?

(4) क्या यह भी सही है कि डामर का बहुत कम प्रयोग किया गया है जिससे सड़क बनते ही टूटनी शुरू हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच करा कर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर-जैसलमेर सड़क कि. मी. 102/0 से 123/0 तक का ठेका मैसर्स वाराह कंस्ट्रक्शन क. जोधपुर को दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। डामर का प्रयोग निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किया जा रहा है।

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न संख्या 48 का विवरण

जिला सवाई माधोपुर के टोडाभीम क्षेत्र में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा जिन ग्रामों में बस सेवायें संचालित की जा रही हैं उनके ठहराव स्थल व रात्रि विश्राम स्थलों का विवरण :—

क्र.स.	मार्ग का नाम	परिचक्र	ठहराव स्थल	रात्रि विश्राम स्थल
1.	हिण्डौन–जयपुर वाया टोडाभीम	5	महू सेलमपुर खेडला गाजीपुर भैंसा पावटा नांगल टोडाभीम बालाजीमोड़ मानपुर सिकन्दरा भाण्डारेज दौसा	कैला देवी करौली बयाना हिण्डौन
2.	हिण्डौन–टोडाभीम वाया गाजीपुर	16	महू सेलमपुर खेडला गाजीपुर	करौली टोडाभीम हिण्डौन
3.	महुवा–टोडाभीम वाया गाजीपुर	13	गाजीपुर पावटा भैंसा नांगल	महुवा टोडाभीम
4.	जयपुर–कमालपुरा वाया दौसा–बालाजी–टोडाभीम	2	घाटगेट दौसा सिकन्दरा मानपुर	कमालपुरा

क्र.सं.	मार्ग का नाम	परिचक्र	ठहराव स्थल	रात्रि विश्राम स्थल
			बालाजी मोड़	
			बालाजी मन्दिर	
			टोडाभीम	
			पदमपुरा	
			गोरडा	
			तमावा	
			धोखेड़ा	
5.	जयपुर–पदमपुरा वाया	2	घाटगेट	पदमपुरा
	दौसा–बालाजी–टोडाभीम		दौसा	
			सिकन्दरा	
			मानपुर	
			बालाजी मोड़	
			बालाजी मन्दिर	
			टोडाभीम	
6,	हिण्डौन–खोहरा वाया	2	महू	खोहरा
	गाजीपुर–टोडाभीम		सेलमपुर	
			खेडला	
			गाजीपुर	
			भैसा	
			नांगल	
			टोडाभीम	
			मान्नोज	
			दादनपुर	
7.	हिण्डौन–मोरडा वाया	1	महू	मोरडा
	गाजीपुर–टोडाभीम		सेलमपुर	
			खेडला	
			गाजीपुर	

(154)

क्र.सं.	मार्ग का नाम	परिचक्र	ठहराव स्थल	रात्रि विश्राम स्थल
			पावटा	
			नांगल	
			टोडाभीम	
			माचेडी	
			बीजलवाडा	
			बालघाट	
			नांगल	
8.	मोरडा ले महुवा वाया टोडाभीम–गाजीपुर	1	नांगल	हिण्डौन
			बालघाट	
			माचेडी	
			टोडाभीम	
			नांगल	
			भैसा	
			पावटा	
			गाजीपुर	
9.	हिण्डौन–नांगल–जयपुर वाया टोडाभीम	1	बालघाट	हिण्डौन
			माचेडी	
			टोडाभीम	
			बालाजी मन्दिर	
			बालाजी मोड	
			मानपुर	
			सिकन्दरा	
			दौसा	
10.	गंगापुर–दिल्ली वाया टोडाभीम	2	नादौती	दिल्ली
			गुढ़ाचन्द्रजी	
			माचेडी	
			घाटोली	

क्र.सं.	मार्ग का नाम	परिचक्र	ठहराव स्थल	रात्रि विश्राम स्थल
			टोडी	
			तमाबा	
			नांद	
			गोरडा	
			तलाई का बाग	
			मज्जूपुरा	
			पदमपुरा	
			सुजानपुरा	
			दादनपुर	
			मान्नोज	
			टोडाभीम	
			बालाजी मन्दिर	
			बालाजी मोड़	
			महुवा	
			खेड़ली	
			नगर	
			पहाडी	
			फिरोजपुर	
			सोहना	
			गुड़गांवा	

156

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 का विवरण

बामनवास तहसील में स्वीकृत जलप्रदाय योजनाओं की प्रगति सम्बन्धी सूचना

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का प्रकार	स्वीकृत राशि	पूर्ण हो चुके कार्य	प्रगतिरत कार्य
1.	बानोर शैफीपुरा	क्षेत्रीय	45·19	नलकूप 5, राइजिंग मेन, 2250 मी.सी. डब्लू.आर–1, उच्च जलाशय-2, डिस्ट्रीब्यूशन 57·20 कि. मी. जी. एल. आर. 14 नं.	राधेकीं एवं ठीकरया पाइपलाइन 4·5 कि. मी. कार्य शेष है। दातासूती एवं श्यामपुरा में भूतल जलाशय का कार्य।
2.	किशनपुरा कुण्डली	क्षेत्रीय	9.67	नलकूप–1, भूतल जलाशय-5, राइजिंग मैंन 400 मीटर जलाशय–1,	पाइपलाइन भौताई/जाहरा 3·5 कि.मी. (आर.सी.सी. उच्च जलाशय जाहरा)
3.	लिवाली बामनवास	क्षेत्रीय	11·02	खुला कुआ–2, राइजिंग मैन 2 कि.मी.; भूतल जलाशय–4 डिस्ट्रीब्यूशन 15 कि.मी.	दो खुले कुए

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 का विवरण

कार्यालय नगर पालिका कानोड़ जिला–उदयपुर (राजस्थान)

क्रमांक/332 दिनांक 10-5-93

श्रीमान् सहायक अभियन्ता महोदय,
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग,
उप खण्ड भीण्डर।

विषय :—स्वीकृत हैण्ड पम्प 5 लगाने के प्रस्ताव।

प्रसंग :—आपका पत्रांक 892 दिनांक 30-4-93.

महोदय,

निवेदन है कि नगर पालिका कानोड़ के लिये 5 हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिनके प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं—

1. श्मशान घाट के पास (दावतों के साथ जाने का रास्ता)
2. जवाहर विद्यापीठ के पास हनुमान जी के पास
3. तुलसी छात्रावास के पास करमड़िया के रास्ते पर
4. सूरजपोल नई बस्ती
5. नगर पालिका उद्यान के पास

उक्त प्रस्ताव अनुसार हैण्ड पम्प लगाने का श्रम करावें।

ह./-
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका कानोड़, उदयपुर (राज.)।

कार्यालय नगर पालिका कानोड़, जिला–उदयपुर (राजस्थान)

क्रमांक/न.पा.का./93/349-350 दिनांक 13-5-93

श्रीमान् सहायक अभियन्ता महोदय,
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग,
उप खण्ड, भीण्डर।

विषय :—हैण्ड पम्प स्वीकृत 5 लगाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :—आपका पत्रांक 892 दिनांक 30-4-93

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पूर्व में आपको नगर पालिका, कानोड़ के पत्रांक 332 दिनांक 10-5-93 भिजवाया गया है। जिसमें 5 स्थानों के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं किन्तु उक्त प्रस्ताव में क्रमांक 3 पर अंकित तुलसी छात्रावास के पास कामडिया के रास्ते पर लगाने का प्रस्ताव था उक्त प्रस्ताव मे आंशिक संशोधन किया गया है। अब उक्त हैण्ड पम्प तुलसी छात्रावास के पहले जहां नई बस्ती बनी है वहां लगाने का श्रम करावें। अन्य चार प्रस्ताव पूर्ववत् ही रहेंगे।

ह./-
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका, कानोड़।

क्रमांक दिनांक 13-5-93

प्रतिलिपि :—श्रीमान् कनिष्ठ अभियन्ता महोदय, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, कानोड़ में सूचनार्थ प्रेषित है।

553
30-6-93

कार्यालय नगर पालिका, कानोड़ (उदयपुर)

प्रेषक :—
अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका, कानोड़।

प्रेषित :—
श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता महोदय,
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग,
जिला ग्रामीण खण्ड, उदयपुर।

क्रमांक/न. पा. का. दिनांक..................

विषय :—पालिका क्षेत्र में हैण्ड पम्प लगाने बाबत।

प्रसंग :—आपका पत्रांक 2332 दिनांक 4-6-93

प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि श्रीमान द्वारा चाही गई सूचना इस प्रकार है।

हैण्ड पम्प तीन के स्थान इस प्रकार हैं—

1. 'पीपलास माता वार्ड नं. 10
2. सार्वजनिक शौचालय शफी मोहमद गली, मारदीन मो. की गली में
3. लक्ष्मी नारायण सुथार की पत्थर फैक्टरी के आसपास।

ह./-
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका, कानोड़ (उदयपुर)।

क्र. सं.	हैण्ड पम्प स्थापना हेतु आवेदन के अनुसार स्थान	हैण्ड पम्प स्थापना का वास्तविक नाम	अन्यत्र लगाने का कारण
1.	श्मशान घाट के पास (दावतों के साथ जाने वाला रास्ता)	श्मशान घाट के पास (दावतों के साथ जाने वाला रास्ता)	निर्धारित स्थान पर लगाया गया है।
2.	जवाहर विद्यापीठ के पास हनुमानजी के पास	जवाहर विद्यापीठ के पास हनुमानजी के पास	,,
3.	सूरजपोल नई बस्ती	सूरजपोल नई बस्ती	,,
4.	नगरपालिका उद्यान के पास सार्वजनिक रास्ते की ओर	नगरपालिका उद्यान के पास सार्वजनिक रास्ते की ओर	,,
5.	तुलसी छात्रावास के पास नई बस्ती	तुलसी छात्रावास के पास नई बस्ती	,,
6.	पीपलास माता वार्ड नं. 10	पीपलास माता वार्ड नं. 10 असफल	,,
7.	लक्ष्मीनारायण सुथार की पत्थर की फैक्टरी के आसपास	लक्ष्मीनारायण सुथार की पत्थर की फैक्ट्री के आसपास	,,
8.	सार्वजनिक शौचालय शफी मोहम्मद की गली में।	तुलसी छात्रावास के पास	शफी मोहम्मद गली में आवेदित किए गए के स्थान से 100 मीटर दूरी पर पूर्व में ही एक हैण्ड पम्प कार्यरत होने के कारण।

क्र. सं.	हैण्डपम्प का स्थान
1.	बस स्टेण्ड के पास
2.	लक्ष्मीनारायण सुथार के पत्थर की फैक्टरी के आसपास (गोवर्धनलाल चौबीसा के घर के पास)
3.	ब्रह्मपुरी पुलिया के पास

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 48 की सूची

नागौर जिले में पक्की सड़कों से जोड़े जाने वाले गांवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	जनसंख्या (1971)
1	2	3
1.	मिडा	4022
2.	बुडगो	4151
3.	रातू	2506
4.	पीन	2639
5.	हरनावा	2872
6.	गुल्लार	2591
7.	खादलो	2029
8.	रोहिसा	2001
9.	पालरी-कालन	2166
10.	जाहरेली	2070
11.	बांसा	2480
12.	रोडू	2416
13.	दायवा	2028
14.	अगाकसर	2342
15.	जिलाया	2160
16.	लोचाना	2425
17.	गूडरसठ	2354
18.	खुर्दा	2133
19.	चाहूं	1575
20.	रोहिनी	1662
21.	उन्त्यावाला	1579
22.	धावंदा	1551

1	2	3
23.	पालरी-जोदा	1814
24.	जानाना	1641
25.	नीमरी-चन्दावता	1971
26.	जाखेरा	1794
27.	मेवरा	1750
28.	रोतू	1590
29.	बोदवा	1559
30.	बादलीया	1555
31.	अलखपुरा	1538
32.	सुनारी	1606
33.	दोलिया	1517
34.	लेरो	1606
35.	बालूद्र	1872
36.	मिथराली	1645
37.	टोडास	1954
38.	रासल	1951
39.	चावंडिया	1562
40.	बूनी	1644
41.	भानोता	1534
42.	नालोत	1657
43.	सबलपुरा	1608
44.	बीलोन	1595
45.	बेसरोली	1694
46.	बींचवा	1706
47.	बाजवास	1760

162

परिशिष्ट—7

सूची (क)

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 की सूचियां

1. R. D. Bridge on River Dhoond near village Kanota at km. 220-221.

(i) Year of Construction : April, 1985

(ii) Cost of Construction : Rs. 169.61 lacs.

REVENUE COLLECTION INFORMATION

S. No.	Years	Amount
1.	1985-86	Rs. 11,45,602.00 Deptt.
2.	1986-87	Rs. 37,63,090.00 ,,
3.	1987-88	Rs. 39,61,660.00 ,,
4.	1988-89	Rs. 47,65,000.00 By Auction.
5.	1989-90	Rs. 42,50,000 00 ,,
6.	1990-91	Rs. 44,26,000.00 ,,
7.	1991-92	Rs. 49,00,000.00 ,,
8.	1992-93	Rs. 61.00,000.00 ,,
9.	Upto Dec. 93	Rs. 54,25,000·00 ,,
	Grand Total	Rs. 3,87,36,352.00

Balance amount to be recovered from 1-1-94 to 5-4-94 Rs. 15.75 lacs.

सूची (ख)

टोल टैक्स की वसूली से मुक्त वाहन

भाग प्रथम भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर—

1 प्रतिरक्षा विभाग के वाहन

2. पुलिस विभाग के वाहन

3 अग्नि शमन सम्बन्धी वाहन

4. रोगी वाहन

5. मृतकों को ले जाने वाले वाहन

6. डाक एवं तार विभाग के वाहन

7. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के वाहन
पंचायत समिति एव स्थानीय विभाग के वाहन

8. राज्य विद्युत मण्डल के वाहन जो ड्यूटी पर हों।

निम्न वाहन विशिष्ट व्यक्तियों के माने जायेंगे—
भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, केन्द्रीय एवं राज्य मंत्री, राज्य सभा, लोक सभा, राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता जिन्हें मंत्री स्तर प्राप्त है, राज्यपाल, लेफ्टीनेन्ट गर्वनर, एक्जीक्यूटिव काउन्सलर, स्पीकर, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की लोक सभा/विधान सभा के अध्यक्ष/भारत में विदेशी विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति जो कि राज्य सरकार के मेहमान हैं, विदेशी डिप्लोमेट जो भारत में रह रहे हैं एवं सी. डी. सिम्बल की कारों का उपयोग करते हैं।

भाग द्वितीय–राज्य सरकार के उच्च मार्ग/सड़कें—

प्रतिरक्षा विभाग के वाहन, पुलिस वाहन, अग्नि शमन वाहन, रोगी वाहन, मृतकों को ले जाने वाले वाहन, डाक व तार विभाग के वाहन, केन्द्रीय, राज्य सरकार, पंचायत समिति एवं स्थानीय निकाय के वाहन जो ड्यूटी पर हों।

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	योजना का नाम
नादौती तहसील की पूर्ण सड़कें :—		
1.	गंगापुर नादोती गुढाचन्द्रजी सड़क	
2.	नादोती महावीर जी सड़क	
नादौती तहसील की अपूर्ण सड़कें :—		
1	शहरगढ़ खेड़ा वाया नागौर	एन.आर.ई.पी.
2.	शहर से सोप	आर.एल ई.जी.पी.
3.	सोप कुंजेला केमला	आर.एल ई जी.पी.
4.	सम्पर्क सड़क सहाबद	एन.आर.ई.पी.
5.	सम्पर्क सड़क भोलापाड़ा	,,
6.	सम्पर्क सड़क रौंसी	आर.एल.ई.जी.पी.
7.	सम्पर्क सड़क तेसगांव	एन आर.ई.पी.
8.	सम्पर्क सड़क राजपुरा	आर.एल.ई.जी पी
9.	सम्पर्क सड़क रामपुर	एन.आर.ई.पी.
10.	सम्पर्क सड़क जीतकीपुर वाया दलपुरा	,,
11.	सम्पर्क सड़क गुढाचन्द्रजी लालसरपाल अलूवा–नादौती	,,
12.	सम्पर्क सड़क सलावद	,,

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 55 की सूचियां

राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर में गत तीन वर्षों से रिक्त पदों की सूचना :—As on 1–12–93

क्र.सं.	पद का नाम	पद संख्या	रिक्त रहने की अवधि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	वरिष्ठ प्रवक्ता	3	मई, 92 से लगातार	
2.	प्रवक्ता (सी. डी.)	1	मई, 92 से लगातार	
3.	प्रवक्ता (सी. ए.)	1	मई, 92 से लगातार	
4.	प्रवक्ता (कम्पयूटर)	1	5 दिसम्बर, 92 से लगातार	
5.	तकनीकी सहायक	1	अप्रेल, 92 से लगातार	
6.	चतुर्थ श्रेणी सेवा वर्ग (लैब-अटेन्ड)	4	अप्रेल, 90 से लगातार	

राजकीय रामचन्द्र खेतान पोलीटेक्निक, जयपुर

वर्तमान में निम्नांकित पद रिक्त हैं—

क्र.सं.	पद का नाम	पद की संख्या	पद कब से रिक्त है
1	2	3	4
1.	विभागाध्यक्ष, प्रोडक्शन इंजी.	1	6-8-93
2.	विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर	1	21-4-92
3.	विभागाध्यक्ष, आरकीटेक्चर	1	21-4-92
4.	वरिष्ठ प्रवक्ता, कम्प्यूटर	1	"
5.	वरिष्ठ प्रवक्ता, इलैक्ट्रानिक्स	1	"
6.	प्रवक्ता सिविल	1	2-12-91
7.	प्रवक्ता यांत्रिकी	1	"
8.	प्रवक्ता विद्युत	1	16-11-93
9.	प्रवक्ता तकनिकी	1	6-5-93
10.	प्रवक्ता अतकनिकी	1	"
11.	ए.टी पी.ओ.	1	21-4-92
12.	प्रोग्रामर	2	21-4-92 6-5-93

(166)

1	2	3	4
13.	वरिष्ठ लिपिक कम स्टेनो	1	21-4-93
14.	कम्प्यूटर आपरेटर	1	6-5-93
15.	टैक्नीशियन इलैक्ट्रोनिक्स	1	21-5-92
16.	टैक्नीशयन कम्प्यूटर	1	6-5-93
17.	प्रयोगशाला सहायक	1	8-4-91
18.	कनिष्ठ लिपिक	2	8-5-93 14 8-93
	कुल रिक्तया	20	

ह./–
प्रधानाचार्य,
राजकीय रामचन्द्र खेतान पोलीटेक्निक,
जयपुर।

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

क्रमांक : एफ. 3 (4) (53)/अधिशेष/संआज./769 दिनांक : 31-5-93

प्रधानाचार्य,
खेतान पोलिटेक्निक, जयपुर।

विषय :— वेतनमान–1 पद फर्राश (स्वीपर) को भरने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :—आपका पत्र क्रमांक : खेपोज/स्था/93/2865 दिनांक 4-5-93

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि इस संभाग में फर्रास (स्वीपर) के पद हेतु वांछित योग्यता के अधिशेष वर्कचार्ज कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। अतः इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग के पत्र क्रमांक प. 13 (15) साप्र./3183 दिनांक 11-5-93 के अनुसार अन्य संभागीय आयुक्तों एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, राजस्थान, जयपुर से सम्पर्क करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह./–
(आर. एन. चतुर्वेदी)
अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर

राजस्थान सरकार

पत्र संख्या—प. 2 (1) संआवी/संस्था/93/7012 तारीख 19-10-93

प्रेषक :—
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर ।

प्रधानाचार्य,
खेतान पोलिटेकनिक महाविद्यालय,
जयपुर ।

विषय :— फर्राश के पद को भरने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :—आपका पत्रांक : 5555 दिनांक 16-9-93

महोदय,

संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में बीकानेर संभाग में फर्राश (स्केल न. 1) के पद हेतु उपयुक्त अधिशेष वर्कचार्ज कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। अनुपलब्धता प्रमाण पत्र हेतु कृपया सम्बन्धित संभागीय आयुक्त से सम्पर्क करने का कष्ट करें ।

भवदीय,
ह./-
अति. संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

कार्यालय संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा

क्रमांक :—प-2 (88) डीसी/स्टेट/विकास/93/1726 दिनांक : 14-10-93

निमित्त :—
प्रधानाचार्य,
खेतान पोलीटेक्निक, जयपुर

विषय :—वेतन श्रृंखला 1 से 11 के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों हेतु अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र ।

संदर्भ :—आपका पत्रांक 5554 दिनांक 16-9-93

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषय में लेख है कि सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प-13 (15) सा.प्र./3183 दिनांक 13-9-93 के

अनुसार अब वेतन श्रृंखला 1 से 11 के रिक्त पदों हेतु सम्बन्धित संभागीय आयुक्त द्वारा एवं वेतन श्रृंखला 11 से उच्च वेतन श्रृंखला के रिक्त पदों हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। अन्य संभागीय आयुक्तगण से सम्पर्क करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

भवदीय,
ह./-
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
एवं
सदस्य सचिव,
संभागीय समावेशन समिति,
कोटा संभाग, कोटा।

राजस्थान सरकार

ओर से :—	को :—
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	प्रधानाचार्य,
सिचाई संभाग, जोधपुर	रामचन्द्र खेतान पोलिटेक्निक
	महाविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : प. 18 (11)/श्रम/13371 दिनांक : 1-12-93

विषय :—वेतनमान एक पद पर फर्राश (स्वीपर) को भरने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :—आपका पत्र सं. 5556 दि. 16-9-93 (मुख्य अभियन्ता, सिचाई राज. जयपुर को)

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रसंगित पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि इस सम्भाग के अधीन स्वीपर पद पर कोई अधिशेष कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,
ह./-
अधिशासी अभियन्ता एवं प्रा. सहा.
वास्ते अति. मुख्य अभियन्ता,
सिचाई सम्भाग, जोधपुर

कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर

क्रमांक एफ 3 (15) 11/स्था/93/7185 दिनांक 20-11-93

निमित्त,

प्रधानाचार्य,

रामचन्द्र खेतान पोलिटेक्निक महाविद्यालय,

जयपुर ।

विषय :—अनुपलब्धता प्रमाण पत्र बाबत ।

प्रसंग :—आपका पत्र क्रमांक 5553, दिनांक 16-9-93

विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा अपेक्षित निम्न पदों के लिए वांछित योग्यता प्राप्त वर्क चार्ज्ड अधिशेष कर्मचारी वर्तमान में इस संभाग में उपलब्ध नहीं है, अतः कृपया अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र हेतु संभागीय आयुक्त, जयपुर से सम्पर्क करने का श्रम करें ।

भवदीय,

ह./–

अति. सम्भागीय आयुक्त,

उदयपुर

परिशिष्ट—10

अधिसूचनाएँ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री द्वारा उपस्थापित)

(क) वित्त (ग्रुप–4) विभाग—

1. अधिसूचना संख्या एफ-4 (8) वित्त/ग्रुप-4/89-53 दिनांक 12 फरवरी, 1993 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं;

2. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (67) वित्त/ग्रुप-4/92-50 दिनांक 12 जनवरी, 1993 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं;

3. अधिसूचना संख्या एफ 4 (8) वित्त/ग्रुप-4/89-60 दिनांक 23 मार्च, 1993 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं;

4. अधिसूचना संख्या एफ 2 (11) वित्त/ग्रुप 4/92 दिनांक 5 नवम्बर, 1992 जिसके द्वारा राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 जिल्द-I में संशोधन किये गये हैं; एवं

5. अधिसूचना संख्या एफ. 2 (5) वित्त/ग्रुप-4/92 दिनांक 15 मई, 1993 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा उपस्थापित)

(ख) ऊर्जा विभाग

1 अधिसूचना क्रमांक प. 7 (4) ऊर्जा/92 दिनांक 31 अक्टूबर, 1992 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत (प्रदाय) नियम, 1963 में संशोधन का प्रारूप अधिसूचित किया गया है; एवं

2. अधिसूचना क्रमांक प. 7 (5) ऊर्जा/92 दिनांक 8 दिसम्बर, 1992 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत (प्रदाय) नियम, 1963 में संशोधन किये गये हैं।

(श्री नाथूसिंह गुर्जर, राज्य मंत्री, पंचायती राज द्वारा उपस्थापित)

(ग) ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग

1. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (1) एल एण्ड.जे. / आर.डी.पी./90/2114 दिनांक 25-5-1993 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं; एवं

2. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) विधि/ग्रा.वि.प /93/2641 दिनांक 30-6-1993 जिसके द्वारा राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद् (सेवा के सदस्यों के आश्रितों की भर्ती) नियम, 1978 में संशोधन किये गये हैं।

(श्री रोहिताश्व, राज्य मंत्री, यातायात द्वारा उपस्थापित)

(घ) परिवहन विभाग

1. अधिसूचना संख्या एफ. 7 (2) ट्रांस/रूल्स/89-90/एच.क्यू दिनांक 26 जुलाई, 1993 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में संशोधन किये गये हैं;

2. अधिसूचना संख्या एफ. 7 (2) परि/रूल्स, फीस, अमेण्ड/93 दिनांक 6 अक्टूबर, 1993 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में संशोधन किये गये हैं;

3. अधिसूचना संख्या एफ. 10 (24) परि/पी डी./91/पार्ट–III दिनांक 22 अप्रेल, 1993 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अनिनियम, 1951 के अन्तर्गत मल्टी एक्सल माल यान को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित कर के संदाय से आंशिक रूप से छूट दी गई है;

4. अधिसूचना संख्या एफ. 10 (240) परि/पी.डी./91/पार्ट–III दिनांक 27 अगस्त, 1993 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, सार्वजनिक वाहक माल यानों को आंशिक रूप से छूट दी गई है;

(172)

5. अधिसूचना संख्या प. 6 (96) कर/शैक्षणिक/89 दिनांक 21 जुलाई 1993;

6. अधिसूचना संख्या परि/प 6 (1) कर/87 दिनांक 5 अक्टूबर, 1993;

7. अधिसूचना संख्या प. 6 (1) कर/परि/87 दिनांक 16-2-1993;

8. अधिसूचना क्रमांक प. 6 (1) कर/परि/87 दिनांक 8-4-1993;

9. अधिसूचना क्रमांक प. 6 (1) कर/परि/87 दिनांक 23-9-1993;

10. अधिसूचना क्रमांक परि/प. 6 (1) कर/87 दिनांक 6-10-1993;

11. अधिसूचना क्रमांक परि/प. 6 (1) कर/87 दिनांक 9-11-1993

जिनके द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के शैक्षणिक भ्रमण हेतु बसें कर मुक्त की गयी हैं।